दलों के मुखियाओं को सख्ती बरतनी चाहिए

कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह कथन बिल्कुल उचित है कि, संदेशखालि में यदि यौन उत्पीडऩ की एक प्रतिशत आरोप सही पाए गए तो यह बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। यौन उत्पीडऩ के कथित पीड़ितों के लगभग सौ हलफनामे इसमें शामिल हैं। इसमें जमीन कब्जा के मामले व हिंसा की घटनाएं भी हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने कहा पूरा जिला प्रशासन और सत्तारूढ़ शासन को जिम्मेदारी निभानी होगी। सौ प्रतिशत जिम्मेदारी निभानी होगी। संदेशखालि में निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख व उसके सहयोगियों पर स्थानीय लोगों की जमीनें हड़पने व महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं। इस पर एक याचिकाकर्ता वकील ने इस घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजंसी से कराने की मांग अदालत से की। जिस पर पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता ने विरोध करते हुए दावा किया कि केंद्रीय एजंसियों ने भरोसा खो दिया है। पशिचम बंगाल के कूचविहार में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संदेशखालि की घटनाओं का जिक्र करते हुए आासन दिया कि दोषियों को अपना शेष जीवन जेल में बिताना होगा। इस दरम्यान ईडी ने शेख के बैंक खातों समेत उसके स्वामित्व वाले व्यवसायों से जुड़े खातों को फ्रीज करना चालू कर दिया है। पीड़िताओं ने दिल दहलाने वाली आपबीती सुनाई। उन्हें मजदूरी की आड़ में बुलाया जाता था, परंतु युवा व आकषर्क महिलाओं को मनोरंजन के नाम पर जबरन रोक लिया जाता था। उनके साथ मारपीट होती व अन्य तरीकों से उन्हें प्रताड़ित किया जाता। हालांकि स्थानीय नेता व ममता बनर्जी के करीबी इसे शुरुआत से ही बंगाल विरोधी प्रचार बता रहे हैं, परंतु यह सिर्फ भाजपा या सीपीएम के दुष्प्रचार का नतीजा नहीं कहा जा सकता। घटना को लेकर राज्य सरकार के भीतर शंका न होती तो वह आनन-फानन शेख को निलंबित करने से हिचकती। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नेतागीरी की आड़ में यह दबंगई केवल बंगाल में ही हो रही है। वास्तव में इस तरह का अत्याचार राजनीति की छतछ्राया में देश भर में होता रहता है। जिस में जमीनों के कब्जे व बेवजह आम जनता का उत्पीडऩ शामिल है। यह गंभीर समस्या है, इस पर दलों के मुखियाओं को सख्ती बरतनी चाहिए और ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना चाहिए।

परिवारवाद की जकड़न में फसता लोकतंत्र

आरती कुमारी

भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। यह सभी जानते हैं कि भारत में जनता के लिए जनता का ही शासन है। जनता के शासन का सीधा तात्पर्य यही है कि जनता अपने बीच के किसी व्यक्ति को नायक बनाकर अपना प्रतिनिधि बनाती है। लोकतंत्र में जनता की पसंद और नापसन्द को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आज हमारे देश में राजनीतिक दल अपने ही परिवार के कुछ लोगों को जबरदस्ती आगे करके नायक बनाने का खेल खेल रहीं हैं। यह खेल निश्चित रूप से लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कहा जा सकता है। इस श्रेणी में एक या दो दल नहीं, कमोवेश हर राजनीतिक दल आज परिवारवाद की राह का अनुसरण करने के लिए अग्रसर हो रहा है। सवाल यह आता है कि आज नेता का बेटा या बेटी को ही विरासत सौंपने का चलन क्यों बढ़ रहा है, जबकि सारे राजनीतिक दल विशेषकर विपक्षी राजनीतिक दल लोकतंत्र को बचाने का नाराज बुलंद करने का सब्जबाग़ दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर एक रैली की, जिसमें परिवार को राजनीतिक विरासत सौपने की ही राजनीति दिखाई दी। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि अब विपक्षी दल लोकतंत्र के बजाय परिवारवाद को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सत्ता चाह की रास्ते तलाश करने वाला विपक्ष आज पूरी तरह से परिवारवाद की राजनीति को ही चरितार्थ करने की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की गिरफ़्तारी के पश्चात विपक्षी राजनीतिक दलों की राजनीति परिवार को आगे लाने की क़वायद करने वाली ही लग रही है। पहले कांग्रेस, समाज़वादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और राष्ट्रीय जनता दल केवल अपने परिवार को ही आगे करके राजनीति करते रहे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस दिशा में आम आदमी पार्टी और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा भी शामिल हो गयी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी अब सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। हालांकि वे जनता की सहानुभूति पाने के लिए अरविन्द केजरीवाल के राजनीतिक अस्तित्व को फिर से स्थापित करने का प्रयास करेंगी, लेकिन केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष की ओर से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आज से एक दशक पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान से पटकथा लिखी गई, आज वही रामलीला मैदान भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर केजरीवाल को बचाने का गवाह बना। लोकतंत्र बचाने के नाम पर की गयी इस रैली को किसी आभासी प्रहसन से कम नहीं कहा जा सकता। अगर केजरीवाल ने कुछ किया नहीं होता तो उसे न्यायालय से आरोप मुक्त करके छोड़ दिया जाता। पहले प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत के बाद अब केजरीवाल न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास अपने बचाव के लिए ठोस प्रमाण नहीं हैं। यह बात सही है कि एक समय दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार और वर्तमान राजनीतिक कार्य प्रणाली से बहुत त्रस्त हो गई थी, ऐसी स्थिति में जनता को केजरीवाल में एक नायक दिखाई दिया, जो जननायक बनने की श्रेणी में आ सकता था, लेकिन ज़ब उन पर और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, तब इस पटकथा की इबारत बदली हुई सी लगने लगी। अब आप पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह दो लाख के निजी मुचलके पर जेल से सशर्त बाहर आए तो उनका स्वागत ऐसे किया गया, जैसे वे आरोप मुक्त हो गए हों। आम आदमी पार्टी के इस प्रकार के चरित्र को देखकर यही कहा जा सकता है कि जो पार्टी राजनीति में बदलाव लाने का सपना दिखाकर मैदान में आई थी, आज वह भी समय के अनुसार बदल गई है। खैर... यहां परिवारवाद की बात हो रही है। आप नेता संजय सिंह जेल से छूटने के बाद अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे। यह वाकया निश्चित ही यह संकेत दे रहा है कि अब संभवतः सुनीता केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सपनों को पूरा करने वाली हैं। यह बात एक दम प्रामाणिक रूप से कही जा सकती है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है, इसके बावजूद भी राजनीतिक़ दल अपने परिवार तक ही अपने दल को सीमित रखने की क़वायद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि इन दलों को वास्तविक लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने तो परिवारवाद की सीमाएं लांघ दी। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक योग्यता के एक अनपढ़ पत्नी को राज्य की कमान सौंप दी। अब अपने पुत्रों को गद्दी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार दो बार लोकसभा के चुनावों में पराजय की स्थिति में पहुंचाने वाले विरासती पृष्ठभूमि के नेता राहुल गांधी भी परिवारवाद के ही परिचायक हैं। आज भले ही कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया हो, लेकिन वे भी राहुल गांधी को किनारे करने का साहस नहीं दिखा सकते। कांग्रेस के बारे में यही कहा जा सकता है कि वह आज भी परिवारवाद के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकी है। कुछ ऐसा ही नहीं, बल्कि इससे ज्यादा परिवारवाद समाज़वादी पार्टी में दीखता है। मुलायम सिंह के परिवार के लगभग सभी सदस्य या तो विधायक और सांसद हैं या रह चुके हैं। बसपा नेता मायावती ने भी अपनी विरासत अपने परिवार को ही सौंपी है। ऐसे उदाहरण से क्षेत्रीय दल भी अछूते नहीं हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट पर परिवार कायम है तो नेशनल कान्फ्रेंस पर शेख अब्दुल्लाह का परिवार ही कमान संभाल रहा है। ख़ास बात यह है कि यह सभी परिवार पार्टी के मुखिया ने ही स्थापित किए हैं। लोकतंत्र में ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए परिवारवाद को राजनीति से अलग करने की जरुरत है, क्योंकि जहां परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति होगी, वहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। लोकतंत्र जनता का होता है, जहां जनता को महत्व मिलेगा, वही तो लोकतंत्र है, और जहां परिवार को महत्व दिया जाता हो, वहां तानाशाह जैसी प्रवृति जन्म लेती है। उनको इसका अहंकार भी हो सकता है कि हम तो सत्ता के लिए ही बने हैं और यही अहंकार भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए अब इस बात की बहुत आवश्यकता है कि भारत में लोकतंत्र को कायम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं, नहीं तो जनता के शासन के स्थान पर परिवारवाद के सहारे तानाशाही का राजनीति कायम हो जाएगा। भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। यह सभी जानते हैं कि भारत में जनता के लिए जनता का ही शासन है। जनता के शासन का सीधा तात्पर्य यही है कि जनता अपने बीच के किसी व्यक्ति को नायक बनाकर अपना प्रतिनिधि बनाती है। लोकतंत्र में जनता की पसंद और नापसन्द को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आज हमारे देश में राजनीतिक दल अपने ही परिवार के कुछ लोगों को जबरदस्ती आगे करके नायक बनाने का खेल खेल रहीं हैं। यह खेल निश्चित रूप से लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कहा जा सकता है। इस श्रेणी में एक या दो दल नहीं, कमोवेश हर राजनीतिक दल आज परिवारवाद की राह का अनुसरण करने के लिए अग्रसर हो रहा है। सवाल यह आता है कि आज नेता का बेटा या बेटी को ही विरासत सौंपने का चलन क्यों बढ़ रहा है, जबकि सारे राजनीतिक दल विशेषकर विपक्षी राजनीतिक दल लोकतंत्र को बचाने का नाराज बुलंद करने का सब्जबाग़ दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर एक रैली की, जिसमें परिवार को राजनीतिक विरासत सौपने की ही राजनीति दिखाई दी। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि अब विपक्षी दल लोकतंत्र के बजाय परिवारवाद को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सत्ता चाह की रास्ते तलाश करने वाला विपक्ष आज पूरी तरह से परिवारवाद की राजनीति को ही चरितार्थ करने की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की गिरफ़्तारी के पश्चात विपक्षी राजनीतिक दलों की राजनीति परिवार को आगे लाने की क़वायद करने वाली ही लग रही है। पहले कांग्रेस, समाज़वादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और राष्ट्रीय जनता दल केवल अपने परिवार को ही आगे करके राजनीति करते रहे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस दिशा में आम आदमी पार्टी और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा भी शामिल हो गयी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी अब सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। हालांकि वे जनता की सहानुभूति पाने के लिए अरविन्द केजरीवाल के राजनीतिक अस्तित्व को फिर से स्थापित करने का प्रयास करेंगी, लेकिन केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष की ओर से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आज से एक दशक पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान से पटकथा लिखी गई, आज वही रामलीला मैदान भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर केजरीवाल को बचाने का गवाह बना। लोकतंत्र बचाने के नाम पर की गयी इस रैली को किसी आभासी प्रहसन से कम नहीं कहा जा सकता। अगर केजरीवाल ने कुछ किया नहीं होता तो उसे न्यायालय से आरोप मुक्त करके छोड़ दिया जाता। पहले प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत के बाद अब केजरीवाल न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास अपने बचाव के लिए ठोस प्रमाण नहीं हैं। यह बात सही है कि एक समय दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार और वर्तमान राजनीतिक कार्य प्रणाली से बहुत त्रस्त हो गई थी, ऐसी स्थिति में जनता को केजरीवाल में एक नायक दिखाई दिया, जो जननायक बनने की श्रेणी में आ सकता था, लेकिन ज़ब उन पर और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, तब इस पटकथा की इबारत बदली हुई सी लगने लगी। अब आप पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह दो लाख के निजी मुचलके पर जेल से सशर्त बाहर आए तो उनका स्वागत ऐसे किया गया, जैसे वे आरोप मुक्त हो गए हों। आम आदमी पार्टी के इस प्रकार के चरित्र को देखकर यही कहा जा सकता है कि जो पार्टी राजनीति में बदलाव लाने का सपना दिखाकर मैदान में आई थी, आज वह भी समय के अनुसार बदल गई है। खैर... यहां परिवारवाद की बात हो रही है। आप नेता संजय सिंह जेल से छूटने के बाद अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे। यह वाकया निश्चित ही यह संकेत दे रहा है कि अब संभवतः सुनीता केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सपनों को पूरा करने वाली हैं। यह बात एक दम प्रामाणिक रूप से कही जा सकती है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है, इसके बावजूद भी राजनीतिक़ दल अपने परिवार तक ही अपने दल को सीमित रखने की क़वायद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि इन दलों को वास्तविक लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने तो परिवारवाद की सीमाएं लांघ दी। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक योग्यता के एक अनपढ़ पत्नी को राज्य की कमान सौंप दी। अब अपने पुत्रों को गद्दी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार दो बार लोकसभा के चुनावों में पराजय की स्थिति में पहुंचाने वाले विरासती पृष्ठभूमि के नेता राहुल गांधी भी परिवारवाद के ही परिचायक हैं। आज भले ही कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया हो, लेकिन वे भी राहुल गांधी को किनारे करने का साहस नहीं दिखा सकते। कांग्रेस के बारे में यही कहा जा सकता है कि वह आज भी परिवारवाद के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकी है। कुछ ऐसा ही नहीं, बल्कि इससे ज्यादा परिवारवाद समाज़वादी पार्टी में दीखता है। मुलायम सिंह के परिवार के लगभग सभी सदस्य या तो विधायक और सांसद हैं या रह चुके हैं। बसपा नेता मायावती ने भी अपनी विरासत अपने परिवार को ही सौंपी है। ऐसे उदाहरण से क्षेत्रीय दल भी अछूते नहीं हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट पर परिवार कायम है तो नेशनल कान्फ्रेंस पर शेख अब्दुल्लाह का परिवार ही कमान संभाल रहा है। ख़ास बात यह है कि यह सभी परिवार पार्टी के मुखिया ने ही स्थापित किए हैं। लोकतंत्र में ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए परिवारवाद को राजनीति से अलग करने की जरुरत है, क्योंकि जहां परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति होगी, वहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। लोकतंत्र जनता का होता है, जहां जनता को महत्व मिलेगा, वही तो लोकतंत्र है, और जहां परिवार को महत्व दिया जाता हो, वहां तानाशाह जैसी प्रवृति जन्म लेती है। उनको इसका अहंकार भी हो सकता है कि हम तो सत्ता के लिए ही बने हैं और यही अहंकार भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए अब इस बात की बहुत आवश्यकता है कि भारत में लोकतंत्र को कायम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं, नहीं तो जनता के शासन के स्थान पर परिवारवाद के सहारे तानाशाही का राजनीति कायम हो जाएगा।

भाजपा से ज्यादा तो प्रशांत किशोर कर रहे ममता पर हमले!

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। एक तरफ अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। इस बार बंगाल में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए ममता ने पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है । इस बीच रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। कहने को समय-समय पर उनकी तरफ से विपक्ष को सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जिस अंदाज में उन्होंने बंगाल में ममता को घेरा है, उसके अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वे ममता से अपना बदल निकाल रहे है या भाजपा का प्रचार । गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा राज्य की सत्ता में बैठी टीएमसी से बेहतर परफॉर्म करेगी। भाजपा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरेगी, चौंकाने वाले रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। ज्ञात हो कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार रहे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि भाजपा बंगाल में 100 विधानसभा सीट नहीं जीत पाएगी और उनकी भविष्यवाणी सही निकली। दावों के बावजूद भाजपा 77 सीट ही जीत सकी और टीएमसी ने 212 सीटों जीतकर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी चुनावी पंडितों को भी चकरा रही है। गरीबों को मुफ्त राशन, चुनाव से पहले सीएए लागू होना और बंगाल में इंडिया गठबंधन में दरार के कारण बंगाल में चुनावी उलट-पुलट भी संभव है। हालांकि टीएमसी का दावा है कि इस बार भाजपा 2019 से कम सीटें जीतेंगी। सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर ये बातें किस आधार पर कह रहे हैं। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बंगाल में भाजपा के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं रही हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हों या स्थानीय निकाय चुनाव सभी में भाजपा की दुर्गति हुई है। उपचुनावों में भी भाजपा को टीएमसी ने पस्त कर दिया। भाजपा के तमाम कद्दावर नेता ,मंत्री तक पार्टी छोड़कर टीएमसी शामिल हो चुके हैं। तो आखिर किशोर को उम्मीद की किरण कहां से दिख रही है? आइए जानते हैं कि क्यों प्रशांत किशोर की बातें सच हो सकती हैं ? कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा इतिहास रचने को तैयार थी पर पीएम नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप भारी पड़ गया था। और अंतिम समय में बाजी पलट गई थी । ममता के लिए पीएम मोदी का कहा गया संबोधन दीदी ओ दीदी। । को टीएमसी ने मां -माटी और मानुष के अपमान का मामला बना दिया और देखते ही देखते भाजपा पर भारी पड़ गई टीएमसी। इस बार भाजपा ने रणनीति बदल दी है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जा रहा है। हर बात के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते दिख रहे हैं। भाजपा के अन्य नेता भी ममता के खिलाफ अपमानजनक चुटकुले और संवेदनशील आरोप लगाने से बच रहे हैं । अनंत राय राजबंशी समुदाय से आते हैं। मतुआ के बाद ये पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय है। अनंत राय को उम्मीदवार बनाने से भाजपा की उत्तरी बंगाल में अच्छी-खासी पकड़ बन गई है। क्योंकि वहां राजबंशी समुदाय का अच्छा-खासा दबदबा है। उत्तरी बंगाल की आठ में से चार लोकसभा सीटों पर राजबंशी ही जीतते रहे हैं। 2019 में भाजपा ने इनमें से सात सीटें जीती थीं। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार आठों सीट भाजपा जीत सकेगी। राज्य में इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही टीएमसी अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा को मजबूत होने का एक और अवसर दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने के टीएमसी के फैसले के चलते टीएमसी विरोधी वोट भाजपा को मिलेंगे। इसके अलावा वोट बंटने का भी फायदा भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी के युसूफ पठान ताल ठोंक रहे हैं। पठान सेलेब्रेटी क्रिकेटर भी हैं और मुसलमान भी हैं। ऐसे में अगर वोट बंटता है तो किसका फायदा होगा। जाहिर है दोनों की लड़ाई में भाजपा अगर मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो यहां से जीत भी सकती है। सीएए बंगाल में भाजपा का चुनावी वादा रहा है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने बंगाल में सीएए लागू करने की बात करते रहे हैं । शायद यही कारण है कि भाजपा ने कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए लागू होने का सबसे बड़ा फायदा बंगाल में मतुआ समुदाय को मिलेगा। मतुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि मतुआ वोट जहां भी जाता है उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। बंगाल में लगभग एक करोड़ अस्सी लाख मतुआ समुदाय के मतदाता हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम चार लोकसभा सीट में यह समुदाय निर्णायक है। मतुआ समुदाय की तरह राजवंशी समुदाय को भी सीएए का लाभ मिलने वाला है। राजवंशी भी हिंदू हैं। 1971 के बाद से इन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। इस तरह करीब 10 से 12 सीटों पर सीधे भाजपा बढ़त बनाती दिख रही है। हिंदुओं में अनुसूचित जाति के राजबंशी, मतुआ और बाउड़ी, जो राज्य की जनसंख्या के करीब 23 फीसदी हैं इस बार और बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। 2019 में चाय श्रमिक और जंगलमहल के आदिवासी ने भी भाजपा को वोट दिए। उम्मीद की जा रही है कि सीएए के तहत मतुआ और राजवंशियों को होने वाले फायदे का भावनात्मक असर दूसरी अनुसूचित जातियों पर भी पड़ेगा । भाजपा के पक्ष में थोक के भाव में एससी वोट पड़ने की उम्मीद की जा रही है। अनंत महाराज को राज्यसभा भेजना,राजबंशी समुदाय के नेता और भाजपा के वर्तमान लोकसभा एमपी निशिथ प्रमाणिक को मंत्री बनाने आदि से इस वर्ग में भाजपा को लेकर अपनापन बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में लगातार यात्राएं कर रहे हैं और संदेशखाली को लेकर जिस तरह हमलावर हैं उससे यही लगता है कि बंगाल में इस बार यह मुद्दा बड़ा बनने वाला है। स्थानीय भाजपा नेता संदेशखाली को उसी तरह ले रहे हैं जिस तरह कभी टीएमसी ने सिंगूर और नंदीग्राम को आंदोलन बना दिया था। संदेशखाली पर आंदोलन तेज़ करने की अपनी रणनीति के तहत ही पार्टी ने 'द बिग रिवील-द संदेशखाली शॉकर' शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की थी। यह सभी जानते हैं कि नंदीग्राम में जबरन ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के सहारे ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ़ हुआ था। नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि संदेशखाली की परिस्थिति नंदीग्राम जैसी है। नंदीग्राम में लोगों ने ज़मीन के अधिग्रहण के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी और यहां ज़मीन पर जबरन कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। संदेशखाली में खेती की ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा यौन उत्पीड़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का विशेष महत्व रहा है,शायद यही कारण है कि सीपीएम से लेकर टीएमसी तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। भाजपा ने पहली बार राज्य में अलग तरह की राजनीति की है जिसके चलते पिछले चुनावों में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य की हिंदू आबादी कुल आबादी का लगभग 71% है। लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कई सर्वेक्षणों के अनुसार करीब 55% हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में गए। शायद यही कारण है कि इस बार भाजपा भावनात्मक मुद्दे पर ही फोक्सड है। भाजपा सांसद और राज्य के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे ने पहले भी भाजपा को फायदा पहुंचाया है और इस बार भी यह पश्चिम बंगाल समेत देशभर के हिंदुओं को एकजुट करने में हमारी मदद करेगा। सीएए के चलते भी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और अधिक होने की उम्मीद है ।

मेष राशि–आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपका विनम्र स्वभाव साराहा जाएगा। आपका धन कहां खर्च हो रहा है। इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको बेकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का एक बड़ा सबक इस बात को मान लेना है, कि बहुत सी चीजों को बदलना नामुमकिन है।

वृष राशि–आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज का दिन तरक्की के नए नये मार्ग खोलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें, जल्द ही आपको परीक्षा में सफलता हासिल होगी। प्राइवेट जॉब में कार्यरत लोगों को आज प्रमोशन मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आप तोल मोलकर बोले, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि–आज का दिन आपके लिए ठीक- ठाक रहने वाला है। आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। पैसों का उपयोग सही तरीके से करेंगे। और जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे और कुछ बातों में बदलाव होने में समय लगेगा। आज किसी कामों को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे।

कर्क राशि– आज आपके दिन की शुरुआत थोड़ा कमजोर रहेगी, लेकिन बाद में अच्छा लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना आज पूरा होगा। आप आज किसी से अपने मन की बातों को शेयर करोगे और वह आपकी बातों की अहमियत देगा।

सिंह राशि–आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आपके मकान, प्लॉट, दुकान को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। संतान को अच्छी नौकरी मिलने से माता- पिता काफी खुश नजर आएंगे। आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आज किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिशोध की भावना न रखें। जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसे ही अनुभव मिलेंगे।

कन्या राशि–आज का दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज आप अपना ध्यान किसी रचनात्मक कार्य में लगायेंगे जिससे आपका अनुभव और अधिक बढ़ेगा। परिवार के कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपना स्वभाव सुधारना होगा। किसी को उधार देने से पहले सोच- विचार करेंगे।

तुला राशि–कार्यक्षेत्र में आज आपको काफी हद तक सफलता हासिल होगी। पारिवारिक मामलों में आज आपको ठण्डे दिमाग़ से सोचेने की जरूरत है , परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आज भाई अपने काम में आपकी मदद मांगेगे। समाज में आज आप अपने बढ़िया कार्यो के कारण पहचाने जायेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहें छात्रो को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। घर के जरूरी कागजों का खास ख्याल रखें। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण तनाव बढ़ सकता है लेकिन जल्द ही सब ठीक होगा।

वृश्चिक राशि–आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को आगें बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। परिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में बड़े- बुजुर्गो का सहयोग प्राप्त होगा। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगो को आज बड़ा मुनाफा होगा। पिता से आज आपको कुछ नया सिखने को मिलेगा। आज कोई ऐसी पुरानी चीज आपके हाथ लग सकती है, जिसे पा कर आपको खुशी महसूस होगी।

धनु राशि–आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर आपकी परफॉरमेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगें। आज सभी जरुरी काम आसानी से पूरा कर लेंगे। पिता ने व्यापार में जो जिम्मेदारिया दी हुई हैं उसे आप आसानी से निभा लेंगें। इस राशि के जो लोग फर्नीचर का व्यापार कर रहे है, उन्हें उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा।

मकर राशि–आज का दिन आपके लिए ठीक- ठाक रहने वाला है। आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। इस राशि के जो जिम ट्रेनर है उनको आज अच्छे ग्राहक मिलेंगे। आपके व्यावसायिक कौशल में तेजी आयेगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दौड़ में खुद को आगे पाएंगे।

कुंभ राशि–आज का दिन ठीक- ठाक रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है। जिसके लिये आपको ओवर टाईम करना पड़ेगा। रुपए- पैसों के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। टूर- ट्रेवल्स और मीडिया संबंधी बिजनेस में नया मोड़ आ सकता है। आज अपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी, जिससे आपको काफी फायदा होगा।

मीन राशि–आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। जो लोग बैंक में कार्य करते हैं वह आज अपना काम बहुत जल्द निपटा लेंगें। लवमेट आज साथ में समय बितायेंगे। रूका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज आपके कार्यों कीप्रशंसा दूर- दूर तक लोगों में इत्र की तरह महकेगी। आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जायेंगे। छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे, तो सब ठीक हो जाएगा।

सू- दोकू क्र.021

नियम
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक ही होने है। किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.020 का हल

शब्द सामर्थ्य -021

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं
1. आय व्यय का लेखा-जोखा, गणित, एकाउंट 3. विनती, अदब 6. दृष्टांत, सुपुर्दगी, उदाहरण 7. मूल्यवान, बहुमूल्य 8. अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत 10. बराबर, सम 12. मुख, चेहरा 14. अनुकृति, अनुकरण, असल का विलोम 17. दिमाग, मस्तिष्क 18. मनोहर, सुंदर, इच्छित, प्यारा 19. गर्मी, ताप 21. रसिया, प्रेमी, रसपान करने वाला 23. दबाव, भार 24. भीख 25. काम से जी चुराने वाला, आलसी।

ऊपर से नीचे
1. साहस, वीरता, बहादुरी 2. बहिन, प्रवाहित होना 3. प्रणय क्रीडा, सुखोपभोग, हावभाव 4. विश्वास, प्रतीति 5. इंतजार 9. खाने-पीने का सामान, रसद 11. नशीला, मदभरा 12. घायल, जख्मी 13. झुकना, प्रणाम, नमस्कार 14. दृष्टि, निगाह 15. तीव्रइच्छा 16. अर्थ, अभिप्राय, स्वार्थ 20. इम्तिहान, योग्यता आदि को परखना 22. जुल्म, अन्याय 23. पत्नी, बीवी, एक प्रत्यय।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 020 का हल

अविव

वे लोग जो इस दुनिया में सुखी है। जो अपने संबंधियों के प्रति उदार है। अनजाने लोगो के प्रति सहृदय है। अच्छे लोगो के प्रति प्रेम भाव रखते है। नीच लोगों से धूर्तता पूर्ण व्यवहार करते है। विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते। दुश्मनों के सामने साहस दिखाते है। बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त है। चाणक्य

[redacted]
पटना, मंगलवार, 09 अप्रैल 2024
www.live7tv.com

राम ने क्यों भोगा पत्नी-वियोग का कष्ट?

आशुतोष गर्ग-जलज मिश्रा

देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध होते रहते थे। एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य तपस्या करने चले गए और दैत्यों का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर दैत्यों पर धावा बोल दिया। शुक्राचार्य की माता और महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा का दैत्यों पर बड़ा स्नेह था। इसलिए दैत्य भागकर र महर्षि भृगु के आश्रम में आ गए और उन्होंने पुलोमा से रक्षा की याचना की। संयोग से, उस समय भृगु आश्रम में नहीं थे। पुलोमा ने दैत्यों को निश्चिंत रहने को कहा और उन्हें आश्रम में शरण दे दी। देवताओं को पता लगा, तो उन्होंने भगवान विष्णु को साथ लेकर भृगु के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। दैत्य हमले के लिए तैयार नहीं थे। वे सब घबराकर पुलोमा के पास दौड़े तो पुलोमा, देवताओं और दैत्यों के बीच आकर खड़ी हो गई। हमारा आपसे कोई वैर नहीं हैं, विष्णु ने पुलोमा से कहा। हम दैत्यों का संहार करने आए हैं। कृपया मार्ग से हट जाइए। पुलोमा ने विष्णु से कहा, ये मेरे पुत्र शुक्र के शिष्य हैं और मैंने इन्हें रक्षा का वचन दिया है। मेरे रहते आप दैत्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विष्णु ने हाथ जोड़कर पुलोमा से विनती की, देवी, मैं आपके वचन का सम्मान करता हूं। परंतु दैत्य अनाचारी और निरंकुश हैं। शुक्राचार्य के संरक्षण में ये निरंतर उच्छृंखल होते जा रहे हैं। प्रकृति में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका संहार आवश्यक है। शुक्राचार्य अपना दायित्व निभाते हैं, तो आप हमें भी अपना कार्य करने दीजिए। विष्णु के समझाने पर भी पुलोमा नहीं मानीं। यह देखकर देवताओं ने पुलोमा पर आक्रमण करना चाहा, किंतु पुलोमा ने समस्त देवताओं को स्तंभित कर दिया। हालांकि विष्णु पर पुलोमा की शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी वह पुलोमा को देखकर अचंभित थे। उन्होंने पुलोमा से पुनः विनती करते हुए मार्ग से हटने और दैत्यों को शरण न देने का आग्रह किया। परंतु पुलोमा अपने निश्चय पर अडिग रहीं। यहां तक कि पुलोमा ने देवताओं को भस्म करने की धमकी दे डाली। विष्णु समझ गए कि पुलोमा के रहते दैत्यों का संहार संभव नहीं होगा। भगवान ने आंखें मूंदी और दिव्य सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। अगले ही पल विष्णु की तर्जनी पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान विष्णु ने उस चक्र से अनेक राक्षसों और दुष्टों का संहार किया था, किंतु इस बार उनके सामने एक स्त्री थी और वह भी कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु महर्षि भृगु की पत्नी! धर्मसंकट का

क्षण था। अधर्म और अनाचार किसी भी रूप में सामने आए, उसे मिटाना भगवान अपना कर्तव्य मानते हैं। विष्णु जानते थे कि पुलोमा का संहार किए बिना उनके लिए धर्म की अनुपालना करना संभव नहीं था। विष्णु ने निर्णय ले लिया था। अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र ने भृगु-पत्नी पुलोमा का सिर काटकर नीचे गिरा दिया। विष्णु के हाथ से स्त्री-वध हो गया था। उन्हें इसका परिणाम पता था, परंतु धर्म-रक्षक विष्णु अपने स्थान पर अडिग खड़े मुस्कराते रहे। उसी समय महर्षि भृगु ने आश्रम में प्रवेश किया। पुलोमा का कटा शीश देखकर भृगु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने विष्णु से कहा, प्रभु ! यह आपने क्या किया? स्त्री-वध का पाप करके आपको क्या मिला? हे महर्षि, विष्णु ने शांत भाव से कहा, मेरी दृष्टि में पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है। मैं केवल धर्म और अधर्म का अंतर समझता हूं। आपकी पत्नी पुलोमा धर्म की रक्षा में बाधा उत्पन्न कर थीं, इसलिए मुझे इनका वध करना पड़ा। हे नारायण, आपने मुझे आपको भी जो पीड़ा पहुंचाई है वही पीड़ा अह आपको भी भोगनी होगी। मैं आपको शाप देता हूं कि जिस तरह मैं पत्नी के वियोग से दुखी हूं, उसी तरह आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पत्नी-वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपका शाप स्वीकार है! भृगु के इसी शाप के फलस्वरूप, विष्णु ने त्रेता युग में दशरथ-नंदन राम के रूप में जन्म लिया और रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद राम (विष्णु) को पत्नी-वियोग का कष्ट भोगना पड़ा।

न्यायपत्र का पथ

देश चुनावी रंग में नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने वायदे-इरादे जाहिर कर रहे हैं। यूं तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के झंडे तले राजग का विकल्प बनाने की तैयारी में जुटी है लेकिन शुक्रवार को उसने कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आदि की उपस्थिति में अपना घोषणा पत्र जारी किया। यूं तो घोषणापत्र में वे सभी मुद्दे शामिल हैं, जिनके आधार पर वह पिछले पांच सालों में मोदी सरकार को घेरती रही है। लेकिन पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया और 25 गारंटियों का जिक्र किया। जिसमें एससी,एसटी और ओबीसी के लिये आरक्षण की निर्धारित सीमा संविधान संशोधन के जरिये बढ़ाने की बात कही है। वहीं देश में किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का वायदा किया गया। पार्टी ने दावा किया है कि जो हिंदुस्तान चाहता है वह कांग्रेस घोषणा पत्र में दिख जाएगा। इसमें शैक्षणिक संस्थानों व नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दस फीसदी आरक्षण का भी वायदा है। वहीं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीस लाख नौकरियों के रिक्त पदों को भरने की बात कही गई। साथ ही राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में पच्चीस लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई। जैसे कि पहले भी राहुल गांधी कहते रहे हैं- देश में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे कराने की बात कही गई है। वहीं हाल में बार-बार सामने आए पेपर लीक मामले में कहा गया है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के जरिये कार्रवाई करके पीड़ितों को आर्थिक राहत दी जाएगी। डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझते हुए पार्टी ने कक्षा नौ से बारह तक के छात्रों को मोबाइल फोन दिलाने का वायदा किया है। दूसरी ओर 21 साल से कम उम्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को दस हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को लुभाने के लिये गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये हर साल व 2025 से केंद्र सरकार की आधी नौकरियां महिलाओं के लिये आरक्षित करने का वायदा भी है। पार्टी ने मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने के साथ ही चार सौ रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी भी दी है। कई मुद्दों पर राजग सरकार के दौरान उठे विवाद के चलते कांग्रेस ने वायदा किया है कि पार्टी की सरकार बनी तो भोजन, पहनावे, प्यार, शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा व निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेगी। साथ ही ऐसे कानूनों को रद्द करेगी। पार्टी ने हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसियां तीन साल में भरने, अग्निपथ योजना को खत्म करने और शिक्षा नीति में बदलाव लाने की भी बात कही है। पार्टी ने कहा कि यदि हम सत्ता में आए तो पहली से बारहवीं तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने के साथ ही पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कांग्रेस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद राजस्थान की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि भाजपा जो कहती है, वो जरूर करती है।

हाथ भी बातें करते हैं...सोचने और महसूस करने पर भी असर, मनुष्य को भी मिलती है संतुष्टी

मर्खेम हीड

अपने हाथों को कम मत समझिए। पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्राणी, यहां तक कि मानव के निकटतम प्राइमेट रिश्तेदारों के हाथ भी हमारे जैसे नहीं हैं, जो इतनी सटीक पकड़ और हेरफेर करने में सक्षम हों। यह दीगर बात है कि पहले के समय की तुलना में आज हम अपने हाथों से कम जटिल कार्य कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हाथों से कम, जटिल काम करते रहने का हमारे सोचने और महसूस करने पर भी असर पड़ता है? वर्जीनिया की एक यूनिवर्सिटी में व्यावहारिक मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉ. लैंबर्ट का कहना है कि जब हम किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, और वह चीज हमें मिलती है, तो दोनों के बीच एक संबंध होता है। वह यह भी मानती हैं कि अपने हाथों से काम करना मनुष्य को अद्वितीय रूप से संतुष्टि दे सकता है। जानवरों पर किए गए एक शोध में भी यह बात सामने आई है कि जो चूहे भोजन खोदने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें तनाव झेलने की क्षमता दूसरे चूहों से ज्यादा होती है। डॉ लैंबर्ट इस शोध के निष्कर्षों की तुलना मनुष्यों पर किए अध्ययनों से करती हैं। उन्होंने पाया कि बुनाई, बागवानी और रंग भरने जैसे काम करने वालों को संज्ञानात्मक और भावनात्मक लाभ होता है, जिससे याददाश्त भी अच्छी रहती है। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऑक्युपेशनल थेरेपी की प्रोफेसर कैथरीन बेकमैन कहती हैं कि कढ़ाई जैसे कामों में दोहराव तो होता है, पर बार-बार एक ही चीज करने से इसके प्रभान ध्यान करने जैसे होते हैं। नौवें की एक यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर ऑड्रे वॉन डेर मोर के अनुसार, हाथ से लिखने के फायदे कंप्यूटर पर टाइप करने से कहीं ज्यादा होते हैं। प्रोफेसर डॉ. रस्टी गेज कहती हैं कि हाथ से की गई क्रियाएं मस्तिष्क में नई कोशिकाओं के विकास में सहायक होती हैं। उनके अनुसार, जब आप कोई जटिल काम करते हैं, जिसमें निर्णय लेना और योजना बनाना शामिल होता है, तब यह काफी मायने रखता है कि आप अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जैसे, जब आप बागवानी, हस्तशिल्प, चित्रकेला करते या फिर वाद्ययंत्र बजाते हैं, आपके हाथ और दिमाग एक आदर्श तालमेल दिखाते हैं। वह कहती हैं कि यह दुनिया त्रिआगामी है और ऐसे हाथ व दिमाग के तालमेल वाले रचनात्मक कार्यों की मदद से आप दुनिया से उसकी ही भाषा में बात कर सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं, दुनिया से भागना नहीं है इनके 'पास जाना'

ईड यंग

अपनी जिंदगियों में हम इतने व्यस्त होते हैं कि पक्षियों को देखने का हमारे पास वक्त ही नहीं होता। रोजमर्रा के कार्यों में हम इतने खोए रहते हैं कि अपने आस-पास मौजूद पक्षियों की दिलचस्प दुनिया को नहीं देख पाते। अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर, या सड़क पर यों ही घूमते हुए या कार पर जाते हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई पक्षी दिखाई न दे। एक बार आप उन्हें देखना शुरू तो करें, धीरे-धीरे आप उन्हें पहचानने लगेंगे, उनमें फर्क करने लगेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, जब वे आपको पहचानने लगेंगे और तभी उनकी जादुई दुनिया आपके सामने खुद-ब-खुद अपने रहस्य खोलने लगेगी।

विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं : पिछले साल सितंबर की बात है। मैं कैलिफोर्निया स्थित अपने घर के पास ही एक संरक्षित आर्द्र भूमि के अंतिम छोर तक गया और तरह-तरह के पक्षियों को देखने लगा। इससे पहले मैं गर्मियों में अपने कुत्ते को घुमाते हुए दूरबीन साथ में लेकर लंबी पैदल यात्रा करना पसंद करता था, लेकिन यह पहली बार था, जब मैं सिर्फ और सिर्फ पक्षियों को देखने निकला था। अमूमन माना जाता है कि पक्षियों को लगातार निहारते रहने वाला व्यक्ति एक पेशेवर या विशुद्ध पक्षी प्रेमी होता है। पर मैं ऐसा नहीं मानता। किसी क्षेत्र में रुचि रखने वाला व्यक्ति उसमें पारंगत हो, यह जरूरी तो नहीं। मेरा यह मतलब नहीं कि पेशेवर बनने के लिए कौशल जरूरी नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि कौशल न भी हो पर गंभीर प्रयास और इरादे तो दिखने ही चाहिए। मसलन, नाच तो कोई भी सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर

नाचने वाला नर्तक हो। ठीक यही बात मुझ पर लागू होती है। पूरी जिंदगी पशुओं व पक्षियों में मेरी रुचि रही है, पर अपने भीतर पक्षियों को लेकर पेशेवर विशेषज्ञता मैं कभी विकसितु नहीं कर पाया।

देखने का अभ्यास : दो दशकों तक एक विज्ञान लेखक के रूप में मैंने पक्षियों के बारे में विस्तार से लिखा है, लेकिन मेरे लिए वह पल विशेष महत्व रखता है, जब मैंने सिर्फ पक्षियों लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा समर्पित करने का फैसला किया। यह पहली बार था, जब पक्षियों को लेकर मैंने पेशेवर ढंग से सोचना शुरू किया। पेशेवर ढंग से मेरा आशय है कि पक्षियों को देखने में एक तरह की विशेषज्ञता का मैंने अभ्यास करना शुरू किया। पिछले सात महीनों में मैंने पक्षियों की तकरीबन 452 प्रजातियां देखी हैं। पक्षियों को देखने का मेरा अनुभव इस प्रकार हो चुका है कि में आवाज सुनकर ही बहुत-सी पक्षी प्रजातियों की पहचान कर सकता हूं। मैं बड़े और छोटे पीले पैरों, घरेलू और बैंगनी फिंच, कूपर और तेज-चमड़ी वाले बाजों में स्पष्ट अंतर कर सकता हूं। दुर्लभ पक्षियों की तलाश में भी मैंने काफी समय गुजारा है। हालांकि पक्षियों के बारे में मुझे पहले से भी काफी जानकारी थी। पक्षियों के आवासों और उनके तौर-तरीकों के बारे में काफी कुछ समझता भी हूं। सोशल मीडिया पर पक्षी प्रेमियों के कई समूहों का भी हिस्सा हूं और उनसे बातें भी करता रहता हूं।

देखेंगे तभी समझेंगे : पक्षी-प्रेमी होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पक्षियों का ज्ञान और इसके लिए पक्षियों को जानना महत्वपूर्ण है। पक्षियों को जानने के लिए उन्हें देखना शुरू करना जरूरी है। मेरे पक्षी-प्रेम ने मुझे कैलिफोर्निया में ऐसे स्थानों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया, जहां पक्षी हो सकते हैं। मैं पक्षियों को देखने में इतना खो जाता हूं कि मुझे गर्मी, सर्दी, भूख और प्यास से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं पहली बार किसी नई प्रजाति को देखता हूं, तो मुझे एक अजीब शांति का अनुभव होता है, मानो मैंने कोई नशा किया हो।

पक्षियों से दोस्ती का एक प्रयोग : जब मैं सुबह अपने घर से बाहर निकलता हूं, तो आस- पड़ोस में पक्षियों के चहकने पर ध्यान देता हूं, जो हमेशा वहां रहते थे, लेकिन जिन पर पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पक्षी प्रेमियों के लिए ऋतुओं को समझना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन विशेष प्रजातियों के आगमन और प्रस्थान का एक महत्वपूर्ण संकेत है। मैं मौसम में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों और निवास स्थान के फर्क पर विशेष ध्यान देता हूं। पक्षियों से दोस्ती करनी हो, तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप जहां भी रहते हों, अपनी बालकनी या छत पर अनाज के कुछ दाने और पीने का थोड़ा पानी पक्षियों के लिए रखना शुरू कीजिए। हो सकता है कि शुरूआती कुछ दिन एक भी पक्षी न आए, लेकिन आप क्रम न तोड़िए। एक दिन आप देखेंगे कि कुछ पक्षियों ने आना शुरू किया, फिर कुछ और दिन बाद पक्षियों की संख्या बढ़ने लगेगी, और कुछ पक्षी तो लौट-लौट कर आने लगेंगे। उन पक्षियों के पास न जाइए, पर उनके व्यवहार को दूर से देखने-समझने की कोशिश करते रहिए।

खुद से करें सवाल : जब मैंने पक्षियों को देखना शुरू किया, तो मुझे लगा था कि अधिकांश पक्षी प्रजातियों को शायद ही देख पाऊं। मेरा मानना था कि रॉबिन और वेस्टर्न ब्लूबर्ड जैसे पक्षियों को देखना आसान होगा, वहीं ब्लैक स्कीमर या पेरेग्रीन फाल्कन या लॉगरहेड श्राइक, सुनहरी चीलों, बड़े सींग बाले उल्लुओं जैसे दुर्लभ पक्षियों को देखना मुश्किल होगा, पर पक्षियों के प्रति मेरी जिज्ञासा ने इसे सरल बना दिया। रैत की पहाड़ी पर नाचते हुए क्रेनों को देखकर और प्रशांत महासागर में उनकी गोताखोरी देखते हुए उत्सुकता भरा मेरा प्रश्न कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा अब मैं उसे कहां पा सकता हूं? में बदल गया है।

यही वास्तविक जीवन है : निस्संदेह, पक्षियों के लिए समय निकालना बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि लोग इसे सेवानिवृत्ति के बाद का विषय मानते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पक्षियों को पालने जैसी चीजें तब की जाती हैं, जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इनसे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि हाल के वर्षों ने मुझे सिखाया है कि पक्षियों को पालने जैसे कामों में जो खुशी, आश्चर्य और जगह से जुड़ाव होता है, वह किसी और कार्य में नहीं है। पक्षियों में दिलचस्पी लेना वास्तविक दुनिया से भागना नहीं है बल्कि यही तो असली जीवन है। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से ज्यादा सुख किसी पक्षी की खोज में है। वसंत के दिनों में पक्षियों को देखने के लिए में बेहद उत्साहित हूं, क्योंकि गाने वाले और अन्य प्रवासी पक्षी खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। जिन पक्षियों को मैंने केवल हल्के भूरे रंग में देखा है, वे इस मौसम में अपने नए आकर्षक पंखों को धारण करने वाले हैं। जिन प्रजातियों को मैं पहले से जानता हूं, उनके नए सुरों को मुझे सीखना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि नए पक्षी मेरा इंतजार कर रहे हैं।

संपादकीय

नौ माताओं के पुण्य स्मरण के साथ पवित्र नव वर्ष की शुभकामनाएं

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

नवरात्रि का पहला दिन यानी प्रतिपदा तिथि मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। इस दिन जौ (जवार)बोने तथा कलश स्थापना पूजन के साथ ही देवी का पूजन किया जाना शुभ माना जाता है' यह भी शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रथम दिवस में माता की पूजा करते समय आराधक यदि लाल, गुलाबी ,नारंगी और रानी रंग के कपड़े पहन कर पूजा करने से माता का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है' द्वितीय दिवस यानी नवरात्रि के दूसरे दिन अत्यंत दिव्य देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है सिद्धि के लिए इस दिन मां की उपासना करते समय सफेद,पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है एवं इस पवित्र दिन में आराधना करने से मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है। तृतीय दिवस में बाघ पर सवार स्वर्ण के समान रंग एवं छटा वाली मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है।इस दिन पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग कपड़े पहनना शुभ माने जाते हैं एवं इन रंगों के कपड़े पहनकर देवी की आराधना करने से उनका आशीर्वाद एवं कृपा की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में चतुर्थ दिवस में इस भव संसार के ब्रह्मांड की रचना करने वाली दुर्गा मां के चौथे रूप के रूप में देवी कुष्मांडा की आराधना एवं भक्ति की जाती है। इस दिन इस प्रकृति की देवी के स्वरूप की मन से आराधना करना शुभ फल देने वाला है एवं देवी प्रकृति की देवी हैं इनकी उपासना इस दिवस में पीला ,हरा, लाल और भूरे रंग का वस्त्र पहनकर करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, एवं देवी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पंचम दिवस पर पंचमी तिथि को भगवान कार्तिकेय की माता देवी स्कंदमाता की आराधना एवं श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर छठवें दिन ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी मां की पूजा अर्चना का शास्त्रों में पूजा का विधान माना जाता है। माता कात्यायनी अमोघ फलदाईनी होती हैं भक्तों द्वारा इस दिन लाल, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ, मूंगा रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करने से ऐश्वर्य के साथ वैवाहिक जीवन में शांति सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा तथा अर्चना का विधान है, नवरात्रि की पूजा में तंत्र साधना करने वाले लोग इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करके इनकी पूजा अर्चना करते हैं साधकों को इस दिन बैगनी, स्लेटी ,नीला एवं आसमानी रंग का वस्त्र धारण कर मां के इस दिव्य रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे संपूर्ण ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के आठवें दिन सर्व सौभाग्य दाइनी देवी महागौरी की उपासना का दिन माना जाता है। यह अत्यंत पवित्र दिन होता है और यह देवी धन, वैभव, सुख, शांति की शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा के दौरान साधकों को रातों को केसरिया संतरी गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए जिससे सुख एवं सौभाग्य की अखंड प्राप्ति होती है। शिवरात्रि में माताओं के नौ रूपों में दुर्गा पूजा के नौवें तथा आखरी दिन संपूर्ण विधि विधान, रीति रिवाज और पूर्ण निष्ठा के साथ देवी की आराधना करने वाले साधकों को संपूर्ण सिद्धिया प्राप्त होती हैं और इनकी उपासना के समय हरा धागों को लाल गुलाबी नारंगी रंग के वस्त्र पहनने से समाज में पद प्रतिष्ठा वैभव एवं धन की प्राप्ति होती है।

इष्टदेव झूलेलाल जयंती महोत्सव चेट्रीचंड्र व सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल 2024 पर्व का शुभ योग एक साथ

इष्टदेव झूलेलाल जयंती महोत्सव पर खुशियों की बौछार-चार राज्यों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा से समाज हर्षोल्लास से सराबोर हुआ : एडवोकेट किशन भावनानी

आयोलाल सभई चओ झूलेलाल-चेट्री चंड्र जूं लख लख वाधायूं

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियां में सबसे अधिक आस्था के प्रतीक भारत में अब आधुनिक डिजिटल युग में भी जनवरी से शुरू होने वाले नववर्ष भले ही पश्चिमी देशों में हर तिथी को अपनेअपने अनुसार मानते हों परंतु भारत में आज भी विक्रम संवत में गहरी आस्था,मान्यता व विश्वास है जो रेखांकित करने वाली बात है, करीब करीब हर समाज इससे प्रेरित होकर अपने त्यौहार विक्रम संवत के हिसाब से मनाते हैं, जैसे पंजाबी समाज बैसाखी, सिंधी समाज चेट्रीचंड्र महाराष्ट्रीयन समाज गुड़ी पड़वा, केरल में कोकणी पर्व जिसे पड़वो भी कहते हैं सभी नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल 2024 को सिंधी समाज अपने इष्ट देव झूलेलाल जयंती महोत्सव चेट्रीचंड्र के रूप में पूरी दुनियां में मनाते है,जिसकी तिथि भी हमेशा विक्रम संवत के अनुसार होती है जो हर वर्ष अलग-अलग तारीखों में परंतु समानायतःमार्च या अप्रैल माह में होती है। इस महान प्यारे पर्वको महोत्सव के रूप में मनाने की भी एक विशेष अनोखीकहानी है जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। परंतु इस वर्ष छत्तीसगढ़ राजस्थान गुजरात और मध्यप्रदेश ने 10 अप्रैल 2024 को अवकाश घोषित किया है,यह जानकारी मीडियामें उपलब्ध है,जोरेखांकित करने वाली बात है।सिंधी समाज इस पर्व को बड़ी आस्था व विशालता से मानता है। इस दिन समाज अपनी पूरी दुकानें व्यवसाय बंद रखकर पर्व मनाने में शामिल होता है।

इष्ट देव झूलेलाल की विभिन्न झांकियों सहित शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसमें समाज का हर नागरिक शामिल होता है जिससे समाज में एकता देखने लायक होती है। चूंकि इष्ट देव झूलेलाल जयंती क्षेत्री चंड्र व सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल 2024 का एक साथ योग आया है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे इष्ट देव झूलेलाल जयंती महोत्सव पर खुशियों की बौछार चार राज्यों ने सार्वजनिक अवकाश घोषणा से समाज हर्षोल्लाह से सराबोर हुआ। आयोलाल सभीई चाओ झूलेलाल चेट्री चंड्र जूं लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। साथियों बात अगर हम इस झूलेलाल जयंती महोत्सव चेट्रीचंड्र की करें तो, चेट्री चंड्र सिंधियों द्वारा मनाये जाने वाला महत्पूर्ण त्यौहार है। हर साल इसे चैत्र शुक्ल पक्ष के दुसरे दिन मनाया जाता है।इस बार ये 10 अप्रैल 2023, को मनाया जाएगी। ज्यादातर ये त्यौहार गुडी पड़वा व उगडी के दुसरे दिन पड़ता है, इसे पड़ोसी देश सहित विश्व के हर देश में में रहने वाले सिन्धी भी मनाते है। इस दिन चाँद कई दिनों बाद पूरा नजर आता है, सभी लोग जल देव की आराधना करते है। चेट्रीचंड्र त्यौहार सिन्धी समाज द्वारा अपने इष्टदेव झुलेलाल जी की याद में मनाया जाता है। इस दिन सिन्धी समाज जल देव व झुलेलाल जी की पूजा अर्चना करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, जूलूस निकाले जाते है। इस दिन प्रसाद के तौर पर उबले काले चने व मीठा भात सबको दिया जाता है। इस बार सिंधी समाज के आराध्य देव वरुणावतार भगवान झूलेलाल की जयंती 10 अप्रैल को मनाई जा रही है। इस बार संयोग यह है कि इसी दिन सिंधी भाषा दिवस भी है। वर्ष 1967 में इसी दिन 10 अप्रैल को सिंधी भाषा को 21 वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8 वीं अनुसूची में जोड़ा गया था जो सिंधी समाज के लिए गर्व की बात है। साथियों बात अगर हम झूलेलाल जयंती महोत्सव चेट्रीचंड्र मनाने के कारणों की करें तो, दुनियां में जब जब अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान ने अपने भक्तों के लिए धरती में जन्म लिया है। युगों से ये बात चली आ रही है, भारत देश में कई भगवान, साधू संत ने जन्म लिया और दुनियां को सही गलत में फर्क समझाया है। सभी समाज धर्म के भगवान पाप को खत्म करने के लिए इस धरती पर आये- राम, कृष्ण, अल्लाह येशु ऐसे ही कुछ नाम है। ऐसे ही एक और भगवान इस धरती पर आये, जिन्हें झुलेलाल नाम से जाना जाता है। इन्हें सिन्धी समाज का इष्टदेव कहा जाता है। ये हिन्दू जाति के भगवान वरुण का अवतार है, जिनका जन्म 10 वीं शताब्दी के आस पास हुआ था। कुछ लोग इन्हें सूफी संत भी बोला करते है, जिन्हें मुस्लिम भी काफी पूजते थे। कुछ लोग इन्हें जल देव का अवतार मानते थे। सिन्धु घाटी की सबसे पहली व पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ोहै,यही सिंध में ही झुलेलाल जी का जन्म हुआ था।उनके जन्म को आज भी सिन्धी समाज व पड़ोसी मुल्क के कुछ हिस्सों में लोग झुलेलाल जयंती या चेट्री चंड्र नाम से मनाते है। इस दिन ने सिन्धी समाज का नया वर्ष शुरू होता है, जिसे वे बड़ी धूमधाम से मनाते है। साथियों बात कर हम सिंधी समाज के इष्टदेव झूलेलाल के जन्म याने अवतरण की करें तो, सिंधी समाज पर हो रहे अत्याचार की पुकार सुन जल देवता से आकाशवाणी के 2 दिन बाद चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में नासरपुर (पाकिस्तान की सिन्धु घाटी) के देवकी व ताराचंद के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उदयचंद रखा गया। हिंदी में उदय का मतलब उगना होता है। भविष्य में ये छोटा बच्चा हिन्दू सिन्धी समाज का रक्षक बना, जिसने मिरक शाह जैसे शैतान का अंत किया अपने नाम को चरितार्थ करते हुए उदयचंद जी ने सिंध के हिंदुओ के जीवन के अँधेरे को खत्म कर उजयाला फैला दिया। पहले उन्हें भगवान का रूप नहीं समझा गया, लेकिन अपने जन्म के बाद ही वेचमत्कार करने लगे। जन्म के बाद जब उनके माता पिता ने उनके मुख के अंदर पूरी सिन्धु नदी को देखा, जिसमें पलो नाम की एक मछली भी तैर रही थी, तब वे हैरान रह गए,इसलिए झुलेलाल जी को पले वारो भी कहा जाता है। बहुत से सिन्धी हिन्दू उन पर विश्वास करते थे, और उनको भगवान का रूप मानते थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें अमरलाल भी कहते थे।झुलेलाल जी को उदेरोलाल भी कहते है, संस्कृत में इसका मतलब है कि जो पानी के करीब रहता है या पानी में तैरता है। बाल्यावस्था में उदयचंद को झुला बहुत पसंद था, वे उसी पर आराम करते थे, इसी के बाद उनका नाम झुलेलाल पड़ गया,उनकी माता देवकी उन्हें प्यार से झुल्लण बोलती थी, उनकी माता का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण सौतेली माँ ने ही किया। बता दें एक अन्याई राजा द्वारा हिंदुओ पर जुल्म करना शुरू कर दिया था, सभी हिंदुओ को बोला गया, कि उन्हें इस्लाम अपनाना होगा, नहीं तो उन्हें मार डाला जायेगा, ऐसे में सिंध के सभी हिन्दू बहुत घबरा गए, तब सभी हिंदुओ को सिन्धु के नदी के पास इक्कठे होने के लिए बुलावा भेजा गया हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए, सबने मिलकर जल देवता दरिया शाह की उपासना और प्रार्थना की, कि इस विपदा में वे उनकी मदद करें। सभी ने लगातर 40 दिनों तक तप किया, तब भगवान वरुण ने खुश होकर उन्हें आकाशवाणी के द्वारा बताया, कि वे नासरपुर में देवकी व ताराचंद के यहाँ जन्म लेंगें, वही बालक इनका रक्षक बनेगा। साथियों बात अगर हम इष्टदेव झूलेलाल जयंती के उपलक्ष में चार राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की करें तो, छत्तीसगढ़ में चेट्रीचंड्र महोत्सव के अवसर पर 9 अप्रैल मंगलवार को सामान्य अवकाश की घोषणा की थी, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है, अब 9 अप्रैल के स्थान पर 10 अप्रैल बुधवार को चेट्रीचंड्र महोत्सव के लिए सामान्य अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने चेट्रीचंड को सरकारी अवकाश घोषित करके सिंधी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। इससे पहले मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में चेट्रीचंड की छुट्टी रहती है। मेरा मानना है कि चूंकि सिंधी समाज का राज्य भी उस तरफ छूट गया है, यहां समाज का कोई विशेष राज्य नहीं है, इसलिए हर राज्य में चेट्रीचंड्र उत्सव पर सार्वजनिक अवकाश पर विचार करने के साथ ही राष्ट्रीय अवकाश पर ध्यान देने की अपील सिंधी समाज द्वारा की जा रही है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आयोलाल सभई चओ झूलेलाल चेट्री चंड्र जूं लख लखकरोड़ करोड़ वाधायूं।इष्टदेव झूलेलाल जयंती महोत्सव चेट्रीचंड्र व सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल 2024 पर्व का शुभ योग एक साथ।इष्टदेव झूलेलाल जयंती महोत्सव पर खुशियों की बौछार-चार राज्यों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा से समाज हर्षोल्लास से सराबोर हुआ।

इंटीरियर डिजाइनर में नौकरी के अवसर

विजय गर्ग

क्या आप अपने कमरे की सजावट को आकर्षक बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं? उदाहरण के लिए, क्या आप आमतौर पर होटलों, इमारतों और फ्लैटों के अंदरूनी हिस्सों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? यदि आपका उत्तर हां है, तो आप पहले से ही इंटीरियर डिजाइनर बनने की राह पर हैं! वैश्वीकरण और विकसित और विकासशील दोनों देशों में मल्टीप्लेक्स संस्कृति की शुरुआत के साथ, इन संरचनाओं के अंदरूनी हिस्सों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि न केवल आकर्षक सौंदर्यशास्त्र प्रदान किया जा सके बल्कि सीमित स्थान का अधिकतम उपयोग भी किया जा सके। यह प्रवृत्ति केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ निजी आवासों में भी तेजी से बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिससे अपेक्षाकृत कम समय में इस विशेषज्ञों की आवश्यकता बढ़ रही है। इंटीरियर डिजाइनर कौन है? इंटीरियर डिजाइनर वह व्यक्ति होता है जो हस्य रूप से आकर्षक क्षेत्र तैयार करने के लिए ग्राहक की आवश्यकताओं के साथ काम करता है। ग्राहकों में निजी व्यक्तियों से लेकर प्रमुख उद्यम तक शामिल हैं। इंटीरियर डिजाइनर स्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाते हैं, साधारण घर की इनडोर और आउटडोर सजावट से लेकर भव्य होटल के अंदरूनी हिस्से तक। सभी इंटीरियर डिजाइनरों को अंतरिक्ष प्रबंधन के साथ-साथ सौंदर्य सज्जा की भी समझ होनी चाहिए। निर्मित स्थान को सुरक्षा मानकों को भी पूरा करना होगा। इंटीरियर डिजाइनर के पेशे के लिए रचनात्मक बुद्धि और दायरे से परे सोचने की क्षमता की आवश्यकता होती है। आजकल अधिकांश व्यक्ति अपने घरों और व्यवसायों को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनरों को नियुक्त करते हैं। उन्हें ग्राहक की मांग, बजट और उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर सजावट विकसित करनी चाहिए। इंटीरियर डिजाइनरों का काम बुर्ज खलीफा, द पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन, ताज महल पैलेस होटल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुंबई और कई अन्य स्थानों पर देखा जा सकता है। इंटीरियर डिजाइनर पात्रता इंटीरियर डिजाइन में स्नातक या मास्टर डिग्री आवश्यक है। सामान्य इंटीरियर डिजाइन डिग्रियों में इ.यू., इअ, इ.डीर (बैचलर ऑफ डिजाइन), ट.यू, और टअ शामिल हैं। इंटीरियर डिजाइन में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की पढ़ाई फायदेमंद है। इंटीरियर डिजाइनर कैसे बनें? आप तीन तरीकों में से एक में इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं: कैरियर पथ 1 छात्र 12वीं (कोई भी स्ट्रीम) पूरी कर सकते हैं। फिर इंटीरियर डिजाइन में अपना बी.डेस पूरा करें। फिर आप इंटीरियर डिजाइन में एम.डेस कर सकते हैं। कैरियर पथ 2 छात्र 12वीं (गणित) पूरी कर सकते हैं। फिर इंटीरियर डिजाइन में बीएससी करें। आप इंटीरियर डिजाइन में एमएससी करके अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। कैरियर पथ 3 छात्र 12वीं (गणित) पूरी कर सकते हैं। फिर अपना बी.आर्क पूरा करें। आप एम.डेस इंटीरियर डिजाइन जारी रख सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल क्या हैं? इंटीरियर डिजाइनरों के पास एक नीरस क्षेत्र को जीवंत में बदलने की क्षमता होती है। यदि आप अपने ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और दायरे से परे सोच सकते हैं, तो आप अपना पेशा शुरू करने के लिए सही रास्ते पर हैं। इस क्षेत्र को रचनात्मक व्यक्तियों की आवश्यकता है। जो लोग इस रोमांचक करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें बुनियादी कौशल सीखने की जरूरत है। एक भावी इंटीरियर डिजाइनर को अपने इंटीरियर डिजाइन करियर पथ में निम्नलिखित कौशल सेट की तलाश करनी चाहिए: रचनात्मकता संचार कौशल डिजाइन करने की क्षमता [illegible] समस्या को सुलझाना तकनीकी कौशल: 3डी प्रतिपादन एडोब फोटोशॉप कॉरल ड्रा कंप्यूटर-सहायता प्राप्त प्रारूपण एवं डिजाइन (सीएडीडी) परियोजना प्रबंधन इंटीरियर डिजाइनर- दायरा हालांकि इंटीरियर डिजाइन के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, जिन व्यक्तियों ने कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है या जिनके पास स्नातक की डिग्री है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। मास्टर ऑरडॉक्टरेट की उपाधियाँ भी उपलब्ध हैं। आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक स्थान, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और शैक्षणिक संस्थान सभी इंटीरियर डिजाइन के दायरे में शामिल हैं। इंटीरियर डिजाइनर ग्राहकों के साथ मिलकर उपयोगी, देखने में सुंदर स्थान बनाने के लिए काम करते हैं जो समुदाय के बाकी लोगों को भी आकर्षित करते हैं। रचनात्मक दिमाग और विषय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा करियर मार्ग है। इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम करना आज सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक है क्योंकि यह आपको रचनात्मक उद्योग में काम करने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता भी देता है। इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर की क्या संभावनाएं हैं? इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री वाले उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के इंटीरियर डिजाइन करियर विकल्पों में से चुन सकते हैं। डिजाइन प्रबंधक डिजाइन प्रबंधकों को कभी-कभी डिजाइन समन्वयक या डिज़ाइन और निर्माण प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। डिजाइन प्रबंधक किसी परियोजना के डिजाइन पहलुओं को व्यवस्थित करते हैं, यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि परियोजना की बहु-विषयक टीमें एक साथ अच्छी तरह से काम करती हैं और सब कुछ समय पर और बजट के भीतर पूरा हो जाता है। सजावट सलाहकार इंटीरियर डिजाइन सलाहकार ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो व्यक्तियों को उनके घरों, कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों को सजाने और डिजाइन करने में सहायता करते हैं। वे अक्सर उस क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं जिसे ग्राहक पुनर्निर्मित करना चाहता है, विभिन्न विचारों के रेखाचित्र और मॉडल बनाते हैं, और अपने दृष्टिकोण को जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। डिजाइनर/इंटीरियर डिजाइनर इंटीरियर डिजाइनर ऐसे आंतरिक क्षेत्र बनाते हैं जो लगभग किसी भी प्रकार की संरचना के लिए उपयोगी, सुरक्षित और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन होते हैं। इंटीरियर डिजाइनर स्थान की जरूरतों का विश्लेषण करके और रंग, प्रकाश व्यवस्था और सामग्री जैसे महत्वपूर्ण और सजावटी घटकों का चयन करके उपयोगी, सुरक्षित और सुंदर आंतरिक स्थान बनाते हैं। इंटीरियर डिजाइन निदेशक इंटीरियर डिजाइन निदेशक अपने संगठन के आंतरिक क्षेत्रों में डिजाइन कार्यों के मार्गदर्शन के प्रभारी होते हैं। वे अपने इंटीरियर डिजाइन कौशल और जरूरतों के आधार पर महत्वपूर्ण परियोजना डिजाइन निर्णय लेने के प्रभारी हैं। इंटीरियर डिजाइन प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल डिजाइनर एक डिजाइनर या कोई भी हो सकता है जो यह प्रदर्शित कर सके कि उनके पास कार्य स्थल पर काम करने वाले अन्य लोगों के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, योग्यताएं और अनुभव है। इंटीरियर डिजाइन सलाहकार इंटीरियर डिजाइन सलाहकार ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो व्यक्तियों को उनके घरों, कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों को सजाने और डिजाइन करने में सहायता करते हैं। वे अक्सर उस क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं जिसे ग्राहक पुनर्निर्मित करना चाहता है, विभिन्न विचारों के रेखाचित्र और मॉडल बनाते हैं, और अपने दृष्टिकोण को जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। इंटीरियर डिजाइन समन्वयक एक इंटीरियर डिजाइन समन्वयक बड़े कॉर्पोरेट, वाणिज्यिक या औद्योगिक परियोजनाओं की योजना बनाने, बनाने और प्रस्तुत करने के लिए इंटीरियर या आर्किटेक्चरल डिजाइन टीम के साथ काम करता है। इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट मैनेजर अपने व्यवसाय में इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट योजना, बजट और कार्यान्वयन के सभी क्षेत्रों का प्रभारी होता है। शोरूम के कार्यकारी निदेशक एक शोरूम मैनेजर किसी ब्रांड के शोरूम को चलाने का प्रभारी व्यक्ति होता है। विजुअल मर्चेंडाइजर्स एक विजुअल मर्चेंडाइजर के रूप में, आप स्टोर में, कैटलॉग में और इंटरनेट पर खुदरा ब्रांडों, वस्तुओं और सेवाओं का विपणन करेंगे।

भाजपा से ज्यादा तो प्रशांत किशोर कर रहे ममता पर हमले!

लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। एक तरफ अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। इस बार बंगाल में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए ममता ने पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है । इस बीच रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। कहने को समय-समय पर उनकी तरफ से विपक्ष को सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जिस अंदाज में उन्होंने बंगाल में ममता को घेरा है, उसके अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वे ममता से अपना बदल निकाल रहे है या भाजपा का प्रचार । गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा राज्य की सत्ता में बैठी टीएमसी से बेहतर परफॉर्म करेगी। भाजपा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरेगी, चौंकाने वाले रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। ज्ञात हो कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार रहे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि भाजपा बंगाल में 100 विधानसभा सीट नहीं जीत पाएगी और उनकी भविष्यवाणी सही निकली। दावों के बावजूद भाजपा 77 सीट ही जीत सकी और टीएमसी ने 212 सीटों जीतकर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी चुनावी पंडितों को भी चकरा रही है। गरीबों को मुफ्त राशन, चुनाव से पहले सीएए लागू होना और बंगाल में इंडिया गठबंधन में दरार के कारण बंगाल में चुनावी उलट-पुलट भी संभव है। हालांकि टीएमसी का दावा है कि इस बार भाजपा 2019 से कम सीटें जीतेंगी। सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर ये बातें किस आधार पर कह रहे हैं। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बंगाल में भाजपा के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं रही हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हों या स्थानीय निकाय चुनाव सभी में भाजपा की दुर्गति हुई है। उपचुनावों में भी भाजपा को टीएमसी ने पस्त कर दिया। भाजपा के तमाम कद्दावर नेता ,मंत्री तक पार्टी छोड़कर टीएमसी शामिल हो चुके हैं। तो आखिर किशोर को उम्मीद की किरण कहां से दिख रही है? आइए जानते हैं कि क्यों प्रशांत किशोर की बातें सच हो सकती हैं ? कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा इतिहास रचने को तैयार थी पर पीएम नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप भारी पड़ गया था। और अंतिम समय में बाजी पलट गई थी । ममता के लिए पीएम मोदी का कहा गया संबोधन दीदी ओ दीदी। । को टीएमसी ने मां -माटी और मानुष के अपमान का मामला बना दिया और देखते ही देखते भाजपा पर भारी पड़ गई टीएमसी। इस बार भाजपा ने रणनीति बदल दी है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जा रहा है। हर बात के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते दिख रहे हैं। भाजपा के अन्य नेता भी ममता के खिलाफ अपमानजनक चुटकुले और संवेदनशील आरोप लगाने से बच रहे हैं । अनंत राय राजबंशी समुदाय से आते हैं। मतुआ के बाद ये पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय है। अनंत राय को उम्मीदवार बनाने से भाजपा की उत्तरी बंगाल में अच्छी-खासी पकड़ बन गई है। क्योंकि वहां राजबंशी समुदाय का अच्छा-खासा दबदबा है। उत्तरी बंगाल की आठ में से चार लोकसभा सीटों पर राजबंशी ही जीतते रहे हैं। 2019 में भाजपा ने इनमें से सात सीटें जीती थीं। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार आठों सीट भाजपा जीत सकेगी। राज्य में इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही टीएमसी अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा को मजबूत होने का एक और अवसर दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने के टीएमसी के फैसले के चलते टीएमसी विरोधी वोट भाजपा को मिलेंगे। इसके अलावा वोट बंटने का भी फायदा भाजपा को मिल सकता है।

लेखक
अशोक भाटिया
वसई पूर्व, मुंबई

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी के युसूफ पठान ताल ठोंक रहे हैं। पठान सेलेब्रेटी क्रिकेटर भी हैं और मुसलमान भी हैं। ऐसे में अगर वोट बंटता है तो किसका फायदा होगा। जाहिर है दोनों की लड़ाई में भाजपा अगर मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो यहां से जीत भी सकती है। सीएए बंगाल में भाजपा का चुनावी वादा रहा है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने बंगाल में सीएए लागू करने की बात करते रहे हैं । शायद यही कारण है कि भाजपा ने कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए लागू होने का सबसे बड़ा फायदा बंगाल में मतुआ समुदाय को मिलेगा। मतुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि मतुआ वोट जहां भी जाता है उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। बंगाल में लगभग एक करोड़ अस्सी लाख मतुआ समुदाय के मतदाता हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम चार लोकसभा सीट में यह समुदाय निर्णायक है। मतुआ समुदाय की तरह राजवंशी समुदाय को भी सीएए का लाभ मिलने वाला है। राजवंशी भी हिंदू हैं। 1971 के बाद से इन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। इस तरह करीब 10 से 12 सीटों पर सीधे भाजपा बढ़त बनाती दिख रही है। हिंदुओं में अनुसूचित जाति के राजबंशी, मतुआ और बाउड़ी, जो राज्य की जनसंख्या के करीब 23 फीसदी हैं इस बार और बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। 2019 में चाय श्रमिक और जंगलमहल के आदिवासी ने भी भाजपा को वोट दिए। उम्मीद की जा रही है कि सीएए के तहत मतुआ और राजवंशियों को होने वाले फायदे का भावनात्मक असर दूसरी अनुसूचित जातियों पर भी पड़ेगा । भाजपा के पक्ष में थोक के भाव में एससी वोट पड़ने की उम्मीद की जा रही है। अनंत महाराज को राज्यसभा भेजना,राजबंशी समुदाय के नेता और भाजपा के वर्तमान लोकसभा एमपी निशिथ प्रमाणिक को मंत्री बनाने आदि से इस वर्ग में भाजपा को लेकर अपनापन बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में लगातार यात्राएं कर रहे हैं और संदेशखाली को लेकर जिस तरह हमलावर हैं उससे यही लगता है कि बंगाल में इस बार यह मुद्दा बड़ा बनने वाला है। स्थानीय भाजपा नेता संदेशखाली को उसी तरह ले रहे हैं जिस तरह कभी टीएमसी ने सिंगूर और नंदीग्राम को आंदोलन बना दिया था। संदेशखाली पर आंदोलन तेज करने की अपनी रणनीति के तहत ही पार्टी ने 'द बिग रिवील-द संदेशखाली शॉकर' शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की थी। यह सभी जानते हैं कि नंदीग्राम में जबरन जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के सहारे ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हुआ था। नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि संदेशखाली की परिस्थिति नंदीग्राम जैसी है। नंदीग्राम में लोगों ने जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई की थी और यहां जमीन पर जबरन कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। संदेशखाली में खेती की जमीन पर जबरन कब्जा यौन उत्पीड़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का विशेष महत्व रहा है,शायद यही कारण है कि सीपीएम से लेकर टीएमसी तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। भाजपा ने पहली बार राज्य में अलग तरह की राजनीति की है जिसके चलते पिछले चुनावों में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य की हिंदू आबादी कुल आबादी का लगभग 71% है। लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कई सर्वेक्षणों के अनुसार करीब 55% हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में गए। शायद यही कारण है कि इस बार भाजपा भावनात्मक मुद्दे पर ही फोक्सड है। भाजपा सांसद और राज्य के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे ने पहले भी भाजपा को फायदा पहुंचाया है और इस बार भी यह पश्चिम बंगाल समेत देशभर के हिंदुओं को एकजुट करने में हमारी मदद करेगा। सीएए के चलते भी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और अधिक होने की उम्मीद है ।

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सप्रर्टस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कॉमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र ॥ 9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

सुभाषित: *सफलताका कोई गुप्त रहस्य नहीं होता। क्या आप किसी सफल व्यक्तिको जानते हैं जिसने अपनी सफलताका बखान न किया हो।* ❐ किन हबार्ड

समानताका अधिकार

जलवायु परिवर्तका हर क्षेत्रपर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा है। मानवसे लेकर पशु-पक्षीतक सभी जीव इससे प्रभावित हुए हैं। यह वैश्विक चिन्ताका विषय है और न्यायपालिका भी इससे चिन्तित है। इस सन्दर्भमें सर्वोच्च न्यायालयने बहुत गम्भीर टिप्पणी की है, जो पूरी तरहसे उचित और चिन्तन योग्य है। शीर्ष न्यायालयका कहना है कि जलवायु परिवर्तन समानताके अधिकारकी संवैधानिक गारण्टीको प्रभावित करता है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रकी पीठने कहा है कि जलवायु परिवर्तनकी अनिश्चितताओंसे स्थिर और अप्रभावित स्वच्छ पर्यावरणके बिना जीवनका अधिकार पूरी तरहसे साकार नहीं होता है। स्वास्थ्यका अधिकार (जो अनुच्छेद २१ के तहत जीवनके अधिकारका हिस्सा है) वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियोंमें बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखा, फसल खराब होनेके कारण खाद्य आपूर्तिमें कमी, तूफान और बाढ़ जैसे कारकोंके कारण प्रभावित होता है। शीर्ष न्यायालयका यह कहना भी विशेष रूपसे महत्वपूर्ण है कि नागरिकोंके लिए बिजली आपूर्तिकी कमी न केवल आर्थिक विकासमें बाधा डालती है, बल्कि महिलाओं और कम आयवाले परिवारों सहित समुदायोंको भी प्रतिकूल रूपसे प्रभावित करती है, जिससे असमानताएं और बढ़ती हैं। सर्वोच्च न्यायालयकी यह टिप्पणी राजस्थान और गुजरातमें लुप्तप्राय पक्षी 'ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड' के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचेके बीच सन्तुलनसे सम्बन्धित एक मामलेमें की गयी है। न्यायालयने इसके लिए एक समितिका गठन भी कर दिया है। इसीके साथ ही शीर्ष न्यायालयने अप्रैल २०२१ के पहलेके आदेशको भी वापस ले लिया है, जिसमें दोनों राज्योंमें ८० हजार वर्ग किलोमीटरसे अधिक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनोंको भूमिगत करनेकी आवश्यकता थी। उल्लेखनीय है कि ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड (जीआईबी) पक्षी विशेष रूपसे राजस्थान और गुजरातमें पाये जाते हैं और इनकी संख्यामें निरन्तर कमीका सबसे बड़ा कारण उनके निवास स्थानके पास सौर संयंत्रों सहित ओवरहेड बिजली पारेषण लाइनोंसे उनका टकराना है। सर्वोच्च न्यायालयकी टिप्पणियों और आदेशोंको दो राज्योंतक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसे व्यापक संदर्भोंमें देखनेकी जरूरत है। साथ ही जलवायु परिवर्तनसे उत्पन्न खतरोंपर भी गम्भीरतासे सोचनेकी आवश्यकता है।

सुखोईका रोमांचक अभ्यास

गगनशक्ति अभ्यासके दूसरे दिन रविवारको आगरा, लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर लड़ाकू सुखोई विमानोंने वायुसेनाके जिस साहस और शौर्यका प्रदर्शन किया, वह रोमांचित करनेवाला था। आगरा एक्सप्रेस-वे के ३.५ किलोमीटर लम्बी हवाईपट्टीपर लड़ाकू विमानोंके साथ मालवाहक विमानकी भी सफल लैण्डिंगका अभ्यास हुआ जो वायु सेनाकी बड़ी उपलब्धि है। चार घण्टेतक चले अभ्यासमें छह सुखाई, दो मिराज और एक एएन-३२ शामिल रहे। इनमेंसे दो सुखोई और एनएन-३२ धरतीपर उतरे। सबसे पहले दो सुखोई विमानोंने हवाईपट्टीपर लैण्डिंग की। उसके बाद लखनऊकी ओर आये दो अन्य सुखोई हवाईपट्टीसे गुजरे और सफलतापूर्वक टचडाउन किया। उसके सात मिनट बाद मात्र तीन मिनटके अन्तरालमें रनवेपर खड़े दो सुखोईने डमी मिसाइल लोड होनेके बाद आगराकी ओर उड़ान भरी। यह एक हैरतअंगेज ऐतिहासिक पल था जिसपर हर भारतीयको गर्व है। इस अद्भुत नजारेको देखनेके लिए अभ्यास स्थलपर जुटे लोगोंमें गजबका उत्साह था। इस सफलतासे भारतीय वायुसेना और मजबूत हुई है और सुरक्षाकी जरूरतोंको पूरा करनेमें पूरी तरह सक्षम है। लड़ाकू विमानोंको किसी भी क्षण कहीं भी उतारा जा सकता है जो भारतके विरुद्ध कुटिल मानसिकतावाले देशोंके लिए कड़ा सन्देश है। देशमें किसी भी विषम और आपात स्थितिमें वायुसेनाके जवान बेहतरीन लड़ाकू विमानोंके साथ तैयार हैं। इससे देशकी सीमाओंकी सुरक्षामें काफी मदद मिलेगी। साथ ही चीन और पाकिस्तानपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा।

लोक संवाद

अहंकार एवं आत्मविश्वास

महोदय,- आत्मविश्व एवं आत्मसम्मानमें व्यक्ति स्वयंपर विश्वास करता है जबकि अहंकारमें सोचता है कि सब मैंने ही किया है। आत्मविश्वास ही आपको कठिन निर्णय लेनेमें एवं आत्मज्ञान विकसित करनेमें शक्ति प्रदान करता है। अहंकार अपनी किसी कमीको स्वीकार नहीं करता, न ही उन कमियोंको दूर करनेकी कोशिश करता है। व्यक्ति थोड़ा-सा बल, बुद्धि, धन-ऐश्वर्य एवं पद मिलनेसे अहंकारी हो जाता है। हर समय अपना ही गुणगान करता है जिस व्यक्तिमें ज्यादा आत्मविश्वास होता है उसे बड़े स्तरका अहंकारी माना जाता है। अहंकार एवं आत्मविश्वास एक ही चीज है। अहंकारीका ध्यान खुदपर और अपनी उपलब्धियोंपर ही होता है, जो अहंकारीकी विशेषताओंमें एक है। व्यक्ति दूसरेका दुख एवं सुख अपना दुख एवं सुख मानने लगता है तो धीरे-धीरे अहंकार विदा हो जाता है। अहंकारी दूसरेकी बुराई करना, खुदकी आलोचना न सुनना, बातचीतमें दूसरेपर हावी होना, किसीपर भी सहानुभूति न करना अहंकारीकी पहचान है। सहानुभूति करके दूसरेका सम्मानसे मदद करनेका भाव रखना चाहिए। अपनी आलोचनापर भी ध्यान दे उसकी सुने समयका सदुपयोग करे एवं प्रयत्नशीन रहे। विनासिता या ताकतसे अहंकार आता है। अहंकार ज्ञानका होता है अहंकार आत्मविश्वासका भी हो सकता है। अहंकारमें कमी तब आती है जब हम किसीसे तुलना करने लगते हैं। किसीसे तुलना न करें अपनी कमीपर ध्यान दें, दूसरेकी कमीको न देंखें और अपनेपर विश्वास रखें नियमित रूपसे व्यायाम करें, अच्छी नींद एवं स्वस्थ आहार ले आप अपनेको अच्छा महसूस करेंगे। **-गिरीशचन्द्र पाण्डेय, बीज भण्डार, सिकन्दरा, कानपुर देहात।**

भ्रष्टाचारपर अंकुश जरूरी

महोदय,-राजस्थान चुरूमें जनसभाको संबोधित करते हुए मोदीने विरोधियोंको चारों तरफसे घेर लिया। मोदीके भाषणके दौरान जनतामें काफी उत्साह था। मोदीकी दस सालकी उपलब्धिको कम आंकते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तीन तलाकको महत्वपूर्ण कानून करार देते हुए कहा कि मुस्लिम बहनोंके लिए यह कानून कारगर साबित हुआ है। लोकसभाका चुनाव होना है। राममन्दिरकी बात कांग्रेसके लिए गौण है। कांग्रेसने तो भगवान रामको काल्पनिक बताया था। महिला सशक्तिकरणकी नींव मोदीने रखी है। आधी आबादीके लिए केन्द्र सरकार हर कार्यमें महिलाओंकी भागीदारी सुनिश्चित की है। कांग्रेसके शासनकालमें राजस्थानमें गैंगस्टरका जमावड़ा था। मोदीने विकसित भारतकी नींव तैयार की है। भारत तेजीसे विकास कर रहा है। मोदीने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसके कार्याकालमें देशकी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी थी। दुनियामें भारतकी साख गिर रही थी। मोदीके भाषणके बाद कांग्रेस पस्त नजर आ रही है। करोड़ों लोगोंके घरपर छत नहीं थी। जीवनकी छोटी-छोटी चीजोंके लिए लोग लालायित थे। राजस्थानके चुरूकी सभामें करोड़ों लोग शामिल हुए। करोड़ों-अरबोंकी लूट और बिजलीके अभावमें लोग अंधेरेमें रात काटनेके लिए मजबूर थे। ईमानदारीसे काब्म किया। मोदीने कोरोना कालको याद किया और कहा कि दुनिया सोच रही थी कि भारत बर्बाद हो जायगा। लेकिन कामकी लगनसे दुनियाकी पांचवी इकोनॉमीवाला देश बन गया है। कांग्रेस घोषणा करती है लेकिन भाजपा संकल्प पत्र देती है। उस संकल्प पत्रको पूरा किया जाता है। राजस्थानमें चुनाव प्रचारके लिए पहुंचे मोदीने कांग्रेस और विरोधियोंको आड़े हाथों लिया। कांग्रेसके पास कोई जवाब नहीं है। मोदीने पेपरलिक मामलोंमें बैठक बैठानेका भरोसा दिलाया। आज वे सलाखोंके पीछे है। ईआरसी प्रोजेक्टको लटका कर रखा था। जबतक कांग्रेस सत्तामें रही थी, हमारे जवानोंके हाथ बांध कर रखा था। कांग्रेस तुष्टीकरणकी चाहमें देशके करोड़ों लोगोंका जीवन ही भूल गयी। स्वार्थकी रोटियां सेंकनेवाली कांग्रेसने देशको दिवालियाकी कगारपर लाकर छोड़ दिया। **-कांतिलाल मांडोत, सूरत।**

कठघरेमें ममता सरकार

पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां बिगड़ती कानून-व्यवस्थाको लेकर अदालतोंकी सर्वाधिक फटकार और निर्देशोंका सामना करना पड़ा है। अराजकताकी ऐसी हालत एक दशक पहले उत्तर प्रदेश और बिहारकी थी। पश्चिम बंगालमें जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ़ थी तब ममता बनर्जीने सरकारको उखाड़ फेंकनेकी शपथ ली थी।

❐ योगेन्द्र

पश्चिम बंगालमें एक प्रदर्शनके दौरान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टीके कार्यकर्ताओंने तत्कालीन कांग्रेस नेता ममता बनर्जीके साथ जब बदसलूकी करी थी, इसपर ममताने कम्युनिस्ट सरकारको उखाड़ फेंकनेकी शपथ ली थी। ममताने हिंसा और अराजकतासे गुजर रहे बंगालको कम्युनिस्टोंसे मुक्ति दिलायी। कम्युनिस्टोंके खिलाफ जिस आन्दोलनसे ममता ने सत्ताकी सीढ़ियां चढ़ी, अब अपने विरोधियोंको परास्त करनेके लिए ममताने वही रास्ता अपना लिया है। संदेशखालीकी घटनाके बाद हाईकोर्टने जिस तरहकी टिप्पणी ममता सरकारके खिलाफ की है, उससे जाहिर है कि पश्चिम बंगालमें कानून-व्यवस्था रसातलमें जा रही है। ममताकी पार्टी तृणमूलका एकमात्र उद्देश्य रह गया है अपने विरोधियोंकी आवाज बंद करना, इसके लिए चाहे गैरकानूनी तरीकोंका इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़ा। संदेशखाली मामलेको लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्टने बंगालके प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी टीएमसीको भी बेहद तल्ख लहजेमें फटकार लगायी। कोर्टने कहा कि यदि संदेशखाली मामलेमें एक प्रतिशत भी सच है तो प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसकी जिम्मेदार है। कोर्टने कहा कि यह मामला बेहद शर्मनाक है। अदालतने कहा कि हर नागरिककी सुरक्षा राज्य सरकारकी जिम्मेदारी है। कोर्टने कहा कि संदेशखाली मामलेमें जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकारको खुदसे नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्टने कहा कि यदि इस मामलेमें एक प्रतिशत भी सचाई है तो यह शर्मनाक है और पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौरपर सौ प्रतिशत जिम्मेदार हैं। कलकत्ता हाईकोर्टके चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानमने तल्ख लहजेमें कहा कि यदि इसका एक भी एफिडेविट सही है तो यह शर्मनाक है। यह लोगोंकी सुरक्षाका मामला है। चीफ जस्टिसने कहा कि यदि आप एससी-एसटी नेशनल कमीशनकी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें यदि एक फीसदी भी सच है तो यह सौ फीसदी शर्मनाक है। वहीं इस दौरान एक अन्य जनहित याचिकाकर्ताके वकीलने कहा कि इस मामलेमें गवाहोंको सुरक्षा प्रदान की जाय। सुरक्षा कारणोंसे कोई भी महिला अदालतमें गवाही देने नहीं आयी। एक अन्य याचिकाकर्ताकी वकील प्रियंका टिबरेवालने कहा कि उनके पास अनेक महिलाओंने यौन उत्पीड़नकी शिकायत की है। ये लोग कह रहे हैं कि यदि महिलाओंने बयान दिया तो उनके पति-बच्चोंका सिर काटकर फुटबाल खेलेंगे। राज्यकी ओरसे वकालत करते हुए महाधिवक्ता (एजी) ने कहा कि हमें देखना होगा कि संदेशखालीमें क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सीबीआईने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सुप्रीम कोर्टने भी सीबीआईको पिंजरेमें बंद तोता कहा था। सभी पक्षोंकी बातें सुननेके बाद मुख्य न्यायाधीशने शाहजहांके वकीलसे सख्त लहजेमें कहा कि आप एक आरोपितकी ओरसे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले अपने आसपासकी परछाइयोंसे छुटकारा पायें। इसके बाद दूसरे लोगोंकी शिकायतोंके बारेमें बात करें। यदि हलफनामेमें एक भी आरोप सच है तो वह भी शर्मनाक है। सरकार कहती है कि यहां महिलाएं सुरक्षित हैं। यदि हलफनामेमें कोई आरोप साबित हो जाता है तो ऐसे सभी दावे झूठे होंगे। हालांकि सुनवाई पूरी होनेके बाद भी हाईकोर्टने गुरुवारको फैसला सुरक्षित रख लिया। संदेशखालीमें ईडी और सीएपीएफ कर्मियोंपर हमलेके मास्टरमाइंड और तृणमूल कांग्रेसके निलंबित नेता शाहजहां शेखने कहा था कि वह राजनीतिक साजिशका शिकार है। उसके खिलाफ लगाये गये आरोप झूठे हैं। उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पूछताछके दौरान शाहजहांने पांच जनवरीको संदेशखालीमें केंद्रीय एजेंसी कर्मियोंपर हमला करनेवालोंके साथ किसी भी तरहके संबंधसे इनकार किया था। शाहजहांने अधिकारियोंसे कहा था कि वह इस हमलेकी दिलसे निंदा करता है और चाहता है कि हमलेके लिए जिम्मेदार लोगोंको सजा मिले। ईडी ने शाहजहांसे उसकी कम्पनी सबीना एंटरप्राइजेजके जरिये काली कमाईको सफेद करनेके मामलेमें पूछताछ की। जिसपर शाहजहांने कहा कि सब झूठ है। अनुसूचित जाति-जनजातिके पैनलने पश्चिम बंगालमें राष्ट्रपति शासनकी सिफारिश की थी। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको पैनलने एक रिपोर्ट सौंपी थी। पैनलने अपनी रिपोर्टमें कहा है था कि राज्यमें कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है। पैनलका यह भी कहना था कि आरोपियोंपर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानूनके तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। देशमें पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां राज्यपालने केन्द्र सरकारको कई बार बिगड़े हालात की जानकारी दी है। विपक्षी दलोंकी शासित राज्योंमें भी राज्यपालों और सत्तारूढ़ दलकी सरकारोंमें अनबन होती रहती है, किन्तु संवैधानिक पदपर रहते हुए जितने खराब संबंध पश्चिम बंगालमें रहे हैं, उतने किसी भी राज्यमें नहीं रहे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने एक चुनावी सभामें कहा कि जो लोग संदेशखालीकी महिलाओंके उत्पीड़नके जिम्मेदार हैं, उनको अब अपना बाकी जीवन सलाखोंके पीछे बिताना होगा। कूचबिहारमें एक रैलीको संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने कहा कि हालमें पूरे देशने देखा कि कैसे टीएमसी और राज्य सरकारने संदेशखालीकी महिलाओंका शोषण करनेवाले लोगोंको बचाया। लेकिन उन्हें किसी भी कीमतपर बख्शा नहीं जायगा। जिन लोगोंने इस जघन्य अपराधको अंजाम दिया है, उन्हें अब अपना शेष जीवन सलाखोंके पीछे बिताना होगा। चुनाव प्रचारके दौरान ममता बनर्जी पूर्वमें भी जहर उगलनेमें पीछे नहीं रही हैं। ममता पूर्वमें पीएम मोदी और स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहके खिलाफ अपशब्दोंका इस्तेमाल करती रही हैं। ममता बनर्जी कूचबिहार रैलीमें यहांतक कह गयीं कि आप जहरीले सांपपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भाजपापर नहीं। ममता बनर्जीने कूचबिहारसे भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिकका नाम लिये बिना उनपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुम मंत्रीके नामपर कलंक हो। ममताने कहा कि राज्य सरकारके अधिकारियोंका ट्रांसफर हो रहा है, केंद्रीय एजेंसीका कितना ट्रांसफर हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा निर्वाचनके कोड नहीं मानती। उन्होंने आरोप लगाया कि शीतलकुचीमें जिसने गोली मारकर हत्या किया वह अभी बीरभूममें बीजेपी प्रार्थी बन गया। ममताने आरोप लगाया कि तीन सालोंसे आवास योजनाका पैसा नहीं दिया जा रहा है। सड़कके पैसे नहीं दिये जा रहे हैं। पहले सौ दिनके कामपर बंगाल एक नंबर पर था। पश्चिम बंगालमें शायद ही कोई ऐसा चुनाव रहा हो जहां हिंसाका तांडव नहीं हुआ हो। चुनाव आयोगके तमाम सख्त प्रयासोंके बावजूद पश्चिम बंगाल चुनावके दौरान हिंसाका शिकार रहा है। वर्ष २०२३ में हुए पंचायत चुनावके मतदानके दौरान चुनावी हिंसामें १७ लोगोंकी जान गयी। तृणमूल कांग्रेसका दावा था कि चुनावी हिंसामें सबसे ज्यादा उनके कार्यकर्ताओंकी हत्या हुई। मरनेवालोंमें ६० फीसदी उनके कार्यकर्ता हैं, जबकि विपक्षी पार्टियोंने चुनाव हिंसाको लेकर ममता बनर्जीकी सरकार और चुनाव आयोगपर निशाना साधा। देखना यही है कि हिंसासे त्रस्त रहे पश्चिम बंगालमें चुनाव आयोग कैसे शांतिपूर्ण और निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराता है। पीड़ित महिलाओंको न्याय दिलाना सभी दलोंका एजेंडा होना चाहिए। तभी उन्हें न्याय मिल पायेगा।

पश्चिम बंगालमें शायद ही कोई ऐसा चुनाव रहा हो जहां हिंसाका तांडव न हुआ हो। चुनाव आयोगके तमाम सख्त प्रयासोंके बावजूद पश्चिम बंगाल चुनावके दौरान हिंसाका शिकार रहा है। वर्ष २०२३ में हुए पंचायत चुनावके मतदानके दौरान हिंसामें १७ लोगोंकी जानें गयीं। विपक्षी पार्टियोंने चुनाव हिंसाको लेकर ममता बनर्जीकी सरकार और चुनाव आयोगपर निशाना साधा। देखना यही है कि हिंसासे त्रस्त रहे पश्चिम बंगालमें चुनाव आयोग कैसे शांतिपूर्ण और निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराता है। पीड़ित महिलाओंको न्याय दिलाना सभी दलोंका एजेंडा होना चाहिए। तभी उन्हें न्याय मिल पायेगा।

बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं वाड्रा

कांग्रेस उत्तर प्रदेशकी ८० लोकसभा सीटोंपर अखिलेश यादवके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेसको अमेठी और रायबरेली समेत १७ सीटें मिली हैं। अमेठी और रायबरेली सीटें हमेशा गांधी परिवारका गढ़ रही हैं।

❐ अजय कुमार

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्राके पति और राहुल गांधीके जीजा रॉबर्ट वाड्राने अमेठीसे लोकसभा चुनाव लड़नेकी इच्छा जता कर अमेठीकी राजनीतिमें सनसनी फैला दी है। रॉबर्ट वाड्राका नाम कहीं औरसे चर्चामें नहीं आया। वाड्राने स्वयं अमेठीसे चुनाव लड़नेकी इच्छा जतायी है, लेकिन संभवता गांधी परिवारके लिए यह फैसला लेना मुश्किल होगा कि रॉबर्टको अमेठीसे चुनाव लढ़ाया जाये। इसके पीछे ठोस आधार भी है। रॉबर्टको लड़ानेमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी छवि काफी खराब यानी एक भ्रष्टाचारीके रूपमें बनी हुई है। रॉबर्टको अमेठीसे चुनाव लड़ाया गया तो बीजेपीके लिए कांग्रेस और गांधी परिवारपर भ्रष्टाचारको लेकर हमला तेज करनेका और भी मौका मिल जायेगा। फिर रॉबर्टकी कोई सियासी पहचान भी नहीं है। रॉबर्टको चुनाव लड़नेपर यदि गांधी परिवारके भीतर सहमति बनी हुई होती तो कांग्रेसियोंकी एक बफी फौज रॉबर्टको चुनाव लड़ानेके लिए हो-हल्ला मचाने लगती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस मतलब साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी ससुरालसे अलग लाइनपर चल रहे हैं। दरअसल रॉबर्ट चुनाव लड़कर कांग्रेसमें अपना रूतबा बढ़ाना चाहते हैं। ऐसेमें वह राहुल गांधीके समानांतर खड़े नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवारके सामने एक बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं। वह गांधी परिवारको चुनौती देते दिख सकते हैं। इसलिए राबर्टका अमेठीसे चुनाव लड़नेका सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है।

रॉबर्ट वाड्राके अमेठीसे चुनाव लड़नेकी इच्छा जाहिर करनेके बाद इतना जरूर हुआ है कि अब कांग्रेसका ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि अमेठीकी चुनावी रणभूमिमें जल्दसे जल्द अपना योद्धा उतारकर कमजोर हो रहे कार्यकर्ताओंको मजबूती देनेका है। माना जा रहा है कि पार्टी अब कांग्रेस विधानमंडल दलकी नेता प्रतापगढ़से रामपुर खाससे विधायक आराधना मिश्र मोनापर दांव खेल सकती है। अब सभीको कांग्रेस राहुल गांधीकी हां और न का ही इंतजार है। राहुल गांधीकी ओरसे तस्वीर साफ होते ही किसी एक प्रत्याशीका नाम उजागर हो जायेगा। वहीं, कांग्रेसके अमेठीके जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघलने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमारे हिसाबसे तो राहुल भइया ही अमेठीसे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। गौरतलब हो, रॉबर्ट वाड्राने एक समाचार एजेंसीसे बातचीत करते हुए कहा कि अमेठीके लोग चाहते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करूं। वर्षोंतक गांधी परिवारने रायबरेली एवं अमेठीमें कड़ी मेहनत की। अमेठीके लोग वास्तवमें वर्तमान सांसद (स्मृति ईरानी) से परेशान हैं, मतदाताओंको लगता है कि उन्होंने स्मृति ईरानीको चुनकर गलती की है।

फिलहाल कांग्रेस उत्तर प्रदेशकी ८० लोकसभा सीटोंपर अखिलेश यादवके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेसको अमेठी और रायबरेली समेत १७ सीटें लड़नेके लिए मिली हैं। अमेठी और रायबरेली सीटपर कांग्रेसने अभीतक अपने उम्मीदवारोंका ऐलान नहीं किया है। इन दोनों ही सीटोंपर संशय बना हुआ है। ये दोनों सीटें अहम हैं, क्योंकि ये सीटें हमेशा गांधी परिवारका गढ़ रही हैं। हालांकि २०१९ में राहुल गांधी अमेठी सीट हार गये थे। दशकोंतक जिस अमेठीमें गांधी-नेहरु परिवारका डंका बजता था। आज उसी अमेठीमें भाजपाकी स्मृतिका जादू चल रहा है। दस साल पहले आम चुनाव २०१४ में भाजपा प्रत्याशीके रूपमें कांग्रेस नेता राहुल गांधीसे मुकाबला करने अमेठी आयी स्मृति ईरानीने मात्र २३ दिनोंमें ही यहांके लोगोंसे कुछ ऐसा नाता जोड़ा कि उन्हें तीन लाखसे अधिक मत प्राप्त हुए।

मोदी सरकारमें स्मृति ईरानीको हारके बाद भी मंत्री बनाया गया। इसीके साथ स्मृतिने अमेठीमें अपनी सक्रियता बढ़ा दी। स्मृतिकी सक्रियताका लाभ भाजपाको मिलने लगा और एकके बाद एक चुनाव परिणाम भाजपाके पक्षमें आने लगे। गांव-गांव, घर-घर स्मृति अपनी नयी पहचान बनानेमें पूरी तरह सफल रही। आम चुनाव २०१९ में स्मृति अमेठीमें भाजपाका कमल खिलानेमें कामयाब हुई। इसीके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीकी जीतका सिलसिला भी चौथी बार थम गया। इससे पहले राहुल गांधीने २००४, २००९ एवं २०१४ में अमेठी हैट्रिक लगा चुके थे। अमेठीके चुनावी रणभूमिमें भले ही अभीतक केंद्रीय मंत्री एवं सांसद स्मृति ईरानी अकेली घोषित योद्धा हों परन्तु उनकी सक्रियता चुनावको लेकर काफी बढ़ गयी है। पिछले चार दिन वह अमेठीमें रहकर बूथवार चुनावी लड़ाईमें बड़ी जीतके लिए रणनीति बनानेमें जुटी रही। वर्ष १९६७ में अस्तित्वमें आयी अमेठी संसदीय सीटमें कुल पांच विधानसभाएं हैं। इनमें अमेठी, जगदीशपुर, गौरीगंज एवं तिलोई अमेठी जिलेकी हैं, जबकि सलोन विधानसभा रायबरेली जिलेकी है। बीते तीन चुनावोंकी बात करें तो अमेठीकी जनताका मूड बदला-बदला नजर आया। वर्ष २००९ में कांग्रेसके टिकटपर चुनावी समरमें उतरे राहुल गांधीने ५७.२४ फीसदी मतोंके अंतरसे जीत दर्ज कीए, लेकिन २०१४ के चुनावमें परिणाम कुछ अलग दिखा। इस बार भाजपाके टिकटपर चुनाव मैदानमें उतरीं स्मृति जूबिन ईरानी मजबूतीसे लड़ीं। यह बात अलग है कि राहुल गांधीने जीत दर्ज की, लेकिन मतोंका प्रतिशत २५.०७ फीसदी घटनेके साथ ही जीतके अंतरमें ३२.८३ फीसदी कमी आयी। फिर वर्ष २०१९ के चुनावमें स्मृतिने गांधी परिवारके गढ़को ध्वस्त कर जीत दर्ज कर ली। संसदीय सीटकी पांच विधानसभाओंमेंसे चारपर भाजपाने जीत हासिल की थी। ऐसेमें इस बार गैर-कांग्रेसी सांसदके दोबारा जीतने, जीतका अंतर बढ़ाने, सभी पांचों विधानसभा सीटोंसे जीत हासिल करनेकी एक बड़ी चुनौती स्मृति ईरानीके सामने है।

आत्मबोध

नवसंवत्सर

❐ निमेष शास्त्री

हिंदू पंचांगके अनुसार चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे नवसंवत्सरका प्रारंभ माना जाता है। इसी दिनसे चैत्र नवरात्रिकी शुरुआत हो जाती है। इस दिनको गुड़ी पड़वाके नामसे मनाया जाता है जिसका हिंदू धर्ममें बहुत महत्व माना गया है। गुड़ीका अर्थ है ध्वज अर्थात् झंडा और प्रतिपदा तिथिको पड़वा कहा जाता है। इस पर्वको हिंदू धर्मके नये वर्षके आगाजके रूपमें मनाया जाता है। पूरे भारतमें अलग-अलग नामोंसे इस त्योहारको मनानेके साथ ही अनुष्ठान भी कराया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्माने सृष्टिकी रचना की थी। रामायण कालमें दक्षिण भारतपर बालीका अत्याचारी शासन था। सीताजीको ढूंढ़ते हुए जब भगवान रामकी मुलाकात सुग्रीवसे हुई तो उन्होंने श्री रामको बालीके अत्याचारोंसे अवगत कराया। तब भगवान रामने बालीका वध कर वहांके लोगोंको उसके कुशासनसे मुक्ति दिलायी। मान्यता है कि यह दिन चैत्र प्रतिपदाका था। इसलिए इस दिन गुड़ी या विजय पताका फहराई जाती है। महाभारत कालमें इसी शुभ दिनपर युधिष्ठिरका भी राज्याभिषेक हुआ था। माना जाता है कि इसी दिनसे सतयुगकी शुरुआत हुई थी। ब्रह्माने इसी दिन ब्रह्मांडका निर्माण किया था और जीवनकी शुरुआत की थी। इसी दिन भगवान विष्णुने मत्स्य अवतार लिया था। चैत्र ही एक ऐसा महीना है, जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित एवं पुष्पित होती हैं। शुक्ल प्रतिपदाका दिन चंद्रमाकी कलाका प्रथम दिवस माना जाता है। जीवनका मुख्य आधार वनस्पतियोंको सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियोंका राजा कहा गया है। इसीलिए इस दिनको वर्षारंभ माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन भारतके महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्रीने अपने अनुसंधानके फलस्वरूप सूर्योदयसे सूर्यास्ततक दिन, महीने और वर्षकी गणना करते हुए भारतीय पंचांगकी रचना की थी। इस पर्वका उल्लास पूरे देशमें अलग-अलग रूपोंमें देखनेको मिलता है, जो दुर्गा पूजाके साथ रामनवमीके दिन समाप्त होता है। इस दिन सूर्यदेवकी आराधना की जाती है। इस दिन सुंदरकांड, रामरक्षास्तोत्र, देवी भगवतीके मंत्रोंका जाप भी किया जाता है।

किशोरोंपर सोशल मीडियाका कुप्रभाव

❐ दीपिका अरोड़ा

तकनीकी विकासकी करिश्माई देन, मोबाइल फोन अपनी विविधताकी उपयोगिताके चलते युवाओं तथा बड़े-बुजुर्गोंसे लेकर बच्चोंतकका चहेता बन चुका है। अवयस्कों द्वारा सोशल मीडियापर अधिक समय बिताना उनके शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकासको प्रभावित कर रहा है। मोबाइलके बढ़ते दुष्प्रभावोंपर संज्ञान लेते हुए, हाल ही में अमेरिकाके फ्लोरिडा राज्यमें नाबालिगोंके लिए सोशल मीडियाके इस्तेमालपर पाबंदी लगानेका ऐलान किया गया। इसके अंतर्गत १४ वर्षसे कम आयुवर्गके बच्चोंके सोशल मीडिया खातोंपर रोक रहेगी। सोशल मीडियाके प्रयोगसे पूर्व अभिभावकोंकी अनुमति अनिवार्य होगी। नियमोल्लंघनपर संबद्ध छात्रका मोबाइल जब्त करने एवं आदेश पालन सुनिश्चित बनाने हेतु शिक्षकोंको बच्चोंके बैग सख्तीपूर्वक जांचनेका अधिकार दिया गया है। सुधारात्मक दृष्टिकोणसे इसे एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। फ्रांस सरकार पहले ही अपने देशमें इससे संबद्ध कानून लागू कर चुकी है। ब्रिटेनके शिक्षा मंत्रालयने भी कुछ ही समय पूर्व, छात्रोंका व्यवहार संयमित करने तथा पढ़ाईपर एकाग्रता बढ़ानेके उद्देश्यसे विद्यालयोंमें मोबाइल फोनके प्रयोगपर पूर्ण पाबंदी लगाने संबंधी निर्देश जारी करते हुए कहा कि पाठशालामें इसका प्रयोग पढ़ाई तथा अन्य गतिविधियोंमें व्यवधान उत्पन्न करता है।

बच्चोंमें मोबाइलकी बढ़ती लतके विषयमें भारतवर्ष भी अपवाद नहीं। सोशल मीडियाने मानो बच्चोंका बचपन ही छीन लिया है। परम्परागत खेल खेलनेकी बजाय मोबाइलपर अंगुलियां घुमाना बच्चे मनोरंजनका बेहतर उपाय मानते हैं। डब्ल्यूएचओकी रिपोर्टके मुताबिक पांच सालतकके ९९ प्रतिशत बच्चे गैजेट एडिक्शनके शिकार हैं। अधिक स्क्रीन टाइम बच्चेके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, देशके ६६ प्रतिशत अभिभावक इस तथ्यसे अनभिज्ञ हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययनके अनुसार ६५ प्रतिशत परिवार खाना खिलाते समय बच्चोंको टीवी-मोबाइल दिखाते हैं। १२ माहका बच्चा प्रतिदिन ५३ मिनट स्क्रीन देखनेमें बिताता है, तीन वर्षकी उम्र होनेतक यह अवधि बढ़कर डेढ़ घंटा हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञोंके मुताबिक बचपनमें ही मोबाइलकी लत लगनेसे बच्चे अनेक रोगोंकी चपेटमें आने लगते हैं। स्क्रीन टाइम बढ़नेसे शारीरिक गतिविधि कम होती है तथा ओवरइटिंगकी आदत पनपती है, जिसके फलस्वरूप मोटापा घेरने लगता है एवं अल्पायुमें ही मधुमेह, हृदय रोग आदि गम्भीर रोगोंसे पीड़ित होनेकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

सोशल मीडियापर अधिक समय बिताना जहां समूची दिनचर्याको प्रभावित करता है, वहीं बच्चोंमें आलस्य, अनिद्रा, अवसाद, चिंता, तनाव आदि मानसिक समस्याएं बढ़ानेके साथ ही बेचैनी, झल्लाहट तथा हिंसक प्रवृत्ति उपजाने का भी प्रमुख कारण बनता है। अभिभावकोंके साथ गुणवत्तापूर्ण समय न बिताना उन्हें समाजसे अलग-थलग कर, आत्मकेंद्रित तो बनाता ही है, उनकी एकाग्रताको भी प्रभावित करता है। विशेषकर रील बनानेका आधुनिक प्रचलन अवयस्कोंको ऐसी आत्ममुग्धताकी ओर धकेल रहा है, जिसमें बहुत बार मर्यादाएं भी तार-तार होती दिखाई पड़ती हैं। गैजेट्सपर ज्यादा समय बितानेसे बच्चोंको बोलनेमें दिक्कत एवं समाजमें दूसरे लोगोंसे तारतम्य स्थापित करनेमें परेशानी महसूस होने लगती है। दूसरे शब्दोंमें, मोबाइल, टेबलेट, कंप्यूटर आदिका अधिक प्रयोग बच्चोंको वर्चुअल ऑटिज्मका शिकार बना रहा है।

मोबाइल टाइमका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आंखोंपर देखनेमें आया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नयी दिल्लीकी हालिया रिपोर्टके मुताबिक २० वर्षोंके दौरान छोटे बच्चोंमें मायोपियाकी बीमारी तीन गुणा बढ़ गयी। इस संदर्भमें अकेले राजधानी दिल्लीकी ही बात करें तो २००१ में बच्चोंमें आंखसे कम दिखनेकी समस्या सात प्रतिशत थी जो कि २०११ में बढ़कर १३.५ प्रतिशत तक जा पहुंची। कोविडके पश्चात् २०२१ में किये गये सर्वेक्षणमें २० से २२ प्रतिशत बच्चे मायोपियाकी समस्यासे ग्रस्त पाये गये, जिसका सबसे बड़ा कारण बच्चोंमें बढ़ता स्क्रीन टाइम रहा। सोशल मीडियाकी लतसे बचानेके लिए अभिभावकोंसे अपेक्षित है कि बच्चोंको गुणवत्तापूर्वक समय देनेके साथ ही उनकी हॉबीजको उभारनेमें भी सहायक बने। फैमिली टाइमके दौरान स्वयं भी मोबाइलसे दूरी बनाये रखना निहायत जरूरी है। बच्चोंको प्रतिदिन २०-३० मिनट साइकिल चलानेके लिए प्रेरित करना एवं बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस जैसी आउटडोर खेलें खेलने हेतु प्रोत्साहित करना बच्चोंको शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूपसे पुष्ट बनायेगा। खेल विशेषज्ञोंके अनुसार रोजाना बाहर खेलनेसे आंखोंकी रोशनीमें सुधार होता है। अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस सरकारोंका यह निर्णय निश्चय ही छात्रोंके लिए हितकारी है। इससे न केवल वे पढ़ाईपर ध्यान केंद्रित कर पायंगे, बल्कि मोबाइल फोनपर अनुचित सामग्री देखनेसे भी बच सकेंगे। अपराधीकरणमें प्रवृत्त अवयस्कोंकी बढ़ती संख्याके दृष्टिगत, भारत जैसे देशोंको भी इस संदर्भमें ठोस उपाय ढूंढ़ने चाहिए। बच्चे तो कच्ची माटीकी मानिंद हैं, उनके व्यक्तित्वको सही आकार प्रदान करना अभिभावकों, समाज एवं सरकारोंका ही साझा दायित्व है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जांच में बाधा डालना दुर्भाग्यपूर्ण

पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर इलाके में शनिवार तड़के एनआईए अधिकारियों पर हुआ भीड़ का हमला बताता है कि हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र ने पिछले अनुभव से कोई सबक नहीं लिया है। इस घटना ने इसी जनवरी में हुए संदेशखाली प्रकरण की याद ताजा कर दी है, जिसमें भीड़ ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की टीम को निशाना बनाया था। एक बार फिर दोनों पक्षों की ओर से राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की संभावना को धूमिल बनाता है। ऐसे में यह ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक बयानों से हटकर पहले इस मामले से जुड़े ठोस तथ्यों पर गौर कर लिया जाए। पहली बात, इस मामले की जांच एनआईए कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर कर रहा है। दूसरी बात, मामला एक बम ब्लास्ट से जुड़ा है, जो दिसंबर 2022 में हुआ था। तीसरी, घटना भले दो साल पहले की हो, उसकी जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए को बाद में सौंपी गई। चौथी, इन आरोपियों को पहले भी एनआईए की तरफ से समन किया गया था, जिसे इन लोगों ने अनदेखा कर दिया था। पांचवीं और आखिरी बात यह कि एनआईए की टीम उपयुक्त वारंट के साथ गई थी। किसी राज्य में सेंट्रल एजेंसी से जुड़े अधिकारियों के कामकाज में इस तरह बाधा डाला जाना बेहद खतरनाक और नुकसानदेह है। संदेशखाली वाले मामले में भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि बाद में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय दबंग नेता माना जाता था। पार्टी ने उसे निलंबित भी कर दिया। लेकिन उस घटना ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। हैरत की बात है कि पिछले अनुभव के बावजूद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी परोक्ष रूप से एनआईए की कार्रवाई पर ही सवाल उठाया है। तृणमूल से जुड़े कई अन्य नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि भाजपा , तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में डर बैठाना चाहती है। उनका कहना है कि इस तरह से रात में टीम भेजकर आरोपियों को पकड़ने का मकसद यही है। इस मामले में प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी न की जाए। जांच एजेंसियों की जांच में बाधा डालने का मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है।

लालू, रोहिणी, सिंगापुर और सारण

अनुभव सिन्हा

इस परिवार के लिए सारण संसदीय सीट ने बराबर का हिसाब किया है। लालू यहां से जितनी बार जीते हैं, उतनी ही बार उनको और उनकी श्रीमती जी को हार का भी मुंह देखना पड़ा है। इससे यह वहम तो नहीं रहता कि यह सीट लालू यादव का गढ़ है और जीत की पूरी गारंटी है। लेकिन रोहिणी के समर्थन में राजद कार्यकताओं का उत्साह यही बताता है कि रोहिणी के रूप में युवा राजद उम्मीदवार का समर्थकों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। इस रोड शो में खुद को लांच करते हुए रोहिणी ने जिस तरह से डेब्यू किया और जो कहा उसपर ध्यान देने की जरूरत है।

लालू परिवार गदगद है। यह पहली बार है जब इस परिवार की दो बेटियां लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि तीसरी बार चुनाव लड़ रही मीसा भारती अभी तक लोकसभा नहीं जा पायीं हैं। लेकिन, लालू की चार संतानों की बात की जाय जिनका प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक रुझान सामने है तो तेज प्रताप यादव और मीसा भारती की लोकतान्त्रिक समझ तथा तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की समझ में अंतर साफ दिखाई देता है। पर अभी बात हो रही है रोहिणी आचार्य की। विवाहित हैं और इनका एक ठिकाना सिंगापुर है, जहां उनके पति का व्यवसाय है। अब लोकसभा की सारण संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के क्रम में 2 अप्रैल को उन्होंने रोड शो किया। रोड शो की सामने आई तस्वीरों से यह साफ पता चलता है कि इस सीट पर युवा उम्मीदवार और वह भी यदि लालू परिवार से हो तो शायद ही कोई राजद समर्थक होगा जिसने अपनी उपस्थिति न दिखाई हो।

इस परिवार के लिए सारण संसदीय सीट ने बराबर का हिसाब किया है। लालू यहां से जितनी बार जीते हैं, उतनी ही बार उनको और उनकी श्रीमती जी को हार का भी मुंह देखना पड़ा है। इससे यह वहम तो नहीं रहता कि यह सीट लालू यादव का गढ़ है और जीत की पूरी गारंटी है। लेकिन रोहिणी के समर्थन में राजद कार्यकताओं का उत्साह यही बताता है कि रोहिणी के रूप में युवा राजद उम्मीदवार का समर्थकों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। इस रोड शो में खुद को लांच करते हुए रोहिणी ने जिस तरह से डेब्यू किया और जो कहा उसपर ध्यान देने की जरूरत है। रोहिणी ने कहा कि अपने पिता के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी एक किडनी दी और सारण के लोगों के लिए वह अपनी जान भी दे सकती हैं। यह अपने पिता और अपने संसदीय जीवन की सम्भावना को देखते हुए उनकी भावनात्मक अपील थी।

लालू प्रसाद की कोशिश सारण संसदीय सीट को हॉट सीट बनाने की है। रोहिणी अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में रहीं हैं। पर अब वह लोगों के बीच हैं। उनकी यह पृष्ठभूमि उस सीट के लिए मायने रखती है जहां से वह चुनावी समर में भाजपा के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी के मुकाबले में हैं। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या और भी है और, यह उनके लिए बड़ा अन्तर पैदा कर सकता है। छपरा में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ससुराल भी है। जहां उनकी ससुराल है वह एक प्रतिष्ठित राजनीतिक घराना है। लालू यादव को जब कोई जानता तक नहीं था, इस परिवार के दरोगा प्रसाद राय 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके पांच में से दूसरे पुत्र चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव का विवाह जल्द ही विवादों में घिर गया और स्थिति तलाक तक पहुंच गई लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। सारण की उस बेटी के साथ लालू परिवार के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। फौरी तौर पर यह लगता है कि लालू यादव ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस रिश्ते पर पड़ी बर्फ को पिघलाना भले ही जरुरी न समझा हो, लेकिन यह भावनात्मक मुद्दा है।

इसमें दिलचस्प यह भी है ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय की ओर से इस चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, पर भाजपा ने ऐश्वर्या के बहाने लालू यादव पर जो निशाना साधा है, वह चुनाव नजदीक आते-आते रोहिणी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भाजपा ने सारण के लोगों को तेज प्रताप-ऐश्वर्या राय की बेमेल शादी की याद दिला दी है। तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं कि दरोगा प्रसाद राय के परिवार से लालू यादव के परिवार की तुलना नहीं हो सकती। पांच भाइयों में चंद्रिका राय दूसरे नंबर हैं। वह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके बड़े भाई व्यवसायी हैं। एक भाई सेना से रिटायर्ड कर्नल हैं। एक भाई टिस्को में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं और एक भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इनकी तुलना में लालू यादव परिवार में सबसे ज्यादा शिक्षित मीसा भारती और रोहिणी ही हैं जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है लेकिन दोनों को कभी आला पकडे हुए नहीं देखा गया । दूसरे तेजस्वी यादव हैं जो 9 वीं फेल हैं। लेकिन राजद की बागडोर उनके ही हाथ में है। ऐश्वर्या राय के पति तेज प्रताप यादव की शिक्षा इंटर फेल तक की है। जबकि ऐश्वर्या ने उच्च शिक्षा हासिल कर रखी है। दो परिवारों के बीच के इस गुणात्मक अंतर का असर राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। लालू प्रसाद ने जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को राजनीति में लांच किया और सारण से चुनाव लड़ने का एलान किया, उससे यह स्पष्ट है कि ऐसा करते समय उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का ही ध्यान रखा। लेकिन जब चुनाव हो तो जनाधार की बात भी सामने आती ही है और भले चन्द्रिका राय ने किसी भी तरह की राजनीतिक सक्रियता से परहेज किया हो, सारण के लोगों के मन में यह कुलबुलाहट तो है ही।

रोहिणी की उम्मीदवारी को लालू की राजनीति से अलग करके देखा नहीं जा सकता। उनकी सक्रियता तब सामने आयेगी जब वह सांसद बन जाएं। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उनकी उम्मीदवारी के पहले कुख्यात रीतलाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। रीतलाल ने बजाप्ता बयान दिया था कि उनकी उम्मीदवारी पर राजद सुप्रीमो सहमत हैं। इसका क्लाईमेक्स तब सामने आया जब भाई-बहन(रीत लाल-मीसा भारती) के ऊपर ही तय करने के लिए छोड़ दिया गया कि किसे लड़ना चाहिए। लेकिन जब मीसा भारती के ही लड़ने पर मुहर लग गयी तब जाकर यह स्पष्ट हुआ कि भाई-बहन का नाटक सिर्फ रीतलाल के समर्थन को लेकर ही था। लालू यादव को यह तसल्ली हो सकती है कि रोहिणी चूंकि पहली बार चुनाव मैदान में हैं इसलिए उनका क्रेज मीसा भारती के मुकाबले ज्यादा होगा, तब भी क्या इतना ही काफी है चुनाव जीतने लिए ? अपनी विशिष्ट राजनीति की बदौलत लालू यादव ने अपनी गरीबी को असाधारण तरीके से बदल दिया। लेकिन दिलचस्प यह है कि लालू के समर्थकों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे 30 साल पहले लालू यादव की सभाओं में पहुंचने वाला युवा आमतौर पर नंगे पांव होता था, उनकी उम्र अब 60 साल की हो गयी होगी। अब उनके 25-30 साल के बेटे तेजस्वी यादव की सभाओं में उनका हौसला बढ़ाते हैं पर, उनके पांव नंगे ही होते हैं।

चारा घोटाले में सीबीआई की अदालत से सजायाफ्ता और एमपी-एमएलए कोर्ट ग्वालियर से फरार घोषित लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी की सफलता और असफलता उनके पिता की छवि से भी निर्धारित होगी। राजद ने अपना एक विशिष्ट वोट बैंक तैयार किया हुआ है। एकीकृत और विभाजित बिहार में कभी भी लालू यादव का नेतृत्व सिंपल मेजॉरिटी प्राप्त नहीं कर पाया। जोड़-तोड़ लालू यादव की राजनीति का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें खुद को केंद्र में बनाये रखने के लिए राजद सुप्रीमो ने जितना नुकसान कांग्रेस और वाम दलों को पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान बिहार को पहुंचाया है। लेकिन सुखद यह है कि राजनीतिक दलों की मजबूरी, बिहार की मजबूरी उस तरह से नहीं बन पाई जैसा लालू यादव ने चाहा होगा या अब जैसा तेजस्वी यादव चाहते होंगे।

2014 के बाद यह तीसरा चुनाव है। इस चुनाव की विशेषता यह है कि अकेले नरेन्द्र मोदी ने सारे भ्रष्टाचारियों को महागठबंधन के नाम पर गोलबंद कर दिया है। बिहार सहित जहां भी महागठबंधन है उसमें दरार भी है पर, बिहार में इसकी कमान लालू यादव के हाथ में है। एक और तथ्य है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए- 2019 के लोकसभा चुनावों में राजद एक भी सीट जीत नहीं पाया था और पिछले पांच वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो राजद के खाते में उपलब्धि के तौर पर शामिल हुआ हो। इसके उलट आगामी लोकसभा चुनावों में बिहार की 40 सीटों का बंटवारा जिस तरह से लालू यादव ने किया उससे महागठबंधन के अन्य दल अपनी हकमारी से नाखुश भी है। बावजूद इसके महागठबंधन की लगाम लालू यादव के हाथ में है, वैसी स्थिति में नजर तो लालू यादव पर ही है और उन सीटों पर ज्यादा है जिनपर राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन्ही में से एक सीट छपरा भी है।

https://t.me/Newspaperpaid

हिंद पर तिरंगा पहले सुभाष ने फहराया था, अतः वे ही पीएम

के. विक्रम राव

अंतरराष्ट्रीय कानून भी इसी प्रावधान की पुष्टि करता है कि राष्ट्र के लिये निश्चित भूभाग, स्वायत प्रशासन और वित्तीय तथा सैन्य व्यवस्था हो। अंतः सुभाष बोस ने 29 दिसम्बर 1943 के दिन शहीद तथा स्वराज द्वीप घोषित कर दिया था। अण्डमान फिर उपनिवेश नहीं रहा। मुक्त हो गया था। जबकि गुलाम भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ था। नेहरु ने लालकिले पर तब तिरंगा लहराया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सरकार तो भागकर लंदन आये, पनाह पाये फ्रेंच, नार्वे, डेनमार्क आदि राष्ट्रों के समानान्तर अस्तित्व को कानूनी मान्यता दे दी थी। इन्हीं सब के देश पर हिटलर का कब्जा हो गया था। अतः मुक्त अण्डमान भी वैसा ही था, तो उसे अधिमान्यता क्यों नहीं ? इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि दिल्ली में शासक-ब्रिटेन ने अपनी संसद में अधिनियम पारित कर दिल्ली का राज कांग्रेस को हस्तांतरित किया था। स्वतंत्र शब्द कहीं उल्लिखित ही नहीं है। दूसरा भूभाग जिन्ना को सौंप दिया। बोस ने सैन्य शक्ति के बल साम्राज्यवादियों को शिकस्त देकर अण्डमान छीना था। स्वयं बोस कहा करते थे कि वे भीख में स्वतंत्रता नहीं लेंगे। वायसराय लुई माउंटबेटन ने नेहरू को स्वतंत्रता बख्श दी थी। वैधानिक स्थिति यहीं है। अर्थात आजाद हिन्द की सरकार ही प्रथम स्वचालित स्वतंत्र शासन था। पर बोस के असामयिक निधन से स्थिति बदल गयी। यूं नेताजी के बारे में मेरी मान्यता है कि नेताजी स्वतंत्रता इतिहास के सर्वाधिक त्रासदीपूर्ण नायक हैं।

लोकसभा चुनाव में नए कलेवर में एक पुराना विवाद अब वाद वितंडा के आयाम लिए सर्जा है। बांग्ला भाषियों का आग्रह है कि नेताजी सुभाष बोस को प्रथम प्रधानमंत्री माना जाए। शेरनी-बांग्ला कुमारी ममता बनर्जी की राय है कि अविभाजित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बोस थे, जब उन्होंने अंडमान द्वीप में आजाद भारत सरकार रची थी। सुभाष बोस के अनुज के पड़पोते श्री चंद्र कुमार बोस की भी ऐसी ही मान्यता है कि जब बंगाल और पंजाब एक थे उस समय भारत के नेता उनके दादाजी थे। याद रहे अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर में 21 अक्टूबर 1943 सुभाष बोस ने अविभाजित भारत की आजाद सरकार बनाई थी। इसी अवधारणा को मंडी (हिमाचल) से भाजपा प्रत्याशी तथा फिल्मी सितारा कंगना राणावत ने एक मांग के रूप में उठा दी। इस पर सोनिया-कांग्रेस ने आपत्ति जताई। हालांकि जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश राज ने सत्ता हस्तांतरण द्वारा विभाजित भारत का प्रधानमंत्री नामित किया। हिंदुस्तान को काटकर पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपा था।

कंगना की अवधारणा के समर्थन में विधिसम्मत तर्क 'हिन्दुस्तानी' नाम के एक ग्रुप के विस्तृत विवरण में है : 'सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी भारत सरकार 'आजाद हिन्द सरकार' हुयी थी। इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री का जिम्मा संभाला। जापान के अलावा नौ देशों की सरकारों ने आजाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, फिलीपींस, थाईलैंड, मंचूरिया और क्रोएशिया आदि राष्ट्र शामिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के कैथी सिनेमा हॉल में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। वहां पर नेताजी स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, युद्ध और विदेशी मामलों के मंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति निर्वाचित हो गए थे। वित्त विभाग एस.सी चटर्जी को, प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। बाद में अय्यर साहब स्वाधीन भारत सरकार के सूचना विभाग के निदेशक बने थे।

इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने जापान-जर्मनी की मदद से आजाद हिंद सरकार के नोट छपवाने का प्रबंध किया और डाक टिकट भी तैयार करवाए। जुलाई, 1943 में बोस पनडुब्बी से जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने 'दिल्ली चलो' का प्रसिद्ध नारा दिया। फिर 4 जुलाई 1943 को बोस ने 'आजाद हिन्द फौज ' और 'इंडियन लीग' की कमान को संभाला। उसके बाद उन्होंने सिंगापुर में ही 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार 'आजाद हिन्द सरकार' की स्थापना की तथा दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था।' तर्क और प्रमाण वाजिब हैं।

अंतरराष्ट्रीय कानून भी इसी प्रावधान की पुष्टि करता है कि राष्ट्र के लिये निश्चित भूभाग, स्वायत प्रशासन और वित्तीय तथा सैन्य व्यवस्था हो। अंतः सुभाष बोस ने 29 दिसम्बर 1943 के दिन शहीद तथा स्वराज द्वीप घोषित कर दिया था। अण्डमान फिर उपनिवेश नहीं रहा। मुक्त हो गया था। जबकि गुलाम भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ था। नेहरु ने लालकिले पर तब तिरंगा लहराया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सरकार तो भागकर लंदन आये, पनाह पाये फ्रेंच, नार्वे, डेनमार्क आदि राष्ट्रों के समानान्तर अस्तित्व को कानूनी मान्यता दे दी थी। इन्हीं सब के देश पर हिटलर का कब्जा हो गया था। अतः मुक्त अण्डमान भी वैसा ही था, तो उसे अधिमान्यता क्यों नहीं ?

इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि दिल्ली में शासक–ब्रिटेन ने अपनी संसद में अधिनियम पारित कर दिल्ली का राज कांग्रेस को हस्तांतरित किया था। स्वतंत्र शब्द कहीं उल्लिखित ही नहीं है। दूसरा भूभाग जिन्ना को सौंप दिया। बोस ने सैन्य शक्ति के बल साम्राज्यवादियों को शिकस्त देकर अण्डमान छीना था। स्वयं बोस कहा करते थे कि वे भीख में स्वतंत्रता नहीं लेंगे। वायसराय लुई माउंटबेटन ने नेहरू को स्वतंत्रता बख्श दी थी। वैधानिक स्थिति यहीं है। अर्थात आजाद हिन्द की सरकार ही प्रथम स्वचालित स्वतंत्र शासन था। पर बोस के असामयिक निधन से स्थिति बदल गयी। यूं नेताजी के बारे में मेरी मान्यता है कि नेताजी स्वतंत्रता इतिहास के सर्वाधिक त्रासदीपूर्ण नायक हैं। शेक्सपियर होते तो एक दुखांत नाटक लिख डालते। एक संघर्षशील जननायक जो स्वनिर्मित था।

दुनियादारी भरे प्रपंची उन्हें गिराने में दशकों तक ओवरटाइम करते रहे। गौर करें। डा. पट्टाभि सीतारमैया (रिश्ते में मेरे सगे ताऊ) को बहुमत से पराजित कर नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष (त्रिपुरी अधिवेशन : 1939) चुने गये थे। पहला प्रत्याशी गांधीजी ने जवाहरलाल नेहरू को सुझाया था। तभी यूरोप में लम्बे विश्राम के बाद नेहरु भारत लौटे थे। उन्होंने खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद का प्रस्ताव रखा। मगर निश्चित पराजय की आशंका से मौलाना ने भी किनारा कर लिया। सुभाष बाबू तब तक भारत के युवजन का सपना बन गये थे। नेहरू तब पचास के पार थे। नेताजी चालीस के थे। अजेय थे। आज्ञाबद्ध होकर पट्टाभि ने, जो साठ के करीब रहे, उम्मीदवारी हेतु हामी भर दी। मुझ जैसे गांधीवादी को अचरज होता है कि समभाव और मयार्दा के कठोर अनुयायी बापू को सुभाष से इतनी बेरुखी क्यों थी ? शायद सुभाष की कार्य योजना में हिंसा से वितृष्णा नहीं थी। खासकर चौरा–चौरी के बाद जन आंदोलन को वापस लेने के कारण। बापू को बोस ही ने सर्वप्रथम 'राष्ट्रपिता' कहकर रंगून रेडियो से संबोधित किया था। फिर भी उनकी उपेक्षा क्यों ? हिचक कैसी ?

दैनिक
जलते दीप

जयपुर, मंगलवार 9 अप्रैल 2024

संकट की दस्तक

पिछले साल सिक्किम में लहोनक ग्लेशियर झील फटने की घटना पुरानी नहीं है जिसमें 180 लोगों के मरने व पांच हजार करोड़ के नुकसान की खबर थी। इसी तरह केदारनाथ में चौराबाड़ी ग्लेशियर झील फटने से हजारों लोगों की जल प्रलय में मौत हुई थी। 2021 में उत्तराखंड की नीति घाटी में ग्लेशियर झील फटने से दो सौ लोगों के मरने समेत डेढ़ हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। अब हिमालय पर्यावरण विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि देश के हिमालय क्षेत्र में आने वाले राज्यों में खतरनाक किस्म की 188 ग्लेशियर झीलें बन चुकी हैं, जो किसी बड़े भूकंप आने पर लाखों लोगों के जीवन पर घातक प्रभाव डाल सकती हैं। यूं तो सबसे ज्यादा खतरे की वजह पूर्वोत्तर की झीलें हैं, लेकिन खतरा कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में भी लगातार बना हुआ है। दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन और हिमालय अध्ययन विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए एक साल की स्टडी के बाद जो निष्कर्ष सामने आए हैं वे चिंता में डालने वाले हैं। दरअसल, अब ग्लोबल वार्मिंग का वास्तविक खतरा सामने दिखायी दे रहा है। लगातार बढ़ते तापमान से हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पहाड़ों में बर्फ पिघलने से बने जल को निकासी का रास्ता न मिलने पर ये बर्फीला पानी झीलों के रूप में एकत्र हो जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि यदि इन संवेदनशील इलाकों में सात तीव्रता जैसा भूकंप आता है तो ये झीलें जल बम बनकर फूट सकती हैं। इससे छह राज्यों की करीब तीन करोड़ आबादी प्रभावित हो सकती है। दरअसल, इस हालिया अध्ययन में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग संकट के चलते इन हिमालयी क्षेत्रों में 28 हजार से अधिक झीलें बन गई हैं। जिसमें 188 ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन संवेदनशील झीलों को ए श्रेणी में रखा गया है। इन इलाकों में ग्लेशियरों के पिघलने व खिसकने का खतरनाक ट्रेंड देखा गया है। वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियरों की पिघलने की दर 15 प्रतिशत बढ़ गई है। जो हमारे लिए गंभीर चेतावनी का कारण बन रही है। केंद्र सरकार के अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ ग्राउंड जीरो व उपग्रहों के जरिये इन झीलों की बराबर निगरानी कर रहे हैं। इन इलाकों में स्वचालित मौसम निगरानी केंद्र बनाये गए हैं। इस दिशा में मंथन किया जा रहा है कि कैसे इन खतरनाक झीलों का पानी आधुनिक तरीकों से रिलीज किया जाए। एक ओर जहां झीलों से जल निकासी के रास्ते तलाशे जा रहे हैं, वहीं ड्रिल करके पानी को नियंत्रित करने पर भी विचार हो रहा है। इसके अलावा भूमिगत पानी के साथ मिलाने के लिये भूमिगत टनल बनाने पर भी मंथन हो रहा है। निस्संदेह,यह एक गंभीर पर्यावरणीय संकट हैं और छह राज्यों के करोड़ों लोग इस संकट से प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल, झील के फटने पर मिट्टी व भारी मलबा ढलान पर गोली की तरह उतरता है, जो भारी तबाही का कारण बन सकता है।

आपराधिक घटनाओं को सियासी रंग देना कानून-व्यवस्था के लिए घातक

पश्चिम बंगाल में आपराधिक घटनाओं को अक्सर राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अब तो ऐसी घटनाओं की जांच करने वालों पर हमले की संस्कृति भी विकसित हो चली है। इसका ताजा उदाहरण राष्ट्रीय जांच एजंसी यानी एनआइए के दल पर स्थानीय लोगों का हमला है। दो महीने पहले इसी तरह संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के जांच दल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। ताजा घटना मिदनापुर जिले के भूपतिनगर की है। दरअसल, एनआइए कर्मी करीब सवा साल पहले वहां हुए एक बम विस्फोट के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए थे। तभी स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जांच दल की गाड़ियों के कांच टूट गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जांच दल को रात में वहां जाने की क्या जरूरत थी। क्या उन्हें यह पता नहीं था कि रात के अंधेरे में गांव वाले अनजान लोगों को देख कर हमलावर हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पता नहीं, एनआइए ने स्थानीय पुलिस से सहयोग लिया था या नहीं। जबकि एनआइए अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस से सहयोग मांगा था, पर उसका रवैया सहयोगात्मक नहीं था। ममता बनर्जी ने पूछा है कि चुनाव के वक्त में इस तरह गिरफ्तारियां करने की आखिर वजह क्या है। बता दें कि एनआइए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई थी, वह तृणमूल कांग्रेस का नेता है। अब ममता बनर्जी इस घटना को भाजपा के उकसावे पर की गई कार्रवाई बता रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी इस तरह अपने किसी नेता या कार्यकर्ता के पक्ष में सीधे मैदान में कूद पड़ी हैं। वे तो एक बार अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सीधे थाने में पहुंच गई थीं। राज्य के पुलिस अधीक्षक की अनियमितताओं के खिलाफ जब सीबीआइ ने पूछताछ की कोशिश की थी, तब भी वे धरने पर बैठ गई थीं। चुनावी हिंसा के मामलों में भी वे अक्सर अपने कार्यकर्ताओं का बचाव और भाजपा कार्यकर्ताओं के उपद्रव पर तल्खबयानी करती रही हैं। यह ठीक है कि भाजपा और तृणमूल के बीच सियासी रस्साकशी चलती रहती है और यह अक्सर केंद्र-राज्य संबंधों में टकराव बन कर भी उभरती है, मगर क्या हर आपराधिक घटना को सियासी रंग दे देने से राज्य की कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होती! आखिर कानून-व्यवस्था की जवाबदेही राज्य सरकार की है। बम विस्फोट के जिस मामले में एनआइए जांच कर रही है, उसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। यह राज्य सरकार की भी चिंता का विषय होना चाहिए कि जिस घर में विस्फोट हुआ, वहां इतना ताकतवर बम पहुंचा कैसे और उसका किस मकसद से इस्तेमाल किया जाना था। आपराधिक घटनाओं को सियासी रंग दे देने का नतीजा यह होता है कि राजनीतिक दलों के बीच हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर लगातार चलता रहता है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल पर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। चुनाव के दौरान तो व्यापक हिंसा देखी जाती है। इस समय आमचुनाव का माहौल है और ममता बनर्जी अगर एनआइए जांच में सहयोग करने के बजाय इसके पीछे भाजपा का हाथ बता रही हैं, जो जाहिर है, उनके कार्यकर्ताओं को एक तरह से उकसावा ही मिलेगा। इस तरह हिंसा के बल पर कोई राजनीतिक दल अपना आधार बेशक कुछ मजबूत बना ले, पर राज्य की कानून-व्यवस्था कमजोर ही होगी।

प्रसंगतः भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान

गंगा और यमुना, दोनों हिमालय से निकलीं. लेकिन गंगा ठहरी कुछ गोरी और यमुना का रंग काला. गंगा को अपनी शुभ्रता का अभिमान हुआ. वह ऊपर-ऊपर चली. बेचारी यमुना अपने श्यामल वर्ण के कारण उससे कुछ दूर-दूर चली. लेकिन गर्वीली गंगा ने आगे चलकर देखा कि बिना यमुना के वह शतमुख से सागर में नहीं मिल सकेगी. इसलिए नम्रभाव से गंगा रुकी. उधर से यमुना आई. गंगा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत करते हुए कहा, ''यमुना बहन, तू मेरे पास आ. मैंने तेरा रंग देखकर तुझे हेय माना. पर तेरे किनारे पर कृष्णा भगवान ने भक्ति की वर्षा की, छोटे-बड़ों को एक किया, अपनी वंशी से एकता का गान किया, मिल-बांटकर खाने की प्रेरणा दी. अरे, तेरी महिमा के क्या कहने !'' यमुना ने गद्‌गद् स्वर में गंगा से यह सुनकर कहा, ''क्यों बहन, तुम मेरी बड़ाई करती हो, किन्तु तुम्हारी महिमा तो अपरम्पार है. मेरे किनारे पर भक्ति का विकास अवश्य हुआ, पर तुम्हारे किनारे से ज्ञान का प्रकाश फैला. भगवान पशुपतिनाथ तुम्हारे किनारे पर साधना-लीन हुए. असंख्य ऋषि-मुनि तुम्हारे ही तट पर तपस्या करते हैं. राजा-महाराजा अपना राजपाट त्यागकर ब्रह्मचिंतन करते हैं. बहन, तुम पूर्ण ज्ञान हो.'' तभी गुप्त रहनेवाली सरस्वती बोली, ''भक्ति और ज्ञान आवश्यक हैं, पर बिना कर्म के वे अधूरे हैं. इसलिए भक्ति का ज्ञान से और भक्ति-ज्ञान का कर्म से मिलन अनिवार्य है.'' फिर क्या था ! ज्ञानमयी गंगा, भक्तिमयी यमुना और कर्ममयी सरस्वती बाहें फैलाकर एक-दूसरें के आलिंगन में बंध गई. तीनों नदियों का संयम ज्ञान, भक्ति और कर्म की धाराओं का संगम है. भारतीय संस्कृति का यही अधिष्ठान हैं.

किराये की खबरें भारत को नहीं हिला सकती

भारत में ठीक चुनाव के वक्त ब्रिटिश अखबार के बेबुनियाद खुलासे का आखिर मकसद क्या है?

विजय दर्डा

इतिहास गवाह है कि भारत कभी हमलावर नहीं रहा। हां, किसी ने आंख दिखाने की जुर्रत की तो भारत ने आंख जरूर निकाल ली।

ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने खुलासा किया है कि 2020 से लेकर अब तक भारत ने पाकिस्तान में टार्गेट किलिंग की है और 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मैं इसे कोई खुलासा नहीं मानता क्योंकि गार्जियन की इस रिपोर्ट का कोई पुख्ता आधार नहीं है। केवल कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों के बयान को आधार बनाकर इस तरह की रिपोर्ट छापना हर हाल में गैरजिम्मेदाराना पत्रकारिता की श्रेणी में ही रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारत में ठीक चुनाव के बीच इस तरह की रिपोर्ट छापे जाने का आखिर मकसद क्या है?

चलिए, सबसे पहले यह जानते हैं कि गार्जियन ने लिखा क्या है? उसका कहना है कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) ने एक मिशन पर काम करना शुरू किया कि आतंकी हमले के खतरे को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। भले ही वह विदेशी धरती पर क्यों न हो। इसी के तहत पाकिस्तान में अभी तक 20 हत्याएं हो चुकी हैं। यह भी बात रिपोर्ट में है कि रॉ को पीएम नरेंद्र मोदी का ऑफिस नियंत्रित करता है। आप समझ सकते हैं कि गार्जियन के कहने का आशय क्या है। उसकी नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गार्जियन ने ये सारी बातें पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से मिले दस्तावेजों के आधार पर की है। जाहिर सी बात है कि वह तो ऐसे ही दस्तावेज तैयार करेगा जो भारत को बदनाम कर सके। मसलन यह कहना कि टार्गेट किलिंग का यह मिशन संयुक्त अरब अमीरात से भारत संचालित कर रहा था। इसके लिए बाकायदा स्लीपर सेल तैयार किया गया। अच्छी-खासी राशि खर्च हुई। इसमें दो साल का वक्त लगा। तो सवाल यह है कि इन दो सालों में पाकिस्तान क्या कर रहा था? संयुक्त अरब अमीरात में स्लीपर सेल बना और उसे भनक भी नहीं लगी?

यह पूरी रिपोर्ट ही फर्जी तौर पर तैयार की गई लगती है। रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरा हुआ लिख दिया गया जबकि वह जिंदा है। इस पर जब लोगों ने सवाल उठाए तो गार्जियन ने तत्काल इसमें सुधार तो कर लिया लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की कि एक जिंदा व्यक्ति को उसने मरे हुए लोगों की सूची में कैसे डाल दिया?

भारत पर टार्गेट किलिंग का आरोप तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी लगा दिया था। वहां खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर आपसी रंजिश में मारा गया था। आरोप के बावजूद कनाडा कभी कोई सबूत नहीं दे पाया। अमेरिका ने भी भारत को घेरने की कोशिश की। ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख अवतार सिंह खांडा की रहस्यमयी मौत और पाकिस्तान में आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या के मामले को भी भारत से जोड़ा गया। भारत ने हमेशा ऐसे आरोपों को खारिज किया है। मैं हमारे विदेश मंत्री एस। जयशंकर की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि विदेशी धरती पर टार्गेट किलिंग भारत की नीतियों के अनुरूप नहीं है। मेरा सवाल तो यह है कि कौन किसको मार रहा है? पाकिस्तान में जितने भी लोग अज्ञात हमलावरों की गोली से मरे हैं वे कोई पाकिस्तान के राजनेता नहीं थे, न ही भलेमानुष थे। वे आतंकवादी थे और आतंकवादियों के बीच खतरनाक रंजिशें होती है क्योंकि अब आतंकवाद के पीछे ड्रग्स माफिया, हथियारों के सौदागरों का हाथ होता है। आतंकवाद का किसी विचारधारा से अब कोई लेना-देना नहीं है। आपसी रंजिश में हत्याएं होती है।

इसमें भारत को क्यों घसीटा जाता है? अपने चुनावी फायदे के लिए कनाडा खालिस्तानियों को पालता-पोसता है। अमेरिका में ट्रम्प और जो बाइडेन के बीच संघर्ष की स्थिति है। भारत में चुनाव चल ही रहे हैं। ऐसे माहौल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करना ही गार्जियन की रिपोर्ट का मकसद नजर आता है। एक समय था जब ब्रिटेन की पत्रकारिता की पूरी दुनिया में साख थी। उसका आदर था लेकिन उसकी पत्रकारिता में भारत के प्रति विद्वेष साफ दिख रहा है। कई देशों को भारत का विकास हजम नहीं हो रहा है। ये हमले इसीलिए हो रहे हैं।

हमला करने वालों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत का लोकतंत्र कच्ची मिट्टी का बना शेर नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इन जड़ों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान ने सींचा है। इस देश का हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। अलग-अलग पार्टियों की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, चुनाव में डट कर लड़ते भी हैं लेकिन हमारे देश के राजनेता अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचते, न देश को लूटकर अपना घर भरते हैं। ऐसे लुटेरे जब नसीहत देते हैं तो उन पर तरस आता है। उनकी वह ताकत नहीं कि हमारे देश के लोकतंत्र की नींव को छू भी सके।

एक बात और बता देना चाहूंगा कि हम भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के अनुयायी जरूर हैं। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। घर में घुसकर मारने का ठेका किसी एक राष्ट्र ने नहीं लेकर रखा है। भारत भी यह कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हम घर में घुसेंगे। दुनिया ध्यान रखे कि हमारी आन-बान-शान को यदि कोई हाथ लगाने का प्रयास करेगा तो हम उसे नेस्तनाबूद कर देने में जरा भी नहीं हिचकेंगे।

(लेखक विजय दर्डा वरिष्ठ पत्रकार, लोकमत समाचार पत्र समूह के अध्यक्ष व 1998 से 2016 तक राज्य सभा सांसद रहे हैं। vijaydarda@lokmat.com)

https://t.me/All_Newspaper_Paid

सोशल मीडिया डाटा संग्रहण से उपजी साइबर सुरक्षा चिंताएं

मार्च माह में अमेरिकी संसद में एक कानून लाया गया है जिसकी वजह से टिक-टॉक ऐप की मूल मालिक, चीन की विशालकाय तकनीक कंपनी 'बाईट-डांस' को मजबूरन या तो अपनी सोशल मीडिया ऐप बेचनी पड़ जाएगी या फिर तमाम अमेरिकी डिवाइसेज पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। यह दर्शाता है कि तकनीक आधारित बड़ी कंपनियों को लेकर अमेरिकी कानून निर्माताओं के अंदर असहजता किस कदर है। जहां राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि वे टिक-टॉक को बैन करने वाले कानून पर दस्तखत कर मंजूरी दे देंगे वहीं अभी यह पक्का नहीं है कि सीनेट में इस बिल का हश्र क्या होगा, और इससे बने प्रभाव न तो इतने सरल होंगे न ही सीधे।

अमेरिका में लगभग 17 करोड़ टिक-टॉक यूज़र्स हैं। इस ऐप पर प्रतिबंध लगने से करोड़ों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। न केवल कलाकारों को एक मंच से महरूम होना पड़ेगा बल्कि देशभर में रोचक वीडियो बनाने वाले करोड़ों लोगों का धंधा प्रभावित होगा। इससे भी आगे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का कयास है, फेसबुक के दबदबे में इजाफा होगा। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, जिसे एक वजह गिनाया जा रहा है, कहीं अधिक अहम है।

वर्ष 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टिक-टॉक और वी-चैट को गैर-कानूनी घोषित करने वाला प्रस्ताव लाये थे लेकिन अगले राष्ट्रपति बाइडेन ने वह निर्णय उलट दिया। विभिन्न देशों में सरकारों ने साइबर सिक्योरिटी और निजता संबंधी चिंताओं के कारण टिक-टॉक प्रतिबंधित कर रखा है। भारत ने भी 2020 में टिक-टॉक और वी-चैट सहित चीन की दर्जनों एप पर रोक लगा दी थी। मार्च, 2023 में, टिक-टॉक के सीईओ शाउ ज़ी चियु ने अमेरिकी संसदीय कमेटी के समक्ष हलफनामा दिया। सुरक्षा विशेषज्ञों को यकीन है कि अमेरिकी सरकार की चिंता मुख्यतः टिक-टॉक का उपयोग विदेशी जासूसी एजेंसियों द्वारा किए जाने की आशंका को लेकर है। अमेरिकी कानून-निर्माताओं की यह धारणा कायम है कि टिक-टॉक का संबंध चीन से होने की वजह से उनके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे गंभीर खतरा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यहां तक कहा कि टिक-टॉक बंद करना ही होगा।

साल 2020 में वाशिंगटन पोस्ट अखबार और एक निजी अनुसंधान कंपनी द्वारा करवाए साझे अध्ययन का निष्कर्ष था - लगता नहीं कि टिक-टॉक ऐप औसतन किसी अन्य सोशल मीडिया मंच से अधिक यूज़र्स डाटा इकट्ठा करती है। हालांकि यूआरएल जीनियस नामक मोबाइल मार्किटिंग कंपनी द्वारा 2022 में करवाए अध्ययन में बताया कि तमाम सोशल मीडिया ऐप में, यूट्यूब व टिक-टॉक यूज़र्स डाटा पर अधिक निगाह रखते हैं। परंतु यदि टिक-टॉक के डाटा एकत्रण की तुलना फेसबुक या एक्स आदि से की जाए, तो वे भी बहुत अधिक सूचना संगृहीत करते हैं। इसमें वीडियो देखने वालों की विस्तृत जानकारी, उनके कमेंट, निजी मैसेज और यदि उन्होंने अनुमति दे रखी हो डाटा तक पहुंच का स्तर, उनकी सटीक जियो-लोकेशन और कॉन्टेक्ट लिस्ट इत्यादि से संबंधित जानकारी कंपनी इकट्ठा कर लेगी। इसके अलावा, टिक-टॉक की प्राइवेसी स्टेटमेंट के अनुसार, यूज़र्स डाटा जैसे ई-मेल एड्रेस, फोन नम्बर, आयु, सर्च एवं

- अतनु बिस्वास

ब्राउसिंग हिस्ट्री, अपलोडेड इमेज और वीडियो संबंधी जानकारी और यदि उपभोक्ता ने स्वीकृति दे रखी हो तो उनके डिवाइस क्लिपबोर्ड की सामग्री तक पहुंच करके, एप्लीकेशन कंपनी उसको कॉपी-पेस्ट करने का अधिकार रखती है।

कई अध्ययनों के अनुसार, जिस वक्त उपभोक्ता टिक-टॉक का उपयोग न भी कर रहा हो तब भी वह उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखती है। हालांकि टिक-टॉक कहना है कि वह इस जानकारी को अपने विज्ञापन व्यवसाय को विस्तार देने में बरतती है। न केवल टिक-टॉक बल्कि अन्य अनेक तकनीक आधारित बड़ी कंपनियां इसी किस्म के औजारों का उपयोग बड़े स्तर पर करती हैं। इसलिए टिक-टॉक तो आनलाइन निगरानी करने वाले इस व्यापक कार्पोरेट अर्थव्यवस्था तंत्र का महज एक पुर्जा है। जिन एप्लीकेशन्स का उपयोग हम करते हैं, उनमें कुछ हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा निजी सूचना एकत्र करती हैं। मुख्यतः वे यूज़र्स डाटा का उपयोग अपने लिए करती हैं ताकि उपभोक्ता के रुझान के मुताबिक उसको संबंधित वस्तु या सेवा का विज्ञापन दिखाया जाए। कंपनियां हमारी तरजीहों, कमियों और अभिरुचियों के बारे में इस तरह सूचना इकट्ठा कर ब्राउसिंग व्यवहार को प्रभावित करती हैं कि अक्सर हमें पता तक नहीं चलता। कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रसंग ने दिखा दिया कि कैसे व्यक्तिगत सूचना का दोहन करके मुख्य चुनाव के परिणामों तक को प्रभावित किया जा सकता है।

हालांकि, खुद एप्लीकेशन से कहीं अधिक चिंता टिक-टॉक की मिल्कियत और प्रबंधन नीतियों को लेकर है। डर है कि बाईट डांस और इसके विस्तारित अंग के तौर पर टिक-टॉक को चीनी सरकार मजबूर कर सकती है कि वह विभिन्न सुरक्षा गतिविधियों में सहयोग करे, इसमें शायद डाटा ट्रांसफर करना भी शामिल है, क्योंकि अपने अधिकार क्षेत्र में चीनी सरकार कंपनियों पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है।

एक चिंता यह भी है कि यदि टिक-टॉक के यूज़र्स डाटा तक चीन की सरकार की पहुंच हो जाए तो वह इसका इस्तेमाल जासूसी करने के लिए कर सकता है। अन्य फिक्र है कि चीनी सरकार टिक-टॉक को मजबूर कर सकती है कि उपभोक्ता की अभिरुचियों को कुछ इस तरह प्रभावित करे कि वह साइट पर वही देखने लगे, जो उसे दिखाना चाहते हैं। ऐसे में इसका असर अमेरिकी आम चुनाव के परिणामों, नीति-निर्धारण और लोकतांत्रिक बहसों पर काफी हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि भले ही यह कयास लगे, लेकिन टिक-टॉक की स्वामित्व संरचना और और चीनी कानून के चलते यह सच हो सकता है। हालांकि, फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं कि चीन ने टिक-टॉक का व्यावसायिक डाटा हासिल कर इसका उपयोग जासूसी में किया हो। जैसा कि चियु का कहना है कि उनकी कंपनी चीनी सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रयास को कभी नहीं मान सकती। हालांकि, वे अपने दावे पर कितना टिक पाएंगे, इसको लेकर भी फिक्र है। विशेषज्ञों का दावा है कि तमाम सोशल मीडिया मंचों पर भ्रामक सूचनाओं की भरमार है और निजता संबंधी चिंताएं एक समान हैं। अतएव केवल टिक-टॉक पर ध्यान केंद्रित करने से बृहद नजरिया बाधित हो सकता है। वास्तव में, सोशल मीडिया कंपनियों के बारे में माना जाता है कि वे तीसरे पक्ष को यूज़र्स डाटा बेच देती हैं। ऐसे में अमित्र विदेशियों के पास डाटा खरीदने-पाने के बहुत विकल्प बन जाते हैं।

बहुप्रचारित अमेरिकी कानून के बारे में विशेषज्ञों की भविष्यवाणी है कि यह कानून बनने से रुक जाएगा और यदि बन भी गया तो टिक-टॉक अदालत में केस दायर कर देगी। वहीं चीन के पास क्षमता है कि वह 2020 के तकनीक निर्यात कानून संशोधन के जरिये इस कदम पर रोक लगवा दे। वर्ष 2018 में, अमेरिकी कानून निर्माताओं ने मार्क जुकरबर्ग से उनकी कंपनी द्वारा यूज़र्स डाटा का इस्तेमाल करने पर जवाबतलबी की थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में हैरानीजनक रहस्योद्घाटन के चलते यह करना पड़ा। तब जुकरबर्ग ने तंत्र में सुधारक उपाय लाने का शपथपत्र दाखिल किया था। उस वक्त, सीनेटर बिल नेलसन ने कहा - यदि 'फेसबुक या कोई अन्य ऑनलाइन कंपनी इन निजता संबंधी अपने अतिक्रमणों को दुरुस्त नहीं करेगी तो हम करेंगे'। आज, छह साल बाद, क्या यह सही वक्त नहीं है आत्मनिरीक्षण करने का? **(लेखक भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में प्रोफेसर हैं।)**

कानूनी सख्ती के बावजूद क्यों पनप रही है बाल-तस्करी

-ललित गर्ग

देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जांच एजेंसियों की नाक के नीचे नवजात बच्चों की खरीद-फरोश्त की मंडी चल रही थी जहां दूधमुंहे एवं मासूम बच्चों को खरीदने-बेचने का धंधा चल रहा था। दिल्ली की ह्यबच्चा मंडीह्न के शर्मनाक एवं खौफनाक घटनाक्रम का पदार्पाश होना, अमानवीतया एवं संवेदनहीनता की चरम पराकाष्ठा है। जिसने अनेक ज्वलंत सवालों को खड़ा किया है। आखिर मनुष्य क्यों बन रहा है इतना क्रूर, अनैतिक एवं अमानवीय? सचमुच पैसे का नशा जब, जहां, जिसके भी सर चढ़ता है वह इंसान शैतान बन जाता है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी कर ऐसे ही शैतानों के कुकृत्यों का भंडाफोड किया और एक महिला समेत सात लोगों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया, इसके साथ ही तीन नवजात शिशुओं को उनके चंगुल से बचाया। आरोपियों में एक अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर को इस धंधे का मास्टर माइंड माना जा रहा है। न केवल दिल्ली वालों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए यह खबर चिंता पैदा करने वाली ही नहीं है, बल्कि खौफ पैदा करने वाली भी है।

दिल दहाले देने वाली इस घटना में सीबीआई की अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन के माध्यम से बच्चे गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों से जुड़ते थे। आरोपी कथित तौर पर वास्तविक माता-पिता के साथ-साथ सेरोगेट माताओं से भी नवजात बच्चे खरीदते थे। इन नवजात बच्चों को चार से छह लाख रुपए में बेच दिया जाता था। जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारियों के अनुसार एजेंसी की गिरफ्त में आए आरोपी बच्चों को गोद लेने से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कराते थे। आरोपी कई निसंतान दंपतियों से लाखों रुपए की ठगी करने में भी संलिप्त हैं। इस गिरोह के तार कहां-कहां हैं इसकी भी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। यह गिरोह आईवीएफ के माध्यम से युवतियों को गर्भधारण कराता था फिर इन शिशुओं को बेचता था। गरीब माता-पिता से भी बच्चे खरीदे जाते थे। बच्चों की खरीद-फरोख्त और बच्चों की तस्करी एक ऐसी समस्या है जिस पर तभी ध्यान जाता है जब कोई सनसनीखेज खबर सामने आती है।

अर्थ की अंधी दौड़ में इंसान कितने क्रूर एवं अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने लगा है कि चेहरे ही नहीं चरित्र तक अपनी पहचान खोने लगे हैं। नीति एवं निष्ठा के केन्द्र बदलने लगे हैं। मानवीयता एवं नैतिकता की नींव कमजोर होने लगी है। आदमी इतना खुदगर्ज बन जाता है कि उसकी सारी संवेदनाएं सूख जाती है। बाल तस्करी के खिलाफ कई सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद भारत में यह समस्या नासूर बनती जा रही है। नवजात बच्चे चुराने वाले गिरोह के पदार्फाश से फिर यह तथ्य उभरा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में कानून का कोई खौफ नहीं है। बच्चों की तस्करी पर भारी जुमार्ने के साथ उम्रकैद तक का प्रावधान होने के बावजूद यह कड़वी हकीकत है कि ऐसे दस फीसदी से भी कम मामले दोषियों को सजा तक पहुंच पाते हैं। मुकदमों की पैरवी सही तरीके से नहीं होने के कारण अपराधी बच निकलते हैं और वे फिर बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद-फरोश्त में लिप्त हो जाते हैं।

बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद-फरोश्त के अनेक कारण हैं। निसंतान दंपतियों द्वारा बच्चों को खरीदना एकमात्र कारण नहीं है बल्कि गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, सुविधावादी जीवनशैली, भौतिकवाद, बच्चों की अधिक संख्या, बेरोजगारी भी बड़ा कारण है। पैसे की अपसंस्कृति ने अपराधों को अनियंत्रित किया है। पैसे कमाने के लिए कई लोग बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद-फरोश्त के व्यापार में लग गए हैं। वो गरीब लोगों को बहकाकर उनके बच्चों को काम दिलवाने का झांसा देकर शहर ले जाते हैं फिर शहर में जाकर उन बच्चों को बेचा जाता है फिर शुरू होता है बच्चों के शोषण का अंतहीन सिलसिला। जो बच्चे बेचे नहीं जाते हैं उनको अपराधी अगवा कर बेच देते हैं। लड़कियों को देह व्यापार के लिए विवश किया जाता है। हजारों बच्चों को फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। 16-16 घंटे काम करके इन को भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता। इस तरह कारणों से देश का बचपन कराह रहा है।

देश में युवाओं के एक वर्ग की सोच में बदलाव भी परोक्ष रूप से बाल-तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। एक सर्वे में खुलासा हुआ था कि भारत के नौ फीसदी युवा शादी तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। संतान सुख के लिए उन्हें बच्चे खरीदने से परहेज नहीं है। हैरत की बात यह है कि देश के ढाई करोड़ से ज्यादा अनाथ बच्चों में से किसी को गोद लेने का विकल्प होने के बावजूद ऐसे युवा कई बार बाल तस्करी करने वालों से बच्चे खरीदने का साध लेते हैं। बाल-तस्करी भारत की एक उभरती एवं ज्वलंत समस्या है। यह केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की बड़ी समस्या है। पिछले साल एक एनजीओ की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2016 से 2022 के बीच बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार क्रमशः दूसरे, तीसरे नंबर पर थे। इस अवधि में मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में भी कई मामले दर्ज हुए। कोरोना काल के बाद दिल्ली में बाल तस्करी के मामलों में 68 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह भी देखने में आया कि जिलों का बाल तस्करी से जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा।

पिछले साल संसद में पेश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2021 में हर दिन औसतन आठ बच्चों की तस्करी हुई। देश के भीतर यह तस्करी होती है लेकिन संगठित गिरोह कुछ बच्चों की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भी तस्करी करते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच देश में 18 साल से कम उम्र की 2.51 लाख लड़कियां लापता हुईं। इनमें से ज्यादातर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की थी। बचपन अगर बाल तस्करी के बीच फंसकर रह जाए तो बच्चा अपने बचपन, क्षमता और मानवीय गरिमा के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक विकास से भी वंचित रह जाता है। गौरतलब है कि बच्चों के घरेलू काम, विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रम, भीख मांगना, अंग तस्करी और व्यावसायिक यौनकर्म जैसी अवैध गतिविधियां बाल तस्करी की कोख से ही जन्म लेती हैं। सरकार और समाज को इससे मिलकर निपटना होगा। इस समस्या की जड़ में गरीबी भी है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यावहारिक और ठोस नीति बनाई जानी चाहिए कि बाल तस्करी के समूल उन्मूलन की जमीन तैयार हो सके।

इसे देश की विडंबना कहें या दुर्भाग्य कि आज बहुत से अजन्मे मासूम तो मां के गर्भ में आते ही जीवन-मृत्यु से जूझने लगते हैं। जन्म लेने के बाद इस देश में बच्चों को बेच दिया जाता है या ऐसे बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग चौराहों, रेलवे स्टेशन, गली-मोहल्ले में भीख मांगता मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का बचपन होटलों पर काम करते या जूठे बर्तन धोते हुए या फिर काल कोठरियों में जीवन बिताते हुए कट जाता है। यों भी कह सकते हैं कि उनका जीवन आज अंधेरे में कट रहा है, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत का बचपन आर्थिक कारणों से घायल है। बच्चे को बेचे और खरीदे जाने में जितने लोग, जिस तरह शामिल होते थे, वह नये बनते भारत के भाल पर एक बदनुमा दाग है। क्यों कानून का डर ऐसे अपराधियों को नहीं होता? क्यों सरकारी एजेंसियों की सख्ती भी काम नहीं आ रही है और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां प्रश्न कार्रवाई का नहीं है, प्रश्न है कि ऐसी विकृत एवं अमानवीय सोच क्यों पनप रही है?

भाजपा से ज्यादा तो प्रशांत किशोर कर रहे ममता पर हमले!

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। एक तरफ अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। इस बार बंगाल में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए ममता ने पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है । इस बीच रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। कहने को समय-समय पर उनकी तरफ से विपक्ष को सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जिस अंदाज में उन्होंने बंगाल में ममता को घेरा है, उसके अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वे ममता से अपना बदल निकाल रहे है या भाजपा का प्रचार। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा राज्य की सत्ता में बैठी टीएमसी से बेहतर परफॉर्म करेगी। भाजपा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरेगी, चौंकाने वाले रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। ज्ञात हो कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार रहे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि भाजपा बंगाल में 100 विधानसभा सीट नहीं जीत पाएगी और उनकी भविष्यवाणी सही निकली। दावों के बावजूद भाजपा 77 सीट ही जीत सकी और टीएमसी ने 212 सीटों जीतकर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी चुनावी पंडितों को भी चकरा रही है। गरीबों को मुफ्त राशन, चुनाव से पहले सीएए लागू होना और बंगाल में इंडिया गठबंधन में दरार के कारण बंगाल में चुनावी उलट-पुलट भी संभव है। हालांकि टीएमसी का दावा है कि इस बार भाजपा 2019 से कम सीटें जीतेंगी।

सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर ये बातें किस आधार पर कह रहे हैं। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बंगाल में भाजपा के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं रही हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हों या स्थानीय निकाय चुनाव सभी में भाजपा की दुर्गति हुई है। उपचुनावों में भी भाजपा को टीएमसी ने पस्त कर दिया। भाजपा के तमाम कद्दावर नेता ,मंत्री तक पार्टी छोड़कर टीएमसी शामिल हो चुके हैं। तो आखिर किशोर को उम्मीद की किरण कहां से दिख रही है? आइए जानते हैं कि क्यों प्रशांत किशोर की बातें सच हो सकती हैं ?

कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा इतिहास रचने को तैयार थी पर पीएम नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप भारी पड़ गया था। और अंतिम समय में बाजी पलट गई थी । ममता के लिए पीएम मोदी का कहा गया संबोधन दीदी ओ दीदी। । को टीएमसी ने मां -माटी और मानुष के अपमान का मामला बना दिया और देखते ही देखते भाजपा पर भारी पड़ गई टीएमसी। इस बार भाजपा ने रणनीति बदल दी है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जा रहा है। हर बात के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते दिख रहे हैं। भाजपा के अन्य नेता भी ममता के खिलाफ अपमानजनक चुटकुले और संवेदनशील आरोप लगाने से बच रहे हैं।

अनंत राय राजबंशी समुदाय से आते हैं। मतुआ के बाद ये पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय है। अनंत राय को उम्मीदवार बनाने से भाजपा की उत्तरी बंगाल में अच्छी-खासी पकड़ बन गई है। क्योंकि वहां राजबंशी समुदाय का अच्छा-खासा दबदबा है। उत्तरी बंगाल की आठ में से चार लोकसभा सीटों पर राजबंशी ही जीतते रहे हैं। 2019 में भाजपा ने इनमें से सात सीटें जीती थीं। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार आठों सीट भाजपा जीत सकेगी। राज्य में इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही टीएमसी अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा को मजबूत होने का एक और अवसर दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने के टीएमसी के फैसले के चलते टीएमसी विरोधी वोट भाजपा को मिलेंगे। इसके अलावा वोट बंटने का भी फायदा भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी के युसूफ पठान ताल ठोंक रहे हैं। पठान सेलेब्रेटी क्रिकेटर भी हैं और मुसलमान भी हैं। ऐसे में अगर वोट बंटता है तो किसका फायदा होगा। जाहिर है दोनों की लड़ाई में भाजपा अगर मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो यहां से जीत भी सकती है।

सीएए बंगाल में भाजपा का चुनावी वादा रहा है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने बंगाल में सीएए लागू करने की बात करते रहे हैं । शायद यही कारण है कि भाजपा ने कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए लागू होने का सबसे बड़ा फायदा बंगाल में मतुआ समुदाय को मिलेगा। मतुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि मतुआ वोट जहां भी जाता है उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। बंगाल में लगभग एक करोड़ अस्सी लाख मतुआ समुदाय के मतदाता हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम चार लोकसभा सीट में यह समुदाय निर्णायक है। मतुआ समुदाय की तरह राजवंशी समुदाय को भी सीएए का लाभ मिलने वाला है। राजवंशी भी हिंदू हैं। 1971 के बाद से इन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। इस तरह करीब 10 से 12 सीटों पर सीधे भाजपा बढ़त बनाती दिख रही है।

हिंदुओं में अनुसूचित जाति के राजबंशी, मतुआ और बाउड़ी, जो राज्य की जनसंख्या के करीब 23 फीसदी हैं इस बार और बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। 2019 में चाय श्रमिक और जंगलमहल के आदिवासी ने भी भाजपा को वोट दिए। उम्मीद की जा रही है कि सीएए के तहत मतुआ और राजवंशियों को होने वाले फायदे का भावनात्मक असर दूसरी अनुसूचित जातियों पर भी पड़ेगा । भाजपा के पक्ष में थोक के भाव में एससी वोट पड़ने की उम्मीद की जा रही है। अनंत महाराज को राज्यसभा भेजना,राजबंशी समुदाय के नेता और भाजपा के वर्तमान लोकसभा एमपी निशिथ प्रमाणिक को मंत्री बनाने आदि से इस वर्ग में भाजपा को लेकर अपनापन बढ़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में लगातार यात्राएं कर रहे हैं और संदेशखाली को लेकर जिस तरह हमलावर हैं उससे यही लगता है कि बंगाल में इस बार यह मुद्दा बड़ा बनने वाला है। स्थानीय भाजपा नेता संदेशखाली को उसी तरह ले रहे हैं जिस तरह कभी टीएमसी ने सिंगूर और नंदीग्राम को आंदोलन बना दिया था। संदेशखाली पर आंदोलन तेज करने की अपनी रणनीति के तहत ही पार्टी ने 'द बिग रिवील-द संदेशखाली शॉकर' शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की थी। यह सभी जानते हैं कि नंदीग्राम में जबरन जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के सहारे ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हुआ था। नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि संदेशखाली की परिस्थिति नंदीग्राम जैसी है। नंदीग्राम में लोगों ने जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई की थी और यहां जमीन पर जबरन कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। संदेशखाली में खेती की जमीन पर जबरन कब्जा यौन उत्पीड़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का विशेष महत्व रहा है,शायद यही कारण है कि सीपीएम से लेकर टीएमसी तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। भाजपा ने पहली बार राज्य में अलग तरह की राजनीति की है जिसके चलते पिछले चुनावों में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य की हिंदू आबादी कुल आबादी का लगभग 71% है। लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कई सर्वेक्षणों के अनुसार करीब 55% हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में गए। शायद यही कारण है कि इस बार भाजपा भावनात्मक मुद्दे पर ही फोक्सड है। भाजपा सांसद और राज्य के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे ने पहले भी भाजपा को फायदा पहुंचाया है और इस बार भी यह पश्चिम बंगाल समेत देशभर के हिंदुओं को एकजुट करने में हमारी मदद करेगा। सीएए के चलते भी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और अधिक होने की उम्मीद है ।

नौ माताओं के पुण्य स्मरण के साथ पवित्र नव वर्ष की शुभकामनाएं

संजीव ठाकुर

नवरात्रि का पहला दिन यानी प्रतिपदा तिथि मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। इस दिन जौ (जवार)बोने तथा कलश स्थापना पूजन के साथ ही देवी का पूजन किया जाना शुभ माना जाता है' यह भी शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रथम दिवस में माता की पूजा करते समय आराधक यदि लाल, गुलाबी ,नारंगी और रानी रंग के कपड़े पहन कर पूजा करने से माता का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है' द्वितीय दिवस यानी नवरात्रि के दूसरे दिन अत्यंत दिव्य देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है सिद्धि के लिए इस दिन मां की उपासना करते समय सफेद,पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है एवं इस पवित्र दिन में आराधना करने से मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है। तृतीय दिवस में बाघ पर सवार स्वर्ण के समान रंग एवं छटा वाली मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है इस दिन पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग कपड़े पहनना शुभ माने जाते हैं एवं इन रंगों के कपड़े पहनकर देवी की आराधना करने से उनका आशीर्वाद एवं कृपा की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में चतुर्थ दिवस में इस भव संसार के ब्रह्मांड की रचना करने वाली दुर्गा मां के चौथे रूप के रूप में देवी कुष्मांडा की आराधना एवं भक्ति की जाति है। इस दिन इस प्रकृति की देवी के स्वरूप की मन से आराधना करना शुभ फल देने वाला है एवं देवी प्रकृति की देवी हैं इनकी उपासना इस दिवस में पीला ,हरा, लाल और भूरे रंग का वस्त्र पहनकर करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, एवं देवी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पंचम दिवस पर पंचमी तिथि को भगवान कार्तिकेय की माता देवी स्कंदमाता की आराधना एवं श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर छठवें दिन ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी मां की पूजा अर्चना का शास्त्रों में पूजा का विधान माना जाता है। माता कात्यायनी अमोघ फलदाईनी होती हैं भक्तों द्वारा इस दिन लाल, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ, मूंगा रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करने से ऐश्वर्या के साथ वैवाहिक जीवन में शांति सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा तथा अर्चना का विधान है, नवरात्रि की पूजा में तंत्र साधना करने वाले लोग इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करके इनकी पूजा अर्चना करते हैं साधकों को इस दिन बैगनी, स्लेटी ,नीला एवं आसमानी रंग का वस्त्र धारण कर मां के इस दिव्य रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे संपूर्ण ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के आठवें दिन सर्व सौभाग्य दाइनी देवी महागौरी की उपासना का दिन माना जाता है। यह अत्यंत पवित्र दिन होता है और यह देवी धन, वैभव, सुख, शांति की शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा के दौरान साधकों को रातों को केसरिया संतरी गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए जिससे सुख एवं सौभाग्य की अखंड प्राप्ति होती है। शिवरात्रि मैं माताओं के नौ रूपों में दुर्गा पूजा के नौवें तथा आखरी दिन संपूर्ण विधि विधान, रीति रिवाज और पूर्ण निष्ठा के साथ देवी की आराधना करने वाले साधकों को संपूर्ण सिद्धिया प्राप्त होती हैं और इनकी उपासना के समय हरा धागों को लाल गुलाबी नारंगी रंग के वस्त्र पहनने से समाज में पद प्रतिष्ठा वैभव एवं धन की प्राप्ति होती है।

नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों का पूजन अर्चना एवं निष्ठा से की गई आराधना से इस जगत का कल्याण भी होता है साथ ही इस पवित्र 9 दिनों में असंख्य दीप जलाकर माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। नवरात्रि में उपवास रखने तथा विधि विधान से अर्चना करने से मनुष्य का जीवन तथा परलोक सफल होना शास्त्रों के अनुसार तय माना जाता है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि कथा हिंदू नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयां।

राजाओं की मंडी में सियासत का रंगमंच

देश के 18वें लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की एक सीट ह्यमंडीह्न ने देश का ध्यानाकर्षित तो किया ही है, वहीं बॉलीवुड की राजनीति में धमाकेदार एंट्री से मंडी खूब खनक रहा है। जो मंडी कभी राजाओं की मंडी हुआ करती थी, वहां रंगमंच की सियासत नया गुल खिला रही है। भाजपा ने इस बेहतरीन व पहले से ही अत्यंत सुविधाजनक सीट पर बॉलीवुड राजपूत अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी जंग में उतार कर कई विवाद मोल ले लिए हैं।

यूं तो भाजपा के लिए यह सीट इसलिए भी सुविधाजनक थी क्योंकि मंडी जिले की 10 में से 9 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में पहले ही थीं और मंडी संसदीय सीट की बाकी विधानसभा सीटों पर वर्ष 2022 में भाजपा का वोट मतांतर बहुत ही कम था। लेकिन इस सीट से कंगना रनौत को उतार कर अचानक भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में तो घिर ही गई, वह भी तब जब सीधा बॉलीवुड से कंगना के कई खैर ख्वाह पहले से ही मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल होती इस एक्ट्रैस व उम्मीदवार पर हिमाचल के देव समाज का सीधा असर दिखा है। यह दीगर बात है कि कंगना का सोशल मीडिया संरक्षक बराबर की टक्कर भी दे रहा है। बहरहाल चुनावी राह और सैलीब्रिटी सिलेबस, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन मंडी से अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते उम्मीदवार को लेकर साफ नहीं किए हैं। ज्यों ही प्रत्याशी घोषित होगा या होगी, तब ही स्टार दौर नए स्वरूप में होगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट की सियासत विवादित भी रही है और दिलचस्प भी क्योंकि यहां से लड? वाले कभी भी सामान्य परिवेश से नहीं थे। राजसी घरानों से महेश्वर सिंह तीन बार, वीरभद्र सिंह 2 बार, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दो बार, केंद्रीय मंत्री रहे पंडित सुखराम तीन बार सांसद रहे। वीरभद्र बुशहर रियासत के, महेश्वर कुल्लू के और सुखराम मंडी जिला से ताल्लुक रखते हैं और तो और यहां से जयराम ठाकुर भी हार गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मंडी से ऐसी पकड़ बनाई कि संघ से जुड़े रामस्वरूप, बेहतरीन मतों से 2019 में जीत गए। परंतु जब उन्होंने दिल्ली में फंदा लगा कर आत्महत्या की तब फिर, प्रतिभा सिंह 49.23 प्रतिशत मत लेकर जीत गईं। हालांकि तब प्रदेश में भाजपा की जयराम सरकार थी। कुल मिलाकर मंडी सीट पर चुनाव हर बार नई दिशा व दशा लेकर आता है। भाजपा ने सैलीब्रिटी कंगना पर दाव लगाया है। हालांकि कंगना की उम्मीदवारी घोषित होने से पहले ही प्रतिभा सिंह ने चुनाव न लड? का ऐलान कर दिया था। माना जा रहा था कि प्रतिभा, मोदी लहर के चलते आगे नहीं आना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने मंडी से कार्यकत्राओं की अपनी सरकार में अनदेखी की बात भी की।

इसी बीच कंगना का दिल्ली से ऐलान होते ही सोशल मीडिया की कमैंट्री व धूम-धड़ाम के बीच मंडी की सीट सुपर हॉट बन गई। मंडी के कार्यकत्रा सुपर स्टार को साक्षात सामने देख सन्न थे तो वहीं मंडी में पार्टी के वरिष्ठ नेता कंगना की छाया भर रह गए। तेज-तर्रार कंगना ने आरोपों का खंडन मंडयाली में किया तो सही, लेकिन सरकाघाटी व बिलासपुरी मिश्रित बोली से, पांगी, लाहौल, रामपुर, छतरी, सराज व मंडी स्थानीय बोली बोलने वाले वोटर अचरज थे क्योंकि कंगना की अगली चुनौती इन बोलियों को बोलना भी होगा। दरअसल मंडी संसदीय सीट में 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। जिसमें चार कुल्लू जिला के, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति व शिमला की एक-एक विधानसभा सीट है। मंडी की 9 सीटें हैं यानी मंडी संसदीय क्षेत्र में 6 जिले आते हैं और इन सभी 6 जिलों की बोलियां अलग-अलग हैं। इन 17 विधानसभा सीटों में दोनों दलों में कांटे की टक्कर है। परंतु सराज में जयराम की सीट, मंडी में अनिल शर्मा की सीट, भरमौर से जनकराज की सीट और सुंदरनगर से राकेश जमवाल की भाजपाई सीटों से पार्टी को बहुत बड़ा वोट शेयर मिलता है। मंडी जिला की इन्हीं सीटों से कंगना का वजन बढ़ता भी है। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं। ज्यों-ज्यों प्रचार परवान चढ़ेगा, कांग्रेस जम कर वार करेगी। कंगना की तस्वीरों को लेकर हो या मुंहफट बयानबाजी या खान-पान को लेकर संघ व पार्टी विचारधारा के विपरीत पुराने मसले, इनकी मुश्किलें खड़ी करेंगे। देखना यह है कि रनौत की सोशल मीडिया मैनेजमैंट व रंगमंच की हवाओं के बीच क्या लोग मंडी में मोदी लहर व चेहरे को जिंदा रख पाएंगे? या मंडी सैलीब्रिटी बॉलीवुड व विवादों को दर-किनार करके जयराम सरीखे साधारण नेता व मोदी के विकास को आत्मसात करेंगे?-**डा. रचना गुप्ता**

आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान के दोहरे मापदंड

आतंकवाद का साया भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों पर मंडराता रहता है। समस्या आतंकवाद की प्रकृति और आयाम की समझ की कमी नहीं है, बल्कि आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उचित उत्तर खोजने में विफलता है क्योंकि यह घरेलू धरती पर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पार से संचालित होता है। बेशक, आतंकवाद से लड़ने में संयुक्त राज्य अमरीका का अपना एजेंडा है। आतंकवाद से लड़ने पर भारतीय वैश्विक दृष्टिकोण अमरीकी गणनाओं और रणनीतियों से काफी भिन्न है।

इस्लामाबाद और बीजिंग प्रायोजित आतंकवाद के हाथों वर्षों तक पीड़ित रहने के बाद, नई दिल्ली के दृष्टिकोण ने अब तक समस्या की अधिक व्यापक वैश्विक समझ हासिल कर ली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एन.एस.ए.) अजीत डोभाल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) की बैठक के दौरान भारत-केंद्रित आतंकवादी समूहों से खतरे से प्रभावी ढंग से लड? की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर दिया और मॉस्को में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और दोहरे मानकों के बिना आतंकवाद से निपटने में निरंतरता का आग्रह किया।

डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख के बारे में बात की और मौजूदा खतरों के रूप में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल कायदा और आई.एस.आई.एस. का उल्लेख किया। उन्होंने आग्रह किया कि जो लोग सीमा पार आतंकवाद में सहायता करते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने उन व्यक्तियों या संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो आतंकवादी कृत्यों का समर्थन, वित्तपोषण या उन्हें इसके लिए सक्षम करते हैं विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा कई आतंकवादी संगठनों को लगातार समर्थन दिए जाने को देखते हुए।

ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व का मानना है कि वह कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा दे सकता है। 24वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने और 2022 के बाद से अपना दूसरा कार्यकाल चिह्नित करने के तुरंत बाद नैशनल असैंबली में अपने विजयी भाषण में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे की तुलना फिलिस्तीन के साथ की और उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले प्रस्तावों की वकालत की। कश्मीर और फिलिस्तीन के बीच समानताएं खींचकर और दोनों क्षेत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले प्रस्तावों की वकालत करके, शरीफ की बयानबाजी भारत के प्रति शत्रुता बनाए रखने और सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने के पाकिस्तान के इरादे को इंगित करती है, जिसने जम्मू-कश्मीर के लोगों को पीड़ा पहुंचाई है। यह टकराव वाला रुख पाकिस्तान की भारत के प्रति चल रही दुश्मनी और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन बंद करने में उसकी अनिच्छा को दशार्ता है। पाकिस्तान की आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में उपयोग करना, संलिप्तता से इन्कार करते हुए, एक सतत रणनीति रही है। इसके आलोक में, भारत को सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब वह चुनाव मोड में प्रवेश कर रहा हो। पाकिस्तान को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, आर्थिक स्थिरता पर आतंकवाद को प्राथमिकता देना एक गंभीर विरोधाभास है। चुनाव नजदीक होने के कारण, पाकिस्तान को हिंसा जारी रखने की बजाय अपनी आर्थिक चुनौतियों और अपने लोगों के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, शरणार्थियों के प्रति पाकिस्तान का दृष्टिकोण एक स्पष्ट असंगतता को दशार्ता है जबकि यह फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में खड़ा है। इसने दशकों से देश में रहने वाले अफगान शरणार्थियों को निष्कासित कर दिया है।

प्रारंभ में, पाकिस्तान ने संघर्ष से बचकर निकले अफगानों को शरण दी, लेकिन हाल के घटनाक्रम एक बदलाव का संकेत देते हैं, जो संभवतः अमरीकी सहायता में कमी के कारण वित्तीय कारणों से प्रभावित है। पाकिस्तानी समाज में उनके योगदान के बावजूद, अफगान शरणार्थियों को अब अन्यायपूर्ण तरीके से सुरक्षा खतरा करार दिया जाता है। इस नीति से दोहरे मानकों की बू आती है। पाकिस्तान को क्षेत्र को अस्थिर करने से रोकना आवश्यक है, और भारत की नई सरकार का ध्यान पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने से रोकना और हिंसा भड़काने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करना होना चाहिए।

पाकिस्तान को एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में मान्यता हमारे नीति निमार्ताओं द्वारा लंबे समय से दी गई है। बेशक, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान दुर्लभ नेतृत्व गुण दिखाए। उन्होंने निर्णायक और कठोरता से कार्य करने के लिए जबरदस्त साहस, दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। आज, हमें अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए और पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के छदम युद्ध के खिलाफ निर्णायक रूप से अपनी लड़ाई लड़ने चाहिए।

-हरि जयसिंह

लोकसभा चुनाव में महिलाओं की निर्णायक भूमिका

एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं का उच्च मतदान आगामी 2024 के चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। परिणामस्वरूप, राजनीतिक दल मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में महिलाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न लाभों की पेशकश कर रहे हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2047 तक महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत घटकर 45 प्रतिशत रह सकता है। संसद ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिछले सितंबर में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। यह विधेयक संसद और राज्य विधानसभाओं में उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने विधेयक के पारित होने का श्रेय लिया। 2008 में, सोनिया गांधी ने इसे उच्च सदन में पारित किया लेकिन लोकसभा में ऐसा करने में विफल रहीं। पी.एम. मोदी ने बड़े गर्व के साथ इस बिल को पेश किया और पिछले साल 27 साल बाद यह लगभग सर्वसम्मति से पास हो गया।

हालांकि, परिसीमन प्रक्रिया और नई जनगणना को पूरा करने में देरी के कारण विधेयक के कार्यान्वयन में 4 साल की देरी होगी। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के प्रमुख निमार्ताओं में से एक बी.आर. अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि ह्यराजनीतिक शक्ति सभी सामाजिक प्रगति की कुंजी है। यह कथन आज भी लागू है, क्योंकि महिलाओं को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी न हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, भारत में केवल एक महिला प्रधानमंत्री और 15 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। हालांकि, 1950 के दशक से चुनाव लड? वाली महिलाओं की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 5 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि 1993 में, पंचायत की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, जिसे अब अधिकांश राज्यों में 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 10 लाख महिलाएं जमीनी स्तर पर सरपंच के रूप में कार्य करती हैं। ये सरपंच अपने स्थूल अनुभव के बल पर उन्नति की सीढियां चढ़ सके। आगामी आम चुनावों में 96.88 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता होंगे, जिनमें से 47 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। 2.63 करोड़ नए मतदाताओं में से 1.41 करोड़ महिलाएं हैं। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में अधिक महिलाओं ने मतदान के लिए पंजीकरण कराया है। कोटा विधेयक से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गई थी कि वे हाल के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। भले ही उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को केवल 10-15 प्रतिशत टिकट आबंटित किए। लोकसभा चुनाव का रुझान भी निराशाजनक है। भाजपा ने घोषित 421 उम्मीदवारों में से 67 महिलाओं को टिकट दिया है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लाभों को समझा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

नौ माताओं के पुण्य स्मरण के साथ आज नव वर्ष का शुभारंभ

नवरात्रि का पहला दिन यानी प्रतिपदा तिथि मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। इस दिन जौ (जवार) बोने तथा कलश स्थापना पूजन के साथ ही देवी का पूजन किया जाना शुभ माना जाता हैद्य यह भी शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रथम दिवस में माता की पूजा करते समय आराधक यदि लाल, गुलाबी ,नारंगी और रानी रंग के कपड़े पहन कर पूजा करने से माता का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता हैद्य द्वितीय दिवस यानी नवरात्रि के दूसरे दिन अत्यंत दिव्य देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है सिद्धि के लिए इस दिन मां की उपासना करते समय सफेद,पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है एवं इस पवित्र दिन में आराधना करने से मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है। तृतीय दिवस में बाघ पर सवार स्वर्ण के समान रंग एवं छटा वाली मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है।इस दिन पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग कपड़े पहनना शुभ माने जाते हैं एवं इन रंगों के कपड़े पहनकर देवी की आराधना करने से उनका आशीर्वाद एवं कृपा की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में चतुर्थ दिवस में इस भव संसार के ब्रह्मांड की रचना करने वाली दुर्गा मां के चौथे रूप के रूप में देवी कुष्मांडा की आराधना एवं भक्ति की जाति है। इस दिन इस प्रकृति की देवी के स्वरूप की मन से आराधना करना शुभ फल देने वाला है एवं देवी प्रकृति की देवी हैं इनकी उपासना इस दिवस में पीला ,हरा, लाल और भूरे रंग का वस्त्र पहनकर करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, एवं देवी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पंचम दिवस पर पंचमी तिथि को भगवान कार्तिकेय की माता देवी स्कंदमाता की आराधना एवं श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर छठवें दिन ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी मां की पूजा अर्चना का शास्त्रों में पूजा का विधान माना जाता है। माता कात्यायनी अमोघ फलदाईनी होती हैं भक्तों द्वारा इस दिन लाल, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ, मूंगा रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करने से ऐश्वर्या के साथ वैवाहिक जीवन में शांति सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा तथा अर्चना का विधान है, नवरात्रि की पूजा में तंत्र साधना करने वाले लोग इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करके इनकी पूजा अर्चना करते हैं साधकों को इस दिन बैगनी, स्लेटी ,नीला एवं आसमानी रंग का वस्त्र धारण कर मां के इस दिव्य रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे संपूर्ण ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के आठवें दिन सर्व सौभाग्य दाइनी देवी महागौरी की उपासना का दिन माना जाता है। यह अत्यंत पवित्र दिन होता है और यह देवी धन, वैभव, सुख, शांति की शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा के दौरान साधकों को रातों को केसरिया संतरी गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए जिससे सुख एवं सौभाग्य की अखंड प्राप्ति होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों का पूजन अर्चना एवं निष्ठा से की गई आराधना से इस जगत का कल्याण भी होता है साथ ही इस पवित्र 9 दिनों में असंख्य दीप जलाकर माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। नवरात्रि में उपवास रखने तथा विधि विधान से अर्चना करने से मनुष्य का जीवन तथा परलोक सफल होना शास्त्रों के अनुसार तय माना जाता है।

नवरात्र मात्र उपवास और कन्याभोज नहीं है

- डॉ नीलम महेन्द्र

चैत्र मास की शुक्लप्रतिपदा यानी नव संवत्सर का आरम्भ। ऐसा नववर्ष जिसमें सम्पूर्ण सृष्टि में एक नईऊर्जा का संचार हो रहा होता है। एक तरफ पेड़ पौधों में नई पत्तियां और फूल खिल रहेहोते हैं तो मौसम भी करवट बदल रहा होता है। शीत ऋतु जा रही होती है, ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है और कोयल की मनमोहककूक वातावरण में रस घोल रही होती है। देखा जाए तो प्रकृति हर ओर से नवीनता औरबदलाव का संदेश दे रही होती है। सनातन संस्कृति में यहसमय शक्ति की आराधना का होता है जिसे नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। नौ दिनोंतक देवी माँ के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यके अनुसार इन दिनों उपवास रखते हैं और कन्याभोज के साथ माता को प्रसन्न करने काप्रयास करते हैं। दरअसल यह सनातन संस्कृतिकी महानता है कि इसमें अत्यंत गहरे और गूढ़ विषयों को जिनके पीछे बहुत गहरा विज्ञानछिपा है उन्हें बेहद सरलता के साथ एक साधारण मनुष्य के सामने प्रस्तुत किया जाताहै। इसका सकारात्मक पक्ष तो यह है कि एक साधारण मनुष्य से लेकर एक बालक के लिए भीवो विषय ग्रहण करना इतना सरल हो गया कि वो उनके जीवन का उनकी दिनचर्या का हिस्साबन गया। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह हुआ कि वो गहरे विषय हमारी दिनचर्या तक हीसीमित रह गए और उनके भाव, उनके लक्ष्य हमसे कहींपीछे छूट गए। नवरात्र को ही लीजिए आजयह केवल उपवास रखने और कन्याभोज कराने तक ही सीमित रह गए। इसके आध्यात्मिकवैज्ञानिक और व्यवहारिक पक्ष के विषय पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसके वैज्ञानिक पक्ष कीबात करें तो नवरात्र साल में चार बार मनाई जाती हैं, चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और दो गुप्त नवरात्र। हर बार दो ऋतुओं के संकर काल में यानी एकऋतु के जाने और दूसरी ऋतु के आने के पहले। आज विज्ञान के द्वारा यह सिद्ध हो चुकाहै कि ऋतु संकर के समय मानव शरीर बदलते वातावरण से तारतम्य बैठाने के लिए संघर्षकर रहा होता है और इस दौरान उसकी पाचन शक्ति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है। ऐसे समय मेंउपवास न सिर्फ मनुष्य के पाचन तंत्र को सुधारने का काम करता है बल्कि उसे डिटॉक्स करके उसमें एक नई ऊर्जा का संचार भीकरता है। किंतु महत्वपूर्ण तथ्य यहहै कि नवरात्र का महत्व मात्र हमारे शरीर की शक्ति एवं उसकी ऊर्जा बढ़ाने तक हीसीमित नहीं है बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। नवरात्र का समय अपनी खगोलीय घटनाओं केकारण प्रकृति का वो समय होता है जब मनुष्य अपने मानव जन्म का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेसकता है। नवरात्र का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि इस समय मनुष्य अपनी शारिरिकशक्तियों से ऊपर उठकर अपने मानस एवं आत्मबल का विकास कर सकता है। नौ दिनों तक व्रतएवं व्रत के नियम हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने में मदद करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक औरआध्यात्मिक पक्ष से इतर नवरात्र का एक व्यवहारिक पक्ष भी है। देखा जाए तो मां केनौ रूपों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कहा जाता है कि मां दुर्गा ने ये सभी नौअवतार इस धरती पर अधर्म और पाप के नाश दैत्यों के विनाश तथा धर्म की स्थापना केउद्देश्य से लिए थे। तो क्यों न हम भी इस समय का उपयोग अपने भीतर के पाप और अधर्मका नाश करने के लिए करें, अपने भीतर के शत्रुओं केविनाश के लिए करें। गीता में कहा गया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्यामनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। नवरात्र के दौरान हम माँ के हर रूप से सफलता केमंत्र सीखकर अपने भीतर के इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमगम्भीरता से सोचें तो पाएंगे कि मां के हर रूप का नाम उनके व्यक्तित्व को परिभाषितकरते हुए हमें अनूठा संदेश देता है। जैसे मां शैलपुत्री (यानीहिमालय की पुत्री) से शिला अर्थात चट्टानकी तरह दृढ़ आत्मबल। मां ब्रह्मचारिणी (यानी ब्रह्म के समान आचरण) से अपने आचरण मेंअनुशासन। मां चंद्रघंटा (इनके माथे पर चन्द्र के आकार का घण्टा है) से अपने मन कोकठिन से कठिन परिस्थिति में चंद्रमा जैसा शीतल यानी ठंडा रखना। मां कुष्मांडा (कूयानी छोटा ऊष्मा यानी ऊर्जा) से स्वयं को सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरे रखना। मांस्कंदमाता (इनकी गोद में बालक कार्तिकेय हैं) से अपने भीतर करुणा ममता प्रेम औरसंवेदनशीलता जैसे गुणों को हमेशा बना कर रखना। मां कात्यायनी (स्वास्थ्य औरचिकित्सा की देवी) से स्वास्थ्य की महत्ता क्योंकि स्वस्थ रहकर ही अपने लक्ष्योंको हासिल किया जा सकता है। माँ कालरात्रि (महाशक्तिशाली और अपराजेय दैत्यों कानाश करने वाली) से जुनून की हद तक लक्ष्य हासिल करने का जज्बा क्योंकि इसके बिनाकठिन लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। मां महागौरी (ये गौर वर्ण की हैं) से जीवन केहर कदम पर अपना आचरण चरित्र और चित को उज्ज्वल एवं स्वच्छ रखना ताकि कहीं कोई दागलगने की गुंजाइश न हो। और अंत में मां सिध्दरात्री (सफलता देने वाली) जब हमनवरात्र में माँ के इन आठ रूपों की सच्चे मन से आराधना करते हैं तो मां सिध्दरात्री सफलता देती हैं। इसीप्रकार जब हम नवरात्र के व्यवहारिक पक्ष को अपने जीवन में उतार कर इन आठ सूत्रों को अपने आचरण में अनाएँगे तोनिसन्देह हमें सफलता की सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस बार नवरात्र कोमात्र उपवास एवं कन्याभोज तक सीमित न रखें बल्कि इस बार नवरात्र में शरीर के साथसाथ मन और आत्मा को भी शुद्ध एवं डिटॉक्स करके अपने जीवन में नई ऊर्जा नई शक्ति को महसूस करें। या देवी सर्वभूतेषुशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:। (लेखिका वरिष्ठ स्तम्भकार हैं)

आखिर जेनेरिक दवाइयां क्यों नहीं बनती चुनावी मुद्दा ?

अगर जेनेरिक दवा लिखना अनिवार्य होता है तो इसके साथ-साथ फार्मा सेक्टर में हजारों नौकरियों पर भी खतरा पैदा हो जाएगा। इनके मुताबिक,एक दवा को कई कंपनियां बनाती हैं। उनके प्रचार-प्रसार या उन्हें प्रमोट करने के लिए भारी भरकम स्टाफ रखती है। इनमें सबसे ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) हैं,जो डॉक्टर्स के पास विजिट कर उन्हें अपनी कंपनी की दवा लिखने को कहते हैं।

- अशोक भाटिया

देश में जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को सख्त निर्देश दे दिया था। सरकार ने आदेश जारी कर सभी डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं पेशेंट्स के लिए लिखने को कहा था। सरकार ने सख्त होते हुए कहा कि अगर डॉक्टर पर्ची में जेनरिक दवा नहीं लिखी जाती तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर जनरल ने आदेश जारी करते हुए इस बात की वार्निंग दी थी कि जो कोई भी डॉक्टर जेनरिक दवाओं को अपने पर्ची में शामिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं ही लिखने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने की चेतावनी जारी की थी ।पर न जाने क्यों यह आदेश समय के अनुसार धुंधला पड़ गया। अब जब लोकसभा के चुनाव हो रहे है तब यह मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है . सत्ताधारी पक्ष तो चुप है पर विपक्ष भी क्यों अज्ञान बना घूम रहा है। सुना था सरकार मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवा लिखनी होंगी, न कि किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की ।ऐसा लगभग 8 साल से सुनते आ रहे हैं पर कानून अमली जामा कब पहनेगा मालूम नहीं ? इसके बाद भी मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने लगेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जेनेरिक दवाओं के प्रिंट रेट यानी इन दवाओं पर छपने वाली कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। हाल ही में लेखक को एक अनुभव मिला जब उसने डॉक्टर की लिखी दवा PANAM D अपने मेडिकल स्टोर से खरीदी तो उसे छपे भाव में मिली और उसे ही जेनेरिक रूप में ओन लाइन TRUE MAD से मंगवाई तो 51% कम में मिली यानि वह जेनेरिक थी। आईएमए के सदस्य और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत जैन ने एक समाचार पत्र को बताया था कि ब्रांडेड मेडिसिन पर फार्मासिस्ट को 5 से 20 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है, पर जेनेरिक मेडिसिन की प्रिंट रेट और रीटेलर की खरीद कीमत में 50 गुना से 350 गुना तक का अंतर होता है। 10 पैसे की बी कॉम्प्लेक्स 35 रुपए तक में बिकती है। इसका आम जनता या मरीजों को उतना फायदा नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए। ऐसे में सरकार को जेनेरिक मेडिसिन के प्रिंट रेट पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, वरना जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। आम तौर पर सभी दवाएं एक तरह का 'केमिकल सॉल्ट' होती हैं। इन्हें शोध के बाद अलग-अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है, उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे- दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासिटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं, जब इसे किसी ब्रांड जैसे- क्रोसिन के नाम से बेचा जाता है तो यह उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि सर्दी-खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी रोजमर्रा की तकलीफों के लिए जेनरिक दवा महज 10 पैसे से लेकर डेढ़ रुपए प्रति टैबलेट तक में उपलब्ध है। ब्रांडेड में यही दवा डेढ़ रुपए से लेकर 35 रुपए तक पहुंच जाती है। लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने और सरकारी नीतियों में बदलाव को लेकर काम कर रहे जन स्वास्थ्य अभियान के डॉ. इंद्रनील मुखोपाध्याय बताते हैं- जेनेरिक दवाओं को लेकर भारत और विदेशों में काफी अंतर है। 2007 के बाद से पेटेंट कानून में कोई प्रभावी संशोधन नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं की कीमतों में भी भारी अंतर होता है। खास तौर पर इनकी प्रिंट रेट और खरीद कीमत में भारी अंतर होता है। ऐसे में सरकार को इन दवाओं की एवरेज प्राइसिंग करनी चाहिए। इससे दवाओं की कीमतों में बड़ा फर्क आ जाएगा। अभी किसी भी मरीज का दवाओं पर औसत खर्च 180% ज्यादा है। दवा कीमतों पर नियंत्रण के बाद इसमें भारी कमी आ जाएगी। डॉ. मुखोपाध्याय बताते हैं कि जेनेरिक दवा ब्रांडेड भी होती है। एक ही कंपनी जेनेरिक और ब्रांडेड, दोनों दवाएं बनाती है, लेकिन उनकी कीमतों में काफी अंतर होता है। ऐसे में अगर सरकार लोगों को या मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाना चाहती है तो उनकी कीमतों पर नियंत्रण जरूरी है। जेनेरिक दवाओं के मामले में भी बड़ा खेल होता है, खासतौर पर सरकारी खरीद या अस्पतालों में खरीदी जाने वाली दवाओं के मामलों में। ऐसे में इनकी कीमतों पर नियंत्रण ही मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने का रास्ता खोल सकता है।

कई जानलेवा बीमारियों जैसे एचआईवी, लंग कैंसर, लीवर कैंसर जैसी बीमारियों में काम आने वाली दवाओं के ज्यादातर पेटेंट बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास हैं। वे इन्हें अलग-अलग ब्रांड से बेचती हैं। अगर यही दवा जेनेरिक में उपलब्ध हो तो इलाज पर खर्च 200 गुना तक घट सकता है। जैसे- एचआईवी की दवा टेनोफिविर या एफाविरेज़ की ब्रांडेड दवा का खर्च 2,500 डॉलर यानी करीब 1 लाख 75 हजार रुपए है, जबकि जेनरिक दवा में यही खर्च 12 डॉलर यानी महज 840 रुपए महीने तक हो सकता है। हालांकि, इन बीमारियों का इलाज ज्यादातर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में होता है। ऐसे में ये दवाएं इन अस्पतालों में या वहां के केमिस्ट के पास ही मिल पाती हैं। - नोवार्टिस की कैंसर की दवा ग्लीवियो-इमेटिनिब मिसाइलेट का एक महीने का खर्च 2,158 डॉलर यानी करीब 1.51 लाख रुपए पड़ता है, जबकि जेनरिक रूप में इसी दवा का खर्च 174 डॉलर प्रति माह (12,180 रुपए) है, यानी 12 गुना या 92% से भी कम। - ऐसे ही बेयर की कैंसर ड्रग सोराफेनिब टोसाइलेट, जिसे वह नेक्सावर के नाम से बेचती है, उसका एक महीने का खर्च करीब 5,030 डॉलर है, जबकि जेनरिक दवा लेने पर यही खर्च महज 122 डॉलर प्रति माह रह जाता है।। जर्नल ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स के मुताबिक, एक पेटेंट इनोवेटर को उस उत्पाद पर रिसर्च के दौरान किए गए खर्च या लागत को वसूलने और उससे लाभ हासिल करने की अनुमति देता है। जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी दवा के इनोवेटर या कंपनी उस दवा को बनाने से लेकर बाजार में उतारने और उसके बाद के 10-15 साल के दौरान करीब 80 करोड़ डॉलर यानी करीब 5,600 करोड़ रुपए खर्च करती है। ऐसे में पेटेंट के 20 साल के दौरान उसे इस खर्च को वसूलने और मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। डॉ. हेमंत जैन और डॉ. मुखोपाध्याय का कहना है कि अगर जेनेरिक दवा लिखना अनिवार्य होता है तो इसके साथ-साथ फार्मा सेक्टर में हजारों नौकरियों पर भी खतरा पैदा हो जाएगा। इनके मुताबिक, एक दवा को कई कंपनियां बनाती हैं। उनके प्रचार-प्रसार या उन्हें प्रमोट करने के लिए भारी भरकम स्टाफ रखती है। इनमें सबसे ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) हैं, जो डॉक्टर्स के पास विजिट कर उन्हें अपनी कंपनी की दवा लिखने को कहते हैं।

कई डॉक्टर्स को इसके लिए बाकायदा कमीशन या महंगे-महंगे गिफ्ट तक दिए जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर जब सिर्फ जेनेरिक दवा लिखेंगे, तो यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका दूसरा असर यह होगा कि ब्रांडिंग खत्म हो जाएगी तो दवा कंपनियों को प्रचार-प्रसार के लिए स्टाफ भी कम रखना पड़ेगा। कई लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज़ की नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। फार्मा और मेडिकल सेक्टर से जुड़ी डॉकप्लेक्सस के मुताबिक, बड़ी कंपनियों में से प्रत्येक अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए 5 हजार से ज्यादा फील्ड स्टाफ रखती है। इसके अलावा फार्मा कंपनियां कुल बजट का 20% फील्ड स्टाफ की भर्ती और खर्च का 60% फील्ड स्टाफ और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करती हैं। इसका दूसरा पहलू भी है। ज्यादातर डॉक्टर्स सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। वे आशंका जता रहे हैं कि ऐसे किसी कानून के लागू होने के बाद दवा से जुड़ी सभी शक्तियां केमिस्ट के हाथों में चली जाएंगी। उनकी दलील है कि डॉक्टर के जेनेरिक दवा लिखने के बाद केमिस्ट तय करेगा कि मरीज को कौन-सी दवा देनी है। ऐसी स्थिति में वह दवा की गुणवत्ता की परवाह किए बिना वही दवा देगा, जिसकी बिक्री से उसे अधिक मार्जिन या मुनाफा हासिल होगा। फार्मा सेक्टर से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें डॉक्टर्स को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो मरीज आते रहेंगे, लेकिन जनता को अच्छी गुणवत्ता की जेनेरिक दवा मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद दवा कंपनियां सीधे स्टॉकिस्ट या केमिस्ट से संपर्क करेंगी और उसे अपनी दवा बिक्री के लिए कई तरह के लालच दे सकती हैं, जिसका नुकसान आखिरकार आम जनता को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में भी सोच-विचार करना चाहिए ।अब यह सरकार को तय करना है कि जिस कानून को वह साल दर साल दोहराती है उसे अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता हैं और यह क्यों नहीं चुनावी मुद्दा बन पा रहा है।

(वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार,लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार, पत्रकारिता में वसई गौरव अवार्ड से सम्मानित, वसई पूर्व, मुंबई)

इंडियन पॉलिटिक्स की व्यथा

- रामविलास जांगिड़

दीपक जी सड़क पर पार्किंग की जगह लेटे हुए ऐसे मिल गए, जैसे शाहबाज शरीफ चाइना के बस अड्डे पर लेटा हो। मैंने उनसे पूछा- आप पार्किंग में ऐसे क्यों लेटे हो? क्या कोई तबीयत खराब है? आप बीमार हो? चलो मैं हॉस्पिटल ले चलूं! तब दीपक जी ने करवट बदली और अपने पांवों को दिल्ली तक फैलाते हुए कहा- भाई साहब! बीमारी जैसी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी नई कार खरीदने गई है और मुझे पार्किंग में जगह मिल गई है। पार्किंग में कोई दूसरा अपनी गाड़ी खड़ी ना कर दे, इसलिए इस जगह को रोके लेटा हूं। दीपक जी ने चाइना थ्योरी समझाते हुए अपनी व्यूह रचना स्पष्ट की। तभी एक पुलिस वाला आया और दीपक जी को डंडा मारते हुए कहने लगा- निकालो पार्किंग का चालान! दीपक जी ने कहा- किस बात की पार्किंग! कैसा चालान? पुलिस वाले ने फिर डंडा फटकारा और कहा- देखो ज्यादा स्याणपति मत करो! पार्किंग की जो लाइन खींची थी, उससे तुम्हारी टांगें बाहर थी। दीपक जी 500 रुपए हवा में लहरा रहे थे। पुलिस वाला हजार पर अड़ा रहा। रिश्वत प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन चल रहा था। मुझे बैंक में काम था। मैंने दीपक जी को उसी अवस्था में छोड़ दिया। फिर सामने बैंक गया। बैंक में लोन देने वाले बैंक अधिकारियों की लंबी कतार लगी थी। एक चेंबर में दीपक जी का बड़ा बेटा कुमार अमीर खड़ा मिला। मैंने उससे पूछा- तुम लोन वाले इस चेंबर में क्यों लगे हो? उसने जवाब दिया- अंकल जी! असल में मेरी मम्मी आज नई कार खरीदने गई है। कार को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल की भी जरूरत होगी। मैं कार में पेट्रोल डलवाने के लिए लोन ले रहा हूं। इसके लिए घर गिरवी रखने हेतु सारे कागजात लेकर आया हूं। कहकर कुमार अमीर ने हाथ में लटके थैले में लोन के सारे कागजात दिखाए।

कार आई। दीपक जी जैसे ही कार में बैठकर सीट बेल्ट बांधने लगे, उनकी बीवी जोर से चिल्लाने लगी। रोते हुए कहने लगी- क्यों सीट बेल्ट मान रहे हो? मेरी करवा चौथ पर विश्वास नहीं है क्या? दीपक जी ने समझाया- भाग्यवान! मुझे तुम्हारी करवा चौथ पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन वो सामने जो पुलिस वाला खड़ा है, उसे केवल नोटों पर ही विश्वास है! तभी एक भिखारिन आई और बोली- आंटी 100 रुपए दे दो। आंटी ने 10 रुपए निकाल कर दिए। भिखारिन ने 10 रुपए और मिलाकर 20 रुपए लौटा दिए और कहा- इसे मेरी ओर से रख लो। भिखारी समझ रखा है क्या? पूरे 1000 रुपए लगेंगे। तब बड़बड़ाते हुए 1000 रुपए दिए। रुपए लेकर भिखारिन जाने लगी। दीपक जी की बीवी ने कहा- इस 1000 रुपए के बदले कुछ दुआएं तो देती जा! तब भिखारिन बोली- इस जमाने में कार पार्किंग के लिए जगह मिल गई। अब इससे बढ़कर अब कौनसी दुआ बाकी रह गई? कहानी सुना कर विक्रम ने कहा बता बेताल; यह कहां की कथा और कहां की व्यथा है? यह इंडियन पॉलिटिकल लीग की चलने वाली गाड़ी की कथा है और इंडियन पॉलिटिक्स की व्यथा है। उत्तर सुनाकर बेताल ने जोरदार कहकहा लगाया और संसद भवन की छत से उल्टा लटक गया।

(18, उत्तम नगर, घूघरा, अजमेर)

लोगों में विवाह शादी के अनावश्यक कार्ड की जगह मिठाई बांटें

ईश्वर ने जब कमाई में बरकत दी है तो गरीबी से निकल कर आज अपनी संतान की शादी में जी भर कर सब कुछ लुटा देने का मन किसका नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर गोवा सिंगापुर अपनी हेसियत के अनुसार जहाँ मन करे वही करना चाहिए तथा अपने रिश्तेदारों व्यावसायिक मित्रों एवं समकक्ष लोगों को ही शादी में ले जाना है तो घर घर निमंत्रण पत्र जो काफी कीमती एवं दर्शनीय होते हैं उसे बांटने की जगह मिठाई बांटें ताकि लोग खुश हो वरवधु को आशीर्वाद देंगे। मैंने दस साल पहले एस एम एस अथवा व्हाट्सएप पर कार्ड भेजने का सुझाव लेख के जरिये दिया तो लोगों में काफी चर्चा हुई लेकिन आज आ गए उसी प्रथा पर। मंहगे-मंहगे कथाकार एवं साहित्यकार कुप्रथा हटाने एवं समाज में समानता लाने के लिए अभियान चलाते हैं ऐसे में कुछ संकोच तो लोगों को, होता ही है। अंबानी ने अपने बेटे की शादी की प्रिवेडिंग में गुजरात में 1400 करोड़ रुपये खर्च किए तो शादी में कितनी राशि खर्च होगी। उसका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकेगा फिर धरती नापने की हुंकार क्यों? धन तुम्हारा मन तुम्हारा तो भला तीसरा क्यों? विवाह शादी जन्म दिन शादी की सालगिरह में अपनी औकात के अनुसार तथा अपने परिवार के लोगों की इच्छा के अनुसार हर कोई खर्च करता है वो करना भी चाहिए बचपन से पचपन तक पानी पीकर ज्युस का आनंद लिया तो आज क्यों कंजुसी करें। लेकिन समाज चाहता है कि कुछ अंश समाज धर्म एवं संस्कृति के लिए आप योगदान दें ताकि आने वाली पीढ़ी याद करेगी। गुप्त दान नैत्र दान आज भी लोग कर रहे हैं इससे दोहरे लाभ होते हैं लेकिन समझ अपनी अपनी है। समाज पहले भी चलता था आज भी चल रहा है तथा भविष्य में भी चलेगा लेकिन आपका तेरा मेरा क्या योगदान है।

- मदन सुमित्रा सिंघल (पत्रकार एवं साहित्यकार, शिलचर असम)

इस लोकसभा में आप तीसरी बार मतदान करेंगे,तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस बार भी धोखा नहीं खाएंगे,युवा साथी इन झूठों एवं उनके झूठे वादों को समझ गए होंगे,वह धोखा नहीं खाएंगे। पर मेरे पहली बार के मतदाता युवा है 18 से 23 वर्ष के होंगे वह धोखे में आ सकते हैं उन्हें लुभावने वादे विपक्ष के जातिवादी नेता गुमराह कर सकते हैं। अत: जो तीसरी बार तथा दूसरी बार लोकसभा के लिए मतदान कर रहे हैं उन युवा साथियों के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है।

राजनीतिक दलों के नारे, जितने दुर्लभ उतने प्यारे

- पंकज कुमार मिश्रा

राजनीतिक पार्टियां अपने अजीबो गरीब स्लोगन के लिए भी जानी जाती है। जिस पार्टी का जितना भयंकर नारा वो पार्टी उतना ही भयंकर परफॉर्मेंस देती है। आपको याद दिला दूँ हर हर मोदी हर घर मोदी, नमो नमो जैसे नारे के साथ भाजपा नें 2014 के चुनाव में भारत जीत लिया था। ऐसे जयघोष समय समय पर राजनीतिक पार्टियां उछाल कर अपना बेजोड़ परफॉर्मेंस देती रहीं है। आज इस कॉलम में मैंने ऐसे ही कुछ नए पुराने नारों का संकलन किया है जो आपको शायद विस्मृत हो चूके होंगे। किसी का उत्साह बढ़ाना हो या ट्रोल करना हो हमारे देश में कहावतों के साथ नारे भी खूब बनाये जाते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल हमारे समाज की विशेषता है वैसे भी आजादी के पहले नारे होते थे ... करो या मरो, अंग्रेज भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा, आजादी के बाद नेहरु ने लोगों को सचेत किया कि ये समय देश निर्माण का है तो कहा कि - आराम हराम है बाद में पाकिस्तान से युद्ध के समय शास्त्री जी बोले - जय जवान जय किसान, पर जब इंदिरा जी आईं तो बोली मेरे खून का अंतिम कतरा देश के काम आएगा और फिर आया जनसंघ और नारा मिला कि... जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तम्बाकू है, कांग्रेस वाला डाकू है। तब इंदिरा का जवाब आया था कि... प्रोग्रेस थ्रो कांग्रेस, शिवसेना ने पूछा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर इट्स कांग्रेस ऑर प्रोग्रेस। जब कांग्रेस का चिन्ह गाय बछड़ा था तो नारा था कि वोट फॉर कॉफ एंड काऊ फॉरगेट एव्रीथिंग नाउ, जनसंघ का नारा था, ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल। और जब 1971 में कांग्रेस ने कहा.. गरीबी हटाओ, इंदिरा को लाओ, देश बचाओ तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि... इंदिरा हटाओ - देश बचाओ। 1978 के चुनावों में जब इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से खड़ी हुई तो नया नारा आया कि - एक शेरनी सौ लंगूर चिकमंगलूर भई चिकमंगलूर, उसके बाद कांग्रेसियों ने एक सुपरहिट नारा दिया। जात पर न पात पर इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद एक नया नारा बना, जब तक सूरज चाँद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। लालू यादव का नारा आया कि... जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू तो मुलायम सिंह का नारा थाकि...नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है। मंदिर को मुद्दा बनाने के बाद भाजपाई बोले कि..बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का और.. कसम राम की खाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तब मुलायम सिंह बोले ...मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए जय श्री राम और ..... चलेगी साइकिल उठेगी धूल, ना रहेगा हाथी ना रहेगा फूल। मायावती जी आईं तो उनकी पार्टी बोली कि ... तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और ... चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। अटल को लेकर जब भाजपा आई तो कहा कि... बारी बारी सबकी बारी अबकी बारी अटल बिहारी। और सोनिया जी के लिये कांग्रेस ने कहा कि... सोनिया नहीं ये आंधी है। दूसरी इंदिरा गांधी है। तब भाजपाई बहुत बुरा फील करते हुये बोले फील गुड। तो कांग्रेसी बोले जय मनमोहन। और 2014 में बीजेपी की आंधी चली... अबकी बार मोदी सरकार और घर घर मोदी से मैं भी चौकीदार। राहुल ने 2019 में पलटवार किया कि चौकीदार चोर है। और अब तो ममता दी का...खेला होबे, बहुत मजेदार था...2015 में केजरीवाल ने भी एक नारा उछाला था दिल्ली के लिए पांच साल केजरीवाल। बिहार के लिए ये नारा नीतीश के जैसा कि सर्वकालिक हो गया है। बिहार में बहार है फिर से नीतीश कुमार है। और भाजपा के लिए भी कुछ ऐसा ही नारा है कि...मोदी है तो मुमकिन है....पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने कहा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो इस बार राहुल ने कहा है .... अब होगा न्याय। प्रथम चरण के मतदान का समय नजदीक है इस अवसर पर में हमारे युवा मतदाताओं से आशा करता हूं और अपेक्षा रखता हूं खासकर 18 से 33 वर्ष के युवा मतदाताओं से वह देश के लिए एवं अपने उज्जवल भविष्य के लिए रोजगारों का सृजन करने वाली सरकार का चयन करेंगे। 2014 में जब आपने अपना लोकसभा के लिए पहला वोट करा होगा तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए 34 रुपए पेट्रोल 30 डीजल एवं ढाई सौ रुपए गैस की टंकी एवं दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की आशा में दिया था। तब आप 18 से 23 वर्ष के रहे होंगे पर आज आपको क्या मिला आज आपकी उम्र 28 से 33 वर्ष के बीच है रोजगार नहीं है, आप परिवार नहीं बना पाए हैं, पेट्रोल 108 का है, डीजल 102 का है, गैस की टंकी 1200 की है। तो अब सरकार अपने मैनिफेस्टो में बीएड और पीएचडी पास बेरोजगारों के लिए पांच हजार रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करें। आप जब अपना दूसरा वोट 2019 में कर रहे थे तब आपकी उम्र 23 से 28 साल की थी और आप रोजगार की कमी के कारण सरकार से निराश थे पर कुछ नेताओं ने आपको देशभक्ति जगा कर जोश दीलाकर पुलवामा अटैक से भावुक कर आपका वोट ले लिया आपने भी भावूक होकर अपना वोट देश के जवानों के लिए समर्पित कर दिया ताकि देश के जवानों को न्याय मिले। आप से कहा जायेगा आप निराश है, आपका वोट बेकार गया और जवानों को न्याय भी नहीं मिला और आप एक बार फिर बेवकूफ बन गए लेकिन आपको राम मंदिर मिला, देश विकसित हुआ हम आर्थिक ताकत बने, जम्मू कश्मीर की रौनक़ लौट आई।

इस लोकसभा में आप तीसरी बार मतदान करेंगे, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस बार भी धोखा नहीं खाएंगे, युवा साथी इन झूठों एवं उनके झूठे वादों को समझ गए होंगे, वह धोखा नहीं खाएंगे। पर मेरे पहली बार के मतदाता युवा है 18 से 23 वर्ष के होंगे वह धोखे में आ सकते हैं उन्हें लुभावने वादे विपक्ष के जातिवादी नेता गुमराह कर सकते हैं। अत: जो तीसरी बार तथा दूसरी बार लोकसभा के लिए मतदान कर रहे हैं उन युवा साथियों के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। पहले तो अपना खुद का वोट जो राष्ट्रहित और रोजगार उपलब्ध कराये उसे देना है तथा दूसरी जिम्मेदारी जो हमारे युवा साथी पहली बार मतदान कर रहे हैं उन्हें भी देश हित और रोजगार उपलब्ध करवाने वाली सरकार को वोट देने के लिए प्रेरित करना है, वरना जो पहली बार का मतदाता है इस बार राममंदिर के लिए वोट करेगा ही। क्योंकि फिर अब आपको मौका सीधे 2029 में मिलेगा जब आप 33 से 38 साल के हो चुके होंगे फिर सोचिए आपका गलत वोट, क्या हाल होगा, क्या पता सनातन के घातक रहे ना रहे, तो उठो साथियों जागो और अपने युवा मतदाताओं को भी जगाओ। आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए मतदान जरूर करें नारों पर ना जाए अपनी अक्ल लगाएं।

(राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार जौनपुर यूपी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

शिक्षा सिर्फ धन अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह सत्य की खोज और सदाचार के लिए मानव आत्मा का प्रशिक्षण भी है।
-विजय लक्ष्मी पंडित

विश्व बैंक के अलावा मूडीज, फिंच, एस ऐंड पी और मॉर्गन स्टेनली जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा भी भारत की डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे में निवेश के ढंग को पूरी दुनिया के लिए मिसाल बताना आश्वस्त करता है।

और अब संयुक्त राष्ट्र

वित्तीय समावेशन और निर्धनता-उन्मूलन संबंधी लक्ष्यों को पाने में डिजिटलीकरण का प्रभावी उपयोग करने और बुनियादी क्षेत्र में निवेश के लिए अगर भारत की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सर्वोच्च पदाधिकारी डेनिस फ्रांसिस खुद करें, तो इसके अर्थ और महत्व, दोनों ही बढ़ जाते हैं। उनका यह कहना वाकई सुखद है कि भारत ने सिर्फ एक मोबाइल फोन और डिजिटलीकरण के अपने मॉडल से जिस तरह देश के करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है, वह दुनिया के तमाम देशों के लिए एक सबक है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने, विश्व बैंक ने अपनी डिजिटल प्रोग्रेस ऐंड ट्रेंड्स रिपोर्ट में भी डिजिटल क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रदर्शन को रेखांकित किया था। दरअसल, आज अगर प्रतिष्ठित वैश्विक संगठन खुल कर भारत में डिजिटलीकरण की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका श्रेय पिछले कुछ वर्षों में की गई पहलों को जाता है। विश्व बैंक तो यहां तक कह चुका है कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें पचास वर्षों में भी करना मुश्किल था। 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान के साथ भारत के डिजिटलीकरण में तेजी आई। 85 करोड़ लोगों को सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराना हो या सवा अरब से ज्यादा लोगों को कवर करने वाला 'आधार' हो या फिर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पहल, ये सभी भारत में डिजिटल क्रांति के आधार बने। आज अगर सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे देश भी भारतीय यूपीआई को अपना रहे हैं, तो यह भारतीय तकनीक पर बढ़ते भरोसे का ही परिचायक है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में यूएनजीए के अध्यक्ष जब भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, तब उन्होंने देश में डिजिटलीकरण के अलावा बुनियादी ढांचे के विकास पर किए जा रहे कार्यों को नजदीक से देखा था। लिहाजा, अब इस क्षेत्र में किए जा रहे निवेश की उनके द्वारा की गई तारीफ दर्शाती है कि पहले कोरोना और

अब मंदी, वैश्विक युद्ध व आपूर्ति शृंखलाओं में पहुंच रही बाधा से दुनिया के त्रस्त होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। दरअसल, बुनियादी क्षेत्र का विकास न सिर्फ अर्थव्यवस्था की ताकत, बल्कि बढ़ती नौकरियों के रूप में भी देखा जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलाव आंकड़ों में भी दिखते हैं। खुद विश्व बैंक के अलावा, अगर मूडीज, फिंच, एस ऐंड पी और मॉर्गन स्टेनली जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भी विकास दर के अनुमानों को बढ़ा रही हैं, तो यह आश्वस्तकारी होने के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर दुनिया के बढ़ते भरोसे को भी दिखाता है।

इतने कम आयकर दाता

कटु सच्चाई यह है कि 7.4 करोड़ आयकर रिटर्न में से 5.16 करोड़ शून्य कर रिटर्न होते हैं। यानी आयकर रिटर्न भरने वाले 5.2 फीसदी भारतीयों में से 70 फीसदी लोग शून्य आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इसका मतलब है कि देश की आबादी का मात्र 1.6 फीसदी हिस्सा आयकर का भुगतान करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कर-राजस्व संग्रहण में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि न केवल आर्थिक गतिशीलता को, बल्कि कर प्रशासन की प्रभावशीलता और करदाताओं के अनुपालन को भी परिलक्षित करती है। सरकार ने एक फरवरी, 2024 को संसद में पेश संशोधित अनुमान में वित्त वर्ष 2023-24 में कर संग्रह का लक्ष्य बढ़ाकर 34.37 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। इसमें प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 19.45 लाख करोड़ रुपये था, जबकि अप्रत्यक्ष करों (जीएसटी, सीमा शुल्क) का लक्ष्य घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपये कर दिया था।

अजय बग्गा
आर्थिक मामलों के जानकार

वित्त वर्ष 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत ज्यादा है। संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने वाले भारतीयों की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 7.4 करोड़ हो गई है। यानी 140 करोड़ की आबादी वाले अपने देश में हर 19वां व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा है। लेकिन कटु सच्चाई यह है कि 7.4 करोड़ आयकर रिटर्न में से 5.16 करोड़ शून्य कर रिटर्न होते हैं। यानी आयकर रिटर्न भरने वाले 5.2 फीसदी भारतीयों में से 70 फीसदी लोग शून्य आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 2.24 करोड़ भारतीय, यानी आबादी का मात्र 1.6 फीसदी हिस्सा भारत में आयकर का भुगतान करता है।

इन रिटर्न दाखिल करने वालों के एक बड़े हिस्से को जांच और यहां तक कि रिटर्न दाखिल करने से छूट देना बेहतर हो सकता है और 1.6 फीसदी में से शीर्ष 10 फीसदी पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, जो वास्तव में आयकर चुकाते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि शून्य कर सीमा बढ़ाकर और इन सीमाओं से कम आय वाले लोगों को रिटर्न दाखिल करने से छूट देकर कर-प्रशासन लागत में कमी लाई जा सकती

है। वे संसाधन उन क्षेत्रों पर लगाए जा सकते हैं, जो उपभोग क्षमता होने के बावजूद कर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं।

दुनिया भर में और भारत में भी, हम देखते हैं कि जब कर की दर घटाई जाती है, तो कर संग्रह में वृद्धि होती है। इसे लाफर वक्र कहा जाता है। लाफर वक्र बताता है कि यदि कर-दर को एक निश्चित सीमा से ऊपर बढ़ाया जाता है, तो कर राजस्व में कमी आ सकती है, क्योंकि उच्च कर दर लोगों को काम करने से हतोत्साहित करती है। इसी तरह, करों में कटौती से उच्च कर राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसका एक उदाहरण यह है कि कुछ साल पहले कॉरपोरेट सीमांत कर दरों में कटौती करने के बाद कॉरपोरेट कर संग्रह में वृद्धि हुई। मध्यम वर्ग, विशेष रूप से वेतनभोगी कर दाताओं को ज्यादा राहत देने की जरूरत है, क्योंकि मुद्रास्फीति ने कर-दर के पिछले स्तर को काफी कम कर दिया है। इसी तरह 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को, जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं है, उच्च चिकित्सा बीमा और अन्य लागतों के लिए भत्ते दिए जाने चाहिए, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

आजादी के समय कल्याणकारी उपाय के तहत कृषि आय को आयकर से छूट दी गई थी, जो एक प्रशंसनीय कदम था। यह देखते हुए कि 60 फीसदी आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जीडीपी के 15 फीसदी पर निर्भर है, अधिकांश किसानों को व्यक्तिगत कर से छूट दी जानी चाहिए। हालांकि अमीर भूस्वामियों और कृषि मूल्य शृंखलाओं पर नियंत्रण रखने वाले अभिजात वर्ग की पहचान करने और उन पर कर लगाने की आवश्यकता है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग कृषि आय के तहत कर छूट का दावा करते हैं, जो और कुछ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग आय को कर-मुक्त करने का उपाय है। उन लोगों को भी कर के दायरे में लाने की जरूरत है, जो कराधान से दूर रहने के लिए कानूनी खामियों का लाभ उठाते हैं। अन्यथा यह 1.6 फीसदी करदाताओं के साथ अन्याय होगा।

वेतनभोगी लोग, जो वोटबैंक नहीं है, और इसलिए बहुत कम राहत मिलती है, उन्हें विशेष भत्ता दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि स्रोत के स्तर पर ही उनसे आयकर काटकर नियोक्ता सरकार के खाते में जमा कर देते हैं। एक वेतनभोगी व्यक्ति अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा (48 फीसदी) कर चुकाने में खर्च करता है। वेतनभोगी वर्ग को राहत देने से होने वाले कर-राजस्व के नुकसान की भरपाई अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि से की जा सकती, क्योंकि इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा और औपचारिक क्षेत्र की बचत से आर्थिक गतिविधि बढ़ सकती है। देश में खरीदारी करने वाला हर व्यक्ति उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और जीएसटी का भुगतान करता है।

वैश्विक स्तर पर औसत कर-जीडीपी अनुपात 14.4 है, जबकि ओईसीडी देशों के लिए यह 16.3 है। भारत का कर-जीडीपी अनुपात 12 है। छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र नाउरू में कर-जीडीपी अनुपात सबसे अधिक 48 है, जिसका अर्थ है कि सरकार देश की कुल अर्थव्यवस्था के लगभग आधे के बराबर कर एकत्र करती है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क में यह अनुपात 35 है।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य ने कराधान के संबंध में बहुत अच्छी सलाह दी है-कि इसकी गणना आसान होनी चाहिए, भुगतान सुविधाजनक होना चाहिए, कर-प्रशासन सस्ता होना चाहिए और इसका बोझ न्यायसंगत होना चाहिए। भारतीय कराधान आज 1.6 फीसदी करदाताओं पर भारी बोझ डालता है, जो कुल संग्रह का 27 फीसदी भुगतान करते हैं। जरूरत इस बात की है कि आबादी का बड़ा हिस्सा किफायती तरीके से कर चुकाए।

सरकार ने कर न चुकाने वाले वर्ग को कर दायरे में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। टीडीएस और टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि कई लेनदेन को उनके दायरे में लाया जा सके। कर विभाग अधिक खपत करने वाले, लेकिन कर न चुकाने वालों पर जीएसटी डाटा के माध्यम से अंकुश लगाने और उन्हें कर के दायरे में लाने में सक्षम है। उम्मीद है कि सरकारी तंत्र कर चोरों पर लक्षित कार्रवाई करके कर दायरे को बढ़ाने में सक्षम होगा। इससे अधिक बोझ वाले वर्गों को कर राहत देने के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनेगी। लेकिन ऐसा तभी संभव है, जब ज्यादा लोग करों का भुगतान करें।

जीवन धारा

श्री श्री रविशंकर

खुशी एक इंसान के लिए सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जब आप भीतर से स्वतंत्र महसूस करते हैं, तभी खुशी प्रकट होती है। जब हम अपने स्व से, अपने स्वभाव से दूर चले जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं।

स्वतंत्र महसूस करने पर ही खुशी प्रकट होती है

जब आप खुशी को नहीं जानते हैं, तो यह महज एक विचार है और जब आप इसे जानते हैं, तो यह आप ही हैं! खुशी एक इंसान की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जब आप भीतर से स्वतंत्र महसूस करते हैं, तभी खुशी प्रकट होती है। जब हम अपने स्व से, अपने स्वभाव से दूर चले जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि, यह विडंबनापूर्ण है कि खुद खुशी का स्रोत होने के बावजूद, हम इसे हर जगह ढूंढते रहते हैं।

हमें उन कारकों पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा पर्यावरण और तीसरा वित्त। चौथी है महत्वाकांक्षा। मान लीजिए कि हमारे पास पहले तीन हैं, लेकिन हम अति महत्वाकांक्षी हैं, तो यह हमारी स्थिति को उत्तेजित कर देगा।

इच्छा का अर्थ है भविष्य में इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से खुशी प्रदर्शित करना। यदि आप कहें कि जब आप सभी इच्छाओं से छुटकारा पा लेंगे, तब खुश होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है!

चुनौती अपनी गतिविधियों को छोड़े बिना खुश रहने की है। यह एक ऐसा कौशल है, जो सीखा जाता है। इसके लिए छोटे बच्चों से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। उनकी आकांक्षाएं होती हैं, फिर भी वे पल में खुश रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वही करते हैं, जो आवश्यक है, लेकिन उन तक ही सीमित नहीं रहते। उनका मन आसानी से एक चीज से दूसरी चीज पर जाता रहता है। हमें मन को इच्छानुसार निर्देशित करना और किसी भी चीज पर अटके न रहने की क्षमता विकसित करनी होगी।

खुशी एक दृष्टिकोण है, जिसे विकसित किया जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने संतोष या खुशी को एक नियम, एक व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में प्रतिपादित किया है। आपको खुद को खुशी के मूड में ढालना होगा। यह सिर्फ एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुशी के स्वभाव में बने रहने का प्रयास करना होगा। दुनिया की किसी भी चीज को अपनी खुशी में खलल न डालने देने का दृढ़ संकल्प विकसित करें। यही ज्ञान का उद्देश्य है।

यही वेदांत का मुख्य विषय है। कई संन्यासियों के नाम 'आनंद' से खत्म होते हैं। उनका नाम ही उन्हें याद दिलाता है कि वे आनंदमय हैं, वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं और अपने चारों ओर खुशियां फैलाने के लिए यहां हैं।

कोई भी मनुष्य अपने घर-परिवार या अड़ोस-पड़ोस से कटा नहीं रहता है। यदि परिवार में एक व्यक्ति दुखी है, तो इसका प्रभाव अन्य सभी सदस्यों पर पड़ता है। हम सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि खुशी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, पर यह हमारे पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है। जब अगली गली में दंगे हों, तो कोई भी खुश होने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना होगा।

खुशहाल समाज का लक्ष्य...

सूत्र

सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक निकायों का मुख्य लक्ष्य एक खुशहाल और स्वस्थ समाज बनाना होना चाहिए। यह केवल रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने से नहीं हो सकता। इसके लिए मानसिकता बदलनी होगी और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा। अपने वास्तविक स्वभाव में बने रहना ही स्थायी खुशी का एकमात्र मार्ग है।

दूसरा पहलू

परिधानों के बहुत ज्यादा उत्पादन और उपभोग को जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

फैशन की दुनिया का एक बदरंग चेहरा भी

पिछली सदी के नौवें दशक में एक नया चलन पैदा हुआ था, वह बेहद तेजी से बदलने वाले फैशन के साथ जीने का था। लोग नए से नए फैशन के साथ चलने लगे। लेकिन हो यह रहा है कि कपड़ों का भंडार बढ़ता जा रहा है, बेचा जा रहा है और जल्दी ही उसे निकाल दिया जा रहा है। यह चक्र वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा संकट बन गया है। हम ऐसे अल्ट्रा फास्ट फैशन की ओर जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की खपत और उनसे निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा बेहद ज्यादा है, जो बढ़ती ही जा रही है।

परिधानों के बहुत ज्यादा उत्पादन और उपभोग जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान दो डिग्री कम करने के लिए कपड़ा उद्योग को दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन कटौती में 26 फीसदी योगदान करना होगा। जाहिर है, फैशन उद्योग को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तेज से बेहद तेज फैशन की ओर बढ़ने के गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम होते हैं। इसमें श्रमिकों का ज्यादा शोषण होता है, जिसकी अनदेखी करना सामाजिक गलती होगी। इससे अधिक टिकाऊ फैशन उद्योग पर खतरा पैदा होता है। ऑस्ट्रेलियाई फैशन काउंसिल सीमलैस नाम से राष्ट्रीय उत्पाद प्रबंधन योजना का नेतृत्व कर रही है, जो वर्ष 2030 तक फैशन उद्योग को बदलने का वादा करती है। इसका लक्ष्य फैशन उद्योग को चक्रीय अर्थव्यवस्था में लाना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उत्पादन और उपभोग का ऐसा मॉडल है, जो सतत विकास को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है शून्य अपशिष्ट। ज्यादा टिकाऊ और जिम्मेदार फैशन उद्योग में बदलाव के लिए अल्ट्रा-फास्ट फैशन की व्यापक समझ, तत्काल व्यवस्थागत बदलाव और सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर्स एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान नेटवर्क का हिस्सा है, जो अल्ट्रा-फास्ट फैशन की जटिलताओं से निपटने के लिए काम करता है। इसमें श्रमिकों को बदतर कार्य स्थिति से बचाने, कचरे के निष्पादन और इस उद्योग को चक्रीय अर्थव्यवस्था में ढालने पर काम हो रहा है। साथ ही यह अध्ययन भी हो रहा है कि युवा पीढ़ी को कैसे टिकाऊ उपभोग की ओर प्रेरित किया जाए। सामूहिक पसंद में अपार शक्ति होती है। इसलिए अपनी फैशन आदतों के नतीजों को समझ कर और उनमें बदलाव करके हम फैशन उद्योग को टिकाऊ और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। (द

टेलर ब्राइजेस

वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान दो डिग्री कम करने के लिए कपड़ा उद्योग को कुल कार्बन उत्सर्जन कटौती में 26 फीसदी योगदान करना होगा। जाहिर है, फैशन उद्योग को भी जिम्मेदारी लेनी ही होगी।

अपनी फैशन आदतों के नतीजों को समझ कर और उनमें बदलाव करके हम फैशन उद्योग को टिकाऊ और न्यायपूर्ण बना सकते हैं।

आंकड़े

प्लास्टिक कचरे की रीसाइक्लिंग

वर्ष 2023 में ओईसीडी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे को भारत में रीसाइकल किया जाता है।

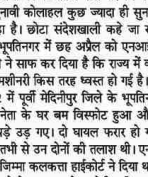

देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उनकी पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

प्रथम शैलपुत्री

अंतर्यात्रा
संकलित

प्रजापति दक्ष ने एक बार सभी देवी-देवताओं को अपने यहां होने वाले यज्ञ का निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। लेकिन देवी सती उस यज्ञ में जाना चाहती थीं। उन्होंने भगवान शिव से चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है और बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं होगा। पर सती ने जब बार-बार आग्रह किया, तो शिव ने जाने की अनुमति दे दी।

अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर पहुंचकर देवी सती ने देखा कि सिर्फ उनकी माता को छोड़कर कोई भी उनके साथ आदर और सम्मान से बातचीत नहीं कर रहा है। उनकी बहनें भी उनका मजाक उड़ा रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी उन्हें अपमानित किया।

देवी सती इस व्यवहार को सह न सकीं और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वह दुख और गुस्से में भर उठे और उस यज्ञ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।

इसी सती ने अगली बार हिमालय के घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ। मान्यता है कि माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

आज का इतिहास

अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अनशन समाप्त किया

आज के दिन का राजधानी में हुए एक चर्चित अनशन से गहरा नाता है, जिसने दिल्ली की सियासत की हवा ही बदल दी। सामाजिक कार्यकर्ता और देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अलख जगाने वाले अन्ना हजारे ने 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में धुआंधार तरीके से 95 घंटे से अनशन किया और 9 अप्रैल को अपने इस अनशन का समापन किया। 1669 : मुगल बादशाह औरंगजेब ने सभी हिन्दू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। 1860 : पहली बार मनुष्य की आवाज रिकार्ड की गई। 1965 : कच्छ के रण में भारत पाक में युद्ध छिड़ा। 1988 : अमेरिका ने पनामा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाये। 2001 : अमेरिकी एयरलाइंस ने ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस का औपचारिक रूप से अधिग्रहण किया और वह उस समय दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। 2003 : इराक को सद्दाम की तानाशाही से मुक्ति मिली। 2005 : प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला से विवाह किया।

आग से खेलतीं दीदी

बंगाल में एनआईए टीम पर हमले ने साफ कर दिया है कि ममता सरकार 'लाठी के जोर पर लोकतंत्र' की परिपाटी को हर हालत में कायम रखना चाहती हैं।

बिमल राय राजनीति

लोकसभा की 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में चुनावी कोलाहल कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ रहा है। छोटा संदेशखाली कहे जा रहे पूर्व मिदनापुर के भूपतिनगर में छह अप्रैल को एनआईए की टीम पर हमले ने साफ कर दिया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की मशीनरी किस तरह ध्वस्त हो गई है।

वर्ष 2022 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर में एक तृणमूल नेता के घर बम विस्फोट हुआ और तीन लोगों के चीथड़े उड़ गए। दो घायल फरार हो गए थे। एनआईए को तभी से उन दोनों की तलाश थी। एनआईए को जांच का जिम्मा कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था। कई बार समन भेजने के बावजूद ये आरोपी हाजिर नहीं हो रहे थे। सफाई देते हुए पांच अप्रैल की सभा में ममता ने उस विस्फोट को पटाखे का विस्फोट बताया। सवाल है कि क्या पटाखा फटने से शरीर के अंग डेढ़ किलोमीटर

दूर जा सकते हैं। हद तो तब हो गई, जब मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि लोगों ने वही किया, जो करना चाहिए था। बंगाल पुलिस ने तो एनआईए की टीम पर ही महिलाओं से छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया। संदेशखाली में ईडी के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगाकर स्थानीय थाने में केस दर्ज किया गया था, पर संभावित कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।

आरोप है कि एक भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने एनआईए के एसपी धनराजराम सिंह से उनके घर पर मुलाकात की। तृणमूल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रही है। वह इस चुनावी मौसम में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। अगर न्याय के लिए तृणमूल सरकार अदालतों की शरण में जाए, तो यह बात समझ में आती है, पर कई मामलों में वह डंडे के जोर पर लोकतंत्र चलाती हैं और अदालती आदेशों को भी ठेंगा दिखाती रही हैं। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर हाल ही में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया है। ममता सरकार ने संदेशखाली में कैंप लगाकर जिन लोगों की हड़पी गई जमीनें वापस लौटाईं, उन पर शाहजहां की गिरोह के दूसरे लेयर के उपद्रवी कब्जा नहीं करने दे रहे। आज भी पुलिस के असहयोग का आलम यह है कि बलात्कार पीड़ित महिलाएं घूंघट में आकर कलकत्ता हाईकोर्ट में बयान दर्ज करा रही हैं।

कई कारणों से सिर्फ बशीरहाट सीट का जनादेश पूरे बंगाल का भविष्य इंगित करेगा। इसी निर्वाचन क्षेत्र में संदेशखाली है, जहां की डरावनी कहानियां झकझोर देती हैं। हिंदी में ठीक-ठाक बात करने में सक्षम रेखा पात्रा को तृणमूल ने बाहरी मान लिया है। वैसे, तृणमूल हिंदी बोलने वालों को बाहरी ही कहती रही है। कुछ साल पहले आसनसोल में एक चुनावी सभा में ममता ने हिंदी भाषियों को अतिथि कहा था।

ऐसे माहौल में, भाजपा ने सही दांव चलते हुए संदेशखाली की पीड़िताओं को एकजुट करने वाली रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया, ताकि पूरे चुनाव में महिला सम्मान का विमर्श जिंदा रहे। ममता की बड़ी ताकत राज्य की 49 प्रतिशत महिला वोटर हैं। इस सीट पर तृणमूल ने मुस्लिम आबादी को देखते हुए एक बार सांसद रह चुके हाजी नुरुल इस्लाम को टिकट दिया है, जिन पर वर्ष 2010 में इसी इलाके में दंगे भड़काने का आरोप लगा था। अभी चार अप्रैल को उत्तर बंगाल की चुनावी सभा में ममता ने लोगों से कहा कि वे दंगा न करें, और दंगा न होने दें। रामनवमी से ठीक पहले यह संदेश जारी करने की क्या जरूरत थी?

बशीरहाट का बड़ा हिस्सा सुंदरबन के जंगलों व टापुओं पर बनी बस्तियों से घिरा है। यहां साढ़े 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें करीब 87 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 46.3 फीसदी मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति के करीब 25.4 प्रतिशत लोग हैं और रेखा पात्रा इसी समुदाय से हैं। पिछले दो महीनों से इलाके की महिलाओं के लक्ष्मी भंडार के रुपये खातों में नहीं आ रहे हैं। इन महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए पूछा कि क्या यह राशि तृणमूल दे रही है?

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 53 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

देशबन्धु

बिलासपुर, मंगलवार 9 अप्रैल 2024

संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

गज़ा में रक्तपात के छह महीने

गज़ा पर इजरायल के हमले को 6 महीने हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से इजरायल पर किए गए हमले के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। हमास ने इजरायल से 253 लोगों को बंधक बना लिया था। जिनमें से 130 अब भी बंधक हैं और कम से कम 34 की मौत हो चुकी है। अपने लोगों को छुड़ाने और हमास के खात्मे के नाम पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा पर आक्रमण किया था। इन छह महीनों में न हमास खत्म हुआ, न बंधकों की सुरक्षित रिहाई का कोई रास्ता निकला, लेकिन इस बीच गज़ा में खून की नदियां खूब बहीं। कम से कम 30 से 35 हजार लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 13 हजार से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, 12 हजार से ज्यादा बच्चे बुरी तरह घायल हैं, हजारों बच्चे विकलांगता का शिकार भी हो चुके हैं। गज़ा के आम लोग पिछले छह महीनों से लगातार आक्रमणों का सामना कर रहे हैं और इसके साथ उन्हें बीमारी, भुखमरी, लूटपाट इन सबका शिकार भी होना पड़ रहा है। गज़ा से जो तस्वीरें बाहर आती हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया में इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। इज़रायल केवल हमास को खत्म करने के नाम पर गज़ा पर बम और गोलियां नहीं दाग रहा, वो लोगों तक राहत सामग्री भी नहीं पहुंचने दे रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि उत्तरी गज़ा में फंसे 30 हज़ार लोग जनवरी से रोज़ाना औसतन 245 कैलोरी पर जी रहे हैं, जबकि सामान्य तौर पर महिलाओं के लिए 12 सौ से 24 सौ और पुरुषों के लिए 2 हजार से 3 हजार कैलोरी की जरूरत बताई जाती है।

निर्दोषों को मारना, बीमारों को इलाज की सुविधा से दूर करना, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण नहीं देना, पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचने से रोकना, ये सब इंसानियत के खिलाफ गंभीर अपराध हैं। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने इज़रायल पर जनसंहार के गंभीर इल्जाम भी लगाए हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में इज़रायल पर मुकदमा दायर किया गया है। लेकिन इज़रायल ने इन आरोपों से इंकार कर दिया है। इज़रायल के वकीलों में से एक टाल बेकर ने द हेग की अदालत में कहा कि इजरायल और फ़िलिस्तीन दोनों ओर नागरिकों को आज जिस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है वो हमास की रणनीति का नतीज़ा है। यानी इज़रायल यह मान रहा है कि गलती हमास की है, लेकिन फिर भी वो सजा आम लोगों को दे रहा है।

9 अक्टूबर को इज़रायल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने बीरशेहा में इज़रायली सेना की दक्षिणी कमान का दौरा करने के बाद कहा था, 'मैंने ग़ज़ा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी करने का आदेश दिया है। वहां न बिजली होगी, न खाना और ना इंसान रूपी जानवरों से लड़ रहे हैं, लिहाजा हम इसी के मुताबिक़ कदम उठाएंगे।' द.अफ्रीका की कानूनी टीम के मुताबिक गैलांट का बयान उनके जनसंहार के इरादे को ही दिखाते हैं।

इज़रायल जनसंहार के आरोपों से बचता है या उस पर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, फिलहाल इज़रायल ने जो रक्तपात मचाया है, उससे इज़रायल की जनता भी नाराज दिख रही है। इज़रायल में जनता लगातार सड़कों पर उतर रही है। बीते शनिवार को भी तेल अवीव, कैसरिया और हाइफ़ा की सड़कों पर आम लोगों ने प्रदर्शन किया और हमास की गिरफ्त में फंसे अपने लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए आवाज उठाई। इसके अलावा धर्म और राजनीति के नाम पर किए जा रहे अत्याचार को बंद करने की अपील भी की। आम जनता का एक बड़ा तबका नेतन्याहू से नाराज नजर आ रहा है। शनिवार के प्रदर्शन में कई लोगों ने हाथ में बैनर ले रखे थे, जिन पर लिखा था– 'नेतन्याहू इज़रायल के लिए खतरनाक हैं।' हाइफ़ा में प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को दोषी कहते हुए सरकार को तानाशाह बताया। कुछ बैनरों पर लिखा था– फौरन चुनाव कराओ, नेतन्याहू भगाओ।

इस बीच खबर आई कि इज़रायल ने दक्षिणी ग़ज़ा की ज़मीन पर लड़ रहे अपने सभी सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया है। लेकिन सैनिकों की यह वापसी युद्ध की एक रणनीति ही है क्योंकि इज़रायली सेना फिर से संगठित हो रही है और युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि वे जीत से बस एक क़दम दूर हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बिना बंधकों की रिहाई के ग़ज़ा में हो रहे इस युद्ध को नहीं रोका जाएगा।

इज़रायल को लगता है कि अब हमास का खात्मा वो कर देगा और अपने बंधकों को छुड़ा लेगा। हो सकता है अपनी सैन्य ताकत के दम पर इज़रायल छह महीने बाद बंधकों को छुड़ा भी ले, लेकिन इस दौरान मानवता पर क्रूरता और हिंसा के जो गहरे दाग इज़रायल ने लगाए हैं, क्या उन्हें किसी तरह मिटाया या छुड़ाया जा सकता है, यह गंभीर सवाल है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की चिंताओं और सवालों को अनसुना करते हुए नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि युद्ध रोका नहीं जाएगा। लेकिन क्या इस दावे में उनकी सनक वैसी ही नजर नहीं आ रही, जिस सनक में हिटलर ने लाखों यहूदियों को उजाड़ा था। गनीमत है कि इज़रायल की जनता यह समझ रही है कि धर्म और राजनीति का घालमेल ठीक नहीं है। नेतन्याहू का बढ़ता विरोध भी यह संकेत दे रहा है कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे और फिर चुनाव जब होंगे, तब तक नेतन्याहू जनाधार खो चुके रहेंगे। किसी भी किस्म की तानाशाही और क्रूरता हमेशा के लिए नहीं रहती है। हालांकि जब भी ये पनपते हैं, तो इनका खामियाजा आम जनता ही भुगतती है। जर्मनी से लेकर गज़ा तक यही कहानी बार–बार दोहराई जा रही है, लेकिन इंसान न इतिहास से सबक ले रहा है, न वर्तमान को सुधार कर भविष्य सुरक्षित कर रहा है।

न सब का साथ, न सब का विश्वास, विकास सिर्फ धन्नासेठों का

सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब का प्रयास' और 'सब को न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं।'

मोदी राज के ये नारे, झूठ बोलने में इस राज के दूसरे सभी नारों से भी आगे हैं। सच्चाई यह है कि यह झूठा नारा लगाते–लगाते, संघ–भाजपा ने स्वतंत्र भारत की धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धताओं को पलटते हुए, देश पर ऐसा राज थोपा है, जिसने अल्पसंख्यकों को तो ज्यादा से ज्यादा 'पराया' बनाया ही है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा दबाया है। इसका नतीजा अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों व ईसाइयों के खिलाफ तेजी से बढ़ते हमलों के साथ–साथ सभी वंचितों के खिलाफ बढ़ते हमलों के रूप में सामने आ रहा है। इसीलिए, तो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ताजातरीन यानी 2022 के आंकड़े, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के खिलाफ अपराधों तथा अत्याचारों में तो बढ़ोतरी दिखाते ही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी पूरे 4 फीसद बढ़ोतरी दिखाते हैं।

ईसाई धार्मिक स्थलों तथा शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ आम हमलों के अलावा, आदिवासी इलाकों में ईसाई आदिवासियों के खिलाफ संघ परिवार द्वारा विशेष रूप से हमलावर अभियान चलाए जा रहे हैं। आदिवासियों पर हिंदू धार्मिक तौर–तरीके थोपने की कोशिश करने के अलावा, जिसका आदिवासियों का एक हिस्सा प्रतिरोध भी कर रहा है, ईसाई आदिवासियों का अनूसूचित जाति का दर्जा समाप्त करने की मांग का अभियान भी अब इस मुद्दे का एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया है। वास्तव में आदिवासियों के अनुसूचित जाति के दर्जे को खत्म कराने के इसी हथियार का, मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई उग्रवादियों द्वारा कुकी समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि उत्तर–पूर्व के इस संवेदनशील राज्य में मैतेई तथा कुकी समुदायों के बीच के इथनिक विभाजन को, हिंदू–ईसाई टकराव के रूप में तब्दील करने की, मौजूदा शासन तथा संघ परिवार की राष्ट्रविरोधी कोशिशों के चलते ही, मणिपुर दस महीने से ज्यादा से जल रहा है।

इसीलिए, हैरानी की बात नहीं है कि प्यू रिसर्च सेंटर के धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को दर्शाने वाले 'सोशल होस्टिलिटीज इंडैक्स' पर, भारत को 'बहुत ऊंचा' की श्रेणी में रखा गया है, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के साथ सबसे ऊपर। और इस सूचकांक पर 2019 और 2020 के बीच, हालात का और बिगडऩा भी दर्ज किया गया है। नौबत यह है कि नरसंहार या होलोकॉस्ट के खतरों पर नजर रखने वाली संस्थाओं/ विशेषज्ञों ने भारत के नरसंहारों की कगार पर पहुंच जाने की चेतावनियां देना भी शुरू कर दिया है। जाहिर है कि इसका रास्ता, नफरती बोल–वचन के बढ़ते प्रकोप से बन रहा है और इसे केंद्र तथा अनेक राज्यों में सत्ता में बैठी भाजपा की खुली शह ने, एक महामारी ही बना दिया है। इसी की पूरक है फेक न्यूज की महामारी। इसके मामले में तो गज़ा में इज़रायली नरसंहार के बीच यह तथ्य भी सामने आया है कि मौजूदा निजाम की शह पर भारत, दुनिया भर की मुस्लिम/ इस्लामद्वेषी फेक न्यूज की राजधानी तो पहले ही बन भी चुका है।

एक और झूठा दावा बार–बार दोहराया जाता है कि मोदी के राज में कोई दंगे नहीं होते। इस झूठे दावे से वे दो मकसद साधने की कोशिश करते हैं। एक, कानून–व्यवस्था के मोर्चे पर मोदी राज की छवि चमकाना। दूसरे, यह दिखाना कि मोदी से पहले रहे उन शासनों में ही दंगे होते थे, जिन्हें वे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाले शासन बताते हैं। यानी दंगे अल्पसंख्यकों को छूट दिए जाने की वजह से ही होते हैं और मोदी राज ने और भाजपा की राज्य सरकारों ने, 'सख्ती' का रुख अपनाकर रोक दिया है! उत्तर प्रदेश के भाजपायी मुख्यमंत्री, आदित्यनाथ ने तो राज्य में 2017 से 2021 के बीच 'एक भी दंगा नहीं होने' का ही दावा कर दिया था।

लेकिन, यह सफेद झूठ है। मोदी राज में तमाम सरकारी आंकड़ों से की गयी छेड़छाड़ के हिस्से के तौर पर, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को कम कर के दिखाने की कोशिश किए जाने के बावजूद, उपलब्ध सरकारी आंकड़े भी यही कहते हैं कि मोदी राज में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं लगातार और अच्छी–खासी संख्या में होती रही हैं। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री, नित्यानंद राय ने 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में यह जानकारी दी थी कि 2017 से 2021 तक, मोदी राज के पांच साल में सांप्रदायिक हिंसा की 2,900 घटनाएं दर्ज हुई थीं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, मोदी राज के पहले तीन वर्षों में यानी 2014 से 2016 तक ऐसी हिंसा की 2,885 घटनाएं दर्ज हुई थीं। दूसरी ओर, 2022 में भी 272 घटनाएं दर्ज हुई थीं। यूनाइेड क्रिश्चियन फोरम ने 2023 के पहले छ: महीने में ही ईसाईविरोधी हिंसा के 525 मामले दर्ज किए थे।

लेकिन, ये संख्याएं तो सिर्फ भाजपा राज में कोई दंगा नहीं होने का झूठा होना ही दिखाती हैं। वास्तविक स्थिति इससे बहुत भयानक है। 2020 की फरवरी के उत्तर–पूर्वी दिल्ली के दंगे, 2023 की जुलाई के हरियाणा के नूह के दंगे और 2024 के उत्तराखंड में हल्द्वानी के दंगे, इस कड़ुवी सच्चाई को दिखाते हैं कि भाजपा के राज में पुलिस–प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमविरोधी सांप्रदायिक दमन के हथियार में तब्दील किया जा रहा है। और प्रशासन के खुद दंगाई की भूमिका संभाल लेने से, जाहिर है कि बाकायदा दंगों की जरूरत बेशक कुछ कम हो जाती है। अल्पसंख्यकों पर हमले और दमन को, बेशर्मी से राजकीय कार्रवाई का रूप देकर छुपाया जा सकता है।

दूसरी ओर, सांप्रदायिक हिंसा का इकतरफापन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बंगाल व अन्य कई राज्यों में, कथित हिंदू नव वर्ष से लेकर, राम नवमी तथा हनुमान जयंती तक के बहाने से, भड़काऊ जुलूस निकालकर, सरासर इकतरफा हिंसा की गयी है और पुलिस–प्रशासन द्वारा पूरी तरह से इकतरफा कार्रवाइयां की गयी हैं। इनमें भाजपा सरकारों की बुलडोजर कार्रवाइयां भी शामिल हैं।

वास्तव में मोदी के राज में बुलडोजर को बहुसंख्यकवादी सरकारी जोर–जब्र की निशानी ही बना दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में ऐसी 128 कार्रवाइयों को दर्ज किया गया है, जिनमें 600 लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें ज्यादातर मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया गया है। ऐसी सबसे ज्यादा 56 कार्रवाइयां भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दर्ज हुई हैं। गुजरात की भाजपा सरकार के गृहमंत्री ने पिछले ही दिनों बाकायदा विधानसभा में गर्व के साथ ऐलान किया कि, '108 मजारें ध्वस्त हो चुकी हैं। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री का बुलडोजर घूम रहा है।'

यह यकायक नहीं हो गया है। इन दस वर्षों में सिर्फ प्रकटत: धार्मिक मुद्दों को लेकर ही नहीं, गोरक्षा, लव जेहाद, धर्मांतरणविरोध, आबादी विस्फोट की चिंता, धारा–370 का खात्मा, समान नागरिक संहिता, नागरिकता अधिकार संशोधन आदि, आदि के नाम पर, तुष्टीकरण विरोध के झूठे नारे की आड़ में, जिस तरह एक के बाद एक अल्पसंख्यकविरोधी तथा सबसे बढ़कर मुस्लिमविरोधी अभियान छेड़े गए हैं, उन्हीं के सहारे देश मौजूदा हालात तक पहुंचा है। सिख अल्पसंख्यक तक इन अभियानों से अछूते नहीं रहे हैं और अपने ऊपर हिंदू पहचान थोपे जाने के खिलाफ, पृथक धार्मिक समुदाय के रूप में अपनी पहचान की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। सत्ताधारी संघ परिवार की हिंदू राष्ट्र की पुकारों और शासन के हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक अमल से, हाशिए पर पड़ी सिख अलगाव की धाराओं को भी बल मिल रहा है।

उत्तराखंड में कथित समान नागरिक कानून के जरिए एक ही झटके में, मुस्लिम निजी कानून को अवैध और उनके पालन का अपराध बना दिया गया है। यह भी वर्तमान शासन के मुस्लिम–द्वेष का ही उदाहरण है कि उच्च शिक्षा में मुसलमानों के पिछड़ेपन को कम करने के लिए, यूपीए के राज में जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप शुरू की गयी थी, उसे बंद करने के बाद, अब मोदी सरकार ने मौलाना आजाद फाउंडेशन को भी भंग कर दिया है। यह कार्रवाई इतनी मनमानी की है कि इसे अदालत में भी चुनौती दी गयी है।

इन्हीं हालात का एक और महत्वपूर्ण संकेतक है— बढ़ती सांप्रदायिक भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग। गोरक्षा के नाम पर और लव जेहाद के विरोध के नाम पर, संगठित भीड़ हिंसा में विशेष तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2014 से अगस्त 2022 के बीच, गाय के नाम पर हिंसा के 206 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 850 लोग प्रभावित हुए। इनके शिकारों में दलित व ईसाई भी शामिल हैं, किंतु 86 फीसद हिस्सा मुसलमानों का ही था। ऐसी 97 फीसद घटनाएं मोदी राज आने के बाद ही हुई थीं। गो तस्करी के नाम पर पहलू खान और घर पर गाय का मांस रखने के नाम पर अखलाक की भीड़ हत्याओं से शुरू हुआ यह सिलसिला न सिर्फ लगातार जारी है, इन हिंसक गिरोहों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका सबूत 2023 के शुरू में हरियाणा में हुआ भिवानी का नासिर–जुनैद हत्याकांड है। गोकुशी और गोमांस के मामले में भाजपा के रुख का दोमुंहापन हैरान करने वाला है। जहां राजनीतिक–चुनावी स्वार्थ इसकी मांग करते हैं, जैसे गोवा में, उत्तर–पूर्व के राज्यों में, यहां तक कि केरल जैसे राज्यों में भी, भाजपा गोकुशी के मुद्दे पर चुप साधने से लेकर, गोमांस सस्ता, सुलभ कराए जाने की मांग उठाने तक चली जाती है। और उत्तरी भारत में वही भाजपा, गोरक्षा के नाम पर अपने गुंडादलों द्वारा हिंसा, यहां तक कि लिंचिंग तक का बचाव करती है।

यह सब हो रहा है मोदी राज में शासन के शीर्ष से धर्मनिरपेक्षता का एक तरह से त्याग ही कर के, शासन का हिंदुत्वकरण किए जाने से। अयोध्या में राम मंदिर के शिलापूजन में प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य यजमान बनने से इसके प्रत्यक्ष संकेत दिए जाने की औपचारिक शुरूआत हुई थी और इसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूरी तरह से शासन प्रायोजित ईवेंट में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया गया। और संसद से मोहर लगवा कर, बहुसंख्यकों के इस धार्मिक आयोजन को, बाकायदा राष्ट्रीय आयोजन बना दिया गया। इससे पहले, सेंगोल की संसद में स्थापना के जरिए भी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया था।

इसी सब के पूरक के रूप में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में और उत्तर–पूर्व को छोड़कर अधिकांश विधानसभाओं में अपना, मुस्लिम–ईसाई अल्पसंख्यक मुक्त होना सचेत रूप से सुनिश्चित किया है। इसी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा घोषित पहली सूची में, 195 उम्मीदवारों में सिर्फ एक मुसलमान था और वह भी केरल से, जहां उनके उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं न्यूनतम हैं। इन हालात में अगर शासन तंत्र बहुसंख्यकवादी रास्ते पर बढ़ता जा रहा है, तो इसमें अचरज की बात नहीं है।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

राजेंद्र शर्मा

उत्तराखंड में कथित समान नागरिक कानून के जरिए एक ही झटके में, मुस्लिम निजी कानून को अवैध और उनके पालन का अपराध बना दिया गया है। यह भी वर्तमान शासन के मुस्लिम–द्वेष का ही उदाहरण है कि उच्च शिक्षा में मुसलमानों के पिछड़ेपन को कम करने के लिए, यूपीए के राज में जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप शुरू की गयी थी।

इलेक्ट्रिक वाहन के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा 2024

■ के रवीन्द्रन

वर्ष 2024 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रांति में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करने के लिए तैयार है। पर्यावरणीय चिंताओं, सख्त नियमों और तकनीकी प्रगति से प्रेरित, ईवी बाजार में विस्फोटक वृद्धि हो रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर परिवहन परिदृश्य बदल रहा है। इस परिवर्तन में सबसे आगे चीन खड़ा है, एक ऐसा देश जिसने रणनीतिक रूप से खुद को ईवी उद्योग में निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया है।

चीन का प्रभुत्व अनेक कारकों के संगम से उत्पन्न होता है। उदार सब्सिडी और आक्रामक उत्पादन लक्ष्य जैसी सरकारी नीतियों ने एक जीवंत घरेलू ईवी बाजार का पोषण किया है। बीवाईडी और एनआईओ जैसे चीनी निर्माताओं ने इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाया है, अनुसंधान और विकास में संसाधन लगाए हैं, और आकर्षक मूल्य बिंदुओं पर प्रतिस्पर्धी ईवी की एक विविध श्रृंखला तैयार की है। सामर्थ्य पर यह ध्यान विशेष रूप से सफल साबित हुआ है, जिससे ईवी चीनी आबादी के व्यापक हिस्से के लिए सुलभ हो गई है।

परिणाम? चीन वैश्विक ईवी बाजार में जबरदस्त हिस्सेदारी का दावा करता है। 2023 में, सभी नई ईवी बिक्री में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 69फीसदी थी। बीवाईडीटेस्ला को पछाड़कर दुनिया की अग्रणी ईवी निर्माता बन गई है। यह प्रभुत्व घरेलू सीमाओं से परे तक फैला हुआ है।

पिछले साल की गति पर सवार होकर, चीनी वाहन निर्माता आक्रामक रूप से उभरते बाजारों में विस्तार कर रहे हैं, तथा वे स्थापित खिलाड़ियों पर भारी पड़ रहे हैं। यह बदलाव विशेष रूप से यूरोप में स्पष्ट है, जहां एक स्थिर ईवी बाजार को बजट–अनुकूल चीनी ब्रांडों के आगमन में आशा मिलती है। चीनी ईवी निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। बीवाईडी और एसएआईसी जैसी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों पर अपनी नजरें जमा रही हैं। यहां, चीन के मजबूत आर्थिक संबंध और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के लिए उसका जोर एक विजयी फॉर्मूला साबित हो रहा है।

हालांकि, चीन का नेतृत्व चुनौतियों से रहित नहीं है। तीव्र वृद्धि ने आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है। लिथियम और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण सामग्री की कमी से उत्पादन बाधित होने का खतरा है, जबकि बैटरी रीसाइक्लिंग और इन संसाधनों के खनन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी ईवी निर्माताओं के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा से मूल्य युद्ध हो सकता है। इससे संभावित रूप से लाभ मार्जिन कम हो सकता है और दीर्घकालिक स्थिरता में बाधा आ सकती है।

इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में स्थापित वाहन निर्माता आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पारंपरिक कार कंपनियां विद्युतीकरण में भारी निवेश कर रही हैं। वे अपने स्वयं के ईवी प्लेटफॉर्म विकसित करने में संसाधन लगा रही हैं और बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही हैं। आगामी 2024 अमेरिकी चुनाव ईवी नीतियों के लिए एक युद्ध का मैदान होने की उम्मीद है, जिसमें संभावित सरकारी प्रोत्साहन अमेरिकी ईवी बाजार के भविष्य को आकार देंगे। यूरोप में, सख्त उत्सर्जन नियम कार निर्माताओं को मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ, अपने ईवी रोलआउट में तेजी लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

जहां एक ओर चीन और स्थापित खिलाड़ी वर्तमान कथा पर हावी हैं, दावेदारों की एक नई लहर उभर रही है। भारत, जिसका बढ़ता मध्यम वर्ग और कुख्यात प्रदूषित परिवहन क्षेत्र ईवी के लिए एक विशाल अप्रयुक्त बाजार प्रस्तुत करता है। भारत सरकार फेम योजना जैसी पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा दे रही है, जो ईवी खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसे प्रमुख भारतीय कार निर्माता तेजी से ईवी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हाल के महीनों में मारुति सुजुकी ईवी एक्स और टाटा नेक्सॉन ईवी जैसे नए मॉडल बाजार में आए हैं।

हालांकि, भारत की ईवी महत्वाकांक्षाओं को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उच्च अग्रिम लागत व्यापक रूप से अपनाने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है, खासकर दोपहिया ईवी के लिए, जो भारतीय बाजार पर हावी है। इसके अतिरिक्त, मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में, संभावित खरीदारों के बीच चिंता पैदा करती है।

इन चुनौतियों के बावजूद, विश्लेषक भारत के ईवी भविष्य को लेकर आशावादी हैं। आने वाले वर्षों में बाजार में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, पूर्वानुमान के अनुसार 2025 तक 6 फीसदी से अधिक की संभावित बाजार हिस्सेदारी होगी। इस उभरते उद्योग की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। सब्सिडी और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से निरंतर सरकारी समर्थन महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त , विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को आकर्षित करना, विशेष रूप से बैटरी विनिर्माण की दिशा में, एक मजबूत घरेलू ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक होगा।

सबसे बड़ी बाधा सामर्थ्य बनी हुई है। सरकारी सब्सिडी के बावजूद, ईवी अभी भी अपने गैसोलीन–संचालित समकक्षों की तुलना में काफी अधिक महंगे हैं। यह विशेष रूप से दोपहिया ईवी के लिए सच है, जो भारतीय बाजार पर हावी हैं। जब तक बैटरी की लागत कम नहीं हो जाती और ईवी पारंपरिक वाहनों के साथ मूल्य समानता तक नहीं पहुंच जाते, तब तक व्यापक रूप से इसे अपनाना एक चुनौती बनी रहेगी।

एक और प्रमुख चिंता है मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी, खासकर प्रमुख शहरों के बाहर। यह संभावित खरीदारों के बीच 'रेंज चिंता' पैदा करता है, जो चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने से पहले बिजली खत्म होने की चिंता करते हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहु–आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की तेजी से स्थापना, सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और बैटरीस्वैपिंग प्रौद्योगिकियों जैसे नवीन समाधानों की खोज करना शामिल है।

भारत की ईवी महत्वाकांक्षाओं को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उच्च अग्रिम लागत व्यापक रूप से अपनाने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है, खासकर दोपहिया ईवी के लिए, जो भारतीय बाजार पर हावी है। इसके अतिरिक्त, मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में, संभावित खरीदारों के बीच चिंता पैदा करती है।

पावन प्रसंग

हिंदू नव वर्ष की सार्थकता वैज्ञानिकों ने भी मानी

भारतीय पंचांग के अनुसार हमारा नया साल प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। इस दिन हम नए विक्रम संवत का आगाज करते हैं। भारतीय काल गणना के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों के पीछे कोई न कोई प्रेरणा विद्यमान है। हम यह भी जानते हैं कि हिंदी पंचांग के अंतिम माह फाल्गुन का वातावरण हमें वर्ष समाप्ति का संकेत देता है साथ ही यह भी देखने में आता है कि नव वर्ष के प्रथम दिन से ही प्रकृति का वातावरण सुखद होने लगता है। हमें गर्व है अपने ऋषि–मुनि और संतों पर जिन्होंने ऐसी काल गणना विकसित की, जिसमें कब क्या होना है? इन तथ्यों की संपूर्ण जानकारी समाहित है।

नव वर्ष के संदर्भ में महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही दिन –मास– वर्ष और युगादि का प्रारंभ माना है। इतिहास उठाकर देखा जाए तो युगों मे प्रथम युग सतयुग का शुभारंभ भी इसी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हुआ था। कल्पयादि–सृष्टियादि– युगादि आरंभ को लेकर इस दिवस के साथ प्राचीनता का इतिहास मिलता है। सृष्टि की रचना को लेकर भी ऋषि–मुनियों तथा वैदिक गणित के विद्वानों ने इसी दिवस की गणना की है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है–

चैत्र–मासि जगदब्रह्म, ससर्ज प्रथमेहनी।
शुक्ल–पक्षे समग्रे तु,सदा सूर्योदये सति।।

विभिन्न ग्रहों, चंद्रमा एवं सूर्य की गति एवं दिशाओं का उतनी प्रामाणिकता के साथ निर्धारण करता है, जितना कि आज का आधुनिक सैटेलाइट। हिंदू नव वर्ष में रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। ठंड की समाप्ति और ग्रीष्म का प्रारंभ अत्यंत ही मधुर व आनंददायक आगमन का अनुभव देता है। पतझड़ समाप्त होता है और बसंत ऋतु के आगमन का आगाज होने लगता है। प्रकृति में हर जगह हरियाली छा जाती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे प्रकृति ने नव श्रृंगार किया हो। चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन का सूर्योदय ही हमारे नए वर्ष का उदय है। यह बिना किसी संशय के कहा जा सकता है कि बिना पंचांग और कैलेंडर के, प्रकृति और आकाश को पढ़कर हिंदू धर्मावलंबी अपने नए वर्ष को पा लेते हैं। भारतीय नव वर्ष को ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ नया वर्ष नहीं कहा जाता है। इसके पीछे की सार्थकता ही इसे महान बनाते हुए वैज्ञानिकता से जोड़ती है। हमारे नव वर्ष को ही सृष्टि रचना का प्रथम दिन माना जाता है। हमारे दुर्लभ ग्रंथों में यह बात सामने आती है कि इसी दिन से 1 अरब 97 करोड़ 39 लाख 49 हजार 109 वर्ष पूर्व सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। विक्रमी संवत का पहला दिन उस राजा के नाम पर प्रारंभ किया जा सकता था जिसके राज्य में न कोई चोर हो, न अपराधी हो और न ही कोई भिक्षुक हो साथ ही वह राजा चक्रवर्ती सम्राट हो। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य ने 2080 वर्ष पूर्व इसी दिन राज्य की स्थापना की थी। हमें धर्म शास्त्र बताते हैं कि इसी दिन मर्यादा पुरषोत्तम भगवान श्रीराम का लंका विजय के बाद राज्याभिषेक किया गया था। समाज को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने हेतु भी इसी दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणावतार संत झूलेलाल का प्रकटोत्सव दिवस भी पूरे समाज को आनंदित करता आ रहा है। आकाश में ग्रहों की स्थिति सूर्य से प्रारंभ होकर क्रमश: बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि की है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा सहित इन्हीं अन्य छह ग्रहों पर सप्ताह के सात दिनों का नामकरण किया गया। यह हमारे भारतीय पंचांग की विशेषता कही जा सकती है कि तिथि घटे या बढ़े किंतु सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होगा और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। इसमें कभी कोई अंतर आ ही नहीं सकता है।

सनातनी नव वर्ष को लेकर महान दार्शनिक और संत विवेकानंद जी ने कहा है–यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है, अपने अंतर्मन में राष्ट्रभक्ति के बीज को पल्लवित करना है तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। गुलाम बनाए रखने वाले लोगों की दिनांकों पर आश्रित रहने वाला अपना आत्म गौरव खो बैठता है। हिंदू नव वर्ष का दिन हमारे मन में यह उद्घोष जगाता है कि हम पृथ्वी माता के पुत्र हैं। सूर्य, चंद्र तथा नवग्रह हमारे आधार हैं। प्राणी मात्र हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। यही कारण है कि हमारी संस्कृति का बोध वाक्य 'वसुधैव कुटुंबकम्' को सार्थकता प्रदान करता है।

सूर्यकांत मिश्रा

आपके पत्र

वर्तमान में प्रगतिशील साहित्य का औचित्य

9 अप्रैल सन् 1936 प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना दिवस है। इसे प्रगतिशील साहित्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सन् 1936 लखनऊ में 9–10 अप्रैल को प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। जबकि इसका अंकुरण लंदन में 7–8 भारतीय छात्रों की टोली, जिसमें मुल्क राज आनंद और सज़्ज़ाद ज़हीर प्रमुख थे, ने कर लिया था जिसका मूल उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फ़ासिज़्म से संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व भर के संस्कृति कर्मियों को लामबंद करना था। इससे पूर्व सन् 1934 में रूस में सोवियत संघ तथा 1935 में पेरिस में विश्व लेखक अधिवेशन हुआ जिसने इन छात्रों को प्रेरणा दी। भारत में इस संगठन के जन्मते ही इसे विदेशी संगठन कहकर प्रतिक्रियावादियों ने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से साहित्य के क्षेत्र में जो नई सोच उत्पन्न हुई उसमें मज़दूर, किसान के अलावा आम शोषित, दलित, पीड़ित सब शामिल हो गये जिससे स्वाधीनता आन्दोलन को भी बल मिला।

वहीं दूसरी ओर प्रेमचंद को रूढ़िवादी लेखकों ने घृणा का प्रचारक एवं ब्राह्मण निंदक घोषित कर दिया मगर हंस, प्रभा एवं रूपाभ जैसी पत्रिकाओं ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कवि,लेखक, कथाकार,समीक्षक बड़ी संख्या में प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर तले आ गये। वहीं कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, सरोजनी नायडू आदि प्रसिद्ध नेताओं ने भी प्रगतिशील लेखक संघ का दिल से स्वागत किया।

प्रगतिशील लेखक संघ के बनने के बाद साहित्य का स्वरूप बदला, उर्दू शायरी भी इससे अछूती नहीं रही। वह आशिक–माशूका के दायरे से निकलकर आम जनता की दिक्कतों,उसकी लड़ाई, दुखदर्द को अपने में समेटने लगी तथा पीड़ित, शोषित वर्ग को सजग बनाकर हौसला अफ़ज़ाई करने लगी। कविता के क्षेत्र में भी जबरदस्त परिवर्तन आया, छंदबद्धता की बाधा को निराला ने तोड़ना शुरू किया,भावों की जगह विचारों ने ली। जीवन की सच्चाईयां एवं विरोध के स्वर लेखन में उभरे तथा अलंकरणों का स्थान विम्बों ने लिया।

प्रगतिशील लेखक संघ के गतिशील होने के बाद जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां यथार्थ रूप में मुखर होने लगीं यह बदलाव संपूर्ण देश की भाषाओं में लिखे साहित्य में भी साथ–साथ आया साहित्य अब विरोध की सार्थक अभिव्यक्ति बन एक आंदोलन के रूप में आ गया था जिसमें शोषणमुक्त भारत ही मूलत: प्रगतिशील लेखन का स्वप्न था।

लेकिन आज़ादी के बाद भी जब परिदृश्य नहीं बदला सरकार आम जन की पीड़ा के साथ नज़र नहीं आई, तो सरकार से इन लेखकों का मोहभंग हुआ और तत्कालीन लेखकों ने शासन की रीति–नीति के विरुद्ध लिखना प्रारंभ किया जो उनका दायित्व था। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, हरिशंकर परसाई से प्रारंभ हुआ यह लेखन एक बार फिर समूचे देश में शुरू किया गया जो वर्तमान में अभी तक जारी है लेकिन दक्षिण पंथी विचारों वाली सरकार के चलते आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ख़तरे में है, सरकार विरोधी लेखन निशाने पर है हमारे पांच प्रगतिशील विचारक डा. नरेंद्र दाभोलकर, कामरेड गोविंद पानसरे,डा. एमएम कलबुर्गी और संपादक गौरी लंकेश की जिस तरह हत्या की गई वह ना केवल चिंतनीय है बल्कि प्रगतिशील सोच पर विराम लगाने की एक सोची समझी साज़िश लगती है।

हालांकि इस समय संसार की प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी शक्तियों में अनवरत यह संग्राम चल रहा है। पूंजीवादी संकट आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों को लीलता जा रहा है। फलस्वरूप साहित्य, कला, दर्शन तथा विज्ञान में भी विकृतियां नज़र आ रही हैं। आज के साहित्य में विशेषकर निराशावादी, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी स्वभाव की बाढ़ , तरह–तरह के आदर्शवादी मतों का प्रचार, रहस्यवाद के गड़े मुर्दों में पुन: जान डालने की कोशिश तथा वैज्ञानिक मतों को झुठलाने की मुहिम चल रही है। ऐसे हालात में क्या हम मीरा की तरह प्रेम दीवाने बनकर गरल पान करते रहेंगे या तुलसी की तरह–कोई नृप होहि हमहू का हानि की रट लगाए रहेंगे?

–सुसंस्कृति परिहार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग भी संजीदगी दिखाएं

सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकारों में वर्णित समानता और जीने के अधिकार (अनुच्छेद 14 और 21) में शामिल मानने का फैसला देकर सरकार को इसके लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि संकट देखते हुए देश को तत्काल 'एनर्जी मिक्स' में सौर ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा। इसके पहले इसी कोर्ट ने जीने के अधिकार में, सम्मान से जीने के अधिकार को शामिल किया था, लेकिन पहली बार इस कोर्ट ने ऐसे संकट पर अपना फैसला दिया है। यानी कोर्ट ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में वर्णित पर्यावरण संरक्षण (जिसमें जंगलों और जीव-जंतुओं की रक्षा भी शामिल है) को नागरिकों के मौलिक अधिकार का अंग माना है। लेकिन कोर्ट को यह नहीं भूलना होगा कि जिम्मेदारी सिर्फ राज्य की नहीं नागरिकों की भी है। नागरिकों को भी ऐसी चेतना को बाध्यकारी बनाना होगा। मोटर चलाकर पानी से कार धोने व लॉन सींचने वाले, बेवजह दफ्तरों-बंगलों में एसी चलाने वाले, पानी जैसे खत्म होते वाले स्रोत को अवैज्ञानिक तरीके से खेतों में बहाने वाले, बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलने वाले भी यह समझें कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण उनका संवैधानिक कर्तव्य है। दुनिया में बिजली खपत में 10% और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 4% योगदान वातानुकूलन का रहता है। क्या अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संपन्न वर्ग इस बात की शपथ लेगा कि वह यथासंभव विलासिता के जीवन से बचकर ऊर्जा खपत को कम करेगा? एसी के इस्तेमाल से कई प्रदूषक वातावरण में फैलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए सरकार को प्रदूषण पैदा करने वाले ऐसे कारक, जो विलासिता के कारण और गैर-जिम्मेदाराना होते हैं, उन पर कार्बन टैक्स लगाना शुरू करना चाहिए।

प्रेरणा

हम सबको बस ये तय करना है कि मिले हुए समय का किस तरह इस्तेमाल करें। - **जे आरआर टॉकीन, लेखक**

बामुलाहिजा • मोदी को सत्ता से बेदखल करने का यकीन खुद विपक्ष को नहीं है...

भाजपा के आंकड़ों में ही उलझ गया विपक्ष

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
𝕏@ShekharGupta

2024 के चुनावी रणबांकुरे जब अपने-अपने घोषणा पत्रों के साथ तैयार हो चुके हैं, तब जनमत सर्वेक्षणों की पहली खेप भी सामने आ चुकी है। टीवी समाचार चैनलों के प्रति भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों का जो यह संशय भाव है कि 'इन लोगों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं', उसे मैं समझता हूं लेकिन विश्लेषण के लिए कुछ आंकड़े हों तो बेहतर है। कुछ ढाबों पर और तीन टैक्सी ड्राइवरों से बात करके नतीजों की भविष्यवाणी करने वाले हम जैसे पत्रकारों और चुनावी पंडितों पर ही छोड़ दें तो हम अपने पसंदीदा लोगों की जीत की घोषणा करके निश्चिंत हो सकते हैं। और असली नतीजे अलग आए तो दोष देने के लिए ईवीएम तो है ही! लेकिन हकीकत यह है कि यह बताने के लिए आपका कोई चुनावी पंडित होना जरूरी नहीं है कि इस बार मुकाबले में भाजपा काफी आगे है। महत्वाकांक्षी विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने एकजुट बने रहने की पूरी कोशिश की है लेकिन भाजपा ने भी एनडीए को पुनर्गठित किया है। दलगत प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, मगर विपक्षी दलों के अंदर भी बातें यही होती हैं कि नरेंद्र मोदी की सीटें कहां-कहां से कम की जा सकती हैं, यह नहीं कि उन्हें सत्ता से कैसे बेदखल किया जा सकता है।

मुकाबले का माहौल फिलहाल कुछ ऐसा ही है। हालांकि विपक्ष को लगता है कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित खुलासों के कारण उसके पक्ष में हवा कुछ मजबूत हुई है। और भाजपा को 'वॉशिंग मशीन' बताने वाले नारे में भी दम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतने प्रभावशाली हैं कि विपक्ष की तकदीर बदल देंगे? अधिकतर विपक्षी नेता तस्वीर को ज्यादा संतुलित नजर से देख रहे होंगे। यह कि मोदी को वाजिब आंकड़े में कैसे 'समेटा' जाए।

विपक्ष के नजरिए का अंदाजा जनवरी के शुरू में इंडिगो की एक फ्लाइट में एक विपक्षी दल के नेता से हुई बातचीत से लगा। एक राजनीतिक परिवार की तीसरी पीढ़ी के इस वारिस को एक सीमित क्षेत्र में, जाति आधारित एक मजबूत वोट बैंक हासिल है। मैंने उनसे पूछा था कि वे क्या उम्मीद कर रहे हैं, और यह कि क्या उनका जातीय वोट बैंक मोदी की हवा में टिका रहेगा? उनका जवाब था कि जातीय वोट बैंक तो कुल मिलाकर सुरक्षित रहेगा, लेकिन लोग जब लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे तब उनके सामने बस एक ही चेहरा होगा। उनका सवाल था कि लोगों को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि इस चेहरे का विकल्प भी है? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी (और विपक्ष) ऐसा मुद्दा खोजने में जुटी है, जो बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर खींच लाए। मसलन, अगर आप 'अग्निवीर' योजना का मुद्दा उछालें तो केवल वे लोग ही विरोध करने के लिए आगे आएंगे जो इससे प्रभावित हैं, बाकी वोटर उदासीन रहेंगे।

मैंने पूछा, तब उपाय क्या है? क्या तीन पीढ़ियों से जारी आपकी राजनीति का अंत हो गया? उनका जवाब था, इसे आप इस तरह देखिए, कि हम एक ऐसे दौर में हैं जिसे परमाणु युद्ध के बाद आए शीतकाल ('न्यूक्लियर विंटर') जैसा दौर कहा जा सकता है। अभी हम यही कर सकते हैं कि अपना वजूद तब तक बनाए रखें, जब तक यह दौर बीत नहीं जाता। इसका अर्थ है कि अपना वोट बैंक बचाकर रखो, कुछ सीटें जीतो और अपने संसाधन सुरक्षित रखो। समय बदलने तक वजूद बनाए रहो।

कांग्रेस के लिए 80 सीटें भी मायने रखने वाली होंगी...

कांग्रेस के नेता अनुभवी हैं और जीत-हार का सामना कर चुके हैं। वे मान सकते हैं कि 80 से ऊपर सीटें भी आ गईं तो उनका आधार मजबूत होगा। इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनावों के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है।

उनका विचार मुझे भविष्यदर्शी और बुद्धिमानी भरा लगा, सिवाय इसके कि इस बातचीत के कुछ ही दिनों बाद वे 'इंडिया' गठबंधन से निकलकर एनडीए में चले गए। 'न्यूक्लियर विंटर' से निबटने का शायद यही उपाय उन्हें बेहतर लगा होगा, ताकि जब भी हालात बदलें, वे मैदान में रहें और नए विकल्प चुनने के लिए तैयार रहें।

विपक्षी दल जबकि खुद को बचाए रखने या अगली लड़ाई के लिए खुद को तैयार रखने की जुगत में हैं, हर एक दल के सामने अपनी अलग-अलग चुनौतियां हैं। जैसे ममता बनर्जी की टीएमसी के सामने चुनौती यह है कि भाजपा के 2019 के आंकड़े में इजाफा हुआ तो उनकी प्रदेश सरकार अस्थिर हो सकती है। फिलहाल लड़ाई में उलझी आम आदमी पार्टी 2019 के सफाए से अलग इस बार कोई बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार के एनसीपी घटक को अपना वजूद बनाए रखने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। अखिलेश यादव की सपा और लालू/तेजस्वी यादव के राजद ने अगर 2019 जैसा प्रदर्शन ही किया तो अपने-अपने राज्य में सत्ता में आने का उनका सपना साकार होना मुश्किल हो जाएगा। इन दलों के लिए फंड के स्रोत भी सीमित ही हैं। जहां वे सत्ता में नहीं हैं, वहां उनके ये स्रोत सूख चुके हैं और जमा-पूंजी घटती जा रही है। जिन राज्यों में वे सत्ता में हैं, वहां वे पैसे वालों को पैसे देने के लिए 'राजी' कर सकते हैं लेकिन 'एजेंसियां' उनके पीछे लगी हैं। यह संभावित डोनर्स को भी डरा सकता है।

यह तो एक राज्य वाले या 'आप' जैसे डेढ़ राज्यों वाले दलों का हाल है। कांग्रेस के लिए चुनौती अलग तरह की है। इन दिनों वह आंतरिक एकजुटता बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटी रही। 2014 से 2019 के बीच उसकी एकमात्र उपलब्धि है, 20 प्रतिशत का अपना ठोस वोट प्रतिशत बनाए रखना। लेकिन इससे उसे इतनी भी सीटें नहीं मिलतीं कि वह लोकसभा में विपक्ष के औपचारिक नेता का दर्जा हासिल कर सके। सवाल यह है कि वह अपने समर्थकों और प्रतिद्वंद्वियों को यह भरोसा दिलाने के लिए कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य तय करे कि भविष्य में वही असली चुनौती दे सकती है?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

इस नवरात्र में हम निर्भय होकर सद्गुणों की रक्षा करें

आज से हिंदू माह परंपरा के अनुसार नव वर्ष आरंभ हो रहा है। वैसे कामकाजी दुनिया में अंग्रेजी कैलेंडर प्रचलित है। लेकिन आज से जो नवरात्र आरंभ होंगी, वो हमारी मनोदशा पर प्रभाव डालेंगी। क्योंकि हिंदू माह का जो गठन हुआ है, वो उस यात्रा के लिए हुआ है, जो मनुष्य अपने शरीर से आत्मा तक की कर सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार, इस संवत्सर का नाम पिंगल है। लेकिन भविष्य वक्ताओं में मतभेद भी है। कुछ इसे क्रोधी संवत्सर भी कह रहे हैं। सामान्य राय है कि इसका राजा मंगल और मंत्री शनि होगा। इसलिए दुर्घटनाएं, खासतौर पर अग्नि से जुड़ी घटनाएं अधिक होंगी। और सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम उस राजा को याद करें, जिसकी सत्ता प्रजा के लिए पूजनीय थी। वो हैं राम। तुलसी ने एक जगह लिखा है, 'एहि बिधि नगर नारि नर करहिं राम गुन गान। सानुकूल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान'। 'इस प्रकार नगर के स्त्री-पुरुष राम जी का गुणगान करते हैं और कृपानिधान श्री रामजी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं'। हम संकल्प लें कि हमारे हृदय पर राम का राज यानी सद्गुणों का राज हो और इस वर्ष हम अपने राजा की यानी अपने सद्गुणों की और हमारे सद्गुण हमारी प्रशंसा और रक्षा करें। इस बार की नवरात्र हमें निर्भय करके भविष्य की ओर बढ़ने को प्रेरित करेंगी। • Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

मुद्दा • पार्टियों को बताने के लिए मजबूर किया जाए कि किस सीमा तक उन्होंने अपने चुनावी वादों को पूरा किया है

घोषणा-पत्रों को ज्यादा महत्व देने का समय आ गया है

अभय कुमार दुबे
अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर
abhaydubey@aud.ac.in

चुनाव में वोटों की होड़ शुरू होने से पहले ही घोषणा-पत्रों के बीच जंग होने लगती है। इस बार लगता है कि मतदाताओं की गोलबंदी में घोषणाओं की अहमियत पहले से ज्यादा होने वाली है। कारण यह कि इस बार लोकसभा चुनाव के ऊपर किसी असाधारण घटना का साया नहीं मंडरा रहा है। 2019 में पुलवामा हमले और उसके जवाब में की गई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक ने मतदाताओं के मानस को बेहद उद्वेलित कर दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रबल भावना और मोदी सरकार द्वारा 'घर में घुसकर मारा' के जबर्दस्त प्रचार के कारण घोषणा-पत्र कमोबेश पृष्ठभूमि में चले गए थे। इस बार नरेंद्र मोदी 'भ्रष्टाचार' के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और विपक्ष 'लोकतंत्र बचाने' का आह्वान कर रहा है। ये मुद्दे लोगों को प्रभावित करेंगे पर इनमें भावनात्मक आवेग नहीं है। जाहिर है कि मतदाताओं के पास इस बार घोषणा-पत्रों के वादों पर ज्यादा गम्भीरता से गौर करने का मौका है। माना जा सकता है कि इस बार कम से कम मतदाताओं का एक हिस्सा पार्टियों के वादों की जांच-परख करके वोट देने का फैसला करेगा।

तकरीबन सभी चुनावशास्त्री इस पर एकमत हैं कि धीरे-धीरे हमारी चुनावी राजनीति में दस से पंद्रह-बीस फीसदी के बीच मतदाताओं का एक ऐसा वर्ग उभर आया है, जो अपनी मतदान-प्राथमिकताओं पर आखिर तक विचार करके फैसला करता है। यह छोटा-सा बीच में बैठा हुआ मतदाताओं का समूह मोटे तौर पर न तो जाति के आधार पर वोट देता है, न धर्म के आधार पर, और न ही यह पार्टियों की विचारधारात्मक दावेदारियों से प्रभावित होता है। वह एक नई श्रेणी से ताल्लुक रखता है। यह सत्ताधारी दल की खामियों और थोड़ी-बहुत एंटी-इनकम्बेंसी के बावजूद उसे समर्थन देने का निर्णय ले सकता है, बशर्ते उसे विपक्ष की बातें पर्याप्त रूप से विश्वसनीय न लग रही हों। इसके उलट वह सरकार बदलने के लिए भी वोट कर सकता है, अगर उसे विपक्ष के नेताओं और उनकी बातों में ज्यादा दम लग रहा हो। ऐसे मतदाता नतीजे को गहराई से प्रभावित करते हैं।

इसका प्रमाण 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में उस समय मिला, जब जीतने के बाद प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय की मांग पर उसे अस्सी पेज की एक रपट भेजी। आंखें खोल देने वाली इस रपट में माना गया था कि भाजपा की जीत में इसी 'फेंस' पर बैठे वोटर-समूह की बड़ी भूमिका थी। अगर यह वोटर आखिर में भाजपा की तरफ झुकने का फैसला न करता तो शायद अखिलेश यादव द्वारा की गई पिछड़ी जातियों की एकता और अल्पसंख्यक वोटों का असाधारण ध्रुवीकरण योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी को मुश्किलों में डाल सकता था। मतदाताओं के इस छोटे लेकिन अहम हिस्से के पास इस समय कांग्रेस का घोषणा-पत्र है। उन्हें यह भी पता है कि पांच-छह दिनों में भाजपा का घोषणा-पत्र भी जारी होने वाला है। इन दोनों को सामने रखकर तुलनात्मक दृष्टि से पसंद-नापसंद करना आसान नहीं होगा।

कांग्रेस अपने घोषणा-पत्र को न्याय-पत्र कहते हुए स्त्री, युवा, किसान और कमजोर जातियों को अपनी ओर खींचना चाहती है। भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि वह 'संकल्प-पत्र' जारी करेगी, जिसके केंद्र में 'ज्ञान' (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) होगा। जो भी हो, कांग्रेस के न्याय-पत्र में हर वादा बहुत ठोस किस्म का है। यानी सामान्य किस्म की बातें कहने के बजाय उन्होंने संख्याओं के जरिए अपने वादों को प्रामाणिक बनाने की चेष्टा की है। सारी बातें सीधे-सीधे हां या ना में हैं। मुझे लगता है कि ऐसे घोषणा-पत्र के बाद अब भाजपा को भी इसी ठोस शैली में अपने वादे मतदाताओं के सामने परोसने पड़ेंगे।

समय आ गया है कि घोषणा-पत्रों को राजनीति के केंद्र में अधिक गम्भीरता से स्थापित किया जाए। इसके लिए कुछ बातें जरूरी हैं। पहली, हर पार्टी अपने हर वादे को पूरा करने के लिए घोषणा-पत्र में स्पष्ट समयसीमा तय करे। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ले, और जीतकर सत्ता में आने वाले दल से लिखित रूप में जवाब-तलबी की जाए कि उसने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया। यह काम गैर-सरकारी क्षेत्र में नागरिक संस्थाएं भी कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि घोषणा-पत्र में जो नहीं लिखा है, उसे वादे के रूप में जनता के सामने परोसने को नियम बना कर रोका जाए। मसलन, कोई पार्टी कहती है कि वह अमुक संख्या में रोजगार देगी, या किसी तबके की आमदनी अमुक सीमा तक बढ़ जाएगी, या लोगों के खातों में अमुक रकम आ जाएगी- लेकिन ये बातें घोषणा-पत्र में बाकायदा लिखी गई नहीं हैं। इस सूरत में आयोग या जिम्मेदार संस्थाओं द्वारा इन अलिखित वादों को नोट किया जाए और उन्हें भी बाकायदा घोषणा-पत्र का लिखित अंग करार दिया जाए। हो सकता है कोई सत्ताधारी दल किसी विशेष स्थिति (जैसे कोविड) के कारण अपने वादे तय समय में पूरे न कर पाया हो। उस सूरत में जरूर मतदाता उसे रियायती नजरिए से देख सकते हैं। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

वेब भास्कर

यहां फोटोग्राफी चुनौती, चार तस्वीरों को मिलाकर बनाई यह एक तस्वीर

स्विट्जरलैंड की इस गुफा में फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहां बर्फ तेजी से पिघलती है। ऊपर से बर्फ के टुकड़े हमेशा गिरते रहते हैं। लेकिन फोटोग्राफर एंजेलिका कहती हैं कि मैं यहां की ऐसी तस्वीर लेना चाहती थी, जिसके बैकग्राउंड में गिरती हुई बर्फ भी दिखे। एंजेलिका ने तस्वीर लेने के लिए आधी रात का समय चुना। गुफा, आसमान, बर्फ और वहां दिख रहे व्यक्ति की चार-अलग तस्वीरें खींचीं और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें आपस में मिलाकर एक तस्वीर बनाई।
तस्वीर साभार : Angelica Fuchs

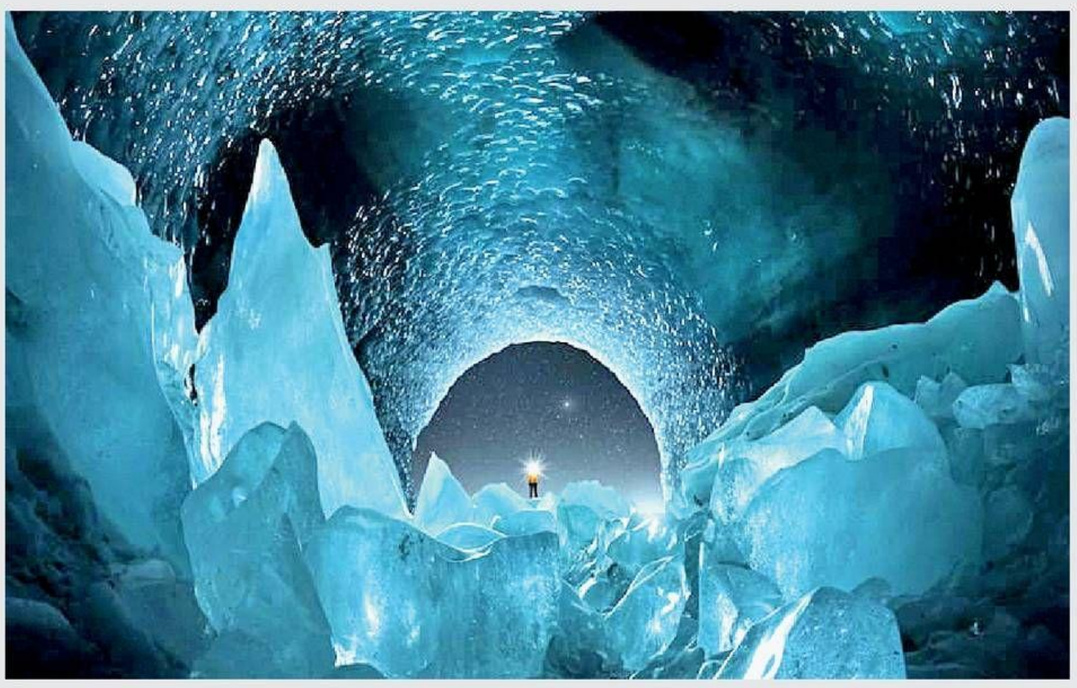

दूरदृष्टि • मॉस्को-हमले के बाद हालात पेचीदा हुए...

रूस अब यूक्रेन पर हमले की धार और तीखी कर सकता है

अभिजीत अय्यर मित्रा
सीनियर फेलो, आईपीसीएस
abhijit@ipcs.org

रूस ने एक बार फिर मॉस्को के एक कॉन्सर्ट-हॉल में हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी जांचकर्ताओं ने बीते सप्ताहांत एक बयान जारी करते हुए कहा कि एक हमलावर के फोन से यूक्रेनी झंडे की तस्वीरें मिली हैं। लेकिन पिछले महीने मॉस्को के क्रोकस मॉल में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कौन-था, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे।

हमला इतना नृशंस था कि उसमें जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाया गया। आईएसआईएस शैली में लोगों का गला रेता गया और शवों को क्षत-विक्षत किया गया। आश्चर्य कि सभी हमलावर जीवित पकड़े गए और उन्हें बहुत चोटें भी नहीं आई थीं। वे सभी ताजिक मूल के थे (जो फारसी होते हैं तुर्क नहीं) और वे अवैध रूप से अपने वीजा की अवधि को बढ़ाकर रूस में रह रहे थे। उनमें से किसी के पास आईएसआईएस से जुड़े नारे और बैनर या आर्मबैंड जैसे सामान नहीं थे। जिन चैनलों ने सबसे पहले यह दावा किया था कि यह हमला आईएसआईएस ने किया था, वो पश्चिमी चैनल थे। उन्होंने खासतौर पर यह भी रेखांकित किया कि अमेरिका ने महीनों पहले ही रूस को आगाह कर दिया था कि निकट भविष्य में आईएसआईएस उसके यहां किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। लेकिन पूर्व रूसी प्रधानमंत्री मेदवेदेव ने कहा कि हमलों में यूक्रेन का हाथ था। अंत में राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने भी हमलों के पीछे यूक्रेन के होने का आरोप लगाया।

क्या यह खुद रूस का एक फाल्स-फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मॉस्को में ही 1999 में भी एक अपार्टमेंट बम विस्फोट में 300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जिसके लिए चेचेन आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन इसके लिए कभी कोई सबूत नहीं दिया गया। रूस ने चेचन्या पर आक्रमण कर दिया। यह लंबा और खूनी युद्ध दस साल बाद उस क्षेत्र के पूर्ण विनाश और पुनर्निर्माण के साथ ही समाप्त हुआ। रूसियों द्वारा आरोपित एक व्यक्ति अचेमेज गोचियायेव था, जो मुस्लिम था लेकिन चेचेन नहीं। वह करायचे नस्ल का था। कुछ साल बाद वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसके बाद से उसके बारे में कभी नहीं सुना गया। अटकलें लगाई गईं कि बम एफएसबी द्वारा ही लगाए गए थे, जिसका नेतृत्व कुछ महीने पहले तक पुतिन कर रहे थे।

पुतिन से पहले कुछ महीनों के लिए रूस के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति- सर्गेई स्तेपाशिन ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि बमबारी हुई थी या नहीं या हमलावर चेचेन थे या नहीं, इसका महत्व नहीं था। महत्व इसका था कि रूस ने चेचन्या पर धावा बोलने

मॉस्को के कॉन्सर्ट-हॉल में हुए नृशंस हमले के लिए चाहे जो जिम्मेदार हो, पुतिन इसके तार यूक्रेन से जोड़ रहे हैं और अब वे यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की धार और तीखी कर सकते हैं। यूक्रेन भी पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं है।

का मन बना लिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बमबारी और उस पर हुई प्रतिक्रिया ने ही कुछ ही महीनों के भीतर व्लादीमीर पुतिन के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसके एक साल बाद वे बोरिस येल्तसिन के स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन गए। बहुत संभव है कि पुतिन ने युद्ध को भड़काने या आगे बढ़ाने के लिए इस बार भी ऐसा ही कुछ किया हो।

यहां यूक्रेन या पश्चिम भी दोषमुक्त नहीं किए जा सकते। 2014 के बाद से- जब रूस ने पहली बार क्रीमिया पर कब्जा किया और दोनेत्स्क और लुगांस्क को स्वतंत्र राज्य घोषित किया- बड़ी संख्या में चेचेन और अन्य विदेशी जिहादी, विशेषकर आईएसआईएस और अल कायदा से संबंधित कई लोग यूक्रेनी पक्ष से लड़ रहे हैं। युद्ध हारने के बाद चेचेन लोगों ने इसे उस युद्ध की निरंतरता और अधिक रूसियों को मारने का एक तरीका माना। सीआईए सहित अन्य पश्चिमी एजेंसियां भी आईएसआईएस और अल कायदा के कुछ तत्वों को बढ़ावा देने में व्यस्त थीं। खुद यूक्रेन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। उस पर नॉर्डस्ट्रीम पाइप लाइन पर बमबारी का आरोप लग चुका है। उसका खुफिया विभाग रूस में असैनिक लोगों को मार रहा है। रूस में हुए कई बम धमाकों के तार यूक्रेन से जुड़े हैं। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

डिफ्रेंट एंगल • उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों कहा कि डॉक्टर्स स्पष्ट हैंडराइटिंग में लिखें

हैंडराइटिंग जीवन और मृत्यु का कारण भी हो सकती है

नंदितेश निलय
वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक
एवं लेखक
nanditeshnilay@gmail.com

महात्मा गांधी का मानना था कि अच्छी लिखावट एक संपत्ति है। उनका एक बड़ा मशहूर कथन है, 'बैड हैंडराइटिंग इज द सिंबल ऑफ इंपरफेक्ट एजुकेशन'। यहां तक कि अब्राहम लिंकन ने भी अपनी आत्मकथा में अपनी खराब लिखाई के लिए बहुत अफसोस जताया है। आप सोच रहे होंगे कि हैंडराइटिंग पर आज अचानक क्यों बात हो रही है। दरअसल हैंडराइटिंग सिर्फ हुनर या व्यक्तित्व का पहलू भर नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का कारण भी बन सकती है!

पिछले दिनों उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पर्ची बड़े-बड़े अक्षरों या सुपाठ्य लिखावट में लिखें। न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी मेडिकल सेंटर्स, निजी क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को एक परिपत्र जारी करें कि जब भी दवा या कुछ मेडिको-लीगल रिपोर्ट लिखी जाए, तो वह उचित लिखावट में हो या टाइप की गई हो। इससे पहले कई कोर्ट्स हैंडराइटिंग के कारण डॉक्टर्स पर जुर्माना भी लगा चुके हैं। दरअसल, दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग सिर्फ इसलिए मौत के शिकार हो जाते हैं क्योंकि खराब हैंडराइटिंग के चलते उन्हें सही दवा नहीं मिल पातीं और वे गलत इलाज या गलत दवा का शिकार हो जाते हैं।

टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि खराब या नहीं पढ़ी जा सकने वाली डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग के चलते दुनिया में हर साल करीब सात हजार से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार साल में करीब डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इसलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर जो दवाएं लिखते हैं, वह खराब राइटिंग की वजह से समझ नहीं आतीं। यह रिपोर्ट बताती है कि हर साल अमेरिका में 32 करोड़ मेडिकल स्क्रिप्ट के समझ में नहीं आने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसका समाधान भी हमें डिजिटल दुनिया के माध्यम से ही ढूंढना पड़ेगा। क्यों ना डिजिटल नुस्खे को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाए, जिससे केमिस्ट को कोई भी दिक्कत ना हो और एक आम आदमी भी गलत दवा खाने से बच जाए।

अभी कुछ साल पहले पढ़ने को मिला कि असम में एक पूर्व संपादक के परिवार में किसी को ऐंठन से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि शुरुआती जांच में इसका कोई ठोस कारण समझ नहीं आया, लेकिन बाद में चौंकाने वाली बात सामने आई कि दिल्ली में एक डॉक्टर ने उन्हें डुओडिल (duodil) लिखी थी। यह एक दर्दनिवारक दवा है। लेकिन मेडिकल स्टोर ने जो दवा दी वह daonil थी। यह दवा मधुमेह रोगियों के लिए थी। इससे मरीज के रक्त में शर्करा के स्तर में अचानक गिरावट आ रही थी, जिससे उन्हें ऐंठन की शिकायत होने लगी। और यह भी इलाज करने वाले डॉक्टर की अस्पष्ट लिखावट के कारण हुआ।

वैसे खराब हैंडराइटिंग सिर्फ मेडिकल पेशे तक सीमित नहीं है। चूंकि यह पेशा सीधा जीवन और मृत्यु से जुड़ा है, इसलिए इसका असर गंभीर है। अमेरिका में वनपोल नाम की संस्था द्वारा कराए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि विभिन्न पेशों के लोगों ने अपनी खराब हैंडराइटिंग के कारण कामकाजी जीवन में कभी न कभी मुसीबत झेली है। एनसीईआरटी द्वारा कराए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि कोविड काल में देश के 75 फीसदी बच्चों की हैंडराइटिंग खराब हो गई थी। आज के दौर में बच्चों के हाथों में पेन-पेंसिल की तुलना में स्क्रीन ज्यादा रहती है। ऐसे में अच्छी हैंडराइटिंग पर कम ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन हैंडराइटिंग, व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहती है, इसलिए इसे हल्के में ना लें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

उत्तर प्रदेश की राजनीति

व्यापक उथलपुथल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक उथलपुथल जारी है। लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजने वाले इस प्रदेश में आम चुनाव के पहले उथलपुथल चल रही है, जबकि आमतौर से यह प्रदेश चुनाव में केन्द्रीय भूमिका निभाता है। यह स्थिति समान रूप से निराशाजनक व हास्यास्पद है कि जहां उम्मीदवार तय करने के मामले में समाजवादी पार्टी अत्यधिक सक्रिय है, वहीं कांग्रेस में निष्क्रियता की स्थिति है, भले ही दोनों का नतीजा एक ही निकले। जहां समाजवादी पार्टी-सपा ने आखिरी क्षण में अपने उम्मीदवारों के नाम बदले हैं, वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत गढ़ समझे जाने वाले अमेठी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रों से भी उम्मीदवार तय करने में हिचक रही है। अखिलेश यादव नीत सपा को विपक्षी 'इंडिया' समूह में स्वयं को आबंटित सीटों पर बार-बार उम्मीदवार बदलने के कारण सुर्खियों में स्थान मिल रहा है। संभवत: इसका कारण चुनावी संभावनायें अधिकतम करने की गणित है। तेजी से उम्मीदवार बदलने से एक ओर जहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पार्टी की परिवर्तनशीलता स्पष्ट होती है, वहीं दूसरी ओर यह अनिर्णय का संकेत भी देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सपा में अंतिम क्षण तक टिकट वितरण पर व्यंग्य भी किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को देश तथा अपनी पार्टी के भविष्य में उत्तर प्रदेश का महत्व अच्छी तरह पता है। 2019 में यहां राजग 51.19 प्रतिशत मतों के साथ प्रमुख गठबंधन के रूप में उभरा था। भाजपा ने अपने दम पर 49.98 प्रतिशत मत प्राप्त किए थे और 62 सीटें जीती थीं। राजग में सहयोगी अपना दल-सोनेलाल को भी दो सीटों पर सफलता मिली थी और इस प्रकार उसे

64 सीटों पर शानदार सफलता मिली थी। मायावती की बसपा को 10 सीटें मिली थीं, जबकि 17.96 प्रतिशत वोटों के साथ सपा को पांच तथा कांग्रेस को एक सीट मिली थी।

इस बार भाजपा पर अपनी पुरानी स्थिति बनाए रखने का दबाव है। सपा अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने वाली बसपा उनके वोट प्रतिशत को नुकसान पहुंचा सकती है। सपा की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय भावनाओं तथा जमीनी परिवर्तनों की गहरी समझ प्रकट करती है। ये तत्व अक्सर उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर निर्णायक छाप छोड़ते हैं। लेकिन सपा की तेज राजनीति के बावजूद कांग्रेस संभवत: उपयुक्त उम्मीदवार पाने के लिए भी संघर्ष कर रही है। कांग्रेस के चुनावी भविष्य पर मोदी की हालिया टिप्पणी उसकी संगठनात्मक कमियों तथा इस प्रमुख राज्य में मजबूत चुनौती पेश करने में विफलता पर लक्षित है। सुसंगत रणनीति के अभाव के साथ ही आंतरिक विरोध तथा नेतृत्व संकट ने देश की 'सबसे पुरानी पार्टी' को चुनावी संकट में डाल दिया है। सपा और कांग्रेस की रणनीतियों में दिखने वाली विपरीत स्थिति उत्तर प्रदेश की चुनावी स्थितियों तथा विपक्षी दलों द्वारा भाजपा के प्रभुत्व का मुकाबला करने की विविधतापूर्ण रणनीतियों का परिणाम है। जहां सपा परिवर्तनशीलता, गठबंधन-निर्माण तथा जमीनी स्तर पर लामबंदी पर जोर देती है, वहीं कांग्रेस आंतरिक विरोध, संगठनात्मक कमजोरियों तथा उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी का शिकार है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए संघर्ष केवल इन राजनीतिक समूहों के बीच चुनावी मुकाबला भर नहीं है, बल्कि यह राज्य के जटिल ढांचे में व्यापक सामाजिक-राजनीतिक विभाजक रेखाओं, जातीय गणित तथा आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी करता है।

मौलिकता से वंचित कांग्रेस घोषणापत्र

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणापत्र में लंबी-चौड़ी बातें की गई हैं, पर उसमें समस्याओं के खोजी समाधान नहीं हैं। वर्तमान राजनीति के प्रति केवल प्रतिक्रिया के कारण इसकी आलोचना हो रही है।

शिवाजी सरकार
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणापत्र में लंबी-चौड़ी बातें की गई हैं, पर उसमें समस्याओं के खोजी समाधान नहीं हैं। वर्तमान राजनीति के प्रति केवल प्रतिक्रिया के कारण इसकी आलोचना हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो घोषणापत्र जारी किया है वह देखने में तो बड़बोली लफ्फाजी से भरा तथा अच्छे इरादों से लाया गया लगता है, पर उसमें कोई मौलिकता नहीं है और यह वर्तमान नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया अधिक लगता है। हालांकि, पार्टी ने नई शिक्षा नीति-एनईपी बदलने की बात कही है, पर उसने अर्थव्यवस्था में गिरावट से निपटने का कोई नया रास्ता नहीं बताया है। वह सार्वजनिक उद्यमों-पीएसयू के बारे में मौन है और उसने अनावश्यक रूप से अत्यधिक खर्चीले 'अमेरिकी माडल' के आधार पर जारी 4 वर्षीय बीए स्नातक पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करने की बात कही है।

इसने एनईपी पर समग्र रूप से असंतोष प्रकट किया है, पर स्वयं को 'राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद नई शिक्षा नीति-एनईपी की समीक्षा' तक सीमित रखा है। क्या इसका अर्थ है कि वह 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जारी रखना चाहती है? इसे समाप्त करने से उन युवाओं में विश्वास पैदा हो सकता था जिनमें से प्रत्येक प्रति वर्ष कम से कम 3 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करता है और रोजगार के बाजार में पहुंचने में उसे विलम्ब होता है। कुल मिला कर चार-वर्षीय नर्सरी से लेकर नए चार-वर्षीय डिग्री कोर्स तक बच्चे के शिक्षा में चार साल खराब होते हैं। कांग्रेस डिग्री में इस अनावश्यक चौथे साल को रेखांकित कर दो करोड़ छात्रों का प्रति वर्ष 6 लाख करोड़ रुपया बचाने की बात कर सकती थी।

कांग्रेस ने पीएसयू पर कुछ नहीं कहा है। 'नव संकल्प आर्थिक नीति' में 'तीन डब्लू'-वर्क, वेल्थ एवं वेलफेयर की बात कही गई है। उसने जीएसटी की समीक्षा की बात कही है। उसे उम्मीद है कि इससे अधिकांश छोटे व्यापारियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार सृजन होगा। इससे 'रोजगार-विहीन वृद्धि' से छुटकारा मिलेगा। 1991 से कल्याण के प्रति नया उन्मुखीकरण सामने आया है। लेकिन उसकी 'कार्य' की परिभाषा वर्तमान की तरह है जिसमें स्व-रोजगार और बिजनेस शुरू करने को प्राथमिकता मिली है। इसमें यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि आरबीआई के अनुसार रुकी हुई 60 प्रतिशत केन्द्रीय परियोजनाओं की लागत में 5 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। वह कह सकती थी कि इनको समाप्त कर दिया जाएगा। श्रम कानूनों के मोर्चे पर भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति भ्रामक है क्योंकि उसने उनके अधिकार छीनने वाले कानून समाप्त करने का वादा नहीं किया है। भ्रष्टाचार के मामले पर उसने कहा है कि वह 'नोटबंदी, राफेल समझौते, पेगासस स्पाईवेयर तथा चुनाव बांड योजना की जांच कराएगी और एक कानून लाएगी जिसके अनुसार इन उपायों से प्राप्त धनराशि को अवैध घोषित किया जाएगा।' राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि चुनाव बांड से भाजपा की राजनीतिक फंडिंग स्पष्ट होती है जो उसने निगमों पर 'दबाव डाल कर जबरन प्राप्त किया है।' उसने 'अग्निपथ' सेना भर्ती योजना समाप्त करने का वादा किया है। विपक्ष के ऐसे अनेक वादों से स्पष्ट है कि सरकार आने के बाद इन मुद्दों को छोड़ दिया जाता है और कुछ लोग ऐसे वादों को चुनाव घोषणापत्रों में शामिल 'जुमले' कह सकते हैं।

1971 का कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र आज तक इसलिए याद किया जाता है कि उसने शानदार 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। पांच 'न्याय' का नारा अच्छा विचार हो सकता है, पर यह आकर्षक नहीं है। इसमें न्याय के पांच आधार-'युवा न्याय', 'महिला न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' तथा 'सबको न्याय' शामिल हैं। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और शायद इसे भाजपा के 'मुमकिन है' के जवाब में लाया गया है। घोषणापत्र निर्माण के समन्वयक पी. चिदंबरम अखबारों के कालमों में सरकारी कामकाज की आलोचना करते रहे हैं और उन्होंने नए आंकड़ों को भी चुनौती दी है। लेकिन यह कहीं कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में दिखाई नहीं देता है। इसमें तीन-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के आंकड़े पर भी सवाल नहीं उठाया गया है जहां 10 लाख करोड़ का भुगतान किया जाना है तथा इसे 2024-25 के बजट में 47 लाख करोड़ से घटा कर 37 लाख करोड़ कर दिया गया है। विश्व बैंक ने 7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के आंकड़े पर सवाल उठाए हैं। इस बारे में संप्रेषण बेहतर किया जा सकता था। आरबीआई के 'उपभोक्ता विश्वास सूचकांक' का हवाला दिया जा सकता था जिसके अनुसार पांच साल पहले की तुलना में उपभोक्ताओं की भावनायें कमजोर हुई हैं। 2024 में कम लोगों ने रोजगार या आय की स्थिति में सुधार की रिपोर्ट की है। मध्य वर्ग को स्थिर आयकर का वादा किया गया था। कांग्रेस घोषणापत्र में यह वादा नहीं किया गया है कि वह कार्पोरेट करों की दर 22 प्रतिशत पर बनाए रखेगी।

बेरोजगारी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने निजी या सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में 25 साल से कम आयु वाले हर युवा डिप्लोमाधारक या स्नातक को एक-वर्षीय अप्रेंटिसशिप की गारंटी की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून-मनरेगा के अंतर्गत कामगारों की मजदूरी प्रति दिन बढ़ा कर 400 रुपये करने का वादा किया गया है जिसे उसने न्यूनतम मजदूरी घोषित किया है। लेकिन शायद कांग्रेस ने यह तथ्य भुला दिया है कि अप्रेंटिसशिप योजना इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में शुरू की थी। यह योजना विफल रही क्योंकि निजी क्षेत्र ने इसे कभी पसंद नहीं किया और पीएसयू की प्रतिक्रिया भी इसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। कोलकाता को छोड़ कर देश की सभी मेट्रो घाटे में चल रही हैं। घोषणापत्र में इसका उल्लेख कर पाकेट व पर्यावरण-हितैषी समाधान सुझाए जा सकते थे। जाति-आधारित जनगणना कांग्रेस को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन यह उसी सीमा तक संभव है जब भविष्य में रोजगार सृजन का रोडमैप स्पष्ट हो। चुनाव घोषणापत्र में जातीय जनगणना की घोषणा कर कांग्रेस एक प्रकार से 'जातीय राजनीति' के शिकंजे में फंस गई है। कांग्रेस ने पेट्रोल की ऊंची कीमतो पर सवाल उठाते हुए 'सेस' राज की बात कही है, लेकिन वह टोल गेट समाप्त करने के नाम पर पेट्रोल पर 32.9 रुपये प्रति लीटर रोड सेस के मामले पर खामोश है। देश को टोल संग्रह की लूट से आजाद करना जरूरी है। यह संग्रह 10 लाख करोड़ से अधिक तथा मुद्रास्फीति का कारण है। इसी प्रकार कांग्रेस कार-ट्रैक्टर को कबाड़ करने तथा शिक्षा की भारी फीस पर मौन है। इसके कारण किसानों तथा औसत परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस थोड़ी संवेदना बरत कर लाखों लोगों के दिल में जगह बना सकती थी।

कांग्रेस यह घोषणा कर सकती थी कि नौकरी के प्रार्थनापत्रों के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। हालांकि, और ज्यादा केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोलने का वादा अच्छा है। कक्षा दस तक शिक्षा मुफ्त करने का कदम सही है। लेकिन क्या यह वादा निजी स्कूलों पर भी लागू होगा? उत्तर प्रदेश ने इसके लिए एक माडल विकसित किया था। 1960 के दशक में कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था की थी जिससे शिक्षा परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया था। इस प्रस्ताव से व्यापक परिवर्तन आ सकता था। कांग्रेस ने दूरसंचार कानून, 2023 की समीक्षा कर ऐसे प्राविधान हटाने का वादा किया है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते तथा निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। लेकिन उसने ज्यादा कठोर 'भारत संहिता' या भारतीय दंड संहिता तथा अपराध प्रक्रिया संहिता में अन्य संशोधनों पर चुप्पी बनाए रखी है। ईडी, सीबीआई व अन्य संस्थानों के दुरुपयोग की शक्तियां इनसे निकलती हैं। लेकिन इसके बावजूद 'निर्भय समाज' बनाने का वादा उम्मीदें जगाता है। देश को उम्मीद है कि इन नए कदमों से राजनीतिक विमर्श बेहतरी की दिशा में जाएगा।

तनाव के कारण और प्रभाव

“तनाव का 'स्ट्रेस बकेट माडल' तनाव के एकत्र होने तथा बेहतरी पर उसके प्रभाव का गहन अवलोकन करता है।”

साक्षी सेठी
(लेखिका, शिक्षाविद हैं)

तनाव आज जनजीवन का सामान्य हिस्सा बन गया है जिससे अनेक शारीरिक व मानसिक परेशानियां पैदा होती हैं। तनाव का 'स्ट्रेस बकेट माडल' तनाव के एकत्र होने तथा बेहतरी पर उसके प्रभाव का गहन अवलोकन करता है। आज यह सवाल प्रमुख बन गया है कि क्या आप उन लोगों में हैं जिन्होंने 2024 में तनाव से बचने का खुद से वादा किया था, लेकिन उनके तनाव का स्तर बढ़ रहा है? आज तनाव जीवनशैली में परिवर्तन का ऐसा परिणाम बन गया है जिससे बचना लगभग असंभव है। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक की 'बाल्टी' अलग आकार की होती है जिसका निर्धारण जीन्स, व्यक्तित्व, आघात के इतिहास तथा सामाजिक सहायता पर निर्भर है। शोध के अनुसार किसी व्यक्ति का जोखिम उसके द्वारा ढोई जाने वाली बाल्टी पर निर्भर है जिसमें रोज तनाव भरता जाता है। अत्यधिक जोखिम वाले लोगों में तनाव का स्तर बढ़ने पर मानसिक स्वास्थ्य समस्यायें पैदा होने का खतरा अधिक होता है। इसके उलट ऐसे भी लोग होते हैं जिनका जोखिम कम होता है और वे उच्च स्तर का तनाव सहन कर सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि तनाव का आकार हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है।

'स्ट्रेस बकेट माडल' एक प्रतीकात्मक अवधारणा है जिसका प्रयोग अक्सर मनोविज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य में यह बताने के लिए किया जाता है कि तनाव कैसे संग्रहीत होता है और यह व्यक्ति की बेहतरी को कैसे प्रभावित करता है। इससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का दिन-प्रतिदिन का तनाव उसके काम, पैसे, संबंध, शरीर की छवि, आदि को प्रभावित करता है। इससे बाल्टी भरती रहती है और व्यक्ति अपनी इच्छा के काम नहीं कर पाता है जिसमें अपनी देखभाल के लिए समय

निकालना, समय प्रबंधन तथा दूसरों के साथ चिन्ता का साझा करना शामिल हैं। इनसे एक प्रकार से बाल्टी का कुछ पानी निकल जाता है।

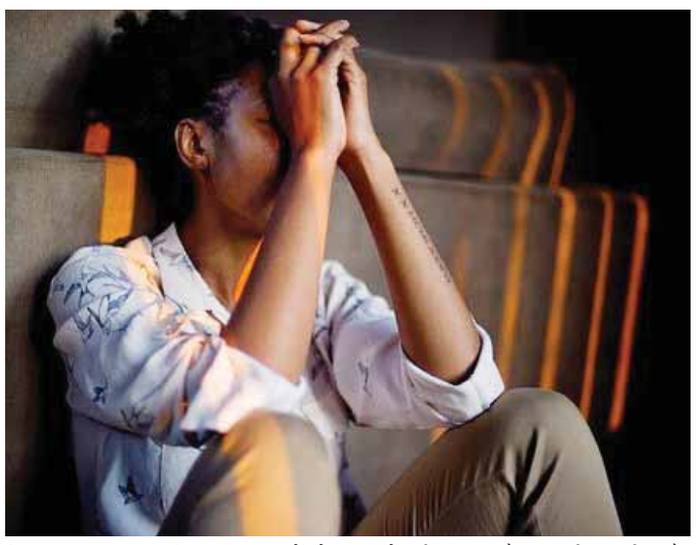

यह तनावों तथा उनसे निपटने वाली व्यवस्थाओं के बीच संबंधों की कल्पना करने की सरल और प्रभावी तकनीक है। यदि कोई व्यक्ति बाल्टी में आने वाले और उसके बाहर निकलने के बीच संतुलन नहीं बनाता है तो बाल्टी छलक सकती है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस अवधारणा का प्रयोग शिक्षा परिवेश, कार्यस्थलों, थेरेपी सत्रों तथा स्वयं-सहायता संसाधनों में किया जा सकता है। इससे तनाव प्रबंधन तथा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। लंबे समय से जारी तनाव के कारण किसी व्यक्ति का बेचैन या थका दिखना जरूरी नहीं है। लेकिन इससे प्रतिरक्षा तथा पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है, शरीर में डि-टाक्सीफिकेशन मार्ग बंद होते हैं तथा हार्मोन असंतुलन पैदा हो सकता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 'स्ट्रेस बकेट माडल' जागरूकता पैदा करने, आत्म-अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने तथा व्यक्तियों को प्रभावी तनाव प्रबंधन रणनीतियां अपनाने के लिए प्रभावशाली है। इससे लोगों को अपने तनाव स्तरों पर नियंत्रण करने तथा आज की तेज गति वाली व हम से लगातार मांग करने वाली दुनिया में बेहतरी को प्राथमिकता देने में सहायता मिलती है। तनाव की कल्पना एक 'बाल्टी' से की जा सकती है जिसमें तनाव लगातार भरते रहते हैं। इससे तनावों की सामूहिक प्रकृति तथा उसके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव समझने में सहायता मिलती है।

'स्ट्रेस बकेट माडल' को समझ कर लोग अपने तनाव पैदा करने वाले कारकों के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकते हैं, उनसे निपटने की व्यवस्थाओं की पहचान कर सकते हैं, इससे प्रभावित होने से बच सकते हैं तथा मजबूत बन सकते हैं। यह तनाव संबंधी चिन्ताओं में अपनी देखभाल तथा चिकित्सकीय हस्तक्षेपों के लिए महत्वपूर्ण है। तनाव का स्तर तथा उसके लक्षण समझ कर समझ जा सकता है कि अब बाल्टी छलकने वाली है। इससे लोग अपने तनाव स्तर का समय रहते प्रबंधन करने में सफल होंगे। अपने तनाव कारकों तथा उनसे निपटने की व्यवस्थाओं की गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद लोग तनाव प्रबंधन के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। इससे वे जीवन की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनते हैं। यह लोगों को अपनी मानसिक तथा भावनात्मक बेहतरी में संवर्धन करने का प्रभावी और सरल तरीका बताता है।

आप की बात

सट्टा बाजार का अनुमान

2024 के आम चुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में बहुमत होने को लेकर तस्वीर एकदम साफ है। आमतौर से चुनाव भविष्यवाणियों के मामले में सट्टा बाजार के अनुमान सही उतरे हैं। अब सट्टा बाजार 400 से कितनी सीटें नीचे ऊपर होगी इस पर दांव लगा रहा है। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि भले ही विपक्षी गठबंधन बहुमत न ला पाए मगर कम से कम सदन में उसकी सम्मानजनक उपस्थिति तो बनी रहे। लेकिन यह भी आसान नहीं दिखता है। विपक्ष इतना हताश और निराश पहले किसी चुनाव में नजर नहीं आया। अब बचे हुए समय में किसी नए चमत्कार की विपक्ष आशा भी नहीं कर सकता है। इस चुनाव में पहली बार न तो महंगाई का मुद्दा है और न बेरोजगारी का। आज अधिकांश लोग छोटी-मोटी समस्याओं को अनदेखा कर राष्ट्रवाद की धारा में बह रहे हैं। रही सही कसर अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरी कर दी है। विपक्षी इंडी गठबंधन की बदहाली का आलम यह है कि कब कौन सा पाया कब खिसक कर अलग हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस को लोकल दलों की शर्तों पर सीटें मिल रही है। विपक्ष की इससे ज्यादा बदहाली की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मोदी सरकार अभी से भविष्य की योजनाओं पर काम कर रही है।

–**सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

राजनीतिक अफवाहें

समाजवादी पार्टी में आंतरिक कलह, खींचतान और सीटों का बंटवारा शुभ संकेत कतई नहीं है। इस बारे में लगातार फैलती राजनीतिक अफवाहें पार्टी की छवि खराब कर रही हैं। अखिलेश यादव ने जोर शोर से घोषणा की थी कि हम 60 से ज्यादा प्रत्याशी उतार कर भाजपा को उत्तर प्रदेश से सभी 80 सीटों पर हरा देंगे। लेकिन अब यह दावा कमजोर दिखाई दे रहा है। सपा द्वारा कई स्थानों पर बार-बार उम्मीदवार बदलने के बाद अब अफवाह है कि लखनऊ में भी पूर्व घोषित प्रत्याशी का टिकट कट सकता है और कुछ नेता उनको हटाने की मुहिम चला रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक सपा कार्यकर्ता और समर्थक मुस्लिम नेताओं के टिकट कटने से नाराज बताए जाते हैं। ऐसे में बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार अनेक सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना देंगे। बसपा अपना दलित-मुसिलम समीकरण मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इस बार बसपा ने कई मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। भले ही बसपा को इस समय मीडिया में सुर्खियां नहीं मिल रही हैं, पर चुनाव के अगले चरणों में जाने के साथ मायावती के वारिस आकाश आनन्द के प्रयासों से मीडिया कवरेज की स्थिति सुधर सकती है।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

राहुल की नजर

भारत जुड़ा हुआ है, न्याय ज़िंदा है और लोकतंत्र बरक़रार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं से भारत मजबूती से जुड़ा हुआ है। उसे कोई डिगा नहीं सकता। हमारी रक्षा व्यवस्था तथा राजनीतिक व कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत हो गई है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि आतंकियों को भारत पाक के घर में जाकर मार गिरायेगा। लेकिन विडंबना है कि यह सब राहुल गांधी को नही दिखाई देता है। वास्तव में उनको भारत जोड़ो और लोकतंत्र बचाओ के बजाय कांग्रेस बचाओ अभियान चलाने की जरूरत ज्यादा है। आज छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़ी हस्तियां तक कांग्रेस पार्टी छोड़ कर भाजपा व अन्य दलों में जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति क्यों हो गई है। इसपर कांग्रेस आलाकमान को आत्ममंथन करना चाहिए। राहुल गांधी को भी पुरखों से विरासत के रूप में मिली प्राचीन पार्टी को बचाने और उसे मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए ताकि उनको क्षेत्रीय दलों की बैशाखियों का सहारा न लेना पड़े। राहुल कार्यकर्ताओं को 2004 की याद दिलाते हैं, लेकिन पिछले बीस साल में भारत आमूल बदल गया है। विडंबना है कि कांग्रेस जमीनी बदलाव देख नहीं पा रही है या वंशवाद के मोह में देखना ही नहीं चाहती है।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

कांग्रेस के वादे

अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई लोक-लुभावन वादे किए हैं। जिनमें से कुछ को तो वास्तविकता के धरातल पर उतरना कतई संभव नहीं है। ओल्ड पेंशन के मामले पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है जो कि उचित है। शायद कांग्रेस ने अपने पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष मांटेक सिंह अहलूवालिया के सुझाव पर गौर किया है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से विभीषिका बताया था। उल्लेखनीय है कि पुरानी पेंशन योजना भले ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने समाप्त की थी, पर कांग्रेस शासित संप्रग-1 व संप्रग-2 सरकारों ने इसे पूरे देश में लागू किया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने कठोर आतंकवाद-विरोधी कानूनों व धनशोधन-विरोधी कानूनों पर भी चुप्पी बनाए रखी है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस पिछले दस साल से चल रही मोदी सरकार की अनेक योजनाओं, कानूनों और परियोजनाओं को सही मानती हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को मोदी सरकार की ऐसी नीतियां भी रेखांकित करनी चाहिए जो वह सत्ता में आने के बाद भी जारी रखना चाहेगी। इससे कांग्रेस का सम्मान बढ़ेगा।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 45

उत्पादक रोजगार

श्रम बाजार के हालात पर होने वाली बहस अक्सर बेरोजगारी और श्रम शक्ति भागीदारी दरों पर निर्भर रहती है। वास्तविक आय की अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। श्रम शक्ति भागीदारी आंकड़ों में सुधार और बेरोजगारी दर में कमी के बीच अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि भारत के श्रम बाजार के नतीजों में सबकुछ अच्छा नहीं है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में वास्तविक मेहनताने में कमी आई है। 2012 और 2022 के बीच के आंकड़े दर्शाते हैं कि नियमित वेतन वाले कर्मचारियों की औसत मासिक वास्तविक आय में हर वर्ष करीब एक फीसदी की गिरावट आई। दस वर्ष की अवधि में यह 12,100 रुपये से कम होकर 10,925 रुपये रह गई। शहरी इलाकों का प्रदर्शन ग्रामीण भारत से खराब रहा। शहरी भारत में 2012 से 2022 के बीच वास्तविक वेतन औसतन 7.3 फीसदी गिरा जबकि समान अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविक वेतन 3.8 फीसदी कम हुआ।

यह बात इसलिए खासतौर पर चिंतित करने वाली है कि वेतनभोगी कर्मचारी बेहतर काम में लगे हैं, उनका कार्यकाल लंबा है, उन्हें किसी न किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा हासिल है और उन्हें नियमित अंतराल पर वेतन मिलता है। नियमित नौकरी करने वालों में भी सरकारी नौकरी करने वालों के वेतन में इजाफा हुआ जबकि निजी क्षेत्र में काम करने वालों के वास्तविक वेतन में कमी आई। निश्चित तौर पर इसकी वजह कम कौशल वाले श्रमिकों की आय में स्थिरता को ठहराया जा सकता है। स्वरोजगार श्रेणी में भी वास्तविक वेतन में ऐसा ही रुझान नजर आता है। देश के कुल श्रमिकों में से करीब 55 फीसदी की आय महामारी के कारण लगने वाले झटकों और लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों के ठप पड़ने से प्रभावित हुई। आश्चर्य की बात है कि आकस्मिक कामगारों की मासिक वास्तविक आय में 2022 तक हर वर्ष 2.4 फीसदी की वृद्धि हुई। नियमित वेतन वाले कर्मचारियों और स्वरोजगार करने वालों की वास्तविक आय का रुझान और साथ ही आकस्मिक कामगारों के वास्तविक वेतन में मामूली वृद्धि को हाल के वर्षों में रोजगार निर्माण की गुणवत्ता में गिरावट के संकेतक के रूप में देखा जा सकता है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगार की मांग में भी देखा जा सकता है जो अभी भी महामारी के पहले की मांग से ऊंचे स्तर पर है।

बेरोजगारी के आंकड़े नीतिगत चर्चाओं में अक्सर जिक्र में आते हैं। भारत की आबादी के एक बड़े और गरीब तबके के लिए ये खास महत्त्व नहीं रखते। यह ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश गरीब लोग बहुत कम बेरोजगार होते हैं। वे घर पर खाली नहीं बैठ सकते। छोटे मोटे कामकाज करने वाले ऐसे लोगों को सर्वेक्षणों में रोजगारशुदा माना जाता है। यह भी मायने रखता है कि वे कितना कमाते हैं। देश में कामकाजी लोगों की गरीबी एक अहम समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है। हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि लाखों लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है और उनकी पहुंच स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक खातों आदि तक हुई है। इसके बावजूद वेतन और आय के स्तर में कमी से सवाल उठता है कि क्या सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच आय की गरीबी दूर करने के लिए पर्याप्त है। महामारी के बाद सरकारी व्यय की बदौलत वृद्धि में तेज वापसी के बावजूद देश में निजी निवेश कमजोर है। यह रोजगार निर्माण को क्षति पहुंचा रहा है। भारत को अपनी आबादी के लिए उत्पादक रोजगार तैयार करने की आवश्यकता है जो आय और बेहतरी बढ़ाएंगे। इससे मांग सुधारने में मदद मिलेगी और वृद्धि चक्र में बेहतरी आएगी।

अजय मोहंती

मानविकी और विज्ञान की खाई पाटेगा डेटा विज्ञान

तेजी से डिजिटल होती दुनिया में डेटा विज्ञान का अध्ययन सभी वर्गों के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। बता रहे हैं अजित बालकृष्णन

चंद रोज पहले एक प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने मुझे इस बात पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया कि वे अपने पाठ्यक्रम को किस प्रकार आधुनिक बनाएंगे। जब बोलने की मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि आधुनिकीकरण की दिशा में सबसे अहम पहला कदम होगा डिजिटल ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी की पढ़ाई शुरू कराना। शुरुआत में इसे स्नातक स्तर पर शुरू किया जा सकता है और स्कूलों से कला या विज्ञान की पढ़ाई करके आने वाले बच्चों को इसे पढ़ाया जा सकता है। जब मैं अपनी बात कह रहा था तब मैंने ध्यान दिया कि वहां बैठे दर्जन भर प्रोफेसरों के चेहरों पर पहेलीनुमा भाव थे। उनमें से एक ने मुझसे कहा, 'मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि कला और मानविकी से पढ़ाई करने वाला एक भी बच्चा इस पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं लेगाः डिजिटल शब्द उसे भयभीत कर देगा।' एक बार उनके यह कह लेने के बाद कक्ष में मौजूद अन्य प्रोफेसरों ने भी उनकी बात से सहमति जताई।

मैंने पूछा, 'क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस वर्ष से देश के सभी विद्यालयों में डेटा विज्ञान पढ़ाया जाएगा?' मेरे इस प्रश्न के उत्तर में भी उन लोगों के चेहरों पर उलझन के भाव नजर आए। तब मैंने बताया कि यह उस 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समूह का प्रमुख सुझाव है जिसमें मैं भी शामिल था और जिसने 2020 की यह शिक्षा नीति तैयार की है। जब विशेषज्ञ समूह के सभी सदस्यों ने मेरे सुझाव को तत्काल सुझाव कर उसे प्रमुख अनुशंसा बनाया था तो मैं भी रोमांचित हो गया था। अब तो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और मैं देख सकता हूं कि प्रारंभिक पुस्तक तैयार भी हो चुकी है। इसे इंटरनेट पर 'डेटा साइंस ग्रेड 8 टीचर हैंडबुक' के नाम से तलाश भी किया जा सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएससी) के स्कूलों ने भी डेटा विज्ञान को लेकर अपनी उत्सुकता दिखाई है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, 'इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य है डेटा विज्ञान के लिए बुनियाद तैयार करना, डेटा संग्रहण के तरीके को समझना, उसका विश्लेषण करना और यह देखना कि समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में उनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें डेटा से जुड़े नैतिकता के प्रश्नों को भी संबोधित किया जाएगा तथा डेटा विज्ञान के एआई आधारित इस्तेमालों का आधार तैयार किया जाएगा। ऐसे में सीबीएसई डेटा विज्ञान का 12 घंटों का एक कौशल मॉड्यूल पेश कर रहा है जो कक्षा आठ के लिए होगा। कक्षा नौ से बारहवीं तक यह एक कौशल संबंधी विषय होगा।'

दूसरे शब्दों में कहें तो तीन वर्षों में हमें देश में कॉलेज जाने के इच्छुक बच्चों में बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की होगी जो डेटा विज्ञान को लेकर उत्साहित होंगे और नई बातें जानने को लेकर उत्सुक भी होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस लक्ष्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे हैंः 'विज्ञान, समाज विज्ञान, कला, मानविकी तथा खेल आदि विविध क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की मदद से हर प्रकार के ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी।' उस दिन मेरे साथ जो प्रोफेसर थे उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया और पूछा, 'क्या आपका कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सभी बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी होगी और कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना होगा?'

जवाब में मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप अपनी बच्ची को साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं तो आप उसे गति के नियमों पर भाषण नहीं देते, आप उसे यह नहीं समझाते कि रबर के टायर कैसे बनते हैं और कैसे धातु से साइकल के अन्य हिस्से बनाए जाते हैं। आप उसे साइकिल पर बिठाते हैं, साइकिल को पकड़कर उसे संतुलन बनाना सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे अपने पैर जमीन पर रखकर संतुलन कायम करना है आदि आदि। समय बीतने के साथ वह खुद साइकिल चलाना सीख जाती है।

इसी प्रकार अगर कोई बच्चा डेटा विज्ञान सीखना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही सिखाई जाए। उदाहरण के लिए वह तीन क्रिकेटरों के 10 मैचों के स्कोर को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए, हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि हर क्रिकेटर का औसत कितना रहा और उनमें से प्रत्येक के बनाए रनों में कितना मानक विचलन रहा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसकी बल्लेबाजी में सबसे अधिक निरंतरता है। ऐसे वास्तविक अनुभवों के साथ डेटा विज्ञान के खास गुण सिखाए जा सकते हैं।

जब मैं यह सब कह रहा था, मैं देख सकता था कि प्रोफेसरों के चेहरे पर राहत के भाव थे लेकिन इसके साथ ही भविष्य की एक चुनौती भी नजर आ रही थी। अगर इसे सही ढंग से अंजाम दिया गया तो सभी स्तरों पर नागरिक डिजिटल दुनिया में कूद पड़ेंगे। उदाहरण के लिए जब मैं मुंबई में अपने आसपास के इलाके से गुजरता हूं तो मैं देख सकता हूं कि कैसे सड़क किनारे फल और मछली बेचने वाले क्यूआर कोड लगाए रहते हैं और डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। इस समय 1.2 अरब भारतीयों के पास आधार संख्या है। करीब 30 करोड़ भारतीय ऑनलाइन खरीदारी करत हैं और उन सभी ने यह डिजिटल बदलाव खुशी-खुशी स्वीकार किया है।

बहरहाल, मैं चेतावनी के रूप में यही कह सकता हूं कि किसी भी नई तकनीकी लहर का तेज प्रसार सामाजिक उथल-पुथल भी पैदा कर सकता है। मुझे अभी भी याद है कि 1971 में जब मैंने आईआईएम कलकत्ता से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करना शुरू किया था तब बंबई के परेल इलाके में 100 के करीब कॉटन मिल थीं जो बहुत अच्छी स्थिति में थीं। उसके बाद हड़ताल और हिंसा तथा सस्ते सिंथेटिक कपड़े मसलन नायलॉन तथा टेरी कॉटन आदि के आगमन के बाद महज आठ से 10 वर्ष में ये मिलें पूरी तरह ढह गईं।

डेटा विज्ञान डिजिटल युग का ही एक हिस्सा है और इसके भी ऐसे पहलू होंगे जो निजता, झूठी खबर और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे खतरों से बने होंगे। इनकी वजह से पहले ही चिंता का माहौल बनने लगा है। इन चुनौतियों से उचित तरीके से निपटने तथा अवसरों का लाभ लेने के लिए जरूरी यह है कि डेटा विज्ञान का ज्ञान हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे। ऐसा होने पर ही मनुष्य के रूप में हम सही चयन कर पाएंगे।

(लेखक इंटरनेट उद्यमी हैं)

माइक्रोप्लास्टिक के खतरे को समझना जरूरी

सिंथेटिक प्लास्टिक का इतिहास 19वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। किसी भी आविष्कार की तरह सिंथेटिक प्लास्टिक की खोज कुछ समस्याओं का समाधान खोजने के मकसद से शुरू हुई थी। दरअसल उस दौर में कछुए के खोल और हाथी दांत की उपलब्धता कम होने लगी थी जिनका इस्तेमाल 19वीं सदी में मुख्य रूप से कंघी, बिलियर्ड गेंदों, पियानो के बटन आदि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप में पियानो की चाबियों, बिलियर्ड की गेंद और कंघी की मांग बढ़ रही थी जबकि हाथी के दांत और कछुए के खोल का मिलना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उनकी आबादी घटने लगी थी।

एक रसायन विशेषज्ञ एलेक्जेंडर पार्क्स को 1862 में पहला वास्तविक सिंथेटिक प्लास्टिक, पार्केसिन बनाने का श्रेय दिया जाता है जो जल्द ही कुछ उत्पादों के लिए कछुए के खोल और हाथी दांत का एक सस्ता विकल्प बन गया।

1907 में बेल्जियम के रसायन विशेषज्ञ लियो बैकलैंड ने बेकलाइट का निर्माण किया जो हर तरह के इस्तेमाल के लिए पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था। इसके बाद, विकास तेजी से हुआ क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन की बड़ी कंपनियों जैसे बीएएसएफ, ड्यूपॉन्ट, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज और डाउ केमिकल्स ने अनुसंधान, उत्पाद विकास और मार्केटिंग में पैसा लगाया।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्लास्टिक का भरपूर इस्तेमाल हुआ और पैराशूट से लेकर रडार केबलिंग, वाहन और विमान के पहिये तक हर चीज में इसका इस्तेमाल किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, प्लास्टिक का नागरिक उपयोग तेजी से बढ़ा। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टिरीन, पीईटी और टेफ्लॉन का इस्तेमाल कपड़ों से लेकर खाद्य पैकेजिंग तक हर चीज में किया जाने लगा।

प्लास्टिक का उपयोग दशकों तक फलता-फूलता रहा और अब वैज्ञानिकों के साथ-साथ नीति निर्माता और नागरिक इस अप्रिय तथ्य को समझ पा रहे हैं कि जिन खूबियों के चलते प्लास्टिक इतना उपयोगी बना दरअसल उसी वजह से धरती प्रदूषित हो रही थी क्योंकि दरअसल प्लास्टिक का अस्तित्व पूरी तरह खत्म नहीं सकता। वे दशकों या सदियों तक न तो सड़ते हैं, न नष्ट होते हैं और न ही इनका क्षरण होता है। ऐसे में फेंका हुआ प्लास्टिक वास्तव में कचरा भरी जाने वाली जगहों और महासागरों में जमा हो जाता है जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी आपदा वाली स्थिति बना देता है।

प्रसेनजित दत्ता

समस्या का पता होना और उसका समाधान ढूंढना दो अलग-अलग बात है। अब तक फेंके गए प्लास्टिक से पृथ्वी को होने वाले खतरे की बात अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है लेकिन अभी तक इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है। समाधान खोजने के प्रयास को जो समर्थन या संसाधन मिलने चाहिए थे, वह नहीं मिला है। जैव रसायन और सूक्ष्म जीव विज्ञान में भी शोध के लिए कई दिलचस्प क्षेत्र हैं। समय-समय पर ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बताया गया जो प्लास्टिक का उपभोग करने के साथ ही उनके तत्त्वों को तोड़ते हैं लेकिन कुछ ही बड़े पैमाने वाले संयंत्रों में पहुंच पाए हैं। फोटोऑक्सिडेशन जैसी अन्य विधियां भी अब तक व्यापक स्तर पर कारगर नहीं हो सकी हैं।

आमतौर पर सभी नीतियां प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर केंद्रित रही हैं लेकिन यह अधिकांश देशों में बहुत सफल नहीं रही है क्योंकि सिंथेटिक प्लास्टिक के विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं या सस्ते नहीं होते हैं।

पिछले दो दशकों में, एक नई चिंता की बात सामने आई है और वह माइक्रो और नैनो-प्लास्टिक के सर्वव्यापी होने से जुड़ी है। प्लास्टिक को खराब होने में दशकों लग जाते हैं और यह कई टुकड़ों में टूट जाता है और ये इतने छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं कि इन्हें अक्सर नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल होता है। पिछले दशक में शोधकर्ताओं ने पाया है कि माइक्रो और नैनो प्लास्टिक की मौजूदगी हर जगह, मिट्टी, महासागरों और नदियों में, समुद्र और धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों, मानव अंगों, रक्त वाहिकाओं से लेकर श्वसन प्रणाली, यकृत और यहां तक कि गर्भनाल में भी है।

आखिर मनुष्यों के लिए माइक्रोप्लास्टिक कितना खतरनाक है? इस पर अभी शोध शुरू हो रहा है। शुरुआती अध्ययन दीर्घकालिक खतरों की ओर इशारा करते हैं लेकिन खतरे की सटीक प्रकृति और इसकी मात्रा निर्धारित करने में समय लगेगा। कुछ प्रमाण हैं कि इससे शरीर में सूजन और जलन पैदा हो सकती है। एक अनुमान है कि शरीर के विभिन्न अंगों में नैनोप्लास्टिक के रसायन के चलते कैंसर सहित कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अन्य अध्ययनों से पता चला है कि संचार प्रणाली में माइक्रो और नैनोप्लास्टिक हृदय संबंधी जोखिम को बढ़ा सकता है।

हालांकि, अभी तक माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का संबंध बीमारियों और जीवन-प्रत्याशा से रहा है लेकिन इसके संबंध को लेकर पर्याप्त शोध नहीं हो पाया है। इन संबंधों को स्थापित करने में काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए, हम हाल तक मानव शरीर के लिए वायु प्रदूषण के खतरों को नहीं समझ पाए थे।

इस क्षेत्र में शोध के लिए बहुत अधिक फंडिंग और अध्ययन की आवश्यकता है। विशेष रूप से उन खतरों के लिहाज से जो शिशुओं, छोटे बच्चों या यहां तक कि गर्भवती महिलाओं के सामने पैदा होते हैं है। साथ ही खतरा उन लोगों के लिए भी है जो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं।

माइक्रोप्लास्टिक से हमारे शरीर को होने वाली बीमारियां, जलन और सूजन से निपटने के तरीके खोजने के लिए अन्य अध्ययनों की आवश्यकता है। समुद्री जीवों और नदी में पाए जाने वाले जीवों के साथ-साथ पौधों और जानवरों पर उनके प्रभाव का भी अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ देश इस पर ध्यान दे रहे हैं मिसाल के तौर पर कनाडा ने कुछ करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं लेकिन यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बड़े पैमाने पर निजी या सार्वजनिक पूंजी को आकर्षित कर रहा है। इसका कारण काफी सरल है। अनुसंधान के अन्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र के निवेश पर बेहतर रिटर्न का वादा कर रहे हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) या नई बैटरी रसायन विज्ञान के व्यावसायिक अवसरों को समझना आसान होता है और इसलिए इसके लिए अरबों डॉलर की फंडिंग होती है। मनुष्यों पर माइक्रोप्लास्टिक के खतरों का अध्ययन करने से बड़े कारोबारी अवसरों का वादा नहीं किया जा सकता है।

जब तक सिलिकन वैली के कुछ अरबपति यह तय नहीं कर लेते कि माइक्रोप्लास्टिक उनकी जीवन-प्रत्याशा को कम कर सकता है तब तक संभावना नहीं है कि इस शोध के लिए बड़ी फंडिंग होगी। जहां तक नीति निर्माताओं का सवाल है तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पहले से ही काफी हैं जिनसे निपटना जरूरी है ताकि इस दीर्घकालिक खतरे को दूर किया जा सके। लेकिन एक दुखद पहलू यह है कि जब तक चीजें चरम सीमा पर नहीं पहुंच जातीं, तब तक कोई भी समाधान खोजना नहीं चाहता।

(लेखक बिज़नेस टुडे और बिज़नेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक और संपादकीय परामर्श संस्था प्रोजैक व्यू के संस्थापक हैं)

आपका पक्ष

कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निर्माण में व्यापक दृष्टिकोण

कौशल प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार करते समय स्थानीय के साथ-साथ वैश्विक जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज पूरी दुनिया में नए प्रशिक्षित कामगारों की मांग बढ़ गई है। प्रशिक्षित भारतीय युवा इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं में टेलरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटीशियन, सौर ऊर्जा टेक्नीशियन, घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग, सिलाई- कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण देकर हजारों युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वहीं कंप्यूटर और परिधान प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी, खुदरा क्षेत्र, आतिथ्य सत्कार, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य प्रसंस्करण आदि में भी कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। युवाओं में यह भाव आना चाहिए कि 'मैं खुद अपना काम करके रोजगार पाऊंगा और अन्य को भी रोजगार दूंगा।'

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं में टेलरिंग, कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है

जल संचयन करने का सबक

बेंगलूरु जल संकट हमें कुशल जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार सोच, आपसी सहयोग और साझेदारी, पानी का पुनः चक्रीकरण और वर्षा जल का संचयन सिखाता है। जल संकट को कुशल जल प्रबंधन से हर शहर में दूर किया जा सकता है बशर्ते पानी की बचत करने की आदत बन जाए। बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए तालाबों का गहरा करने को प्राथमिकता दी जाए और पानी को बहने से रोकने के लिए बांध बनाए जाएं।

भगवानदास छारिया, इंदौर

जल का उचित प्रबंधन जरूरी

जल का उचित प्रबंधन न होने से बेंगलूरु में जल संकट पैदा हुआ है। इससे सबक लेकर हर शहर को अपने जल प्रबंधन का ढांचा उचित ढंग से बनाना होगा। कावेरी नदी के अलावा झीलों से मिल रहे पानी के बाद भी शहर में गंभीर जल संकट पैदा हो गया। शहर में पेयजल और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होना शर्मनाक है।

मनमोहन राजावत, शाजापुर

हर बूंद का हो संरक्षण

जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रही जल गुणवत्ता असल में विश्व के लिए चुनौती है। अगर हम वर्षा जल संरक्षित नहीं कर सके तो हालात गंभीर हो सकते हैं। बेंगलूरु जल संकट हमारे लिए प्रकृति की चेतावनी है। इससे हमें सबक सीखने होंगे और पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण करना ही होगा। प्राकृतिक जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं। इसका एक कारण हमारी लापरवाही भी है। इस विषय पर गहन चिंतन की जरूरत है।

अंकित कुमार सोनी, मनावर

जल का किफायती उपयोग

बेंगलूरू जल संकट से हमें जल की महत्ता अब तो समझ ही लेनी चाहिए। हम सभी जल के समझदारी और किफायती उपयोग के प्रति लापरवाह हैं। जल के किफायती उपयोग के साथ ही जल संरक्षण और संग्रहण की आवश्यकता से अभ्यस्त होना समय की मांग है। भू जल स्तर में हो रही निरंतर गिरावट रोकने के लिए वर्षा जल संचयन के साथ ही जल स्रोतों का अतिक्रमण रोकना भी आवश्यक है।

रमेश चंद्र कर्नावट, उज्जैन

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

ग्रीस के हेलेनिक नैशनल डिफेंस स्टाफ (एचएनडीजीएस) के प्रमुख जनरल दिमित्रियोस चौपिस ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में सोमवार को गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 9 अप्रैल 2024

संतुलित नजरिया

राजस्थान और गुजरात में अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (सोहन चिड़िया) के लिए खतरनाक माने गए सोलर एनर्जी प्रॉजेक्ट से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो संतुलित रुख अपनाया है, वह पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास को लेकर जुडिशरी की नई सोच का संकेत करता है।

रोक से दिक्कत | मामला 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के प्रॉजेक्ट से जुड़ा है, जिस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी थी। कोर्ट के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि बिजली के इन तारों से टकराकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत होती है। राजस्थान और गुजरात का वह इलाका इन पक्षियों के आवागमन की राह में पड़ता है। मगर यही इलाका सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं से भरपूर भी माना जाता है। इस प्रॉजेक्ट पर रोक के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी देश की योजनाएं बुरी तरह बाधित हो रही थीं।

AI Image

पक्षियों के लिए होगा संरक्षित क्षेत्र

बीच की राह | ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि इस तरह की एकतरफा रोक से बात नहीं बनती। पक्षियों को बचाना अगर महत्वपूर्ण है तो वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने का देश का संकल्प पूरा होना भी जरूरी है। लिहाजा, कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि 13000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इन पक्षियों के आवास के रूप में संरक्षित रखने और 77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन पर लगी रोक हटाने की बात कही।

संवैधानिक मूल्यों का संदर्भ | जलवायु बदलाव के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए सरकार नीतियों में जो भी बदलाव ला रही हो, हालात की गंभीरता के मद्देनजर यह काफी नहीं । इन प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए इन्हें संवैधानिक मूल्यों से जोड़ने की जरूरत थी। जलवायु परिवर्तन से आम लोगों के जीवन पर पड़ते विपरीत प्रभावों और ऊर्जा की कमी जैसे संकटों को नागरिकों के जीवन व समानता के अधिकार से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश की है।

वैकल्पिक ऊर्जा | अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा की डिमांड में होने वाले कुल इजाफे का 25% भारत में होगा। पर्यावरण प्रदूषण का दबाव स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत बढ़ाएगा। भारत में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावना भी है। इसे देखते हुए ही भारत सरकार ने 2030 तक 500 गिगावॉट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने और 2070 तक शून्य उत्सर्जन की स्थिति में पहुंचने का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इन सभी तथ्यों का ध्यान रखा गया है।

बेहतर भविष्य की ओर | कुल मिलाकर देखा जाए तो शीर्ष अदालत का यह फैसला ऐसा कानूनी नजरिया देता है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाए रखते हुए तरक्की सुनिश्चित करने की राह पर आगे बढ़ना आसान बनाएगा।

धूप-छांव

कम नहीं यह सदी

प्रणव प्रियदर्शी

भीषण संताप हमारे जीवन की दशा ही नहीं, चिंतन की दिशा निर्धारित करने और उसकी तीव्रता बढ़ाने का भी काम करते हैं। पिछली सदी के ऐसे संताप देखें तो प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध उसमें निश्चित तौर पर शामिल होंगे। जर्मनी में हिटलर के यातना शिविर और भारत में देश-विभाजन भी वैसे ही संताप कहे जाएंगे जो लगभग पूरी सदी कई पीढ़ियों के हालात, सोच और भावनाओं को आकार देने में अहम भूमिका निभाते रहे।

इस सदी में उतने बड़े स्तर पर वैसी कोई बड़ी परिघटना अब तक नहीं नजर आती। कह सकते हैं कि अभी यह सदी हमारे सामने पूरी तरह खुली भी कहां है। ले-देकर एक चौथाई ही तो गुजरी है। लेकिन पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। और फिर जैसा कि हर पीढ़ी अपने बाद वाली पीढ़ी से कहती है कि बेटा तुम्हारी उमर में मैंने तो कितना कुछ कर लिया था, कुछ वैसे ही पिछली सदी कह सकती है कि बच्चू तुम तो पच्चीस के होने को आए, मैंने तो 15 की उमर में ही विश्वयुद्ध दिखा दिया था! लेकिन हर जिंदगी की तरह हर सदी भी अपने हिसाब से चलती, बढ़ती और विकसित होती है। तो इसे भी वक्त देना होगा। वैसे अब तक में यह एक बार वैश्विक मंदी का अहसास तो करा ही चुकी है। कई देशों में ऐसी तानाशाही सोच वाला नेतृत्व फल-फूल भी रहा है, जिसे मौका मिल जाता तो हिटलर उसके सामने पानी भरता नजर आएगा। इस्राइल भले हिटलर के संताप झेलकर निकले यहूदी लोगों का देश हो, लेकिन गाजा के लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी फीलिंग देने में मौजूदा इस्राइली नेतृत्व ने कोई कोर-कसर बाकी तो नहीं रहने दी है।

कोई कारण नहीं है कि मौजूदा सदी पिछली सदी के सामने कमतर महसूस करे। मनुष्यता के सिर पर बड़ी से बड़ी मुसीबतें लाने और उसकी कठिन से कठिन परीक्षा लेने में यह सदी पीछे रहेगी, ऐसा अभी से मान लेना ठीक नहीं होगा। यही देखिए कि पिछली सदी अगर परमाणु बम के रूप में ऐसा हथियार ले आई थी, जिससे पूरी मनुष्यता अपने अस्तित्व पर भीषण खतरा महसूस करती रही, कोई एक-दो साल नहीं शीत युद्ध की पूरी अवधि के दौरान करती रही, तो यह सदी भी जेनरेटिव AI का जो नया टूल लेकर आई है, वह क्या कमाल करेगा, इस बारे में इसे बनाने वाले भी नहीं बता पा रहे। इस तकनीक के अच्छे-बुरे परिणाम आने वाले वक्त में सामने आएंगे। तो इस सदी को कम न समझें। मगर ये सारी मुसीबतें मायने तभी रखती हैं जब उनसे निपटने में मनुष्यता की अपनी कुशलता निखरती रहे। बड़े से बड़ा बॉलर, कठिन से कठिन बॉल फेंके, लेकिन अगर बैट्समैन अपना पूरा कौशल नहीं दिखाएगा तो क्या अच्छे क्रिकेट का मजा मिल सकता है? नहीं ना। इसलिए अहम सवाल यह है कि आने वाली चुनौतियों से निपटने की हमारी यानी इंसानी चेतना की तैयारी कैसी है।

बोल वचन

कहां से आई जूठन

राहुल पाण्डेय

जूठन को लेकर भारतीय समाज में जितनी जटिलताएं पाई जाती हैं, उतनी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं पाई जातीं। जूठन संस्कृत से बोलचाल में आया हुआ शब्द है। संस्कृत में इसे जुष्ट कहते हैं। यह जु धातु से बना है। जु का अर्थ है खाना या भोगना। रामकथा में राम शबरी के जूठे बेर खाकर शबरी को तारते हैं। शादियों में जयमाल के बाद वर-वधू एक-दूसरे की जूठन खाते हैं। अपने यहां किसी का जूठा खाने का अर्थ यह भी है कि उसका पूरी तरह से हो जाना, अपना संपूर्ण अस्तित्व उसे समर्पित कर देना। शायद यही वजह रही कि भारतीय समाज में बहुत सारे लोगों को जूठन खिलाकर अस्तित्वहीन बनाया गया। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा, और बदकिस्मती से ऐसा अभी तक चल रहा है। शहरों में तो यह चलन अब बहुत कम हो गया है, लेकिन गांवों में यह चलन आज भी है। इसमें स्त्री पति के खाना खत्म होने का इंतजार करती रहती है। जब पतिदेव जीमकर उठते हैं तो वह उनकी जूठी थाली में खाती है। इसे वह पतिदेव का प्रसाद मानती है। इसे प्रसाद अस्तित्व को होम कर चुके लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि वहां अस्तित्व का संघर्ष खत्म हो चुका होता है। मशहूर लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' अस्तित्व के इसी संघर्ष की आत्मकथा है। वहीं, प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी भी जूठन की एक अलग जटिलता बयान करती है। वहां भूख और कुछ अच्छा खाने की लालच जूठे-सच्चे का भेद भूल चुकी है। जूठन की यह जटिलता इंग्लिश नहीं पकड़ पाई है। इंग्लिश जूठन को सीधे-सीधे कचरा बताती है। जूठन के लिए इंग्लिश में garbage और leavings जैसे शब्द हैं। पिछले दिनों खबर आई कि दुनिया भर में हर साल सवा अरब टन से भी अधिक जूठन कचरे में फेंक दी जा रही है। इस जूठन को फिंकवाने में 17% रोल आज की सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स का भी है। कहते हैं कि इतनी जूठन अगर ना फेंकी जाए तो एक अरब लोगों का पेट भर सकता है।

Subrata Dhar

पिछले चुनाव में BJP और NDA ने शानदार प्रदर्शन किया था, इस बार का समीकरण आसान नहीं

लोकसभा चुनाव में विपक्ष देने जा रहा चुनौती

राज कुमार सिंह

सत्ता के दावेदारों के दावे अपनी जगह हैं, पर नई सरकार के बारे में भविष्यवाणी करना इस बार उतना आसान नहीं, जितना पिछले दो चुनावों में था। बेशक, सत्तारूढ़ NDA के पास दस साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में लोकप्रिय चेहरा है। BJP की अगुआई वाले NDA ने मोदी सरकार की 'हैट्रिक' का नारा देते हुए क्रमशः 370 और 400 सीटों का लक्ष्य भी घोषित कर दिया है। मगर दस साल की सत्ता के बाद भी छोटे-छोटे दलों पर डोरे डालना प्रतिकूल संदेश दे रहा है।

कुनबा बढ़ाने की मजबूरी | NDA 26 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने अकेले दम बहुमत मिलने के बावजूद केंद्र में NDA की ही सरकार बनाई, लेकिन उसका महत्व पिछले साल I.N.D.I.A. बनने के बाद ज्यादा दिखा। घटक दलों की संख्या में I.N.D.I.A. को पीछे छोड़ने के लिए NDA का कुनबा भी बढ़ाया गया। इस खेल में संसद में नाममात्र की उपस्थिति या बिना उपस्थिति वाले दलों को भी साथ लेने में संकोच दोनों में से किसी गठबंधन ने नहीं किया। क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि लोकसभा चुनाव में मुकाबला इतना कड़ा हो सकता है कि दो-चार प्रतिशत वोट रखने वाले दल-नेता भी महत्वपूर्ण साबित हों?

बिगड़े समीकरण | सवाल यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में विभाजित विपक्ष के बीच और मोदी की लोकप्रियता के चरम पर भी BJP बहुमत के लिए जरूरी संख्या से मात्र 31 सीटें ज्यादा जीत पाई और पूरा NDA 81 सीटें ज्यादा जुटा पाया, तो 2024 के चुनाव में 370 और 400 का लक्ष्य कैसे मुमकिन होगा? ध्यान रहे, जिन राज्यों में पिछले चुनाव में BJP और NDA ने शानदार प्रदर्शन किया था, वहां इस बार समीकरण गड़बड़ाया हुआ है।

राज से दोस्ती का प्रयास | 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र से पिछली बार NDA ने 41 सीटें जीती थीं। राज्य में सरकार के नेतृत्व को लेकर हुई तकरार के बाद अब दोनों अलग-अलग पाले में हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिर गई। बाद में NCP भी टूट गई। दोनों दलों से बगावत करने वाले गुट अब BJP के साथ NDA में हैं। उनके सहारे पुराना प्रदर्शन दोहरा पाने का भरोसा होता तो BJP राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गठबंधन की कोशिश नहीं करती।

विपक्ष का चैलेंज

- कई राज्यों में बदल गए हैं हालात
- नॉर्थ में नुकसान के दिख रहे हैं आसार
- साउथ से भरपाई करनी मुश्किल है

बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला | 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में पिछली बार BJP ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देते हुए 18 सीटें जीती थीं। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. बनने के बावजूद तृणमूल सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तृणमूल, BJP और कांग्रेस-वाम मोर्चा के बीच दिलचस्प त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में BJP पर सीटें बढ़ाने से ज्यादा बचाने का दबाव रहेगा, क्योंकि ममता सरकार से नाराज वोटरों के लिए BJP से इतर भी एक विकल्प उपलब्ध होगा। तृणमूल और कांग्रेस-वाम मोर्चा अलग लड़कर भी जो सीटें जीतेंगे, वे चुनाव के बाद BJP विरोधी खेमे में ही रहेंगी।

रामविलास की कमी | 40 सीटों वाले बिहार में पिछली बार NDA ने 39 सीटें जीत कर लगभग क्लीन स्वीप किया था। नीतीश कुमार फिर पाला बदल कर NDA में लौट चुके हैं, पर रामविलास पासवान की कमी कौन पूरी करेगा, जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने छह सीटें जीती थीं? रामविलास के निधन के बाद LJP भाई और बेटे की बीच बंट गई। पांच सांसदों के नेता के रूप में भाई पशुपति पारस को BJP ने केंद्र में मंत्री भी बना दिया था, लेकिन अब सीट बंटवारे में बेटे चिराग पर दांव लगाया है। दोनों में से कौन-सा फैसला गलत था- चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन NDA के लिए 39 सीटें जीत खासा मुश्किल होगा।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार | 28 लोकसभा सीटों वाले कर्नाटक में पिछली बार BJP की सरकार थी। उसने वहां अकेले दम पर 25 सीटें जीती थीं। BJP समर्थित एक निर्दलीय भी जीता था। पिछले साल कांग्रेस के हाथों राज्य की सत्ता गंवा चुकी BJP के लिए पिछला चुनावी प्रदर्शन दोहरा पाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। बेशक BJP ने एचडी देवेगौड़ा के JDS से गठबंधन किया है, फिर भी कर्नाटक में कांग्रेस की सीटें बढ़ने की तगड़ी संभावना है। आंध्र में तो BJP चंद्रबाबू नायडू की TDP को NDA में वापस लाने में सफल रही, लेकिन ओडिशा में नवीन पटनायक और पंजाब में सुखबीर सिंह बादल ने फिर दोस्ती करने से इनकार कर दिया है।

सर्वश्रेष्ठ के आगे | उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में BJP पिछले चुनाव में लगभग सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रदर्शन कर चुकी है। मोदी आंध्र, तमिलनाडु और केरल में खाता खोलने और दक्षिण में सीटें बढ़ाने की पूरी कवायद कर रहे हैं, पर जमीनी हालात अनुकूल नहीं।

लक्ष्य नहीं, महज नारा | ऐसे में जबकि पुरानी सीटें घटने का खतरा है, 370 और 400 सीटों का नारा माहौल बनाने की रणनीति ज्यादा है। बेशक चुनाव में कई बार मुद्दों से ज्यादा माहौल निर्णायक साबित होता है। BJP को माहौल बनाने में महारत भी हासिल है। उसके पास राम मंदिर, धारा-370 और तीन तलाक जैसे भावनात्मक मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों की कमी विपक्ष के पास भी नहीं।

विपक्ष के मुद्दे | वादा हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का था, लेकिन बेरोजगारी चरम पर है। वादा अच्छे दिन लाने का था, पर महंगाई बेलगाम है। वादा विदेश से काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार समाप्त करने का था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में हो रहे खुलासे ने इन दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ED, CBI और इनकम टैक्स विभाग की विपक्षी नेताओं के विरुद्ध अति सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

तटस्थ दलों की भूमिका | ऐसे में चुनाव परिणाम मुख्यतः इस पर निर्भर करेंगे कि सत्तापक्ष और विपक्ष में से कौन अपने मुद्दों को ज्यादा प्रभावी ढंग से उठाते हुए माहौल बना सकता है। जाहिर है, जो दल तटस्थ हैं, वे चुनाव परिणाम के बाद अपनी सुविधा के अनुसार ही राह चुनेंगे, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु तो होता नहीं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

रील के चक्कर में जेल की हवा नहीं खाने का, क्या?

अपुन नौटंकी करेगा, तुम कैमरा पकड़ना। अक्खा वर्ल्ड को येड़ा बना के पेड़ा खाएंगे अपुन। थोड़े फॉलोवर अपनी कॉलोनी से बन जाएंगे और बाकी अपुन खरीद लेगा

नमिता जोशी

सर्किट, क्या सोच रयेला है? अपने घुटने में काइकू इत्ता जोर लगा रयेला है? क्या थॉट आयेला है भेजे में, बता भी दे। मुन्ना भाई के इतना पूछने पर सर्किट बोला, क्या बताऊं मुन्ना भाई, अभी अपुन नया करियर शुरू करने के बारे में सोच रयेला है सीरियसली। भोत हो गई भाईगिरी। चलो अभी कुछ नया बिजनेस आइडिया सोचते हैं, नया करियर बनाते हैं। तभी कॉकरोच के माफिक एंट्री लिया चम्मन चिरकुट। बोला, भाई अपुन ने तो सोच भी लिया है। अपुन फल-फ्रूट का रेहड़ी लगाने का सोच रयेला है। गर्मी का टाइम आ गयेला है, ये धंधा अच्छा चलने वाला है। अपुन कू भी अब गलत धंधे से बाहर निकलने का है।

चिरकुट की बात सुनके सर्किट उसका अइसे मजाक उड़ाने लगा, जइसे हवा में लोग पतंग उड़ाते हैं। क्या बोल रयेला है चिरकुट तू? एक गलत धंधे से निकलकर तू दूसरे गलत धंधे में एंट्री करने का आइडिया लेके आयेला है, और बोलता है गलत काम बंद करेगा? चिरकुट शोले के माफिक भड़क के बोला, काइकू भेजा फ्राई कर रयेला है। फल-फ्रूट बेचने का काम गलत कइसे हो गया?

अपुन कू मालूम था चिरकुट कि तेरे भेजे में कुछ घुसने वाला नहीं है, सर्किट बोला। अपुन के गांव से चाचा का लड़का आयेला था। परसों अंगूर खा के अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने बोलेला है कि अंगूर में पेस्टिसाइड ने उसके पेट का गेम बजा डाला है। हर फ्रूट में मिलावट है, सबकू इंजेक्शन लगा के मार्केट में बेचते हैं। इससे अच्छी तो अपनी भाईगिरी है। तू अपने पेस्टिसाइड वाले फ्रूट खिलाके हम सबको बीमार करेगा क्या? सर्किट का बात सुनके अपुन कू भी लगा कि ये करेक्ट बोल रयेला है। अपुन बोला, नया बिजनेस आइडिया बताओ, अपुन इसके वास्ते स्ट्रगल करने कू भी तैयार है। अपुन की बात सुनके सर्किट बोला, मुन्ना भाई ये चिरकुट ने डिस्टर्ब कर दिया। अपुन तुमकू बताने वाला था अपुन का धांसू आइडिया। अपुन दोनों रील बनाना शुरू करते हैं। खोली में बैठे-बैठे कमाई होगी, बैंक बैलेंस बनेगा। अपुन बैठे बैठे सिलेब्रिटी बन जाएंगे और फिर धमाल मचाएंगे। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि अपुन कू रील बनाने वाला इन्फ्लुएंसर बनने के वास्ते कोई स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। होंगे ऐसे लोग जो रेलवे स्टेशन पे रात गुजार के या बिना टिकट सफर करके या रेस्टोरेंट में पिलेट धोकर स्ट्रगल करके फेमस होने का सपना देखते होंगे। अपुन दोनों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भोत आगे बढ़ गयेली है। अपुन नौटंकी करेगा, तुम कैमरा पकड़ना। अक्खा वर्ल्ड को येड़ा बना के पेड़ा खाएंगे अपुन। थोड़े फॉलोवर अपनी कॉलोनी से बन जाएंगे और बाकी अपुन खरीद लेगा। अपुन पैपराजी फोटोग्राफर लोग कू भी जानता है। तुम स्टार बन जाओगे दस दिन में। मुन्ना भाई और सर्किट शॉपिंग पे जा रयेले तो पैपराजी फोटो लेने के वास्ते आ जाएंगे। संडास से बाहर निकल रयेले तो क्लिक-क्लिक और अक्खा सोशल मीडिया में अपुन लोग काले बादल के माफिक छा जाएंगे, और वो भी दस दिन में।

सर्किट का आइडिया सुन के अब हंसने की बारी चिरकुट की थी। बोला, ये बिजनेस आइडिया है या जेल जाने का आइडिया है? देखा नहीं, आजकल रोज कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर का उसकी हरकतों की वजह से फाइन हो रयेला है और कितने लोग जेल की हवा खा रयेले हैं। तेरा सोशल मीडिया स्टार का बुलबुला कब फूटेगा, तेरेकू मालूम भी नहीं चलेगा। चिरकुट की बात भी एकदम करेक्ट लगी अपुन कू और सर्किट पे भोत खुन्नस आया। अपुन ने सर्किट कू बोला कि पेट पालने के वास्ते अइसी नौटंकी नहीं करने का है अपुन कू। हटा सावन की घटा... खा, खुजा, बत्ती बुझा के सो जा। बहुत हो गया फुट ले, वट ले, शाणा बन क्या?

AI Image

भेजा फ्राई

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesgroup.com** और सब्जेक्ट मे लिखे-'**भेजा फ्राई**'

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

कब खत्म होगा सस्पेंस

उत्तर प्रदेश की तीन लोकसभा सीटों पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि वहां से उम्मीदवार आखिर होगा कौन। इनमें दो सीटें कांग्रेस से जुड़ी हैं- अमेठी और रायबरेली। रायबरेली से मौजूदा सांसद हैं सोनिया गांधी, जिन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का संकेत दे दिया है। वहीं, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछली बार वह इस सीट पर स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस बार फिर से वह अमेठी से चुनावी मैदान में खम ठोकेंगे या या नहीं, अभी तक यह तय नहीं है। तीसरी सीट है कैसरगंज की, जहां से BJP के नेता बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। वही बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर पिछले दिनों महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद से BJP में उनका टिकट तय नहीं माना जा रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला 26 अप्रैल के बाद होगा। 26 अप्रैल के बाद इसलिए क्योंकि उससे इन तीनों सीटों के तार जुड़े हैं। कांग्रेस के अंदर से आ रही सूचनाओं के अनुसार, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा वह केरल के वायनाड में चुनाव होने के बाद कर सकते हैं ताकि वहां कोई गलत संदेश न जाए। ऐसे ही बृजभूषण सिंह की दावेदारी का एलान BJP राजस्थान में चुनाव होने के बाद कर सकती है ताकि वहां जाट वोटरों में कोई गलत संदेश न जाए। महिला पहलवानों के उन पर आरोप लगाने के बाद जाटों के बीच उन्हें लेकर खासी नाराजगी रही है।

जल्द चौंकाएंगी प्रियंका

पिछले कुछ समय से प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर उतनी सक्रिय नहीं दिख रही हैं, जैसे कि पहले दिखा करती थीं। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव प्रचार की फ्रंट लाइन संभालने के बाद वह अचानक रहस्यमय तरीके से परदे के पीछे चली गईं। इस आम चुनाव में भी उनकी भागीदारी सीमित ही दिख रही है। लेकिन यह तूफान के पहले की शांति बताई जा रही है। पार्टी के अंदर एक वर्ग दावा कर रहा है कि प्रियंका गांधी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही हैं। प्रियंका और उनकी टीम आम चुनाव के बाद बड़ी भूमिका में आ सकती है। पार्टी के अंदर संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव हो सकता है और इसकी पूरी कमान प्रियंका को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो उनके साथ कुछ चौंकाने वाले नाम भी जुड़ सकते हैं। सूत्रों की मानें तो एक चुनावी रणनीतिकार भी ऐसी सूरत में कांग्रेस से जुड़ सकते हैं, जिनकी कांग्रेस में एंट्री होते-होते रह गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि इसके लिए वह पार्टी के अंदर भी हर राज्य में अपने लिए मजबूत नेताओं की पहचान कर चुकी हैं।

मंत्रियों की चिंता

आम चुनाव की व्यस्तता के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रम के अनुसार हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं। इसमें वह चल रहे कामों की समीक्षा कर रहे हैं और जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं। पीएम मोदी पहले ही मंत्रियों से कह चुके हैं कि चुनाव के कारण कामकाज नहीं रुकना चाहिए। लेकिन इस मीटिंग में तमाम मंत्री प्रधानमंत्री से मिले संकेतों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस बात को जानने के लिए व्यग्र दिखते हैं कि अगर तीसरी बार BJP सत्ता में आई, तो क्या इस बार उनके लिए जगह बनेगी या नहीं। एक मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह जानने की इच्छा तो सभी मंत्रियों की है, लेकिन पीएम मोदी कहीं अधिक सतर्क हैं। वह ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे हैं, जिससे किसी को आगे का कोई अंदाजा लग सके।

तैयारी विधानसभा चुनाव की

महाराष्ट्र में आम चुनाव में दोनों पक्षों के अंदर विरोधाभास और दुविधा साफ देखी जा रही है। पिछले दिनों सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी महाविकास अघाड़ी, दोनों के अंदर सीटों पर समझौते को लेकर खासी उठापटक देखने को मिली। वहां स्पष्ट और सरल तरीके से सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया। दोनों पक्षों ने सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक संयुक्त एलान भी नहीं किया। स्थानीय नेताओं के अनुसार, बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं है। दरअसल, महाराष्ट्र में आम चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस और BJP को छोड़कर बाकी दल आम चुनाव से कहीं अधिक विधानसभा चुनाव को लेकर अधिक चिंतित हैं। NDA में चाहे शिंदे सेना हो या अजित पवार की NCP या फिर महाविकास अघाड़ी में उद्धव सेना हो या फिर शरद पवार की NCP, इन सभी दलों के लिए विधानसभा चुनाव उनके अस्तित्व की असली लड़ाई मानी जा रही है। वे इस आम चुनाव में भी विधानसभा चुनावों की तैयारी करते दिख रहे हैं। साथ ही, सभी दल मान रहे हैं कि आम चुनाव के परिणाम उनके दल की आगे की योजना को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही कशमकश BJP और कांग्रेस दोनों को चिंता में डाल रही है।

पारस की चाहत

बिहार में मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस शुरू में गठबंधन की गाड़ी में चढ़ने से वंचित रह गए। सहनी NDA और महागठबंधन दोनों से बारगेन करते रहे तो पारस को NDA ने चिराग पासवान के सामने किनारे कर दिया। लेकिन आखिरकार मुकेश सहनी की लॉटरी लगी और उन्हें महागठबंधन में तीन सीटें मिल गईं। इससे वह मुख्यधारा में आ गए। लेकिन पारस अभी भी खाली हाथ रह गए। उन्हें गठबंधन में भी जगह नहीं मिली। अंततः उन्होंने NDA को एकतरफा समर्थन देने की घोषणा कर दी। उनका दावा है कि चुनाव के बाद उन्हें उनका हक मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि पारस अब अपने लिए राज्यपाल का पद चाहते हैं, जबकि उनके अन्य सहयोगी BJP में शामिल होने का इरादा रखते हैं। BJP की पहली मंशा थी कि चाचा पारस अपने भतीजे चिराग से समझौता कर लें, लेकिन चिराग ने ऐसे किसी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद हालांकि BJP ने पारस से कोई ठोस वादा नहीं किया है, लेकिन उनके सामने उम्मीद रखकर बैठने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

कानून पर भरोसा हो

8 अप्रैल का संपादकीय 'भीड़ की अराजकता' पढ़ा। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर में हुई घटना दर्शाती है कि राज्य में कानून व्यवस्था पर अपराधी और गुंडे भारी पड़ रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से लोकसभा चुनाव के ऐन पहले पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिह्न लगने लगे हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश पर NIA की टीम गिरफ्तारी वारंट के साथ आरोपियों को पकड़ने गई थी। जिला प्रशासन को तो कानूनी कार्रवाई में NIA की टीम का सहयोग करना चाहिए था। अपराध की रोकथाम करना, आरोपियों को गिरफ्तार करना-करवाना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की पूरी जिम्मेदारी है। कानून पर भरोसा करना चाहिए और उसे अपना काम करने देना चाहिए।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

बड़े घराने की शादी

12 फरवरी को 'भेजा फ्राई' कॉलम में 'अपुन को भी आएगा उस शादी का इनविटेशन' बहुत ही बढ़िया लिखा है। गंभीर विश्लेषण वाले लेखों के बीच इस लेख को पढ़कर बहुत मजा आया। लेखिका ने बातों ही बातों में बड़े घराने की शादी और आम पब्लिक की सोच को अपने लेख में जिस अंदाज में दिखाया है, वह प्रशंसा के काबिल है। मुन्ना और सर्किट दोनों सूत्रधारों के बीच की बातचीत में पूंजीवादी सोच का खुलासा कर दिया है।

भेजा फ्राई

कुसुम लता, ईमेल से

पब्लिक की अपेक्षाएं

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपना घोषणापत्र या संकल्प पत्र जारी कर रहा है। इसमें ये दल मतदाताओं से वादे करते हैं जिन्हें सत्ता में आने पर पूरा करने का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये राजनीतिक दल लोगों के सामने वादे कर रहे हैं, उसी तरह से हम वोटरों को भी यह बताने की जरूरत है कि हमारी अपने नेताओं से क्या अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं, रोजगार की ऐसी व्यवस्था हो कि हमें फ्री बिजली, पानी लेने की जरूरत ही न पड़े। कोई भी कर्जमाफी की इच्छा न रखे। किसानों की आय दोगुनी हो जाए। एक सीमा के बाद कृषि आय पर भी कर लगे। राजनीतिक दलों को हमारी अपेक्षाओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

प्रचार के लिए हेलिकॉप्टर और गाड़ियों की धड़ल्ले से हो रही बुकिंग – एक खबर
– पब्लिक को अपना दमखम भी तो दिखाना है!

कपिल भाटी

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

मन में शैलपुत्री का वास हो तो कष्ट स्वयं कट जाते हैं

सलिल पाण्डेय

हमारा मन किसी पर्वत से कम नहीं है। यहीं से इच्छाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं की धारा प्रवाहित होती है। 'यथा मन तथा तन' को परिभाषित किया जाए तो मन जब उन्नत भाव में है, तो जीवन देवत्व के सिंहासन पर जा बैठता है। जब यह निम्न दिशा में लुढ़कता है तब वही मन जीवन में दैत्य भाव लाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने साधना-उपासना तथा जप-तप के सुअवसरों की खोज की। इसी खोज में नवरात्र के एक नहीं, बल्कि दो-दो सुयोग बने। पहला चैत्र नवरात्र तो दूसरा शारदीय नवरात्र। यह दोनों ही आध्यात्मिक साधना के सुअवसर हैं।

चैत्र नवरात्र में रात्रि का अंधकार कम होने लगता है और दिन का प्रकाश बढ़ने लगता है। जबकि शारदीय नवरात्र में इसके विपरीत होता है। यह बताता है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां अंधकार की तरह बढ़ती और घटती रहती हैं। इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखने का दायित्व मन का ही होता है। इसीलिए श्रीदुर्गासप्तशती में नवरात्र के प्रथम दिन ही शैलपुत्री के पूजन को वरीयता दी गई है। मन शैलपुत्री मां पार्वती की कृपा से युक्त रहे तो अनेकानेक संकट स्वयं नष्ट हो जाते हैं। फिर मन हिमालय पर्वत जैसे प्राकृतिक आकर्षण का रूप लेने लगता है।

साहित्य में नवरस का उल्लेख है। इन नवरसों की अधिष्ठात्री मां दुर्गा हैं। दुर्गा की शक्तियों के विविध रूपों में शैलपुत्री के बाद क्रमशः ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री देवियों की पूजा का वर्णन है। ये देवियां माता श्रीदुर्गा की अलग-अलग शक्तियां हैं। सामान्य रूप से इसे 'अनेकता में एकता' का रूप भी कहा जा सकता है। जन्म से लेकर अंत तक अनेकता के दौर से हर किसी को गुजरना पड़ता है। जीवन में शारीरिक और मानसिक स्तर पर विविधताओं को स्वीकार करना ही पड़ता है। इस यात्रा में मिलने वाली अनेकताओं को साधकर एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का संदेश नवरात्र देता है।

दुर्गा की व्याख्या के क्रम में हिंदी साहित्य के विद्वान समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि बहुत ही सार्थक दिखती है। उन्होंने दुर्ग की व्याख्या करते हुए लिखा, 'वह दुर्गम स्थल जहां पहुंचना अत्यंत कठिन हो। इसके भीतर राजा और उसकी सेना रहती है।' ऋग्वेद का उद्धरण भी दिया कि इंद्र ने दस्युओं के 99 दुर्गों को ध्वस्त किया था। यह दुर्ग क्या है? यह हमारा मन ही तो है। अनेकानेक कामनाओं से घिरे मन को कवच पहनाना जरूरी होता है। इस दुर्ग में क्या घट रहा, इसे जान पाना बड़ा दुर्गम कार्य होता है। मनुष्य मन के दुर्ग में कौन सी नकारात्मक शक्तियां घुस आईं, वह खुद नहीं जान पाता है। इसे जानने के लिए अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों को सतर्क करना आवश्यक होता है।

शक्तिहीन या नकारात्मक प्रवृत्तियों के शिकार व्यक्ति की इज्जत नहीं होती। जब अनुपयोगी हुए भौतिक पदार्थों को फेंक दिया जाता है, लोग तो शक्तिहीन व्यक्ति की उपयोगिता न होने पर उसे भी दुत्कार का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में परिवारिक और सामाजिक उपयोगिता के लिए सकारात्मक शक्तियों का होना आवश्यक है। दुर्गा को पराम्बा कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने पराम्बा का अर्थ माता के रूप में किया है। धर्मग्रंथों के अनुसार मनुष्य के अंतर्जगत में मां जैसी ऊर्जा शक्ति विद्यमान है। योग के विद्वान इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। नवरात्र की अवधि कुंडलिनी शक्तियों के जागरण का काल भी है। इसका लाभ हर किसी को अवश्य लेना चाहिए।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 9 अप्रैल • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है, जितना जीवन के लिए हवा-पानी
-अज्ञात

गैर जिम्मेदाराना तर्क

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) टीम पर हमले और फिर एफआईआर, चोरी और सीनाजोरी का मामला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की नजर में कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी; एनआईए, ईडी या सीबीआई हो, वे सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निजी एजेंसियां हैं। इनका इस्तेमाल वे सूबे की सत्ता हासिल करने में करते हैं। लिहाजा, तृणमूल कांग्रेस (तृमूकां) ने निर्वाचन आयोग से मिलकर अनुरोध किया है कि वह भाजपा का चुनावी हित साधने में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग रोके। तृमूकां का वहां अपनी बात रखने और उस पर उचित कार्रवाई की आशा का पूरा अधिकार है। पर अंधाधुंध विरोध में ममता इस बात को भूल जाती हैं कि वे केवल तृमूकां की अभियानी नेता भर नहीं हैं। वे मुख्यमंत्री जैसे एक

संवैधानिक पद पर हैं, जिसका काम प्रदेश के साथ राष्ट्रीय एकता, सम्प्रभुता और अखंडता की रक्षा का भी है। यह तभी हो सकता है कि जब राज्य एवं संघ के कर्त्तव्यों का पालन किया जाए। पहले ईडी और अब एनआईए मामले में ऐसा नहीं हुआ है। एनआईए की टीम 2022 के एक आतंकवादी मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, उस पर उनके समर्थकों, जिन्हें कांग्रेस नेता अधीर रंजन 'दीदी के गुंडे' कहते हैं, ने हमला कर दिया। मुख्यमंत्री एनआई टीम की कार्रवाई का सपोर्ट करने, उसे पुलिस सुरक्षा देने और हमलावरों की गिरफ्तारी का निर्देश देने के बजाय हास्यास्पद तर्क दे रही हैं। ममता मुख्यमंत्री हैं, उनके अधीन पुलिस समेत राज्य की कई जांच एजेंसियां हैं, जिनकी रात की रेड एक रूटीन-वर्क है। इसी बिना पर एनआईए की रेड का विरोध गैरजिम्मेदाराना है। ममता यह भी जानती हैं कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए गई कोई भी टीम, अगर वह पुलिस से अभिरक्षित नहीं है तो गुस्साए परिजनों के हमले का खुला द्वार होती है। बदसलूकी का उस पर इल्जाम तो मामूली बात है जबकि यह कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और अफसरों पर हमले का मामला था, जिसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ममता क्या बताएंगी कि संदेशखालि का मामला इतनी ही फुर्ती से क्यों दर्ज नहीं हो सका था? दरअसल, एनआईए प्रकरण से ममता सरकार में संरक्षित आतंकवाद की फिर पोल-पट्टी खुल गई है। ऐसा करके वे चंद वोटों को ही गारंटिड कर सकी हैं। उसी समुदाय के अधिकतर लोगों एवं सूबे का भरोसा हार गई हैं, जिनकी कामना आतंकवाद-मुक्त शांतिपूर्ण-सहअस्तित्व की है।

भरोसा गारंटी का

मोदी की गारंटी कांग्रेस और राजद वाले इंडी गठबंधन को परेशान कर रही है और कांग्रेस टुकड़े-टुकड़े गैंग की भाषा बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए नवादा में ये बातें कही। अपने तीसरे कार्यकाल में कई और गारंटी आने की बात कहने वाले मोदी ने गांव की तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने व ड्रोन पायलट बनाने की योजना दोहराई। पीएम सूर्य पर चालू की गई अपनी मुफ्त बिजली योजना द्वारा गरीबों व मध्यवर्ग का बिजली बिल शून्य होने की बात भी की। मैं देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं, 24 घंटे काम करूंगा तो क्या यह गुनाह है। मोदी की नीयत साफ है, इसलिए गारंटी देता है, लेकिन अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वाले अपने को देश का स्थायी शासक समझने लगे हैं। हालांकि मोदी के इस भाषण के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी की

गारंटी को चायनीज बताया। साथ ही कांग्रेस के खातों को बंद करने पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रक्रिया दी कि चुनाव परिणामो के बाद मोदी को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ेगा। कहने को तो इन आरोपों प्रत्यारोपों को चुनावी कहा जा सकता है। मगर यह हकीकत है कि मोदी सरकार अपने पिछले दोनों कार्यकालों की विभिन्न योजनाओं का प्रचार निरंतर करती है। मोदी ने खुद को किसी ब्रांड की तरह स्थापित ही नहीं किया है बल्कि इस प्रचार को लगातार गंभीरतापूर्वक प्रसारित भी किया जाता रहा है। मुफ्त योजनाओं के बल पर मतदाताओं को लुभाने का यह कोई नायाब तरीका नहीं है। साल दर साल इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। शिक्षा, सेहत, रोजगार और पर्यावरण जैसी बुनियादी बातों की बजाए लोक-लुभावन वायदों के बल पर मतदाताओं को फौरी तौर पर प्रभावित करना लंबे समय के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। निःसंदेह मोदी बगैर किसी अवकाश के लगातार काम करते हैं। साथ ही चौकन्ने रहते हैं और अपनी बातों से जनता को प्रभावित करने का गुर उन्हें भली-भांति आता है। जैसा कि राम मंदिर बनाने की बात दोहरा कर वे बार-बार अपने वायदे निभाने के अंदाज को दोहरा कर जनता को आश्वस्त करते भी नजर आते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताइगा कि उनके पिछले वायदों के भरोसे रहा मतदाता इन नये वायदों पर कितना विश्वास करता है।

चुनाव जो न कराए

सामयिक

अवधेश कुमार

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर जाकर उसे महान और मसीहा साबित करने की उस अभियान को आगे बढ़ाया जो उसकी मौत के समय से ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जेल में रहते हुए मुख्तार को पांच बार विधायक बनाया तो इसका मतलब है कि वह जनता के दुख दर्द में शामिल रहे और उसी का परिणाम है कि जनाजे में इतनी अधिक भीड़ उमड़ी। उन्होंने बांदा जेल में मुख्तार की मृत्यु पर सरकार को घेरा तथा उसकी तुलना रूस में बिना नाम लिए विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी की जेल में हुई मृत्यु से कर दी।

मुख्तार अंसारी पिछले लंबे समय से जब भी वीडियो में आया काफी कमजोर दिखता था। व्हीलचेयर पर ही उसके बाहर निकलने या अंदर जाने की तस्वीरें आईं थीं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में अनेक बीमारियां लिखी हुई है। इतनी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की कभी भी किसी कारण से मृत्यु हो सकती है। वैसे भी बाहुबल और धनबल की बदौलत बादशाहत कायम करने की मानसिकता में जीने वाले व्यक्ति को जेल में आम अपराधी की तरह व्यवहार से मानसिक आघात लगना बिल्कुल स्वाभाविक है।

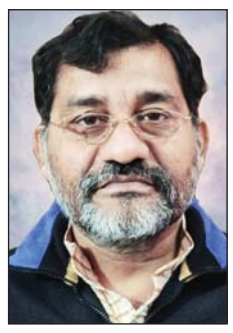

प्रचार यही हो रहा है कि उसे मारा गया है। कुछ दिनों से उसके परिवार और वकील धीमा जहर देने का आरोप एक रणनीति के तहत लग रहे थे, जिसका उद्देश्य जमानत दिलाना या मन मुताबिक किसी जेल में शिफ्ट कराना था। मृत्यु से कुछ दिनों पहले बेटे से बातचीत के ऑडियो से उसके काफी अस्वस्थ व कमजोर होने के साथ गहरी निराशा में डूबे होने का पता भी चलता है। उसकी मृत्यु पर सपा, बसपा या कुछ अन्य पार्टियों, मजहबी नेताओं आदि ने जिस ढंग का माहौल बनाया है उसने आम व्यक्ति को उद्वेलित किया है। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे प्रशासन या जेल या सरकार उसे तत्काल गैरकानूनी तरीके से मारने का कदम उठाए। इस समय उसकी मृत्यु से किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला था। योगी आदित्यनाथ सरकार की दृष्टि से यह स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। मृत्यु के बाद उसे गरीबों का मसीहा और नायक बनाया जाना भय पैदा करता है। जितनी संख्या में उसके नमाज ए जनाजा में लोग शामिल हुए वह सामान्य अवस्था का द्योतक नहीं है। किसी उदारवादी, समाज हितैषी, हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए काम करने वाले मुसलमान की मृत्यु पर न ऐसी प्रतिक्रियाएं आतीं हैं न इतने लोग इकट्ठे होते हैं और न उनमें भावविह्वलता और आक्रामकता देखी जाती है। इसके विपरीत चाहे मुख्तार अंसारी हो, बिहार का बाहुबली सैयद शहाबुद्दीन, अतीक अहमद या मुंबई बम विस्फोटों का आतंकवादी टाइगर मेनन उनके जनाजे में इतने बड़े जन समूह का उभरना मुस्लिम समाज के अंदर बढ़ती ऐसी

प्रवृत्ति है, जिससे डरने और जिसको हर हाल में रोके जाने की आवश्यकता है। मुख्तार अंसारी न्यायालय द्वारा सिद्ध माफिया, हत्यारा, अपहरणकर्ता, सांप्रदायिक दंगा करने वाला बाहुबली था। 65 से ज्यादा मुकदमे उसके नाम पर थे जिनमें आठ में उसे सजा दी जा चुकी थी। इनमें दो में उम्र कैद की सजा थी। न्यायालय द्वारा घोषित सजा प्राप्त अपराधी को मुसलमानों का नायक, गरीबों का मसीहा बताया जाए तथा राजनीतिक पार्टियां और नेता उसके पक्ष में बयान दें इससे ज्यादा डरावना देश के लिए कुछ नहीं हो सकता? वे सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ न्यायपालिका पर भी प्रश्न उठा रहे हैं।

2013 में मुंबई बम विस्फोटों के अपराधी टाइगर मेनन के जनाजे में मुंबई में उमड़ी भीड़ ने पहली बार देश को हैरत में डाला था। उस समय से यह एक स्थापित प्रवृत्ति है। अतीक अहमद की हत्या पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न था लेकिन उसकी मृत्यु पर विशेष नमाज जगह-जगह अदा कर जन्नत की दुआ करना किस बात का द्योतक था? डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु पर इस तरह का दृश्य नहीं था। वस्तुतः उनके जनाजे में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक थी। कांग्रेस के शासनकाल से उत्पन्न राजनीति के अपराधीकरण के भयावह दौर में ऐसे अपराधी और बाहुबली, जिन्हें जेल में होना चाहिए वो माननीय विधायक और सांसद बनकर नीति-नियंता बन गए। अतीक, अंसारी या शहाबुद्दीन जैसों की एकमात्र योग्यता यही थी कि वो अपने अपराध के बल पर साम्राज्य कायम कर चुके थे तथा एक क्षेत्र विशेष में चुनाव जीतने-जिताने में सक्षम थे। इसी कारण सपा-बसपा दोनों ने उन्हें महत्व दिया और कांग्रेस पार्टी का भी उन्हें समर्थन ही रहा। जरा सोचिए, मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की सरेआम हत्या करवाई और आज कांग्रेस उसे अपराधी तक कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने उसे बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कराया तथा उसे वापस न लाया जा सके इसके लिए सर्वोच्च अदालत तक लड़ाइयां लड़ी। ऐसी पार्टियों के होते क्या उसे सजा मिल सकती थी?

ये पार्टियां भूल रही हैं कि देश ने राजनीति के अपराधीकरण और अल्पसंख्यकवाद के दौर को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र या फिर राज्यों में सरकार गठित होने के पीछे भी हिन्दुत्व, राष्ट्रवाद, विकास, जन कल्याण के साथ अपराध और भयमुक्त माहौल की उम्मीद भी बहुत बड़ा कारण रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 में भाजपा सरकार की वापसी का सबसे बड़ा कारण यही था कि अपराधी और माफिया के विरुद्ध अविश्वसनीय स्तर तक कार्रवाई हुई। योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि देश में आम लोगों के बीच अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध किसी भी दबाव से परे अडिग रहते हुए कठोरता से कार्रवाई करने वाले नायक के रूप में खड़े हुए हैं तो इसी कारण। उप्र में सभी समुदायों के आम आदमी की प्रक्रिया होती है कि हम अब निर्भय होकर सड़कों पर चल सकते हैं।

इसलिए बसपा, सपा या कांग्रेस या अन्य पार्टियां अगर मानती है कि ऐसे अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर वे मुस्लिम वोटों से फिर विजय प्राप्त कर सत्ता पा लेंगे तो यह सपना पूरा नहीं होने वाला। पर इस व्यवहार के कारण सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाया गया खतरनाक झूठ कि मुसलमानों की चुन-चुन कर हत्याएं हो रही हैं- देश में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण पैदा कर रहा है। ऐसी राजनीति और एक्टिविज्म भयभीत करने वाली है। मुख्तार जैसे लोग समाज के नायक नहीं खलनायक हैं। खलनायक को नायक बनाने की सांप्रदायिक और विभाजनकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध डटकर खड़ा होने की आवश्यकता है।

किसी उदारवादी, समाज हितैषी, हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए काम करने वाले मुसलमान की मृत्यु पर न ऐसी प्रतिक्रियाएं आतीं हैं न इतने लोग इकट्ठे होते हैं और न उनमें भावविह्वलता और आक्रामकता देखी जाती है। इसके विपरीत चाहे मुख्तार हो, बिहार का बाहुबली शहाबुद्दीन, अतीक अहमद या टाइगर मेनन उनके जनाजे में बड़े जन समूह का उभरना मुस्लिम समाज के अंदर बढ़ती ऐसी प्रवृत्ति है, जिससे डरने और हर हाल में रोके जाने की जरूरत है

- भारत में ऑटिजम के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव है, और शुरुआती दौर में ही इस बीमारी की पहचान के लिए मोबाइल टूल्स बनाए गए हैं, जिनसे बीमारी की पहचान करने में मदद मिल रही है
- यह बीमारी आनुवांशिक, पॉल्यूशन, पिता की ज्यादा उम्र आदि कारणों से होती है। यदि बच्चे ने 12 माह की उम्र में भी बोलना शुरू नहीं किया है या 16 माह में भी वह स्पष्ट शब्द नहीं बोल पा रहा है, तो माता-पिता को गंभीर होने की जरूरत है। यह व्यवहार ऑटिजम की तरफ इशारा कर रहा हो सकता है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

विपक्षी दलों की बड़ी कामयाबीः सरकार भी अब कह रही है कि जरूरत पड़ी तो वह अग्निवीर योजना की समीक्षा करेगी! राजस्थान के चुनाव दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समीक्षा की बात कही। देखिये, किसकी सरकार अग्निवीर योजना को रद्द कर सेना में रेगुलर नियुक्ति की परिपाटी बहाल करती है!

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

डंपिंग यार्ड बनते समुद्र तल

मुद्दा **मनीष कुमार चौधरी**

उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक गहराई की अधिक विस्तृत वैज्ञानिक समझ ने आकार लेना शुरू नहीं किया था। जैसे-जैसे यूरोपीय और अमेरिकियों की वाणिज्यिक और क्षेत्रीय आकांक्षाएं दुनिया भर में विस्तारित हुईं, महासागर के बारे में अधिक सटीक और अधिक विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता भी बढ़ी, लेकिन जल्द ही विकास की अंधाधुंध दौड़ में समुद्र की इन गहराइयों का बेजा इस्तेमाल शुरू हो गया। समुद्र की गहराई का उपयोग बड़ी मात्रा में परमाणु सामग्री के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में भी किया गया।

पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश, अमेरिकी, सोवियत, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई सरकारों ने सैकड़ों-हजारों टन अप्रचलित रासायनिक हथियारों को दुनिया भर के पानी की गहराई में या तो ड्रमों में या टुकड़ों में भेज दिया। हालांकि सार्वजनिक आक्रोश के कारण इस प्रथा को 1972 में समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2019 के एक अध्ययन में आर्कटिक महासागर के तल पर कम से कम 18 हजार रेडियोधर्मी वस्तुएं बिखरी हुई पाई गईं, उनमें से कई को सोवियत संघ द्वारा वहां फेंक दिया गया था। जब ये वस्तुएं अपनी जहरीली विरासत को पानी में छोड़ना शुरू कर देंगी, तब क्या होगा? कई पर्यावरणविदों ने इस स्थिति को 'समुद्र तल पर धीमी गति से चल रहा चेर्नोबिल' कहा है। हालांकि सोवियत संघ ने किसी भी अन्य देश की तुलना में समुद्र तल पर अधिक परमाणु कचरा फेंका था, लेकिन वह निश्चित रूप से अकेला नहीं था। 1948 और 1982 के बीच, ब्रिटिश सरकार ने लगभग 70 हजार टन परमाणु कचरा समुद्र की गहराई में भेज दिया। भले ही कम मात्रा में ही सही, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान और नीदरलैंड ऐसे कुछ देश हैं, जिन्होंने रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान के लिए समुद्र का उपयोग किया है। 2019 में चीनी वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच के तल पर रहने वाले उभयचरों के शरीर में 1940 और 50 के दशक में परमाणु बमों के विस्फोट से उपजे रेडियोधर्मी कार्बन-14 की खोज की। अब जबकि अंतरराष्ट्रीय संधियां समुद्र में रेडियोधर्मी सामग्री के डंपिंग पर रोक लगाती हैं, ब्रिटिश सरकार कुम्ब्रिया के समुद्र तल के नीचे 100 टन से अधिक प्लूटोनियम सहित 750,000 क्यूबिक मीटर परमाणु कचरे के निपटान की योजना तलाश रही है। 1946 से 1993 तक, तेरह देशों ने मुख्य रूप से चिकित्सा, अनुसंधान और परमाणु

उद्योग से निकले लगभग 200,000 टन परमाणु/रेडियोधर्मी कचरे को निपटाने के लिए समुद्रों का किसी डंपिंग यार्ड की तरह उपयोग किया। भले ही समुद्र में डंपिंग के मामले में अब तक केवल निम्न स्तर के रेडियोधर्मी कचरे को ही डंप किया गया है, लेकिन समुद्र तल पर फैले सैकड़ों-हजारों टन परमाणु कचरे के धीमे क्षय की तरह, समुद्री जीवों के शरीर में लिखी गई मानव उद्योग की जहरीली विरासतें याद दिलाती हैं कि गहराई भूलने की जगह नहीं है कि जहां कुछ भी डाल दो और भूल जाओ। यह मान लेना आसान है कि हमारा ग्रह केवल स्थलीय वातावरण द्वारा परिभाषित है, वास्तव में विपरीत सच है। समुद्र में परमाणु कचरे की डंपिंग लापरवाही और लालच की एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं के रूप में भी मानव अपशिष्ट गहरे समुद्र में हर जगह है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात समुद्र की गहराई में माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता संचय है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का निर्माण होता है, इसमें से लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे के रूप में हर साल समंदर में फेंक दिया जाता है। समुद्र में परमाणु कचरे की डंपिंग लापरवाही और लालच की एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं के रूप में भी मानव अपशिष्ट गहरे समुद्र में हर जगह है। खेल बैग, पुतले, समुद्र तट की गेंदें और बच्चों की बोतलें कई हजारों मीटर की गहराई तक समुद्र तल पर फैली हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में ऐसी वस्तुओं की संख्या 300 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जब खोजकर्ता विक्टर वेस्कोवो 2019 में मारियाना ट्रेंच के निचले भाग पर पहुंचे, तो उन्हें न केवल एम्फिपोड्स की पहले से अज्ञात प्रजातियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें प्लास्टिक बैग और मीठे रैपर भी मिले। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात समुद्र की गहराई में माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता संचय है।

समुद्र की ऊपरी परतों में माइक्रोप्लास्टिक ने खाद्य श्रृंखला पर आक्रमण किया है। जैसे-जैसे कोई शिकार की परतों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ता है, उच्च और उच्चतर सांद्रता में एकत्रित होता जाता है। व्हेल और पक्षी जैसे जानवर बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग कर रहे हैं, जिससे कुपोषण हो रहा है और उन जीवों के कई अंगों को नुकसान हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा उजागर किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण 2050 तक चौगुना हो सकता है, जबकि माइक्रोप्लास्टिक्स संभावित रूप से 2100 तक पचास गुना बढ़ सकता है। यह समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा तो है ही, कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा सकता है।

चिंता | ओशो

चिंता का अर्थ ही यह है कि बोझ मुझ पर है। पूरा कर पाऊंगा? नहीं; तुम साक्षी हो जाओ। कृष्ण ने गीता में यही बात अर्जुन से कही है कि तू कर्ता मत हो। तू निमित्त-मात्र है; वही करने वाला है, जिसे उसे

मारना है, मार लेगा। जिसे नहीं मारना है, नहीं मारेगा। तू बीच में मत आ। तू साक्षी भाव से जो आज्ञा दे, उसे पूरी कर दे। परमात्मा कर्ता है-और हम साक्षी। फिर अहंकार विदा हो गया। न हार अपनी है, न जीत अपनी है। हारे तो वह, जीते तो वह। न पुण्य अपना है, न पाप अपना है। पुण्य भी उसका, पाप भी उसका। सब उस पर छोड़ दिया। निर्भार हो गए। यह निर्भार दशा संन्यास की दशा है। 'जा घट चिंता नागिनी, ता मुख जप निहं होय।' और जब तक चिंता है, तब तक जप नहीं होगा। तब तक कैसे करोगे ध्यान? कैसे करोगे हरि-स्मरण? चिंता बीच-बीच में आ जाएगी। तुम किसी तरह हरि की तरफ मन ले जाओगे, चिंता खींच-खींच संसार में ले आएगी। तुमने देखा न कि जब कोई चिंता तुम्हारे मन में होती है, तब बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर पाते। बैठते हो, ओठ से राम-राम जपते हो और भीतर चिंता का पाठ चलता है। चिंता और प्रभु-चिंतन साथ-साथ नहीं हो सकते। चिंता यानी संसार का चिंतन। व्यर्थ का कूड़ा-कचरा तुम्हारे मन को घेरे रहता है। तो उस कूड़े-कचरे में तुम परमात्मा को बुला भी न सकोगे। उसके आने के लिए तो शांत और शून्य होना जरूरी है। और शांत और शून्य वही हो जाता है, जिसने कर्ता का भाव छोड़ दिया।

जा घट चिंता नागिनी ता मुख जप निहं होय।
जो टुक आवै याद भी, उन्हीं जाय फिर खोय।।

और कभी क्षणभर को--टुक--जरा सी याद भी परमात्मा की आती है खिसक-खिसक जाती है। फिर मन संसार में चला जाता है। फिर सोचने लगता है कि ऐसा करूं, वैसा करूं? क्या करूं, क्या न करूं? ऐसा होगा--नहीं होगा? इतना ही नहीं, मन इतना पागल है कि अतीत के संबंध में भी सोचता है कि ऐसा क्यों न किया? ऐसा क्यों कर लिया? अब अतीत तो गया हाथ के बाहर। अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। किए को अनकिया नहीं किया जा सकता। अब अतीत में कोई तरमीम, कोई सुधार, कोई संशोधन नहीं हो सकता। मगर मन उसका भी सोचता है कि फलां आदमी ने ऐसी बात कही थी, काश! हमने ऐसा उत्तर दिया होता! अब तुम क्यों समय गंवा रहे हो? वक्त जा चुका। जो उत्तर दिया--दिया।

रीडर्स मेल

प्रतिपदा का महत्त्व

चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि के अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन ब्रह्माजी ने सृष्टि का निर्माण किया था। भारत के विभिन्न भागों में इस पर्व को भिन्न-भिन्न नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन को 'गुड़ी पड़वा' के रूप में मनाते हैं। 'गुड़ी' का अर्थ होता है- विजय पताका। आज भी आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है। दक्षिण भारत में चंद्रमा के उज्ज्वल चरण का जो पहला दिन होता है उसे 'पाद्य' कहते हैं। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे 'संवत्सर पड़वो' नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में यह पर्व 'युगाड़ी' नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 'उगाड़ी' नाम से मनाते हैं। कश्मीरी हिंदू इस दिन को 'नवरेह' के तौर पर मनाते हैं। मणिपुर में यह दिन 'सजिबु नोंगमा पानबा' या 'मेइतेई चेइराओबा' कहलाता है। दरअसल, इस समय बसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है और उल्लास, उमंग, खुशी और पुष्पों की सुगंध से संपूर्ण वातावरण चमत्कृत हो उठता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन शुरू किए गए कामों में सफलता निश्चित तौर पर मिलती है।

देवेन्द्रराज सुथार, जालौर, राजस्थान

सरकार ध्यान दे

देश में हर वर्ष टाइफाइड बैक्टीरिया गंभीर एवं महामारी का रूप लेता जा रहा है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जिसको हम टाइफाइड कहते हैं। जिस तरह से कोरोनावायरस एक शहर से दूसरे शहर व गांव में फैल रहा था। उसी तरह से टाइफाइड बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। आज टाइफाइड के मामले शहर व गांव में हर जगह देखे जा सकते हैं। यह खुलासा भारत और अमेरिका के 32 वैज्ञानिकों की टीम ने किया है। जिन्होंने भारत में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के लगातार बढ़ते प्रसार के पीछे मुख्य कारणों की जानकारी हासिल की है। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी को गंभीरता से लेना होगा। यह बीमारी धीरे-धीरे करके हर शहर और गांव कस्बों में फैल रही है। इस बीमारी को मामूली समझ कर रोगी दवा खाता रहता है, लेकिन कभी ठीक नहीं हो पाता है। इसके संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। इसका समाधान खोजना ही होगा?

जयदेव राठी भराण, रोहतक, हरियाणा

अखिलेश की कमजोर रणनीति

समाजवादी पार्टी में आंतरिक कलह, खींचतान और सीटों का बंटवारा शुभ संकेत कतई नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिस जोर शोर से घोषणा की थी कि हम 60 से ज्यादा प्रत्याशी उतार कर भाजपा को उत्तर प्रदेश से 80 सीट जीतने नहीं देंगे, यह दावा कमजोर दिखाई दे रहा है। सपा ने कई सीटों मसलन मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, बदायूं, बागपत, संभल, मिश्रिख, बिजनौर, रामपुर और लखनऊ में अपने घोषित प्रत्याशी को बदल डाला। इसे लेकर कार्यकर्ता और समर्थक आलाकमान से नाराज दिखाई देते हैं। इन सभी परिस्थितियों में बसपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी को सीधी टक्कर देगी, यह देखना बेहद रोचक होगा। बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम समीकरण के कारण मजबूत स्थिति में दिखाई देती है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

पुराने नारे, नया चुनाव

एक बहुत बड़े टेंट हाऊस के मालिक के गोदाम में कई माइक पड़े हुए थे, आपस में वार्ता कर रहे थे-

माइक एक-और क्या हाल भाई लोगों क्या चल रहा है, आज तो थक गया मैं मेरेवाले नेता ने ढाई घंटे उस नेता को गाली दे रहा था, गालियां सुन सुनकर पक गए साहब, वो ही गालियां वो ही पुरानी गालियां, नेता कुछ नई गालियां भी ना सोच सकते क्या।

माइक नंबर दो-अबे गालियां क्या ये तो नारे भी नये ना सोच सकते। वही पुराने नारे चल रहे हैं, ये मुफ्त, वो मुफ्त।

माइक एक-क्या मतलब वो ही पुराने नारे दे रहे हैं और पब्लिक सुन रही है।

माइक नंबर दो-पब्लिक का क्या है, कुछ ना कुछ सुनती रहती है, कहां तक याद रखें, कि कौन क्या कह गया था। नेता वो ही बात बार बार कह देता है, पब्लिक बार-बार वही बात सुन लेती है। नेता का काम है कहना, पब्लिक का काम है सुनना। सब अपना अपना काम किये जा रहे हैं। हम माइक भी पब्लिक ही हैं, बस सुन लेना चाहिए। हमारे बस में क्या है सुनने के सिवाय।

माइक नंबर एक-मेरा तो मन करता है कि मैं गरदन पकड़ लूं नेता की और लिपट जाऊंगा उससे और कहूं कि चुप, चुप, चुप पहले पुराने वाले वादे तो पूरे कर।

माइक नंबर दो-ना ना ऐसा मत करना। नेता बोलता है, तो ही हमारे मालिक का कारोबार चलता है। जितने चुनाव, जितने भाषण, जितने झूठ, उतना ही हमारा कारोबार चलेगा। एक बात समझ लेना कि काम की बातें ज्यादा ना होतीं। हमारा धंधा काम की बातों से ना चलता। हमारा तो धंधा ही फिजूल की बातों का है। माइक नंबर एक-बात तो सही है चुप रहो तो धंधा माइक का चलता है, पर नेताओं का धंधा तो बकवास का ही चलता है। मन तो वैसे मेरा भी कभी कभी यही करता है कि जैसे ही नेता ए नेता बी को गालियां देता है, मेरा मन करता है कि मैं गालीबाज नेता को बता दूं कि भाई एक हफ्ते पहले तो तुम उसे सगा भाई बता रहे थे। माइक नंबर दो-वैसे हम पक गये है झूठ सुन सुनकर। अगर सिर्फझूठों से फसल पकनी होती, तो अकाल के बावजूद भारत में कोई फसल कभी भी फ्लाप ना होती।

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 237
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

चीन से बढ़ता आयात

भारत-चीन व्यापार के क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी दो महाशक्तियां हैं। 21वीं सदी में चीन और भारत एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी और मित्र दोनों हैं। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद प्राचीन काल से ही है। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में लगातार तनाव बना हुआ है। लगातार बैठकों के बावजूद सीमा विवाद समाप्त करने के संबंध में कोई सार्थक एवं स्पष्ट नीति नहीं बन पाई। दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी वाले दोनों देशों के बीच व्यापार की संभावनाएं बहुत विशाल हैं। पूर्वी लद्दाख में सीमाओं पर दोनों देशों की सेनाएं अब भी आमने-सामने हैं। चीन लगातार अरुणाचल पर भी अपना दावा जता रहा है। दोनों देशों में तनाव के बावजूद चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में जनवरी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 90 प्रतिशत लैपटाप और पर्सनल कम्प्यूटर्स चीन से आयात होकर भारत आए हैं। पिछले वर्ष नवम्बर में 89 प्रतिशत लैपटाप और पर्सनल कम्प्यूटर्स आयात हुए। भारत में बिकने वाले 10 लैपटाप में से 9 चाईना के होते हैं।

एक तरफ भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का शोर कई बार मचता रहा है तो दूसरी तरफ केन्द्र सरकार भी चीन पर आयात निर्भरता कम करने के प्रयास करती रही है। आम भारतीय चीन को भारत का दुश्मन नम्बर एक मानते हैं, जब भी भारत में चीन विरोधी भावनाएं उभार लेती हैं तब केन्द्र सरकार चीन पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाती है। चीन की बढ़ती मनमानी के चलते उसे झटका देना भी कूटनीति का हिस्सा है। पिछले वर्ष अगस्त में भारत ने पर्सनल कम्प्यूटर, लैपटाप, आटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, माइक्रो कम्प्यूटर, प्रोसैसर के आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया था। भारत इन उत्पादों को घरेलू स्तर पर बढ़ावा देना चाहता था। भारत ने आयात के लिए जिन सात श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया था उनमें से अधिकांश हिस्सा चीन से आता था। अंकुश लगाने के पीछे वैसे तो कई कारण थे लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक बड़ा कारण था। सरकार ने प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा था कि वैध लाइसैंस के बिना इन उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अब सवाल यह है कि इतने तनाव के बावजूद चीन से आयात कम क्यों नहीं हो रहा। दरअसल चीन से जो हम आयात करते हैं वो कच्चा माल ही नहीं बल्कि फिनिशड प्रोडक्ट्स भी है। हमारे यहां तो बड़े-बड़े उत्पाद बनते भी हैं। उनके अन्दर जो छोटे-छोटे पुर्जे लगते हैं उन सबके लिए हम चीन पर निर्भर हैं। चीन में सस्ते मजदूरों की सहज उपलब्धता है। साथ ही उत्पादन के लिए देश के ही कच्चे माल का उपयोग करने की वजह से चीनी उत्पाद बहुत सस्ते होते हैं। भारत के अलावा चीन दुनिया के कई देशों में अपना 'सामान भेजता है। एक तरह से वह दुनिया का सबसे बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग हब है।

केन्द्र सरकार चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने के प्रयास भी लगातार करती रही है लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार ने प्रतिबंधों में छूट दे दी क्योंकि आईटी उद्योग से प्रतिबंधों की जबरदस्त आलोचना की जा रही थी। एक कारण यह भी था कि भारत में मैन्यूफैक्चरिंग की इतनी रफ्तार नहीं थी जिससे घरेलू मांग को पूरा किया जा सके इससे लैपटाप, पीसी और टेबलेट्स की मांग बढ़ी और इनके दाम भी बढ़ गए। लगभग एक-डेढ़ महीने चीन से आयात कम हुआ लेकिन बाद में चीन आयात बढ़ता गया। गलवान और डोकलाम में दोनों देशों की सेनाओं में झड़पें भी हुईं लेकिन इसके बावजूद सीमा के आर-पार व्यापार बढ़ता ही गया। 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का नम्बर वन ट्रेडिंग पार्टनर था। 2018-19 और 2019-20 में चीन की जगह अमेरिका ने ले ली हालांकि 2020-21 और 2022-23 में चीन फिर से भारत का नम्बर वन व्यापारिक साझेदार बन गया और दोनों देशों के बीच 100 बिलियन डालर से ज्यादा का व्यापार हुआ। एक तथ्य यह भी है कि चीन हमेशा से भारत का सबसे अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं था। 1998-99 में चीन-भारत के ट्रेड पार्टनर की सूची में 18वें नम्बर पर आता था। 1999 में 16वें नम्बर पर आया। 2000-2001 में 12वें नम्बर पर रहा। 2001 से 2012 के बीच चीन भारत का 10वें नम्बर का ट्रेड पार्टनर रहा है लेकिन इसके बाद स्थिति बदली और चीन भारत के प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों में शामिल हो गया।

अब सवाल यह है कि इतने तनाव के बावजूद चीन से आयात कम क्यों नहीं हो रहा। दरअसल चीन से जो हम आयात करते हैं वो कच्चा माल ही नहीं बल्कि फिनिशड प्रोडक्ट्स भी है। हमारे यहां तो बड़े-बड़े उत्पाद बनते भी हैं। उनके अन्दर जो छोटे-छोटे पुर्जे लगते हैं उन सबके लिए हम चीन पर निर्भर हैं। चीन में सस्ते मजदूरों की सहज उपलब्धता है। साथ ही उत्पादन के लिए देश के ही कच्चे माल का उपयोग करने की वजह से चीनी उत्पाद बहुत सस्ते होते हैं। भारत के अलावा चीन दुनिया के कई देशों में अपना 'सामान भेजता है। एक तरह से वह दुनिया का सबसे बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग हब है। हमारे देश में बनने वाले अनेक उत्पादों में लगने वाले सामान और कलपुर्जे चीन से ही मंगाए जाते हैं। उत्पादन लागत अधिक होने से हमारे स्व-निर्मित उत्पाद महंगे होते हैं।

कच्चे माल की कमी, कुशल श्रमिकों तथा मूलभूत बुनियादी ढांचों के अभाव में भारत में उत्पादित वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। हमारा पूरा ध्यान बड़े उद्योगों जैसे डिफेंस आटोमोबाइल तक सीमित है जबकि रोजमर्रा की चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम ज्यादा ध्यान नहीं देते जबकि चीन स्कूली बच्चों से लेकर गृहणियों तक इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों पर भी ध्यान देता है और भारतीय बाजार इन सामानों से भरे पड़े हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए हमें मैन्यूफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अन्यथा व्यापार असंतुलन बढ़ता ही जाएगा। केन्द्र सरकार को सतर्कता से काम लेना होगा।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

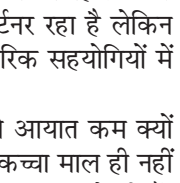

तब तक हम ऐसे गिरोह की कमर...

जब-जब बाल तस्करी के घिनौने मामले सामने आते हैं,
तो कानून व्यवस्था पर ढेरों सवाल खड़े कर जाते हैं,
लेकिन जब तक तालाब के बड़े मगरमच्छ कानून के हाथ नहीं आएंगे,
तब तक हम ऐसे गिरोह की कमर नहीं तोड़ पाएंगे...!!

गीता पाढा

किराये की खबरें भारत को नहीं हिला सकती

डा. विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने खुलासा किया है कि 2020 से लेकर अब तक भारत ने पाकिस्तान में टार्गेट किलिंग की है और 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मैं इसे कोई खुलासा नहीं मानता क्योंकि गार्जियन की इस रिपोर्ट का कोई पुख्ता आधार नहीं है, केवल कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों के बयान को आधार बनाकर इस तरह की रिपोर्ट छापना हर हाल में गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की श्रेणी में ही रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारत में ठीक चुनाव के बीच इस तरह की रिपोर्ट छापे जाने का आखिर मकसद क्या है?

चलिए, सबसे पहले यह जानते हैं कि गार्जियन ने लिखा क्या है? उसका कहना है कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) ने एक मिशन पर काम करना शुरू किया कि आतंकी हमले के खतरे को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। भले ही वह विदेशी धरती पर क्यों न हो। इसी के तहत पाकिस्तान में अभी तक 20 हत्याएं हो चुकी हैं। यह भी बात रिपोर्ट में है कि रॉ को पीएम ऑफिस नियंत्रित करता है। आप समझ सकते हैं कि गार्जियन के कहने का आशय क्या है, उसकी नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गार्जियन ने ये सारी बातें पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से मिले दस्तावेजों के आधार पर की हैं। जाहिर सी बात है कि वह तो ऐसे ही दस्तावेज तैयार करेगा जो भारत को बदनाम कर सके। मसलन यह कहना कि टार्गेट किलिंग का यह मिशन संयुक्त अरब अमीरात से भारत संचालित कर रहा था। इसके लिए बाकायदा स्लीपर सेल तैयार किया गया। अच्छी-खासी राशि खर्च हुई, इसमें दो साल का वक्त लगा, तो सवाल यह है कि इन दो सालों में पाकिस्तान क्या कर रहा था? संयुक्त अरब अमीरात में स्लीपर सेल बना और उसे भनक भी नहीं लगी?

यह पूरी रिपोर्ट ही फर्जी तौर पर तैयार की गई लगती है। रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरा हुआ लिख दिया गया जबकि वह जिंदा है, इस पर जब लोगों ने सवाल उठाए तो गार्जियन ने तत्काल इसमें सुधार तो कर लिया लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की कि एक जिंदा व्यक्ति को उसने मरे हुए लोगों की सूची में कैसे डाल दिया?

भारत पर टार्गेट किलिंग का आरोप तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी लगा दिया था। वहां खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर आपसी रंजिश में मारा गया था। आरोप के बावजूद कनाडा कभी कोई सबूत नहीं दे पाया। अमेरिका ने भी भारत को घेरने की कोशिश की, ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख अवतार सिंह खांडा की रहस्यमयी मौत और पाकिस्तान में आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या के मामले को भी भारत से जोड़ा गया। भारत ने हमेशा ऐसे आरोपों को खारिज किया है। मैं हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि विदेशी धरती पर टार्गेट किलिंग भारत की नीतियों के अनुरूप नहीं है। मेरा सवाल तो यह है कि कौन किसको मार रहा है?

पाकिस्तान में जितने भी लोग अज्ञात हमलावरों की गोली से मरे हैं वे कोई पाकिस्तान के राजनेता नहीं थे, न ही भलेमानुष थे, वे आतंकवादी थे और आतंकवादियों के बीच खतरनाक रंजिशें होती हैं क्योंकि अब आतंकवाद के पीछे ड्रग्स माफिया, हथियारों के सौदागरों का हाथ होता है। आतंकवाद का किसी विचारधारा से अब कोई लेना-देना नहीं है। आपसी रंजिश में हत्याएं होती हैं।

इसमें भारत को क्यों घसीटा जाता है? अपने चुनावी फायदे के लिए कनाडा खालिस्तानियों को पालता-पोसता है। अमेरिका में ट्रम्प और जो बाइडेन के बीच संघर्ष की स्थिति है। भारत में चुनाव चल ही रहे हैं। ऐसे माहौल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करना ही गार्जियन की रिपोर्ट का मकसद नजर आता है। एक समय था जब ब्रिटेन की पत्रकारिता की पूरी दुनिया में साख थी, उसका आदर था लेकिन उसकी पत्रकारिता में भारत के प्रति विद्वेष साफ दिख रहा है। कई देशों को भारत का विकास हजम नहीं हो रहा है, ये हमले इसीलिए हो रहे हैं।

हमला करने वालों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत का लोकतंत्र कच्ची मिट्टी का बना शेर नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इन जड़ों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान ने सींचा है। इस देश का हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। अलग-अलग पार्टियों की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, चुनाव में डट कर लड़ते भी हैं लेकिन हमारे देश के राजनेता अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचते, न देश को लूटकर अपना घर भरते हैं। ऐसे लुटेरे जब नसीहत देते हैं तो उन पर तरस आता है, उनकी वह ताकत नहीं कि हमारे देश के लोकतंत्र की नींव को छू भी सकें।

एक बात और बता देना चाहूंगा कि हम भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के अनुयायी जरूर हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। घर में घुसकर मारने का ठेका किसी एक राष्ट्र ने नहीं लेकर रखा है। भारत भी यह कर सकता है, जरूरत पड़ी तो हम घर में घुसेंगे। दुनिया ध्यान रखे कि हमारी आन-बान-शान को यदि कोई हाथ लगाने का प्रयास करेगा तो हम उसे नेस्तनाबूद कर देने में जरा भी नहीं हिचकेंगे।

सहकारिता से मिलेगा करोड़ों को स्वरोजगार

आर.के. सिन्हा
पूर्व राज्यसभा सांसद

अगर भारत दुनिया की शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है तो इसमें सहकारी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। यह एक ऐसी खिड़की है जहां से सतत् आर्थिक विकास की रोशनी लगातार आ सकती है। इसलिए मोदी सरकार भारत में सहकारिता आंदोलन को गति देना चाहती है। सरकार और अर्थशास्त्रियों को पता है कि सहकारिता क्षेत्र के रास्ते भारत संसार की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। निश्चित रूप से इस सैक्टर को इस लक्ष्य के लिए एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी और शायद इस क्षेत्र में छुपी अपार संभावनाओं को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय का ही गठन कर दिया है ताकि इसके लिए अलग बजट का प्रावधान किया जा सके। चूंकि, यह क्षेत्र बहुत बड़ा है और इस पर करोड़ों लोगों की निर्भरता है, इसलिए इसका पोषण और संरक्षण भी जरूरी है।

देश के 29 राज्यों में लगभग 8,02,639 सहकारी समितियां हैं और ये अरबों का व्यापार भी कर रही हैं। देश में सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1,886 है, जिसमें 1,500 शहरी सहकारी बैंक और 386 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। ये सहकारी संस्थाएं देशभर में विभिन्न समुदायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बेशक, केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। उससे पहले देश में सहकारी समितियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। यहां भी भ्रष्टाचार ने अपने पैर गहरे जमा लिए थे। आपसी मिलीभगत के जरिए वित्तीय लेन-देन में कुछ लोग काफी हेरफेर करते रहे थे। प्रबंधन के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई भर होती थी। व्यक्तिगत मतभेद और लड़ाई-झगड़ा तो आम बात थी और अनावश्यक विवाद डालकर समितियां बंद भी कर देते थे। कुछ बड़े भाग्यशाली समूह मनमानी करते थे और किसानों तथा छोटे उद्यमियों तक काम पहुंच ही नहीं पाते थे लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की निगरानी ने दृश्य बदल कर रख दिया है। कई अहम सुधार किए गए हैं। साथ में जवाबदेही भी तय की जा रही है।

बेशक, अमित शाह की इस बात में दम है कि 115 साल पुराने सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए आजादी के बाद ही एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना दिया जाना चाहिए था लेकिन यह काम तब हुआ जब 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।

सहकारी समितियां आपसी सहयोग से बनाई गई संस्थाएं होती हैं। यह सामूहिकता के सिद्धांत पर काम करती हैं। पूंजी की जुटान साझेदारी की भावना से होती है और उपयोग में दूसरों की मदद करने की भावना होती है। इसकी विशालता और फैलाव का इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि इस समय भारत में करीब 2 लाख सहकारी डेयरी समितियां और 330 सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं। अकेले गुजरात में 81307 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। 19 बहु-राज्य सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों का दर्जा प्राप्त है। टर्नओवर के हिसाब से देखे तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इफ्को का टर्नओवर 60,324 करोड़ रुपये का टर्नओवर था और अमूल का 2023-24 के लिए 12,880 करोड़ रुपये था। यही नहीं इफ्को को दुनिया की 300 सबसे बड़ी सहकारिता समिति की सूची में शामिल किया गया है।

पहले सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय के अंतर्गत था लेकिन जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया ही और गृहमंत्री अमित शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री बने। मंत्रालय ने 2022 में संसद में बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून में संशोधन के जरिए एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की सेवा करना और सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को और लोकतांत्रिक बनाना था। इसके साथ ही संस्थाओं को और अधिक आर्थिक और सांगठनिक स्वायत्तता देना भी उद्देश्य था ताकि इसका चहुंमुखी विकास हो सके। इस नीति के तहत सहकारी समितियों को जरूरी सहयोग, प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है।

खास कर युवाओं और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने में सहकारी समितियां बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। क्षमता निर्माण, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को एकीकृत करने वाले समावेशी सहकारी मॉडल तैयार है। नारी सशक्तिकरण का नारा यदि धरातल पर कहीं उतरता दिखाई दे रहा है तो वह सहकारिता के क्षेत्र में पूर्ण रूप से दिख रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की बेहतरी, सशक्तिकरण और आय सृजन के लिए जो प्रयास किये हैं उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बहु राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिला निदेशकों नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। इससे देश भर में 1,550 से अधिक बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) में भी महिला सदस्यों को आरक्षण दिया गया है। 1 लाख से अधिक पैक्स में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व और निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता के जरिए करोड़ों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की सुदृढ़ व्यवस्था बनाई है। "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्वतंत्र सहकारिता नीति पर अमल की जा रही है। मोदी सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से लेकर राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण तक पूरी सहकारी प्रणाली का आधुनिकीकरण कर दिया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और मध्यम और दीर्घकालिक ऋण चाहने वाले किसानों के लिए नई सुविधा शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने सहकारी क्षेत्र में "दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" की भी शुरुआत कर दी है जो 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में काम करेगी। इस पहल के तहत गोदामों और अन्य कृषि-संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रखी गई है। इस पहल का उद्देश्य पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत करना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और नाबार्ड द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के नेतृत्व में सहयोगात्मक प्रयास से देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

सरकार के सामने सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं, खास कर सहकारी बैंकिंग के मामले में। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी से संबंधित आंकड़ें परेशान करने वाले हैं। आरबीआई के अनुसार पिछले पांच वर्ष में देश भर के सहकारी बैंकों से कुल 4135 धोखाधड़ी की रिपोर्ट सामने आई। 10,856.7 करोड़ रुपये का इन बैंकों में फ्रॉड हुआ लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि सहकारिता राज्यों के विषय में आता है। केंद्र सीधे इसमें दखल नहीं दे सकता लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात से बहुत चिंतित हैं। वह आश्वस्त कर रहे हैं कि गरीबों का बैंक में जमा पैसा लूटने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने हाल ही में केरल के मामले में कहा भी है कि मैं देखूंगा कि प्रत्येक पैसा संबंधित व्यक्ति को वापस मिल जाए। उल्लेखनीय है कि केरल के करुवन्नूर सहकारी बैंक में लगभग 500 करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं और इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस मामले में कुछ स्थानीय सीपीएम नेताओं पर एक्शन भी लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सहकारिता क्षेत्र में फैली गड़बड़ियों को भी दूर करना होगा जिसको लेकर केन्द्र सरकार गंभीर है।

चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा भारत

नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरीशस के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाएगा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ ही मॉरीशस को भारत समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है ताकि वह मौसम संबंधी प्रतिकूल घटनाओं के कारण जान-माल के नुकसान को कम कर सकें। आईएमडी के महानिदेशक महापात्र ने कहा कि भारत मौसम संबंधी प्रतिकूल घटनाओं के प्रभाव से बचाव के प्रयासों में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरीशस के लिए बड़ा भाई और एक सलाहकार की भूमिका निभाएगा। भारत के प्रयास संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित 'सभी के लिए समय-पूर्व चेतावनी' का हिस्सा हैं जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि 2027 के अंत तक पूर्व चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से सबको खतरनाक मौसम, पानी या जलवायु संबंधी घटनाओं से सुरक्षित किया सके। महापात्र ने कहा कि भारत समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की पहल के प्रथम चरण के तहत दुनिया भर में चिह्नित किए गए 30 देशों में से पांच की मदद कर रहा है। आईएमडी प्रमुख ने कहा, " पचास प्रतिशत देशों के पास समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं है। गरीब देशों, अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीप देशों- उदाहरण के लिए मालदीव और सेशेल्स के पास मौसम संबंधी चरम घटनाओं के बारे में समय-पूर्व चेतावनी देने की क्षमता नहीं है। इस वजह से आपदाओं के कारण लोगों की मौत हो रही है और संपत्ति को भी नुकसान हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि इन देशों को अपने मौसम संबंधी पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की जरूरत है। महापात्र के मुताबिक, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और भारत जैसे देशों ने तकनीकी सहायता प्रदान करने का वादा किया है। आईएमडी प्रमुख ने कहा, " हम इन पांच देशों को मौसम संबंधी वेधशालाएं स्थापित करने में मदद करेंगे तथा उन्हें हमारे संख्यात्मक मॉडल तक पहुंच की अनुमति देंगे।" महापात्र ने कहा कि आईएमडी पूर्वानुमान और चेतावनी से जुड़ी जानकारी मुहैया करेगा और संबंधित देशों के संचार मंत्रालयों को डेटा आदान प्रदान और चेतावनी की सूचना देने के लिए एक प्रणाली विकसित करने में मदद के वास्ते इसमें शामिल किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की दिसंबर में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 101 देशों (52 प्रतिशत) के पास अब पूर्व चेतावनी प्रणालियां हैं। डब्ल्यूएमओ के आंकड़ों से पता चलता है कि 1970 से 2019 के बीच मौसम और जलवायु से संबंधित आपदाओं की संख्या पांच गुना तक बढ़ गई है। पानी से संबंधित आपदाएं विश्व स्तर पर सबसे आम हो गई हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया।साल 1970 से 2021 के बीच दुनिया में मौसम, जलवायु या जल संबंधित करीब 12 हजार आपदाएं आईं जिससे 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 4300 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।

● प्रयास संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित 'सभी के लिए समय-पूर्व चेतावनी' का हिस्सा हैं

चुनाव प्रचार में फसल कटाई के गीतों की धूम

पटना, (भाषा): बिहार में फसल कटाई के इस मौसम में ग्रामीण, खेतिहर मजदूर एवं किसान मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकसभा उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए फसल कटाई से जुड़े स्थानीय गाने बजा रहे हैं। बक्सर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बताया, ''फसल कटाई के इस मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करते समय स्थानीय लोक गायकों, कटनी (फसल कटाई) के गीत गाने के लिये लोक गायकों की सेवा ले रहे हैं।'' अधिकतर ग्रामीण मतदाता किसान या खेतिहर मजदूर हैं। लोकसभा के उम्मीदवार प्रचार करने के दौरान ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रसिद्ध स्थानीय लोक गायकों और कटनी के गीतों के विशेषज्ञों की भी सेवा लेते हैं।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में 3-3 सीट पर चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस-नेकां

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को ऐलान किया कि वे इस लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख की कुल छह सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तीन-तीन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सीट बंटवारे की घोषणा की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी तथा दोनों तीन-तीन सीट पर चुनाव लड़ेंगी। ऊधमपुर, जम्मू और लद्दाख लोकसभा सीटों से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने संवाददाताओं से कहा, हम सबने मिलकर प्रयास किया कि जल्द से गठबंधन किया जाए।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य ★ सार्थक ★ सदैव

अभिव्यक्ति को बल

यूट्यूबर्स या यूट्यूब पर विचार व्यक्त करने वालों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष को मजबूत किया है। न्यायालय ने यथोचित फैसला लेते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में यूट्यूबर ए दुरई मुरुगन सत्ताई को दी गई जमानत बहाल कर दी है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मुरुगन की जमानत रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मुरुगन ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। सुनवाई के दौरान सबसे खास टिप्पणी न्यायमूर्ति ओका ने की, 'अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे, तो कल्पना कीजिए कि कितने लोगों को जेल होगी?' वाकई आज के समय में सरकार या राजनेताओं के विरुद्ध बोलने या सवाल उठाने वालों की संख्या कम नहीं है और अनेक यूट्यूब चैनल पर लोग सीधे आरोप लगा देते हैं, कुछ लोग तो दोषी होने का फैसला भी सुना देते हैं!

वैसे, क्या लोकतंत्र में आलोचकों का मुंह बंद किया जा सकता है? क्या कोई सरकार यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाकर कुख्याति मोल लेना चाहेगी? आज देश में जितने भी स्मार्टफोन हैं, सभी में यूट्यूब एप अनिवार्य रूप से रहता है। शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन धारक होगा, जो यूट्यूब न देखता होगा। यह बात भी बार-बार सामने आई है कि यूट्यूब ने लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का अवसर ही नहीं दिया है, बल्कि उसका विस्तार भी किया है। वीडियो बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने की इस आजादी के नकारात्मक पहलू खूब हैं, किंतु सकारात्मक पहलुओं की ही ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में बहुत हद तक अभिव्यक्ति की आजादी लोगों के विवेक पर ही निर्भर है। इस मामले में भी न्यायालय ने यही माना है कि मुरुगन ने विरोध प्रदर्शन और अपने विचार व्यक्त करके अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। कोई शक नहीं कि अदालत ने यथोचित उदारता का परिचय दिया है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में लोगों को भी ज्यादा उदार बनने की जरूरत है। किसी वीडियो की शिकायत करते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। इस मामले में शिकायतकर्ता द्रमुक का सदस्य है और उसने *रावण* नामक यूट्यूब चैनल पर याचिकाकर्ता का भाषण सुना, जिसमें मुख्यमंत्री स्टालिन का मजाक उड़ाया गया था। शिकायतकर्ता को यह बुरा लगा और पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके अक्तूबर 2021 में मुरुगन को गिरफ्तार कर लिया।

सर्वोच्च न्यायालय में एक यूट्यूबर को मिली राहत स्वागतयोग्य है। अभिव्यक्ति के साथ-साथ अभिव्यक्ति की शिकायत के प्रति भी हमें ज्यादा समझदार होने की जरूरत है।

हालांकि, इस मामले का त्रासद पक्ष यह है कि यह विवाद निचले स्तर पर ही सुलझाया जा सकता था, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। न्याय तक पहुंचने में काफी समय लग गया। गौर कीजिए, नवंबर 2021 में मद्रास हाईकोट ने मुरुगन को जमानत दे दी थी, पर बाद में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जमानत रद्द कर दी थी। उसके बाद 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने मुरुगन को अंतरिम जमानत दी और तब से वह जमानत पर बाहर हैं। अब जाकर उन्हें राहत की सांस मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के नए दौर में यह एक ऐसा आदर्श मामला है, जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। आज निंदा में शालीनता व संतुलन का होना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, शिकायत से पहले निंदा पर समझदारी से सोचना।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

09 अप्रैल, 1949

रियासती शासन और सेना

रियासतों को राजाओं के एकतंत्री शासन से मुक्त कर शेष भारत के समक्ष लाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है उसमें हाल ही में और प्रगति हुई है। नई दिल्ली में रियासती संघ के राजप्रमुखों, प्रधानमंत्रियों (तब सूबों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाते थे) और रियासती सचिवालय के प्रतिनिधियों के बीच दो दिन तक जो विचार-विनिमय हुआ, उसमें कुल मिलाकर यह मान लिया गया है कि रियासतों का जब एकीकरण हो रहा है, तो क्रमशः ऐसा किया जाना चाहिए जिससे शेष भारत और उनके बीच भिन्नता न रह जाये।... इधर जब राजाओं का अंकुश घटा है और लोकप्रिय शासन का सूत्रपात किया गया है, तब यह आवश्यक है कि उस शासन पर किसी का अंकुश रहे। रियासती संघों में जब तक एकीकरण होकर निर्वाचन क्षेत्र न बन जाये और उपयुक्त रूप में चुनाव होकर नये विधान न बन जायें, तब तक मंत्रिमंडल का दायित्व किसके प्रति हो, यह प्रश्न भी विचारणीय है। साथ ही जिस कच्ची हालत में रियासतों का धारासभाई वातावरण अभी तक रहा है, उसको देखते हुए मंत्रित्व ग्रहण करने वालों को प्रारंभ में अपने दायित्व-पालन के उपयुक्त बनने का अवसर भी मिलना चाहिए और अपने से अधिक सधे हुए लोगों के परामर्श या अंकुश का लाभ मिलना चाहिए। रियासती संघों के अब तक के कार्यकलाप से जब ऐसी धारणा बनी है तो इस दिशा में कुछ करना आवश्यक हो जाता है। राजप्रमुखों के सम्मेलन का उद्देश्य यही सब तय करना था और यह संतोष की बात है कि इस बारे में उसका कोई मत-विरोध रहा मालूम नहीं पड़ता।

राजप्रमुख सम्मेलन के जो समाचार उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार यह मान लिया गया है कि रियासती संघों पर केन्द्रीय सरकार की पूरी देखभाल रहे और उनके मंत्रिमंडल केन्द्रीय सरकार के प्रति न केवल जिम्मेदार हों, बल्कि केन्द्र से समय-समय पर प्राप्त आदेशों पर वे अमल भी करें। वृहत्तर राजस्थान के विलय-पत्र में यह सिद्धांत स्वीकृत है, अब राजप्रमुख सम्मेलन की सहमति से अन्य रियासती संघों के विलय-पत्रों में भी ऐसा ही संशोधन किया जायेगा। शासन और सेना के मामले भी नई स्थिति में अछूते नहीं रखे जा सकते थे। जब रियासतें भारतीय संघ की अंग बन रही हैं, तब उनका शासन भारतीय संघ के ही ढांचे में ढलना आवश्यक है।

तमिल राजनीति और एक वीरान टापू

कच्चातिवु द्वीप एक समय तमिलनाडु में भावनात्मक मुद्दा था। भाजपा ने इसे पुरजोर तरीके से उठा लिया है। क्या यह मुद्दा दक्षिण में नतीजों को प्रभावित कर सकेगा?

दक्षिण एक्सप्रेस
यहां स्कैन करें

एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक प्रमुख अखबार ने अपने 31 मार्च के संस्करण में बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सन् 1974 में कच्चातिवु नामक द्वीप श्रीलंका को सौंपने का मसला लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में बड़ा मुद्दा बन सकता है। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई से मिले दस्तावेज के आधार पर तैयार रिपोर्ट कहती है कि भारत ने श्रीलंका की हठधर्मिता को स्वीकार कर लिया और वर्षों तक दावा जताने के बाद कच्चातिवु श्रीलंका के हवाले कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो ट्वीट किए गए। पहले में कांग्रेस पर हमला बोला गया और कहा गया, नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कितनी बेरहमी से कच्चातिवु श्रीलंका को दे दिया। ट्वीट में आगे लिखा गया है, कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करती रही है। दूसरे ट्वीट में द्रमुक सरकार को घेरा गया और कहा गया कि इसने द्रमुक के दोहरे मानदंडों को बेपरदा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को भारत सरकार के इस फैसले की पूरी जानकारी थी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि तमिलनाडु के लोगों को तत्कालीन दोनों सरकारों ने गुमराह किया। उन्होंने पत्रकारों को यह मामला समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जाहिर है, राष्ट्रीय समाचारों में यह मुद्दा जल्द ही सुर्खियों में आ गया। हालांकि, तमिलनाडु के समाचार चैनलों ने इस खबर को संतुलित बनाने के लिए राज्य के कांग्रेस व द्रमुक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी दिखाईं। भाजपा नेता इस बात को लेकर भी मुखर थे कि कैसे तमिलनाडु के गरीब मछुआरों के हितों से समझौता किया गया। जाहिर है, इस मुद्दे को हवा देने का मूल कारण तमिलनाडु के मतदाताओं, खासकर तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को अपनी ओर आकर्षित करना है।

कच्चातिवु अतीत में तमिलनाडु में एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। रामेश्वरम के मछुआरों ने द्वीप के पास मछली पकड़ने संबंधी अधिकार और अपने जाल सुखाने व नावों की मरम्मत की सुविधा की मांग की थी। यह मुद्दा 1980 और 1990 के दशक में सूबाई राजनीति में अक्सर उठता रहा, जिसमें द्रमुक और अन्नाद्रमुक एक-दूसरे पर मछुआरों के अधिकारों को खत्म करने का आरोप लगाते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा भी था कि इस द्वीप को श्रीलंका से वापस ले लिया जाना चाहिए।

मगर बीते एक दशक से अधिक वक्त से यह कोई मुद्दा नहीं रहा था, क्योंकि मछुआरों के पास अब बेहतर संचार सुविधा और उन्नत नावें आ गई हैं। वे अब कच्चातिवु के आसपास नहीं जाते, जहां उनके मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। इसके बजाय वे अब गहरे पानी में चले जाते हैं, यहां तक कि श्रीलंकाई तटों के करीब भी पहुंच जाते हैं और वहां के सुरक्षा बलों की नाराजगी मोल लेते हैं। दुर्भाग्यवश, मछुआरों की गिरफ्तारी, भारतीय नौकाओं की जब्ती और भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की नौबत आ जाती है, जिनसे दोनों पड़ोसी देशों में तनाव भी पैदा होता रहा है।

अजीब बात है, तमिलनाडु में मछुआरों का मुद्दा और श्रीलंकाई तमिलों के कत्लेआम भावनात्मक मुद्दे रहे हैं, लेकिन इनका कभी भी राज्य या राष्ट्रीय चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर भी, यह मुद्दा अनवरत राजनीतिक विमर्श में बना रहा है। वास्तव में, जो दल सिर्फ श्रीलंकाई मसले या मछुआरों के मुद्दों पर अपना जोर लगाते हैं, वे लोगों में अपनी जगह बनाने में विफल ही साबित हुए हैं।

यही कारण है कि तमिलनाडु का एक बड़ा तबका हैरान है कि भाजपा ने आखिर इस मुद्दे को अभी क्यों उठाया, क्योंकि इसका मकसद कांग्रेस और उसके क्षेत्रीय सहयोगी द्रमुक को घेरने के अलावा दूसरा कारण नहीं दिखता। भाजपा यही बताने का प्रयास कर रही है कि विपक्षी गठबंधन किस तरह से देश के राष्ट्रीय हितों से समझौता कर चुका है। भाजपा की नजर कन्याकुमारी, थूथुकुडी, नागरकोइल व रामनाथपुरम जैसे तटीय क्षेत्रों की लोकसभा सीटों पर है, जहां उसे लगता है, मछुआरों का मुद्दा प्रभावी साबित होगा।

अगर इस मामले पर नजर डालें, तो करीब 1.9 वर्ग किलोमीटर का यह द्वीप भारत और सीलोन के बीच ब्रिटिश कब्जे से मुक्त होने से बहुत पहले विवादित था। चूंकि ब्रिटिश हुकूमत इस मसले का हल नहीं निकाल सकी, इसलिए उसने दोनों पक्षों के मछुआरों को द्वीप पर जाने की अनुमति दे दी। इसीलिए, कच्चातिवु कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। आजादी के बाद जब यह मुद्दा फिर से उठा, तो 1974 में लंबी चर्चा के बाद भारत और श्रीलंका के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा खींच दी गई और भारत ने इस द्वीप पर अपना दावा छोड़ दिया। इसमें दोनों पक्षों द्वारा वहां मछली पकड़ने का समझौता हुआ। साल 1976 में दोनों देशों के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्र बना, जिसकी वजह से भारत ने मछली पकड़ने का अपना अधिकार वापस ले लिया। वास्तव में, भारत ने कन्याकुमारी की ओर से 'वाड्ज बैंक' के लिए सौदेबाजी की। चूंकि श्रीलंका को कच्चातिवु मिल गया, इसलिए उसने इस पर कोई दावा नहीं किया। नतीजतन, भारत को समुद्र में अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा मिला, जो विविधता के मामले में समृद्ध है और यहां मछली भी खूब है। कुछ पर्यवेक्षक तो इसके लिए इंदिरा गांधी की सराहना करते हैं, क्योंकि यह इलाका तेल व खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है।

चूंकि कच्चातिवु द्रमुक और अन्नाद्रमुक, दोनों के लिए विवादास्पद है, इसलिए वे दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप उछालकर और केंद्र को भी घेरे में लेकर तटीय इलाकों के मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं। अभी यही सब हो रहा है। 'वाड्ज बैंक' कोई द्वीप नहीं है, बल्कि इको सिस्टम के लिए एक सामान्य शब्द है। दुनिया में ऐसे 20 वाड्ज बैंक हैं। भारत सरकार ने हाल ही में यहां तेल की खोज की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन मछुआरों के विरोध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उनको डर है कि इससे यहां के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है।

बेशक, इस पूरे मसले में कोई कांग्रेस पर शक कर सकता है या इंदिरा गांधी को विवादों में घसीट सकता है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वह इंदिरा गांधी ही थीं, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया और सिक्किम का विलय भारत में कराया था।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पानी पर सही शुल्क लगाना और वसूलना हुआ जरूरी

यहां स्कैन करें

नितिन पई | निदेशक, तक्षशिला संस्थान

कुछ साल पहले कर्नाटक के एक शहर की मेयर ने मुझसे पूछा था कि नगरपालिका द्वारा मुहैया कराए जा रहे पानी से अपने प्रांगण, दीवार और वाहन को धोने से वह लोगों को कैसे रोक सकती हैं? उन्होंने मुझे बताया कि जागरूकता अभियान चलाए गए, जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया गया, यहां तक कि नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से भी समझाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैंने उनसे पूछा कि लोग पानी के लिए कितना भुगतान करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रति कनेक्शन मासिक शुल्क सौ रुपये से भी कम है, पर वसूली को सख्ती से लागू नहीं किया गया है। जब मैंने उन्हें बताया कि इसी कारण से उनके संरक्षण के प्रयास असफल रहे, तो वह अचंभित रह गईं।

कम कीमत वाले संसाधनों का अत्यधिक उपभोग किया जाता है। पूरे देश में यही तो हो रहा है, जहां कम कीमत वाले पानी और बिजली के कारण लोग अधिकतम सीमा से अधिक उपभोग कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम जल संकट से जल महा-संकट की ओर जा रहे हैं। पानी को केवल तभी संरक्षित किया जा सकता है, जब इसकी कीमत सही लगाई जाए।

बेंगलुरु में आवासीय पाइप से पानी की कीमत सात रुपये से 45 रुपये प्रति 1,000 लीटर के बीच है। जिन घरों में नगरपालिका जल आपूर्ति की सुविधा नहीं है, वे सामान्य समय में लगभग 150 रुपये और जलाभाव के दिनों में 250 रुपये तक में टैंकरों से पानी खरीदते हैं। इस प्रकार पानी की सीमांत लागत या सही कीमत वास्तव में नगरपालिका द्वारा आपूर्ति होने वाले जल की कीमत से 20 से 35 गुना ज्यादा है। यदि जल की कीमत बढ़ती है, तो लोग संरक्षण के तमाम उपाय भी आजमाने लगेंगे।

यह चिंताजनक है कि लोग बड़े पैमाने पर जल की बर्बादी करना नहीं छोड़ रहे और हम जल संकट से महासंकट की ओर बढ़ रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय किया था कि हरेक इंसान को घर से एक किलोमीटर या 30 मिनट से कम दूरी के स्रोत से प्रतिदिन 50 से 100 लीटर पानी पाने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे देश में, जहां काफी सारे गरीब और कम आय वाले परिवार हैं, यह पानी भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना उपलब्ध होना चाहिए। गरीब परिवारों को पानी की यह बुनियादी मात्रा मुफ्त उपलब्ध कराने का मामला है।

जन-धन, आधार व मोबाइल (जेएएम) की त्रिमूर्ति ने वह बुनियादी ढांचा मुहैया करा दिया है, जिससे पानी की उचित कीमत वसूली जा सकती है और गरीबों को इसे खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है। भारतीय शहरों को कुछ वर्षों पर पानी की कीमतें बढ़ानी चाहिए, जब तक कि वे इसकी सीमांत लागत या सही कीमत के करीब न पहुंच जाएं। इसके साथ ही, गरीब परिवारों को पानी के वाउचर का अधिकार देना चाहिए। ऐसे वाउचरों (या सब्सिडी) को राज्य सरकार के बजट के माध्यम से वित्त-पोषित किया जा सकता है, जब तक कि नगर निगम या जल निगम अपने स्वयं के धन से उन्हें सब्सिडी देने में सक्षम नहीं हो जाते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 100 लीटर पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए। जब तक हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक पाइप, बोरवेल, टैंकर या बोतलों का उपयोग करना उन पर आधारित होना चाहिए। मूल्य निर्धारण से जल विवादों का भी समाधान हो सकता है। जो राज्य ज्यादा पानी पर दावा करते हैं, उनके लिए ज्यादा भुगतान करना अनिवार्य हो और जो राज्य अपने कोटे से कम पानी लेते हैं, उन्हें नकद भुगतान किया जा सकता है। मूल्य निर्धारण से पानी की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा और उसका आवंटन भी ज्यादा कुशल होगा।

जल नीति का निर्धारण कठिन नहीं है और जल परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यावहारिक बनाया जा सकता है। यहां सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक व्यवस्था है, जो लोक-लुभावनवाद की आदी हो चुकी है। भारतीय राजनेता सशुल्क चीजों को मुफ्त करना जानते हैं। वे मुफ्त चीजों को शुल्क योग्य बनाने के विचार से अपरिचित हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, देश में मूल्य निर्धारण ने ही एक बड़ा और बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार किया है। पानी की कीमत इसलिए नहीं तय की जानी चाहिए कि यह सरकारों के लिए राजस्व का नया स्रोत बन जाए, बल्कि इसलिए करनी चाहिए कि यह जल संरक्षण को बढ़ावा दे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अपना-अपना नववर्ष

पूरी धरती पर फैले मानव समूहों के अपने-अपने संवत्सर हैं, जिनके आधार पर वे अपना नववर्ष मनाते हैं। उदाहरण के लिए, सनातन धर्म मानने वालों का नववर्ष विक्रम संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, तो ईस्वी सन् मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर मानने वालों का वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। भारत में मुख्य रूप से पर्व-त्योहार मनाने या नववर्ष की शुरुआत के लिए विक्रम संवत् को ही आधार मानते हैं, परंतु राष्ट्रीय पर्वों, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्तूबर आदि के लिए ईस्वी सन् की तारीख को आधार बनाया जाता है। हालांकि, हमारे मान्य राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम शक संवत्सर है। हमारे सरकारी संस्थान जैसे आकाशवाणी या दूरदर्शन राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार ही तिथियों की घोषणा करते हैं, यानी त्रिभाषा फॉर्मूले की तरह त्रिसंवत् फॉर्मूला!

भारतवर्ष में त्रयी का विशेष महत्व है। त्रयी का भाव इसके जीवन दर्शन में ही छिपा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश- त्रिदेव हों या लक्ष्मी, गौरी, सरस्वती- त्रिदेवियां। तंत्र में जाएं, तो इन त्रिशक्तियों या त्रिदेवों से पूर्व जिस महाशक्ति का अस्तित्व माना जाता है, उसका नाम ही त्रिपुरा है। सांख्य दर्शन जिस प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जीव-जगत के रहस्यों को समझाता है, उस प्रकृति में भी तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। उपासना में त्रिसंध्या का अपना विशेष महत्व है। मनुष्य भी मन, चित्त और अहंकार की त्रयी में डुबकी लगाता है। इसलिए विविधता भरे भारत में त्रयी का अपना आनंद व विमर्श है।

भारतीय समाज में विक्रम संवत् के आधार पर ही आज तक सभी पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं। इस तरह, अघोषित तौर पर ही सही, मगर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है विक्रम संवत्। हर वर्ष पुराना विमर्श आ खड़ा होता है कि जब अपना संवत्सर स्वीकार करना ही था, तो विक्रम संवत् में क्या बुराई थी? क्या इसीलिए कि वह ईस्वी सन् से भी प्राचीन था और अंग्रेजी शासन को यह स्वीकार करने में आपत्ति होती? शक तो बाहर से आए थे, विदेशी थे। भले यहां बसने के बाद हमारी संस्कृति में घुल-मिल गए और अपने से हो गए। विक्रमादित्य को इसीलिए 'शकारि' कहा जाता है, यानी शक का शत्रु। विक्रम संवत् की शुरुआत विक्रमादित्य ने भी तभी की थी, जब उन्होंने उज्जयिनी में शकों को पराजित किया था। यह विमर्श हमेशा बना रहेगा कि स्वतंत्र भारत ने विक्रम संवत् को छोड़ा और शक संवत् को स्वीकार लिया।

हर तारीख का एक इतिहास होता है, जिसे बार-बार याद किया जाता है, शक संवत् शुरू करने वाले राजा कनिष्क भी याद आ रहे हैं और विक्रम संवत् शुरू करने वाले महान विक्रमादित्य भी।

शक संवत् का नया वर्ष 22 मार्च को ही शुरू हो चुका है और विक्रम संवत् का नया वर्ष 9 अप्रैल, यानी आज से शुरू हो रहा है। हर तारीख का एक इतिहास होता है, जिसे बार-बार याद किया जाता है, शक संवत् शुरू करने वाले राजा कनिष्क भी याद आ रहे हैं और विक्रम संवत् शुरू करने वाले महान विक्रमादित्य भी।

नीरजा माधव

पॉल नर्स | नोबेल विजेता चिकित्सा विज्ञानी

मेरा मानना है कि विज्ञान में कूटनीतिक ताकत है। भले ही इसे पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि अक्सर सांस्कृतिक गतिविधियों ने वह भूमिका अधिक निभाई, लेकिन विज्ञान तमाम देशों में समान भाषा में बात करता है।

अनुलोम-विलोम

न्यायपत्र

जनता के हितों से जुड़ा घोषणापत्र

न्यायपत्र के नाम से कांग्रेस का जो घोषणापत्र सामने आया है, उसका महत्व देश की जनता के साथ-साथ गठबंधन के दलों के लिए भी है, क्योंकि अगर विपक्षी गठबंधन यह चुनाव जीतता है, तो सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही करेगी। यह उम्मीद इसलिए भी है कि कांग्रेस गठबंधन में इकलौती ऐसी पार्टी है, जिसका जनाधार संपूर्ण देश में है। ऐसे में, अगर सभी दल मिलकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते हैं, तो कांग्रेस के न्यायपत्र की अधिकांश बातें उसमें आसानी से समाहित हो सकती हैं। वैसे भी, इंडिया ब्लॉक के अधिकांश दल अपने-अपने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हैं, तब भी कांग्रेस को उनसे अधिक सीटें ही मिलेंगी। लिहाजा, कांग्रेस का न्यायपत्र संपूर्ण देश के लिए उत्सुकता का विषय है। संभवतः इसीलिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के घोषणापत्र की इतनी आलोचना कर रहा है, जो अपेक्षित है। चुनाव प्रचार में यह सब होता ही है। हरेक पार्टी के घोषणापत्र के विश्लेषण का अधिकार सबको है, तभी तो दोनों गठबंधनों के चुनावी वायदों का मूल्यांकन मतदाता कर सकेंगे कि अगली सरकार आने पर किसके पिटारे में उनके लिए क्या है? हालांकि, एक सच यह भी है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हैं, वैसी मुखरता कांग्रेस के न्यायपत्र में दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, उससे यही लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी दलों की जमीन कमजोर है। लिहाजा, उनके चुनावी वायदों में इस बात की अपेक्षा रहेगी ही कि वे बताएं चुनावी बॉन्ड, खर्चीले चुनाव, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर क्या सोचते हैं? वास्तव में, चुनाव अब इन्हीं मसलों पर केंद्रित होना चाहिए।

मुकेश कुमार मनन, टिप्पणीकार

उम्मीदों का दस्तावेज

आम चुनाव के पहले चरण के मतदान में बस कुछ दिन शेष हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 48 पन्नों का अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसे न्यायपत्र का नाम दिया गया है। इसमें कई घोषणाएं भविष्य के लिए उम्मीद जगाती हैं। नौकरी देने, किसानों की कर्जमाफी, खाली पद भरने, महिलाओं को भत्ता देने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने जैसे तमाम वायदों का इसमें जिक्र तो है ही, जो कांग्रेस पहले से कह रही थी, इनके अलावा सांविधानिक न्याय की वकालत भी इसमें की गई है। किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय जैसी तमाम बातें इसमें कही गई हैं, जिनकी आज के वक्त में काफी जरूरत है। इसी कारण, कांग्रेस के घोषणापत्र की तारीफ करनी चाहिए।

ममता सिंह, टिप्पणीकार

पूरी नहीं हो सकने वाली घोषणाएं

कांग्रेस के घोषणापत्र पर स्वाभाविक ही देश में सियासी जंग छिड़ गई है। आम चुनाव में अब गिनती के दिन रह गए हैं और कांग्रेस ने न्यायपत्र के नाम से अपना जो घोषणापत्र जारी किया है, उसमें काफी बेकार की बातों का जिक्र है। मिसाल के तौर पर, घोषणापत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के कटाक्ष किए गए हैं और उनकी गारंटी का मजाक उड़ाया गया है, जबकि सच यह है कि कांग्रेस की ही कथनी और करनी में समानता नहीं है। अपने कई वायदों पर वह फिसड्डी शामिल हुई है। इसके उलट, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं, वह करते हैं। किसानों की समस्याओं को सुलझाने, तीन तलाक, श्रीराम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का अंत, मजबूत कानून-व्यवस्था जैसे तमाम काम मोदी सरकार ने वायदे के अनुरूप किए। पिछले दस सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी काम किया है और उसी के आधार पर वह इस बार भी अपने लिए वोट मांग रही है। मगर कांग्रेस तो उन्हीं पुरानी बातों को दोहरा रही है, जो वह शुरू से कहती आ रही है। इतने वर्षों तक सरकार चलाने के बावजूद अगर वह न्याय की बात कह रही है, तो समझा जा सकता है कि किसके शासनकाल में किन-किन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। बात चाहे किसानों को रुलाने की हो, भ्रष्टाचार की तरफ से आंखें मूंदने की या फिर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की, कांग्रेस का इतिहास इस बात की इजाजत नहीं देता कि आज वह 'न्याय' की मांग करे। देखा जाए, तो देश में कांग्रेस का जनाधार अब खत्म हो गया है, इसलिए उसने अपने घोषणापत्र में ऐसी-ऐसी घोषणाओं का जिक्र कर दिया है, जो शायद ही पूरी हों।

ऐसे वक्त में, जब विकास-लक्षित योजनाओं से आसमान छूती भारतीय रफ्तार की पूरी दुनिया कायल है, हम शायद ही इससे पीछे हटना चाहेंगे। कांग्रेस को तो सिर्फ सत्ता प्यारी है। यह ठीक है कि चुनाव के समय सभी दल एक-दूसरे पर निशाना साधते हैं, लेकिन इस आरोप-प्रत्यारोप की भी सीमा होती है, जिसका ध्यान सभी पार्टियों को रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हैं, मगर कांग्रेस भाजपा को घेरने के बजाय प्रधानमंत्री को ही निशाने पर लेती है। वास्तव में, कांग्रेस की चुनावी हार का यह भी एक बड़ा कारण है कि वह व्यक्ति विशेष के खिलाफ अपना चुनाव अभियान चलाती है। न्यायपत्र से भी कुछ इसी तरह की झलक मिल रही है, इसलिए आम चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण
नवीनता नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार करती है

समस्याओं से घिरते बुजुर्ग

नीति आयोग ने बुजुर्गों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई, उसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना चाहिए। निःसंदेह भारत एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि धीरे-धीरे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक 60 से अधिक आयु वाली आबादी आज के मुकाबले करीब नौ प्रतिशत बढ़कर 19 प्रतिशत हो जाएगी। सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह जनसंख्या अच्छी-खासी होगी। चूंकि भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजनाएं नहीं हैं, इसलिए बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत कम वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, जिन्हें गुजारे लायक पेंशन मिलती है। यह पेंशन भी सरकारी सेवाएं देने वाले बुजुर्गों को मिलती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों को पेंशन या तो मिलती नहीं या फिर वह इतनी कम होती है, उसका कोई मतलब नहीं। वास्तव में वह ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं होती। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्गों को प्रति माह कुछ पैसा देती हैं, क्योंकि वह बहुत ही कम है। अपने देश में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते अब बुजुर्गों की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती। बुजुर्ग केवल एकाकीपन का ही सामना नहीं करते, बल्कि आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं। कम से कम वे तो अवश्य ही जूझते हैं, जिन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम किया होता है। बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता।

वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्यगत समस्याओं से भी कहीं अधिक दो-चार होना पड़ता है, लेकिन अधिकांश के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता या यह कहें कि उनके पास स्वास्थ्य बीमा लेने की सामर्थ्य ही नहीं होती। ऐसे में यह समय की मांग है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में पूरी बुजुर्ग आबादी को शामिल किया जाए। जो बुजुर्ग अपनी बचत से होने वाली आय पर निर्भर हैं, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के चलते उनकी आय प्रभावित होती है और कभी-कभी तो वह उनके जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त हो जाती है। नीति आयोग ने बुजुर्गों की जमा रकम पर ब्याज दर की तर्कसंगत सीमा तय करने और रिवर्स मार्गेज के नियमों में बदलाव करने के साथ सीनियर केयर होम्स बढ़ाने के जो सुझाव दिए, उन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। यह ठीक नहीं कि नीति आयोग ने यह पाया कि हाउसिंग सोसायटियां वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जातीं। अपने देश में जिस अनुपात में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में वृद्धावस्था आश्रम और सीनियर सिटिजन केयर होम्स नहीं बन रहे हैं। बुजुर्गों की चिंता सरकारों के साथ समाज को भी करनी होगी, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार 19 प्रतिशत बुजुर्ग या तो तलाकशुदा हैं या फिर उनके घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया है।

लापरवाही किसकी

लापरवाही के परिणाम कभी सुखद नहीं होते, सिर्फ नुकसान ही होता है। पछतावे के अलावा इंसान के पास कोई विकल्प नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में गर्मी के मौसम में नदी-नालों एवं तालाबों में लोगों के डूबने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बिना सोचे-समझे नदी-नालों एवं तालाबों में उतर जाते हैं। यह भी नहीं सोचते कि इससे उन्हें किसी तरह का खतरा हो सकता है। प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ऊना जिले के रायपुर सहौड़ा में तालाब में तीन बच्चों के डूबने की घटना हृदयविदारक है। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद लौट रहे बच्चे नहाने के लिए तालाब में उतरे और दलदल में फंसकर बाहर नहीं निकल पाए। इस मामले में कई पक्षों की लापरवाही सामने आई है। अगर सभी पक्ष सजग होते तो संभवतः इस तरह की दुर्घटना को टाला जा सकता था। हैरत है कि पंचायत ने तालाब के किनारों से पक्का तो करवा दिया, लेकिन चारदीवारी बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। यहां तक कि तालाब के किनारे चेतावनी पट्ट भी नहीं लगाया गया था, जिससे यहां आने वाले सजग रहें। अभिभावकों का भी दायित्व है कि बच्चों को अच्छे-बुरे के बारे में सचेत करते रहें। शासन-प्रशासन का दायित्व है कि ऐसे सभी स्थानों पर चेतावनी पट्ट लगाए, जहां किसी तरह का खतरा हो सकता है। जीवन अनमोल है, इसलिए लोग भी बिना सोचे-समझे नदी-नालों एवं तालाबों में उतरने की आदत छोड़ें।

> गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बिना सोचे-समझे नदी-नालों एवं तालाबों में उतर जाते हैं

राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग का सवाल

अश्विनी कुमार

राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े सवाल केवल केंद्र सरकार के संदर्भ में ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि कई राज्य सरकारें भी सवालों के घेरे में हैं

देश में आम चुनावों की प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां भारत के लोकतंत्र को किसी भी प्रकार से गौरवान्वित करने वाली या उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली नहीं हैं। इन गिरफ्तारियों को लेकर यही आरोप लग रहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्ता विरोधियों पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। जांच एजेंसियों का रवैया भी पक्षपाती दिखता है। ऐसे समय में संवैधानिक संस्थान उदासीन बने हुए हैं। इतिहास पर दृष्टि डालें तो असीमित राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग एक ऐसी सच्चाई है, जिसे हम देश में पहले भी देख चुके है, भले ही सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों। इन चिंताओं के बीच यह प्रश्न उठता है कि क्या चुनाव के वक्त नेताओं के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए? अगर रोक लगनी चाहिए तो उसकी अवधि क्या होनी चाहिए और क्या चुनाव के बीच नेता और आम जनता के बीच भेदभाव रखा जा सकता है? जवाब आएगा-नहीं। हालांकि इसका रास्ता ढूंढ़ना ही होगा कि लोकतंत्र की गरिमा को लेकर समाज में कोई संशय पैदा न हो।

राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े सवाल केवल केंद्र सरकार के संदर्भ में ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि कई राज्य सरकारें भी सवालों के घेरे में हैं। यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए जब जांच पूरी हो जाए और अदालतें अपना फैसला सुना दें। इस लिहाज से वर्तमान में केंद्रीय एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं, उस पर कोई राय व्यक्त करने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पहले जब विपक्षी दलों की ओर से प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के आरोप लगते थे, तब वे इतने तीखे होते नहीं थे।

इस समय ईडी और उसके दायरे में आने वाले पीएमएलए जैसे कानून की बहुत चर्चा है। पीएमएलए के संदर्भ में सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि यह एक कठोर कानून है और इसका इस्तेमाल सोच-विचार कर किया जाना चाहिए। समस्या यह है कि इस कठोर कानून के तहत बिना आरोप सिद्ध हुए आरोपितों को लंबे समय तक जेल में रखे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। यह लोकतंत्र और संविधानप्रदत्त स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। यह सही है कि कानून की नजर में सभी समान हैं और राजनेताओं से उच्च आदर्शों की अपेक्षा की जाती है। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए राजनीतिक वर्ग को इसका ध्यान रखना चाहिए कि देश में ऐसी कोई धारणा नहीं बननी चाहिए कि प्रमुख विपक्षी नेताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे राजनीति से प्रेरित हैं। वैसे भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत लंबी और बेहद थका देने वाली होती है। इसके चलते किसी के लिए भी खुद को दोषमुक्त साबित कर पाना आसान नहीं होता है।

अमेरिका के प्रसिद्ध वकील एफली बेली ने अपनी किताब 'द डिफेंस नेवर रेस्ट्स' में लिखा है कि कानूनी प्रक्रिया की चक्की में जब पिसाई होती है तो अभियुक्त की बेगुनाही अप्रासंगिक हो जाती है। इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय गंगाबाई बनाम संभाजी (2008) में दोहराते हुए कानूनी प्रक्रिया की भंवर के प्रति सचेत किया है। देश यह अपेक्षा करता है कि पीएमएलए जैसे कठोर कानून के प्रविधानों का पालन संविधान के अनुच्छेद-21 (जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार को मान्यता देता है) की मर्यादाओं के भीतर होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि नेताओं के खिलाफ प्रत्येक मुकदमा कुल मिलाकर मीडिया ट्रायल का रूप ले लेता है और इसी के अनुरूप लोग अपनी धारणा बनाने लगते हैं।

राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक मर्यादा, संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का राष्ट्रीय गरिमा के साथ अभिन्न संबंध है। इसका तकाजा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के मुताबिक सहज न्याय मिले। यही एक आदर्श लोकतंत्र की पहचान भी है। राजनीतिक दलों को यह समझना और स्वीकार करना होगा कि विरोधियों के प्रति अनुचित भाषा और रवैया कभी न मिटने वाली व्यक्तिगत शत्रुता को जन्म देते हैं। इस समय देश में जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उसके लिए किसी एक दल अथवा व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कुछ नेता आज खुद पीड़ित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने भी अतीत में राजनीतिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया। वे शायद अतीत की गलतियों की ही सजा भुगत रहे हैं। यह सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देश में तनाव और बिखराव का कारण न बने।

जहां तक राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रश्न है तो इसका स्थायी समाधान व्यापक चुनाव सुधारों में ही निहित है। इन सुधारों के जरिये ही चुनाव प्रक्रिया में धनबल-बाहुबल के बढ़ते दुरुपयोग को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए चुनावी बांड वाले फैसले की आम तौर पर सराहना जरूर हुई है, मगर इसका एक परिणाम यह भी होगा कि चुनावों में फिर से काले धन का बोलबाला हो सकता है। इससे निपटने के लिए तात्कालिक कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को जल्द से जल्द किन्हीं कदमों पर आम राय बनानी होगी। बेहतर हो कि राजनीतिक दल इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें। राजनीतिक प्रतिशोध वास्तव में मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए घातक है। जिस देश का आत्मा मानवीय सम्मान, संवाद, सौहार्द और स्वतंत्र विचारों द्वारा परिभाषित एवं प्रेरित हो, वहां किसी भी व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता पर प्रहार असहनीय होगा। हम इतिहास के इस सबक को भुला नहीं सकते कि जंजीरों के हटने और जख्मों के मिटने के बाद भी उनके निशान रह जाते हैं।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

कांग्रेस के न्याय पत्र पर वामपंथ की छाप

उमेश चतुर्वेदी

कांग्रेस नेतृत्व के सलाहकारों में वामपंथी सोच से ग्रस्त लोगों के बढ़ते दबदबे का असर न्याय पत्र पर भी दिख रहा है

पिछले दिनों कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र-2024 नाम दिया है। 48 पृष्ठों के इस दस्तावेज को पढ़कर ऐसा लगता है कि कांग्रेस दुविधा में है। इसमें पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों का मौन समर्थन करती नजर आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर अपनी गलतियों को सुधारती दिख रही है। साथ ही सामाजिक मुद्दों पर वामपंथी वैचारिकी से पूरी तरह ओतप्रोत नजर भी आ रही है। उसके द्वारा मुस्लिम पर्सनल ला का समर्थन भी इसी का विस्तार लगता है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के न्याय पत्र पर मुस्लिम लीग और वामपंथ की छाप दिखती है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पांच न्याय और 25 गारंटियों के जरिये न्याय देने-दिलाने का वादा किया है। आजाद भारत के 77 में से करीब 55 साल तक कांग्रेस का ही शासन रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि उसके शासन काल में न्याय की गारंटी कभी नहीं रही?

वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व के सलाहकारों में वामपंथी सोच से ग्रस्त लोगों का दबदबा बढ़ा है, जिसका असर न्याय पत्र में भी दिखता है। पुरानी पेंशन योजना की मांग इसी का नतीजा थी। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने इसे लागू करने का जोर-शोर से वादा किया था। माना गया कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को इसी मुद्दे पर जीत मिली, लेकिन न्याय पत्र में पार्टी ने इस पर चुप्पी साध ली। शायद उसे लगने लगा है कि आर्थिक रूप से यह उचित नहीं। उधर कर्नाटक में पांच गारंटियों को ही लागू करने के चलते बीस हजार करोड़ रुपये की योजनाएं ठप करनी पड़ी हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी इस मोर्चे पर कठिनाई महसूस कर रही है। राजस्थान में सत्तारूढ़ रही गहलोत सरकार ने इसे लागू करने का एलान किया था, लेकिन वह भी धन के अभाव के कारण परेशान रही। शायद इसी कारण से कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को टाल दिया है।

पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने न्यूनतम न्याय योजना का वादा किया था, लेकिन इस बार पार्टी ने इससे किनारा कर लिया है। लगता है कांग्रेस समझने लगी है कि न्यूनतम न्याय या पुरानी पेंशन योजना को लागू कर पाना आसान नहीं है। न्याय पत्र में पार्टी ने बेरोजगारी को मुद्दा तो जरूर बनाया है, लेकिन इसे दूर करने की दिशा में उसने सिर्फ सरकारी क्षेत्र में तीस लाख नौकरी देने का ही वादा किया है। सरकारी नौकरी के सोच के मूल में वामपंथी सोच है, जिसे नेहरूवादी समाजवादी व्यवस्था ने भी स्वीकार किया था। कांग्रेस इस मोर्चे पर वामपंथी सोच के साथ नेहरूवादी समाजवाद से ग्रस्त है, लेकिन सवाल है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों से इतने विशाल देश को रोजगार के मोर्चे पर सफलता मिल सकती है?

पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते राहुल। प्रेट्र

यह वामपंथी सोच ही है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना करने और आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से ज्यादा करने का वादा कर रही है। 1951 की जनगणना के दौरान भी जातिगत गणना कराने की मांग रखी गई थी, लेकिन तब पं. नेहरू और सरदार पटेल ने इसे खारिज कर दिया था। सरदार पटेल का मानना था कि इससे जातीय तनाव बढ़ेगा। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया है। कांग्रेस ने इस आरक्षण के दायरे में भी हर वर्ग को शामिल करने का वादा किया है। बीते कुछ वर्षों से आंदोलित कुछ किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। आर्थिक दबाव में इसे पूरी तरह स्वीकार करने से सरकारें बचती रही है। चूंकि कांग्रेस उनके आंदोलन को समर्थन देती रही है, ऐसे में इसका असर न्याय पत्र पर भी दिख रहा है। वामपंथी सोच के चलते कांग्रेस भूल गई है कि मनमोहन सिंह की अगुआई वाली सरकार इस मांग से मुकर गई थी। कांग्रेस ने जीएसटी को भी खत्म करने का वादा किया है। वैसे जीएसटी का विचार मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ही आया था, लेकिन वामपंथ के प्रभाव में आकर कांग्रेस अब इसे नकार रही है। अपने पिछले घोषणा पत्र में पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अफस्पा जैसे कानून तक का विरोध किया था, लेकिन इस बार इसके साथ-साथ अनुच्छेद-370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर भी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। लगता है वह इन मसलों पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने की स्थिति में नहीं है।

इन दिनों चुनाव आयोग पर भी कांग्रेस की नजरें टेढ़ी हैं। वामपंथी अक्सर न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते रहे हैं। परिणामस्वरूप न्याय पत्र में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को स्वायत्त बनाने के साथ न्यायपालिका में भी जाति और महिला हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही है। पार्टी ने निजी स्वतंत्रता का हनन करने वाले कानूनों को भी खत्म करने का वादा किया है। निजी कानून ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों से जुड़े हैं। साफ है पार्टी एक तरह से पर्सनल ला का समर्थन और तीन तलाक जैसे कानूनों का विरोध करती दिख रही है। न्याय पत्र में पार्टी ने ईवीएम का समर्थन किया है। हालांकि वीवीपैट की गिनती पर जोर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस एक ऐसे दलबदल विरोधी कानून के समर्थन में है, जिसमें दल बदलते ही सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि मतदाताओं ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर कितना भरोसा किया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

शक्ति साधना

सृष्टि में तीन कार्य अनवरत चलते रहते हैं-उद्भव, स्थिति और संहार। इन्हें सृजन, पालन और विनाश भी कहते हैं। यद्यपि इनका संचालन स्वतः होता है, किंतु शक्ति के अभाव में न सृजन संभव है, न पालन और न संहार, क्योंकि शक्ति जगत के अस्तित्व का मूल कारण है। छोटे से छोटा कार्य भी इसके बिना नहीं हो सकता। इसकी इसी उपादेयता के कारण भारतीय संस्कृति में शक्ति साधना का महत्व है। वर्ष में दो बार शक्तिस्वरूपा देवी की उपासना की जाती है। शक्ति का अर्जन, संरक्षण और सदुपयोग इसके उद्देश्य हैं। जिस प्रकार शक्ति के बिना जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार उसके संरक्षण एवं सदुपयोग के बिना आत्मकल्याण और लोककल्याण भी संभव नहीं। रावण जैसे राक्षसों ने अपनी तपस्या से विविध शक्तियों का अर्जन तो किया, किंतु न उनका संरक्षण किया और न ही सदुपयोग। इसीलिए वे शक्तियां न केवल लोक के लिए, अपितु अपने लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुईं। देव और दानव संस्कृति में विभेद का मुख्य हेतु यही है। इसी से कोई मानव भी दानव बन जाता है और दानव भी देव। अतः शक्ति का मुख्य प्रयोजन लोकहित में उसका कल्याणकारी प्रयोग है।

ऊर्जा ब्रह्मांड की केंद्रीय शक्ति है और उसके संचलन का आधार भी। इसीलिए सृष्टि के कण-कण में अपरिमित ऊर्जा व्याप्त है, जिसका मानव ने विविध रूपों में अर्जन भी किया है। उसके सुनियोजित एवं कल्याणकारी प्रयोग से दुर्लभ अभीष्ट की प्राप्ति कर विश्व को स्वर्ग से भी सुंदर बनाया जा सकता है। यही मानवता की विजय और पराजय का भी हेतु है, किंतु दुनिया में इसका बढ़ रहा दुरुपयोग चिंता का विषय है। इसीलिए आज मनुष्य त्रिविध दुखों में सर्वाधिक बाहरी प्रभावों के कारण उत्पन्न दुखों से पीड़ित है, क्योंकि ये सभी शक्ति के अमांगलिक प्रयोग से उपजते हैं। अतः मानवता की विजय के लिए शक्ति साधना की सार्थकता उसके सदुपयोग में है।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

प्रकृति एवं मातृशक्ति की उपासना

डा. मोनिका शर्मा

> वासंतिक नवरात्र परिवर्तन का भी काल होता है। इस दौरान प्रकृति नवीन हो जाती है

चैत्र माह के नवरात्र नववर्ष की दस्तक ही नहीं देते, बल्कि पूरी प्रकृति का नयापन भी साथ लाते हैं। नव संवत्सर का यह अवसर प्रकृति के पोर-पोर में नए जीवन की आहट, सृजन और नयापन का सुंदर मेल लिए है। शक्ति को साधने का उत्सव है। भारतीय संस्कृति में तो नारी की प्रखरता और शक्ति सामर्थ्य को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसमें नारी की मातृशक्ति की उपासना सबसे ऊपर है। आदिशक्ति की आराधना का यह महापर्व भी नारी के सम्मान, सामर्थ्य और स्वाभिमान की सार्वजनिक स्वीकार्यता से जुड़ा है, जो यह संदेश देता है कि मां के रूप में अपने बच्चों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाकर समाज को जिम्मेदार नागरिक देने वाली स्त्री स्वयं को कभी कम न आंके। हर महिला अपने-अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहे।

वस्तुतः आस्था का यह भाव स्त्रियों के चेतनामयी अस्तित्व से ही जुड़ा है। घर के भीतर और बाहर महिलाओं के सामने आने वाली बहुत-सी समस्याओं की जड़ अपने ही वजूद के प्रति जागरूक न होना है। हर हाल में अच्छे-बुरे व्यवहार के प्रति स्वीकार्यता का भाव रखने के बजाय जड़तावादी सोच लिए रूढ़िवादी बंधनों से खुद को मुक्त करने का विवेक रखना आवश्यक है। जागृत अस्तित्व और व्यक्तित्व हर मुश्किल से पार पाने का मार्ग सुझाता है। हर अंतर्द्वंद्व पर जीत निश्चित करता है। यह चेतना स्त्री होने के नाते अपने अधिकारों की जानकारी रखने और नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों से भी जुड़ी है। आस्था के भाव संग अंतर्मन की शक्ति साधना हर बहकावे से बचने का संदेश देती है। किसी भी तरह के शोषण के जाल में न फंसने की सजगता का पाठ लिए है। मां दुर्गा का रूप भारतीय स्त्री के असहाय नहीं, बल्कि मातृशक्ति के रूप में पोषक एवं चेतनामयी रूप में सजगता से दमकते चेहरे का प्रतीक है। नवरात्र का संदेश यह भी है कि स्त्रियां शोषण के खेल को समय रहते पहचानें। बुराइयों का प्रतिकार करना सीखें। अपने विरुद्ध होने वाले हर अत्याचार को लेकर आवाज बुलंद करने का बल जुटाएं। अन्याय और अनीति का प्रतिकार करने से न चूकें। हर तरह की दिशाहीनता से बचकर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षक बनें।

सुखद है कि आज हर क्षेत्र में प्रभावी भूमिका दर्ज करवा रहीं महिलाएं अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं। हर मोर्चे पर स्वयं को साबित भी कर रही हैं। यह वाकई एक सकारात्मक पक्ष है कि अपने मन जीवन से जुड़ी कई व्यावहारिक बातों के लिए आज की स्त्रियां जागरूक हुई हैं। वासंतिक नवरात्र परिवर्तन का भी काल होता है। इस दौरान प्रकृति नवीन हो जाती है। वसंत के मौसम में जीवन वापस नए सिरे से खिल उठता है। बदलाव के इस नए दौर में भारतीय स्त्रियों की अपने अस्तित्व को परिष्कृत करने की जिजीविषा ही सही अर्थों में सशक्त होना है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विकल्पहीन एवं दिशाहीन विपक्ष

'मोदी के मुकाबले कौन' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मोदी की विकल्पहीनता की स्थिति को उल्लिखित किया है। दरअसल आज भारत की राजनीति में विपक्षी पार्टियां न तो मोदी का विकल्प ही प्रस्तुत कर पा रही हैं और न ही वर्तमान सरकार के बदले में अपना कोई वैकल्पिक एजेंडा ही बता पा रही हैं। और जब तक विपक्षी दल जनता को इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर देते तब तक भारतीय जनमानस देश को अधर में धकेलने की इजाजत नहीं देने वाला। देश की राजनीति में यह दौर बहुत दिनों बाद आया है जब लोगों को भ्रष्टाचार विहीन सरकार देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वरना थोड़े वर्षों पहले राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय का रूप ले चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्तमान भाजपा सरकार ने न केवल विश्व में अपनी धाक को जमाया है, अपितु अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए राजनेता गठबंधन के सहारे मोदी की स्वच्छ छवि को तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे निकट भविष्य में ऐसी दूर-दूर तक कहीं संभावना नजर नहीं आ रही।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, उप्र

अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु

अयोध्या के नव्य, दिव्य, भव्य राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या दुनिया के सबसे धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित हुआ है। विश्व के सबसे बड़े

मेलबाक्स

धार्मिक स्थलों में मक्का, वेटिकन सिटी माने जाते हैं, लेकिन भव्य राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक शहर के रूप में आज विश्व में स्थापित हुआ है। मक्का और वेटिकन सिटी जितने लोग एक साल में पहुंचते हैं उससे कहीं अधिक इन तीन महीने में अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर निर्माण के पहले अयोध्या में लगभग पांच हजार लोग रोजाना पहुंचते थे, लेकिन अब डेढ़ से दो लाख के करीब लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार रामनवमी के अवसर पर 50 से 80 लाख के करीब लोग अयोध्या "राम-लला" के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं जिसमें देश और विदेश के श्रद्धालु होंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण न सिर्फ राम भक्तों के लिए एक सपने का पूरा होने जैसा है, बल्कि राम मंदिर के निर्माण से सनातन धर्म का गौरव पुनःस्थापित होने जैसा है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

कांग्रेस में बिखराव

एक जमाना था जब देश की राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस का दबदबा था। अब गठबंधन के बिना कांग्रेस का अस्तित्व शून्य समान है। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के 'सयासी ग्राफ' में काफी गिरावट देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण 'नेहरू-गांधी परिवार' का अहंकार तथा कुंठाग्रस्त नीतियां हैं। मुख्यतः राहुल गांधी की अपरिपक्वता और अनुभवहीनता के अतिरिक्त उनकी भाषा के कारण अधिकतर पार्टी नेता असंतुष्ट हो बारी-बारी हाथ झटक रहे हैं। हाल में कई प्रभावशाली नेताओं का कांग्रेस छोड़ "भाजपा" का हाथ थामने से विपक्षी घटक दलों को शर्मनाक झटका लगा है। देश के अनुभवी राजनीतिज्ञों की मानें तो कांग्रेस के अतिरिक्त द्रमुक और वामपंथी नेताओं की सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी 'आइएनडीआइए' को महंगी पड़ सकती है। सनातन धर्म पर प्रहार का दुष्प्रभाव 'आइएनडीआइए' को क्षतिग्रस्त कर सकता है। राहुल गांधी का वामपंथियों के प्रतिअधिक रुझान से भी पार्टी कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। बहरहाल राहुल की ताजपोशी तो दूर की बात, अब कांग्रेस की नैया लाचार दिखती है। एक नजर मोदी सरकार की उपलब्धियों पर डालें। सफल कूटनीति, कटिबद्ध नैतिकता और बेदाग छवि जन समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते देखा जा रहा है। अधिकांश लोगों का कहना है कि अबकी बार कांग्रेस यदि सत्ता में नहीं आती तो बेहतर होगा कि राहुल गांधी राजनीति से संन्यास लें और कांग्रेस की कमान किसी और के हाथों में दें।

कृष्ण खन्ना, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

समस्याओं से घिरते बुजुर्ग

नीति आयोग ने बुजुर्गों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई, उसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय होना चाहिए। निःसंदेह भारत एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि धीरे-धीरे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक 60 से अधिक आयु वाली आबादी आज के मुकाबले करीब नौ प्रतिशत बढ़कर 19 प्रतिशत हो जाएगी। सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह जनसंख्या अच्छी-खासी होगी। चूंकि भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजनाएं नहीं हैं, इसलिए बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत कम वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, जिन्हें गुजारे लायक पेंशन मिलती है। यह पेंशन भी सरकारी सेवाएं देने वाले बुजुर्गों को मिलती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों को पेंशन या तो मिलती नहीं या फिर वह इतनी कम होती है, उसका कोई मतलब नहीं। वास्तव में वह ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं होती। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्गों को प्रति माह कुछ पैसा देती हैं, क्योंकि वह बहुत ही कम है। अपने देश में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते अब बुजुर्गों की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती। बुजुर्ग केवल एकाकीपन का ही सामना नहीं करते, बल्कि आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं। कम से कम वे तो अवश्य ही जूझते हैं, जिन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम किया होता है। बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्यगत समस्याओं से भी कहीं अधिक दो-चार होना पड़ता है, लेकिन अधिकांश के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता या यह कहें कि उनके पास स्वास्थ्य बीमा लेने की सामर्थ्य ही नहीं होती। ऐसे में यह समय की मांग है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में पूरी बुजुर्ग आबादी को शामिल किया जाए। जो बुजुर्ग अपनी बचत से होने वाली आय पर निर्भर हैं, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के चलते उनकी आय प्रभावित होती है और कभी-कभी तो वह उनके जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त हो जाती है। नीति आयोग ने बुजुर्गों की जमा रकम पर ब्याज दर की तर्कसंगत सीमा तय करने और रिवर्स मार्गेज के नियमों में बदलाव करने के साथ सीनियर केयर होम्स बढ़ाने के जो सुझाव दिए, उन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। यह ठीक नहीं कि नीति आयोग ने यह पाया कि हाउसिंग सोसायटियां वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जातीं। अपने देश में जिस अनुपात में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में वृद्धावस्था आश्रम और सीनियर सिटिजन केयर होम्स नहीं बन रहे हैं। बुजुर्गों की चिंता सरकारों के साथ समाज को भी करनी होगी, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार 19 प्रतिशत बुजुर्ग या तो तलाकशुदा हैं या फिर उनके घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया है।

नशे के धंधे पर हो प्रहार

राज्य में पूर्ण शराबबंदी और नशे पर सख्त पाबंदी के बाद भी यह काला धंधा फल फूल रहा है। यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हर दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से शराब की छोटी-बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। अब तो बिहार की पुलिस इस मामले में दूसरे राज्यों में जाकर भी धंधेबाजों की धर- पकड़ कर रही है। इसके बावजूद न तो नशा करने वालों के समक्ष नशा सामग्री की उपलब्धता की कमी है और न ही धंधेबाज तस्करी करने से बाज आ रहे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस को और कठोर कदम उठाने होंगे। चिंता की बात यह कि एक बार इस धंधे में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद भी वे पुनः धंधे में शामिल होने से बाज नहीं आ रहे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई उतनी सख्त नहीं थी, जितनी होनी चाहिए। राजधानी के गोविंद मित्रा रोड के एक मकान और जनता लाज से जब्त की गई नशे की सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि दवा के कारोबार की आड़ में भी इस धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। नशे के धंधेबाज युवाओं को ज्यादा टारगेट करते हैं। ये जहर बेचने वाले भावी पीढ़ी को पंगु बना रहे हैं। इनकी वजह से कई घर बर्बाद हो गए। कई ने अपने मेधावी बच्चों को खो दिया। इतने कड़े प्रतिबंध के बाद भी यदि यह धंधा राजधानी के इलाकों में फल फूल रहा है तो कहा जा सकता है कि कार्रवाई को और भी सख्त करने की जरूरत है। इस धंधे में पुलिस वाले भी कई बार संलिप्त पाए गए। उनपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन धंधे की गति धीमी नहीं हुई। जाहिर है, कहीं न कहीं से इन धंधेबाजों को ताकत मिल रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जरूरत है।

कड़े प्रतिबंध के बाद भी नशे का धंधा फल-फूल रहा है। जाहिर है, कार्रवाई को और भी सख्त करने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एनआइए की टीम पर हमला पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का प्रमाण है?

आज का सवाल

क्या अखिलेश यादव वोट बैंक के लालच में माफिया मुख्तार अंसारी के घर गए?

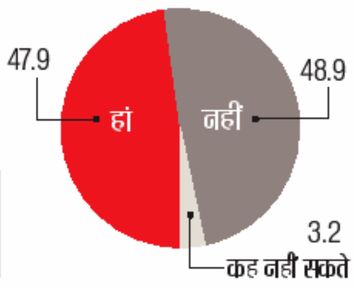

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग का सवाल

अश्विनी कुमार

राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े सवाल केवल केंद्र सरकार के संदर्भ में ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि कई राज्य सरकारें भी सवालों के घेरे में हैं

देश में आम चुनावों की प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां भारत के लोकतंत्र को किसी भी प्रकार से गौरवान्वित करने वाली या उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली नहीं हैं। इन गिरफ्तारियों को लेकर यही आरोप लग रहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्ता विरोधियों पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। जांच एजेंसियों का रवैया भी पक्षपाती दिखता है। ऐसे समय में संवैधानिक संस्थान उदासीन बने हुए हैं। इतिहास पर दृष्टि डालें तो असीमित राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग एक ऐसी सच्चाई है, जिसे हम देश में पहले भी देख चुके है, भले ही सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों। इन चिंताओं के बीच यह प्रश्न उठता है कि क्या चुनाव के वक्त नेताओं के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए? अगर रोक लगनी चाहिए तो उसकी अवधि क्या होनी चाहिए और क्या चुनाव के बीच नेता और आम जनता के बीच भेदभाव रखा जा सकता है? जवाब आएगा-नहीं। हालांकि इसका रास्ता ढूंढ़ना ही होगा कि लोकतंत्र की गरिमा को लेकर समाज में कोई संशय पैदा न हो।

राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े सवाल केवल केंद्र सरकार के संदर्भ में ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि कई राज्य सरकारें भी सवालों के घेरे में हैं। यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए जब जांच पूरी हो जाए और अदालतें अपना फैसला सुना दें। इस लिहाज से वर्तमान में केंद्रीय एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं, उस पर कोई राय व्यक्त करने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पहले जब विपक्षी दलों की ओर से प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के आरोप लगते थे, तब वे इतने तीखे होते नहीं थे।

इस समय ईडी और उसके दायरे में आने वाले पीएमएलए जैसे कानून की बहुत चर्चा है। पीएमएलए के संदर्भ में सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि यह एक कठोर कानून है और इसका इस्तेमाल सोच-विचार कर किया जाना चाहिए। समस्या यह है कि इस कठोर कानून के तहत बिना आरोप सिद्ध हुए आरोपितों को लंबे समय तक जेल में रखे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। यह लोकतंत्र और संविधानप्रदत्त स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। यह सही है कि कानून की नजर में सभी समान हैं और राजनेताओं से उच्च आदर्शों की अपेक्षा की जाती है। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए राजनीतिक वर्ग को इसका ध्यान रखना चाहिए कि देश में ऐसी कोई धारणा नहीं बननी चाहिए कि प्रमुख विपक्षी नेताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे राजनीति से प्रेरित हैं। वैसे भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत लंबी और बेहद थका देने वाली होती है। इसके चलते किसी के लिए भी खुद को दोषमुक्त साबित कर पाना आसान नहीं होता है।

अवधेश राजपूत

अमेरिका के प्रसिद्ध वकील एफली बेली ने अपनी किताब 'द डिफेंस नेवर रेस्ट्स' में लिखा है कि कानूनी प्रक्रिया की चक्की में जब पिसाई होती है तो अभियुक्त की बेगुनाही अप्रासंगिक हो जाती है। इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय गंगाबाई बनाम संभाजी (2008) में दोहराते हुए कानूनी प्रक्रिया की भंवर के प्रति सचेत किया है। देश यह अपेक्षा करता है कि पीएमएलए जैसे कठोर कानून के प्रविधानों का पालन संविधान के अनुच्छेद-21 (जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार को मान्यता देता है) की मर्यादाओं के भीतर होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि नेताओं के खिलाफ प्रत्येक मुकदमा कुल मिलाकर मीडिया ट्रायल का रूप ले लेता है और इसी के अनुरूप लोग अपनी धारणा बनाने लगते हैं।

राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक मर्यादा, संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का राष्ट्रीय गरिमा के साथ अभिन्न संबंध है। इसका तकाजा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के मुताबिक सहज न्याय मिले। यही एक आदर्श लोकतंत्र की पहचान भी है। राजनीतिक दलों को यह समझना और स्वीकार करना होगा कि विरोधियों के प्रति अनुचित भाषा और रवैया कभी न मिटने वाली व्यक्तिगत शत्रुता को जन्म देते हैं। इस समय देश में जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उसके लिए किसी एक दल अथवा व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कुछ नेता आज खुद पीड़ित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने भी अतीत में राजनीतिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया। वे शायद अतीत की गलतियों की ही सजा भुगत रहे हैं। यह सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देश में तनाव और बिखराव का कारण न बने।

जहां तक राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रश्न है तो इसका स्थायी समाधान व्यापक चुनाव सुधारों में ही निहित है। इन सुधारों के जरिये ही चुनाव प्रक्रिया में धनबल-बाहुबल के बढ़ते दुरुपयोग को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए चुनावी बांड वाले फैसले की आम तौर पर सराहना जरूर हुई है, मगर इसका एक परिणाम यह भी होगा कि चुनावों में फिर से काले धन का बोलबाला हो सकता है। इससे निपटने के लिए तात्कालिक कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को जल्द से जल्द किन्हीं कदमों पर आम राय बनानी होगी। बेहतर हो कि राजनीतिक दल इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें। राजनीतिक प्रतिशोध वास्तव में मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए घातक है। जिस देश का आत्मा मानवीय सम्मान, संवाद, सौहार्द और स्वतंत्र विचारों द्वारा परिभाषित एवं प्रेरित हो, वहां किसी भी व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता पर प्रहार असहनीय होगा। हम इतिहास के इस सबक को भुला नहीं सकते कि जंजीरों के हटने और जख्मों के मिटने के बाद भी उनके निशान रह जाते हैं।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

कांग्रेस के न्याय पत्र पर वामपंथ की छाप

उमेश चतुर्वेदी

कांग्रेस नेतृत्व के सलाहकारों में वामपंथी सोच से ग्रस्त लोगों के बढ़ते दबदबे का असर न्याय पत्र पर भी दिख रहा है

पिछले दिनों कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे न्याय पत्र-2024 नाम दिया है। 48 पृष्ठों के इस दस्तावेज को पढ़कर ऐसा लगता है कि कांग्रेस दुविधा में है। इसमें पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों का मौन समर्थन करती नजर आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर अपनी गलतियों को सुधारती दिख रही है। साथ ही सामाजिक मुद्दों पर वामपंथी वैचारिकी से पूरी तरह ओतप्रोत नजर भी आ रही है। उसके द्वारा मुस्लिम पर्सनल ला का समर्थन भी इसी का विस्तार लगता है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के न्याय पत्र पर मुस्लिम लीग और वामपंथ की छाप दिखती है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पांच न्याय और 25 गारंटियों के जरिये न्याय देने-दिलाने का वादा किया है। आजाद भारत के 77 में से करीब 55 साल तक कांग्रेस का ही शासन रहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि उसके शासन काल में न्याय की गारंटी कभी नहीं रही?

वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व के सलाहकारों में वामपंथी सोच से ग्रस्त लोगों का दबदबा बढ़ा है, जिसका असर न्याय पत्र में भी दिखता है। पुरानी पेंशन योजना की मांग इसी का नतीजा थी। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने इसे लागू करने का जोर-शोर से वादा किया था। माना गया कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को इसी मुद्दे पर जीत मिली, लेकिन न्याय पत्र में पार्टी ने इस पर चुप्पी साध ली। शायद उसे लगने लगा है कि आर्थिक रूप से यह उचित नहीं। उधर कर्नाटक में पांच गारंटियों को ही लागू करने के चलते बीस हजार करोड़ रुपये की योजनाएं ठप करनी पड़ी हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी इस मोर्चे पर कठिनाई महसूस कर रही है। राजस्थान में सत्तारूढ़ रही गहलोत सरकार ने इसे लागू करने का एलान किया था, लेकिन वह भी धन के अभाव के कारण परेशान रही। शायद इसी कारण से कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को टाल दिया है।

पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने न्यूनतम न्याय योजना का वादा किया था, लेकिन इस बार पार्टी ने इससे किनारा कर लिया है। लगता है कांग्रेस समझने लगी है कि न्यूनतम न्याय या पुरानी पेंशन योजना को लागू कर पाना आसान नहीं है। न्याय पत्र में पार्टी ने बेरोजगारी को मुद्दा तो जरूर बनाया है, लेकिन इसे दूर करने की दिशा में उसने सिर्फ सरकारी क्षेत्र में तीस लाख नौकरी देने का ही वादा किया है। सरकारी नौकरी के सोच के मूल में वामपंथी सोच है, जिसे नेहरूवादी समाजवादी व्यवस्था ने भी स्वीकार किया था। कांग्रेस इस मोर्चे पर वामपंथी सोच के साथ नेहरूवादी समाजवाद से ग्रस्त है, लेकिन सवाल है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों से इतने विशाल देश को रोजगार के मोर्चे पर सफलता मिल सकती है?

पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते राहुल ● पेट्र

यह वामपंथी सोच ही है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना करने और आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से ज्यादा करने का वादा कर रही है। 1951 की जनगणना के दौरान भी जातिगत गणना कराने की मांग रखी गई थी, लेकिन तब पं. नेहरू और सरदार पटेल ने इसे खारिज कर दिया था। सरदार पटेल का मानना था कि इससे जातीय तनाव बढ़ेगा। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया है। कांग्रेस ने इस आरक्षण के दायरे में भी हर वर्ग को शामिल करने का वादा किया है। बीते कुछ वर्षों से आंदोलित कुछ किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। आर्थिक दबाव में इसे पूरी तरह स्वीकार करने से सरकारें बचती रही है। चूंकि कांग्रेस उनके आंदोलन को समर्थन देती रही है, ऐसे में इसका असर न्याय पत्र पर भी दिख रहा है। वामपंथी सोच के चलते कांग्रेस भूल गई है कि मनमोहन सिंह की अगुआई वाली सरकार इस मांग से मुकर गई थी। कांग्रेस ने जीएसटी को भी खत्म करने का वादा किया है। वैसे जीएसटी का विचार मनमोहन सिंह सरकार के दौरान ही आया था, लेकिन वामपंथ के प्रभाव में आकर कांग्रेस अब इसे नकार रही है। अपने पिछले घोषणा पत्र में पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अफस्पा जैसे कानून तक का विरोध किया था, लेकिन इस बार इसके साथ-साथ अनुच्छेद-370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर भी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। लगता है वह इन मसलों पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने की स्थिति में नहीं है।

इन दिनों चुनाव आयोग पर भी कांग्रेस की नजरें टेढ़ी हैं। वामपंथी अक्सर न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते रहे हैं। परिणामस्वरूप न्याय पत्र में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को स्वायत्त बनाने के साथ न्यायपालिका में भी जाति और महिला हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही है। पार्टी ने निजी स्वतंत्रता का हनन करने वाले कानूनों को भी खत्म करने का वादा किया है। निजी कानून ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों से जुड़े हैं। साफ है पार्टी एक तरह से पर्सनल ला का समर्थन और तीन तलाक जैसे कानूनों का विरोध करती दिख रही है। हाल के वर्षों में ईवीएम पर सवाल उठाने में वामदल और कांग्रेसी आगे रहे हैं, लेकिन न्याय पत्र में पार्टी ने ईवीएम का समर्थन किया है। हालांकि वीवीपैट की गिनती पर जोर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस एक ऐसे दलबदल विरोधी कानून के समर्थन में है, जिसमें दल बदलते ही सांसद या विधायक की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि मतदाताओं ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर कितना भरोसा किया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शक्ति साधना

सृष्टि में तीन कार्य अनवरत चलते रहते हैं-उद्भव, स्थिति और संहार। इन्हें सृजन, पालन और विनाश भी कहते हैं। यद्यपि इनका संचालन स्वतः होता है, किंतु शक्ति के अभाव में न सृजन संभव है, न पालन और न संहार, क्योंकि शक्ति जगत के अस्तित्व का मूल कारण है। छोटे से छोटा कार्य भी इसके बिना नहीं हो सकता। इसकी इसी उपादेयता के कारण भारतीय संस्कृति में शक्ति साधना का महत्व है। वर्ष में दो बार शक्तिस्वरूपा देवी की उपासना की जाती है। शक्ति का अर्जन, संरक्षण और सदुपयोग इसके उद्देश्य हैं। जिस प्रकार शक्ति के बिना जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार उसके संरक्षण एवं सदुपयोग के बिना आत्मकल्याण और लोककल्याण भी संभव नहीं। रावण जैसे राक्षसों ने अपनी तपस्या से विविध शक्तियों का अर्जन तो किया, किंतु न उनका संरक्षण किया और न ही सदुपयोग। इसीलिए वे शक्तियां न केवल लोक के लिए, अपितु अपने लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुईं। देव और दानव संस्कृति में विभेद का मुख्य हेतु यही है। इसी से कोई मानव भी दानव बन जाता है और दानव भी देव। अतः शक्ति का मुख्य प्रयोजन लोकहित में उसका कल्याणकारी प्रयोग है।

ऊर्जा ब्रह्मांड की केंद्रीय शक्ति है और उसके संचलन का आधार भी। इसीलिए सृष्टि के कण-कण में अपरिमित ऊर्जा व्याप्त है, जिसका मानव ने विविध रूपों में अर्जन भी किया है। उसके सुनियोजित एवं कल्याणकारी प्रयोग से दुर्लभ अभीष्ट की प्राप्ति कर विश्व को स्वर्ग से भी सुंदर बनाया जा सकता है। यही मानवता की विजय और पराजय का भी हेतु है, किंतु दुनिया में इसका बढ़ रहा दुरुपयोग चिंता का विषय है। इसीलिए आज मनुष्य त्रिविध दुखों में सर्वाधिक बाहरी प्रभावों के कारण उत्पन्न दुखों से पीड़ित है, क्योंकि ये सभी शक्ति के अमांगलिक प्रयोग से उपजते हैं। लोकमंगल भाव के बिना शक्ति केवल दुख का कारण बनती है। अतः मानवता की विजय के लिए शक्ति साधना की सार्थकता उसके सदुपयोग में है।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

विकल्पहीन एवं दिशाहीन विपक्ष

'मोदी के मुकाबले कौन' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मोदी की विकल्पहीनता की स्थिति को उल्लिखित किया है। दरअसल आज भारत की राजनीति में विपक्षी पार्टियां न तो मोदी का विकल्प ही प्रस्तुत कर पा रही हैं और न ही वर्तमान सरकार के बदले में अपना कोई वैकल्पिक एजेंडा ही बता पा रही हैं। और जब तक विपक्षी दल जनता को इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर देते तब तक भारतीय जनमानस देश को अधर में धकेलने की इजाजत नहीं देने वाला। देश की राजनीति में यह दौर बहुत दिनों बाद आया है जब लोगों को भ्रष्टाचार विहीन सरकार देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वरना थोड़े वर्षों पहले राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय का रूप ले चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्तमान भाजपा सरकार ने न केवल विश्व में अपनी धाक को जमाया है, अपितु अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए राजनेता गठबंधन के सहारे मोदी की स्वच्छ छवि को तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे निकट भविष्य में ऐसी दूर-दूर तक कहीं संभावना नजर नहीं आ रही।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, उप्र

माफिया को मसीहा बताने में संकोच नहीं

संपादकीय आलेख आठ अप्रैल को 'तुष्टीकरण की राजनीति' पढ़ा। कांग्रेस पार्टी के पद चिह्नों पर चलते हुए आज देश के कई क्षेत्रीय दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति के लिए माफिया को मसीहा बताने में भी नेताओं को कोई संकोच नहीं हो रहा है। माफिया के साथ नेता रहे मुख्तार अंसारी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का मुख्तार अंसारी के घर जाकर न्यायिक हिरासत में उपचार के दौरान हुई उनकी मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या एवं अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक की हत्या में भी भारत सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। मुख्तार अंसारी के दादा एवं नाना के योगदान को याद किया। मुख्तार अंसारी के पूर्वजों के अच्छे कार्यों के आधार पर उन्हें उनके अपराधों से क्षमा नहीं मिल सकती है। मुख्तार अंसारी पर साठ से अधिक मुकदमे हैं, जिनमें कई में उन्हें सजा सुनाई गई है। इस तरह के अपराधियों को महिमामंडित करना राष्ट्रद्रोह के समान है। आज की राजनीति में अपराधीकरण हावी हो चुका है, इसलिए नेताओं द्वारा अपराधियों को महिमामंडित किया जाता है। राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को वर्जित करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आम जनता को भी अपने मताधिकार से अपराधियों को चुनाव में रोकना चाहिए। इसके लिए बचपन से ही पाठ्यक्रम में स्वस्थ लोकतंत्र का पाठ सम्मिलित करना होगा, ताकि लोग प्रत्याशी चयन में सही-गलत की पहचान कर सकें। जाति व धर्म के आधार पर किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को समर्थन नहीं करें।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

जमाबंदी को लेकर जद्दोजहद

प्रदेश के अंचल कार्यालयों में पैतृक भूखंड अपने नाम पर जमाबंदी कराने के लिए वंशावली बनवाने एवं बंटवारा कराने को लेकर इन दिनों काफी भागदौड़ की जा रही है। भू माफिया एवं दलालों की सक्रियता से अंचलों में शिविर संचालित होने के बावजूद इस पर खानापूर्ति की जा रही है। बंटवारानामा के लिए एक बड़े हिस्सेदार को छोड़ कर आपसी राजीनामा का फर्जी पत्र तैयार कराया जा रहा है। इस राजीनामे का मुख्य उद्देश्य यादाश्त बंटवारे से है, जिस पर मुखिया एवं सरपंच भी हस्ताक्षर कर देते हैं। इन मामलों में जानबूझ कर निजी स्वार्थ साधने के लिए गांव ही नहीं नजदीकी गांव के लोग भी मामले को तूल देते हैं। गांवों में गवाही करने को लेकर कई विवाद पहले से ही चल रहे हैं। जमीन मालिक के बेटे एवं नाती तक विवाद पैदा करते रहते हैं। भूमि विवाद कम करने की बात हो रही है, जबकि बिना बंटवारे के बख्शीशनामा एवं बयनामा जैसे निबंधित डीड तैयार कराना सामान्य बात हो गई है। भूमि सुधार विभाग या दीवानी न्यायालयों में ऐसे मामले वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। एकपक्षीय निर्णय को भी ऊपरी अदालतों में चुनौती देकर उसे निष्प्रभावी बना दिया जाता है। अंततः तमाम लंबी प्रक्रिया से जूझने के बावजूद पैतृक जमीन के बंटवारे के नाम पर हाथ में शून्य ही लगता है। प्रक्रिया की यही खोट व भू माफिया से सरकारी कर्मियों की मिलीभगत जमीन विवाद सुलझने नहीं दे रहे। इस पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।

कामतानाथ तिवारी, दलसागर, बक्सर

पोस्ट

क्रिकेट में एक बहुत अच्छी बात यह है कि खिलाड़ियों के अधिकांश प्रशंसक उनके खेल की वजह से उनके मुरीद होते हैं। अन्यथा यहां भी सिर्फ अपनी जाति वाले को ही बेस्ट मान रहे होते। अजी हां@AjiHaaan

एक्स पर जाति या समुदाय के आधार पर चल रहे हैंडल बंद होने चाहिए। किसी भी समुदाय के नाम पर हैंडल बनाकर खुद को उसका प्रतिनिधि घोषित करके सामुदायिक वैमनस्य फैलाना साइबर अपराध है। समुदाय की आड़ में सस्ती भावुकता के सहारे सामाजिक कटुता को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मैंने काम किया है और जानता हूं कि पीके बिना पारिश्रमिक कोई सलाह नहीं देते। फिर वह राहुल गांधी जी को क्यों बिन मांगी सलाह दे रहे हैं। उन्हें इसके लिए कहीं से कोई पेमेंट हो रही है क्या? राज बब्बर@RajBabbar23

पंजाब में किसानों द्वारा रोड ब्लाक करने की वजह से कार एक्सीडेंट में पुलिस के दो जवानों की मौत हो गई, जिनमें से एक एसीपी और दूसरा उनका सुरक्षाकर्मी है। इनकी मौत की एफआइआर धरने पर बैठे किसानों पर भी हो। सरपंच मीका गिल@SarpanchMika

जनपथ

अपना झंडा ही गए वायनाड में भूल,
डरते मुस्लिम लीग से इतना मिस्टर कूल!
इतना मिस्टर कूल डांट देंगे यदि लीगी,
जाएंगे किस ओर पैंट ले भीगी-भीगी!!
भाई को है एक धर्म की माला जपना,
इसीलिए तो त्याग दिया है झंडा अपना!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 24 अंक 354

****

प्रवाह
महोत्सव विश्वास का
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

शिक्षा सिर्फ धन अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह सत्य की खोज और सदाचार के लिए मानव आत्मा का प्रशिक्षण भी है।
-विजय लक्ष्मी पंडित

विश्व बैंक के अलावा मूडीज, फिंच, एस ऐंड पी और मॉर्गन स्टेनली जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा भी भारत की डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे में निवेश के ढंग को पूरी दुनिया के लिए मिसाल बताना आश्वस्त करता है।

और अब संयुक्त राष्ट्र

वित्तीय समावेशन और निर्धनता-उन्मूलन संबंधी लक्ष्यों को पाने में डिजिटलीकरण का प्रभावी उपयोग करने और बुनियादी क्षेत्र में निवेश के लिए अगर भारत की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सर्वोच्च पदाधिकारी डेनिस फ्रांसिस खुद करें, तो इसके अर्थ और महत्व, दोनों ही बढ़ जाते हैं। उनका यह कहना वाकई सुखद है कि भारत ने सिर्फ एक मोबाइल फोन और डिजिटलीकरण के अपने मॉडल से जिस तरह देश के करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है, वह दुनिया के तमाम देशों के लिए एक सबक है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने, विश्व बैंक ने अपनी डिजिटल प्रोग्रेस ऐंड ट्रेंड्स रिपोर्ट में भी डिजिटल क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रदर्शन को रेखांकित किया था। दरअसल, आज अगर प्रतिष्ठित वैश्विक संगठन खुल कर भारत में डिजिटलीकरण की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका श्रेय पिछले कुछ वर्षों में की गई पहलों को जाता है। विश्व बैंक तो यहां तक कह चुका है कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें पचास वर्षों में भी करना मुश्किल था। 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान के साथ भारत के डिजिटलीकरण में तेजी आई। 85 करोड़ लोगों को सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराना हो या सवा अरब से ज्यादा लोगों को कवर करने वाला 'आधार' हो या फिर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पहल, ये सभी भारत में डिजिटल क्रांति के आधार बने। आज अगर सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे देश भी भारतीय यूपीआई को अपना रहे हैं, तो यह भारतीय तकनीक पर बढ़ते भरोसे का ही परिचायक है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में यूएनजीए के अध्यक्ष जब भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, तब उन्होंने देश में डिजिटलीकरण के अलावा बुनियादी ढांचे के विकास पर किए जा रहे कार्यों को नजदीक से देखा था। लिहाजा, अब इस क्षेत्र में किए जा रहे निवेश की उनके द्वारा की गई तारीफ दर्शाती है कि पहले कोरोना और

अब मंदी, वैश्विक युद्ध व आपूर्ति शृंखलाओं में पहुंच रही बाधा से दुनिया के त्रस्त होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। दरअसल, बुनियादी क्षेत्र का विकास न सिर्फ अर्थव्यवस्था की ताकत, बल्कि बढ़ती नौकरियों के रूप में भी देखा जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलाव आंकड़ों में भी दिखते हैं। खुद विश्व बैंक के अलावा, अगर मूडीज, फिंच, एस ऐंड पी और मॉर्गन स्टेनली जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भी विकास दर के अनुमानों को बढ़ा रही हैं, तो यह आश्वस्तकारी होने के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर दुनिया के बढ़ते भरोसे को भी दिखाता है।

इतने कम आयकर दाता

कटु सच्चाई यह है कि 7.4 करोड़ आयकर रिटर्न में से 5.16 करोड़ शून्य कर रिटर्न होते हैं। यानी आयकर रिटर्न भरने वाले 5.2 फीसदी भारतीयों में से 70 फीसदी लोग शून्य आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इसका मतलब है कि देश की आबादी का मात्र 1.6 फीसदी हिस्सा आयकर का भुगतान करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कर-राजस्व संग्रहण में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि न केवल आर्थिक गतिशीलता को, बल्कि कर प्रशासन की प्रभावशीलता और करदाताओं के अनुपालन को भी परिलक्षित करती है। सरकार ने एक फरवरी, 2024 को संसद में पेश संशोधित अनुमान में वित्त वर्ष 2023-24 में कर संग्रह का लक्ष्य बढ़ाकर 34.37 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। इसमें प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 19.45 लाख करोड़ रुपये था, जबकि अप्रत्यक्ष करों (जीएसटी, सीमा शुल्क) का लक्ष्य घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपये कर दिया था।

अजय बग्गा
आर्थिक मामलों के जानकार

वित्त वर्ष 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत ज्यादा है। संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने वाले भारतीयों की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 7.4 करोड़ हो गई है। यानी 140 करोड़ की आबादी वाले अपने देश में हर 19वां व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा है। लेकिन कटु सच्चाई यह है कि 7.4 करोड़ आयकर रिटर्न में से 5.16 करोड़ शून्य कर रिटर्न होते हैं। यानी आयकर रिटर्न भरने वाले 5.2 फीसदी भारतीयों में से 70 फीसदी लोग शून्य आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 2.24 करोड़ भारतीय, यानी आबादी का मात्र 1.6 फीसदी हिस्सा भारत में आयकर का भुगतान करता है।

इन रिटर्न दाखिल करने वालों के एक बड़े हिस्से को जांच और यहां तक कि रिटर्न दाखिल करने से छूट देना बेहतर हो सकता है और 1.6 फीसदी में से शीर्ष 10 फीसदी पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, जो वास्तव में आयकर चुकाते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि शून्य कर सीमा बढ़ाकर और इन सीमाओं से कम आय वाले लोगों को रिटर्न दाखिल करने से छूट देकर कर-प्रशासन लागत में कमी लाई जा सकती है। वे संसाधन उन क्षेत्रों पर लगाए जा सकते हैं, जो उपभोग क्षमता होने के बावजूद कर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं।

दुनिया भर में और भारत में भी, हम देखते हैं कि जब कर की दर घटाई जाती है, तो कर संग्रह में वृद्धि होती है। इसे लाफर वक्र कहा जाता है। लाफर वक्र बताता है कि यदि कर-दर को एक निश्चित सीमा से ऊपर बढ़ाया जाता है, तो कर राजस्व में कमी आ सकती है, क्योंकि उच्च कर दर लोगों को काम करने से हतोत्साहित करती है। इसी तरह, करों में कटौती से उच्च कर राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसका एक उदाहरण यह है कि कुछ साल पहले कॉरपोरेट सीमांत कर दरों में कटौती करने के बाद कॉरपोरेट कर संग्रह में वृद्धि हुई। मध्यम वर्ग, विशेष रूप से वेतनभोगी कर दाताओं को ज्यादा राहत देने की जरूरत है, क्योंकि मुद्रास्फीति ने कर-दर के पिछले स्तर को काफी कम कर दिया है। इसी तरह 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को, जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं है, उच्च चिकित्सा बीमा और अन्य लागतों के लिए भत्ते दिए जाने चाहिए, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

आजादी के समय कल्याणकारी उपाय के तहत कृषि आय को आयकर से छूट दी गई थी, जो एक प्रशंसनीय कदम था। यह देखते हुए कि 60 फीसदी आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जीडीपी के 15 फीसदी पर निर्भर है, अधिकांश किसानों को व्यक्तिगत कर से छूट दी जानी चाहिए। हालांकि अमीर भूस्वामियों और कृषि मूल्य शृंखलाओं पर नियंत्रण रखने वाले अभिजात वर्ग की पहचान करने और उन पर कर लगाने की आवश्यकता है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग कृषि आय के तहत कर छूट का दावा करते हैं, जो और कुछ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग आय को कर-मुक्त करने का उपाय है। उन लोगों को भी कर के दायरे में लाने की जरूरत है, जो कराधान से दूर रहने के लिए कानूनी खामियों का लाभ उठाते हैं। अन्यथा यह 1.6 फीसदी करदाताओं के साथ अन्याय होगा।

वेतनभोगी लोग, जो वोटबैंक नहीं है, और इसलिए बहुत कम राहत मिलती है, उन्हें विशेष भत्ता दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि स्रोत के स्तर पर ही उनसे आयकर काटकर नियोक्ता सरकार के खाते में जमा कर देते हैं। एक वेतनभोगी व्यक्ति अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा (48 फीसदी) कर चुकाने में खर्च करता है। वेतनभोगी वर्ग को राहत देने से होने वाले कर-राजस्व के नुकसान की भरपाई अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि से की जा सकती, क्योंकि इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा और औपचारिक क्षेत्र की बचत से आर्थिक गतिविधि बढ़ सकती है। देश में खरीदारी करने वाला हर व्यक्ति उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और जीएसटी का भुगतान करता है।

वैश्विक स्तर पर औसत कर-जीडीपी अनुपात 14.4 है, जबकि ओईसीडी देशों के लिए यह 16.3 है। भारत का कर-जीडीपी अनुपात 12 है। छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र नाउरू में कर-जीडीपी अनुपात सबसे अधिक 48 है, जिसका अर्थ है कि सरकार देश की कुल अर्थव्यवस्था के लगभग आधे के बराबर कर एकत्र करती है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क में यह अनुपात 35 है।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य ने कराधान के संबंध में बहुत अच्छी सलाह दी है-कि इसकी गणना आसान होनी चाहिए, भुगतान सुविधाजनक होना चाहिए, कर-प्रशासन सस्ता होना चाहिए और इसका बोझ न्यायसंगत होना चाहिए। भारतीय कराधान आज 1.6 फीसदी करदाताओं पर भारी बोझ डालता है, जो कुल संग्रह का 27 फीसदी भुगतान करते हैं। जरूरत इस बात की है कि आबादी का बड़ा हिस्सा किफायती तरीके से कर चुकाए।

सरकार ने कर न चुकाने वाले वर्ग को कर दायरे में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। टीडीएस और टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि कई लेनदेन को उनके दायरे में लाया जा सके। कर विभाग अधिक खपत करने वाले, लेकिन कर न चुकाने वालों पर जीएसटी डाटा के माध्यम से अंकुश लगाने और उन्हें कर के दायरे में लाने में सक्षम है। उम्मीद है कि सरकारी तंत्र कर चोरों पर लक्षित कार्रवाई करके कर दायरे को बढ़ाने में सक्षम होगा। इससे अधिक बोझ वाले वर्गों को कर राहत देने के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनेगी। लेकिन ऐसा तभी संभव है, जब ज्यादा लोग करों का भुगतान करें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

श्री श्री रविशंकर

खुशी एक इंसान के लिए सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जब आप भीतर से स्वतंत्र महसूस करते हैं, तभी खुशी प्रकट होती है। जब हम अपने स्व से, अपने स्वभाव से दूर चले जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं।

स्वतंत्र महसूस करने पर ही खुशी प्रकट होती है

जब आप खुशी को नहीं जानते हैं, तो यह महज एक विचार है और जब आप इसे जानते हैं, तो यह आप ही हैं! खुशी एक इंसान की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जब आप भीतर से स्वतंत्र महसूस करते हैं, तभी खुशी प्रकट होती है। जब हम अपने स्व से, अपने स्वभाव से दूर चले जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि, यह विडंबनापूर्ण है कि खुद खुशी का स्रोत होने के बावजूद, हम इसे हर जगह ढूंढते रहते हैं।

हमें उन कारकों पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा पर्यावरण और तीसरा वित्त। चौथी है महत्वाकांक्षा। मान लीजिए कि हमारे पास पहले तीन हैं, लेकिन हम अति महत्वाकांक्षी हैं, तो यह हमारी स्थिति को उत्तेजित कर देगा।

इच्छा का अर्थ है भविष्य में इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से खुशी प्रदर्शित करना। यदि आप कहें कि जब आप सभी इच्छाओं से छुटकारा पा लेंगे, तब खुश होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है!

चुनौती अपनी गतिविधियों को छोड़े बिना खुश रहने की है। यह एक ऐसा कौशल है, जो सीखा जाता है। इसके लिए छोटे बच्चों से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। उनकी आकांक्षाएं होती हैं, फिर भी वे पल में खुश रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वही करते हैं, जो आवश्यक है, लेकिन उन तक ही सीमित नहीं रहते। उनका मन आसानी से एक चीज से दूसरी चीज पर जाता रहता है। हमें मन को इच्छानुसार निर्देशित करना और किसी भी चीज पर अटके न रहने की क्षमता विकसित करनी होगी।

खुशी एक दृष्टिकोण है, जिसे विकसित किया जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने संतोष या खुशी को एक नियम, एक व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में प्रतिपादित किया है। आपको खुद को खुशी के मूड में ढालना होगा। यह सिर्फ एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुशी के स्वभाव में बने रहने का प्रयास करना होगा। दुनिया की किसी भी चीज को अपनी खुशी में खलल न डालने देने का दृढ़ संकल्प विकसित करें। यही ज्ञान का उद्देश्य है।

यही वेदांत का मुख्य विषय है। कई संन्यासियों के नाम 'आनंद' से खत्म होते हैं। उनका नाम ही उन्हें याद दिलाता है कि वे आनंदमय हैं, वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं और अपने चारों ओर खुशियां फैलाने के लिए यहां हैं।

कोई भी मनुष्य अपने घर-परिवार या अड़ोस-पड़ोस से कटा नहीं रहता है। यदि परिवार में एक व्यक्ति दुखी है, तो इसका प्रभाव अन्य सभी सदस्यों पर पड़ता है। हम सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि खुशी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, पर यह हमारे पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है। जब अगली गली में दंगे हों, तो कोई भी खुश होने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना होगा।

खुशहाल समाज का लक्ष्य...

सूत्र

सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक निकायों का मुख्य लक्ष्य एक खुशहाल और स्वस्थ समाज बनाना होना चाहिए। यह केवल रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने से नहीं हो सकता। इसके लिए मानसिकता बदलनी होगी और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा। अपने वास्तविक स्वभाव में बने रहना ही स्थायी खुशी का एकमात्र मार्ग है।

दूसरा पहलू

परिधानों के बहुत ज्यादा उत्पादन और उपभोग को जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

फैशन की दुनिया का एक बदरंग चेहरा भी

पिछली सदी के नौवें दशक में एक नया चलन पैदा हुआ था, वह बेहद तेजी से बदलने वाले फैशन के साथ जीने का था। लोग नए से नए फैशन के साथ चलने लगे। लेकिन हो यह रहा है कि कपड़ों का भंडार बढ़ता जा रहा है, बेचा जा रहा है और जल्दी ही उसे निकाल दिया जा रहा है। यह चक्र वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा संकट बन गया है। हम ऐसे अल्ट्रा फास्ट फैशन की ओर जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की खपत और उनसे निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा बेहद ज्यादा है, जो बढ़ती ही जा रही है।

टेलर ब्राइजेस

वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान दो डिग्री कम करने के लिए कपड़ा उद्योग को कुल कार्बन उत्सर्जन कटौती में 26 फीसदी योगदान करना होगा। जाहिर है, फैशन उद्योग को भी जिम्मेदारी लेनी ही होगी।

परिधानों के बहुत ज्यादा उत्पादन और उपभोग जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान दो डिग्री कम करने के लिए कपड़ा उद्योग को दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन कटौती में 26 फीसदी योगदान करना होगा। जाहिर है, फैशन उद्योग को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तेज से बेहद तेज फैशन की ओर बढ़ने के गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम होते हैं। इसमें श्रमिकों का ज्यादा शोषण होता है, जिसकी अनदेखी करना सामाजिक गलती होगी। इससे अधिक टिकाऊ फैशन उद्योग पर खतरा पैदा होता है।

अपनी फैशन आदतों के नतीजों को समझ कर और उनमें बदलाव करके हम फैशन उद्योग को टिकाऊ और न्यायपूर्ण बना सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई फैशन काउंसिल सीमलैस नाम से राष्ट्रीय उत्पाद प्रबंधन योजना का नेतृत्व कर रही है, जो वर्ष 2030 तक फैशन उद्योग को बदलने का वादा करती है। इसका लक्ष्य फैशन उद्योग को चक्रीय अर्थव्यवस्था में लाना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उत्पादन और उपभोग का ऐसा मॉडल है, जो सतत विकास को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है शून्य अपशिष्ट।

ज्यादा टिकाऊ और जिम्मेदार फैशन उद्योग में बदलाव के लिए अल्ट्रा-फास्ट फैशन की व्यापक समझ, तत्काल व्यवस्थागत बदलाव और सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर्स एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान नेटवर्क का हिस्सा है, जो अल्ट्रा-फास्ट फैशन की जटिलताओं से निपटने के लिए काम करता है। इसमें श्रमिकों को बदतर कार्य स्थिति से बचाने, कचरे के निष्पादन और इस उद्योग को चक्रीय अर्थव्यवस्था में ढालने पर काम हो रहा है। साथ ही यह अध्ययन भी हो रहा है कि युवा पीढ़ी को कैसे टिकाऊ उपभोग की ओर प्रेरित किया जाए।

सामूहिक पसंद में अपार शक्ति होती है। इसलिए अपनी फैशन आदतों के नतीजों को समझ कर और उनमें बदलाव करके हम फैशन उद्योग को टिकाऊ और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। *(द कन्वर्सेशन)*

आंकड़े

प्लास्टिक कचरे की रीसाइक्लिंग

वर्ष 2023 में ओईसीडी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे को भारत में रीसाइकल किया जाता है।

स्रोत : OECD-2023

देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उनकी पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

प्रथम शैलपुत्री

अंतर्यात्रा
संकलित

प्रजापति दक्ष ने एक बार सभी देवी-देवताओं को अपने यहां होने वाले यज्ञ का निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। लेकिन देवी सती उस यज्ञ में जाना चाहती थीं। उन्होंने भगवान शिव से चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है और बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं होगा। पर सती ने जब बार-बार आग्रह किया, तो शिव ने जाने की अनुमति दे दी।

अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर पहुंचकर देवी सती ने देखा कि सिर्फ उनकी माता को छोड़कर कोई भी उनके साथ आदर और सम्मान से बातचीत नहीं कर रहा है। उनकी बहनें भी उनका मजाक उड़ा रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी उन्हें अपमानित किया। देवी सती इस व्यवहार को सह न सकीं और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वह दुख और गुस्से में भर उठे और उस यज्ञ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।

इसी सती ने अगली बार हिमालय के घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ। मान्यता है कि माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 4 जनवरी, 1955

भाखड़ा नांगल बांध निर्माण में धांधली के आरोप में गिरफ्तारी

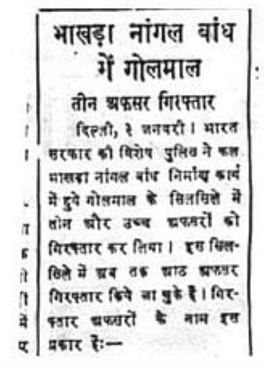

भाखड़ा नांगल बांध में गोलमाल
तीन अफसर गिरफ्तार
दिल्ली, ३ जनवरी। भारत सरकार की विशेष पुलिस ने कल भाखड़ा नांगल बांध निर्माण कार्य में हुये गोलमाल के सिलसिले में तीन और उच्च अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। इस सिल-सिले में अब तक आठ अफसर गिरफ्तार किये जा चुके हैं। गिर-फ्तार अफसरों के नाम इस प्रकार हैः—

केंद्र सरकार की विशेष पुलिस ने भाखड़ा नांगल बांध निर्माण कार्य में हुए गोलमाल के सिलसिले में तीन और उच्च अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में आठ अफसर गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

आग से खेलतीं दीदी

बंगाल में एनआईए टीम पर हमले ने साफ कर दिया है कि ममता सरकार 'लाठी के जोर पर लोकतंत्र' की परिपाटी को हर हालत में कायम रखना चाहती हैं।

बिमल राय | राजनीति

लोकसभा की 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में चुनावी कोलाहल कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ रहा है। छोटा संदेशखाली कहे जा रहे पूर्व मिदनापुर के भूपतिनगर में छह अप्रैल को एनआईए की टीम पर हमले ने साफ कर दिया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की मशीनरी किस तरह ध्वस्त हो गई है।

वर्ष 2022 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर में एक तृणमूल नेता के घर बम विस्फोट हुआ और तीन लोगों के चीथड़े उड़ गए। दो घायल फरार हो गए थे। एनआईए को तभी से उन दोनों की तलाश थी। एनआईए को जांच का जिम्मा कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था। कई बार समन भेजने के बावजूद ये आरोपी हाजिर नहीं हो रहे थे। सफाई देते हुए पांच अप्रैल की सभा में ममता ने उस विस्फोट को पटाखे का विस्फोट बताया। सवाल है कि क्या पटाखा फटने से शरीर के अंग डेढ़ किलोमीटर दूर जा सकते हैं। हद तो तब हो गई, जब मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि लोगों ने वही किया, जो करना चाहिए था। बंगाल

पुलिस ने तो एनआईए की टीम पर ही महिलाओं से छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया। संदेशखाली में ईडी के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगाकर स्थानीय थाने में केस दर्ज किया गया था, पर संभावित कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।

आरोप है कि एक भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने एनआईए के एसपी धनराजराम सिंह से उनके घर पर मुलाकात की। तृणमूल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रही है। वह इस चुनावी मौसम में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं।

अगर न्याय के लिए तृणमूल सरकार अदालतों की शरण में जाए, तो यह बात समझ में आती है, पर कई मामलों में वह डंडे के जोर पर लोकतंत्र चलाती हैं और अदालती आदेशों को भी ठेंगा दिखाती रही हैं। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर हाल ही में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया है। ममता सरकार ने संदेशखाली में कैंप लगाकर जिन लोगों की हड़पी गई जमीनें वापस लौटाईं, उन पर शाहजहां की गिरोह के दूसरे लेयर के उपद्रवी कब्जा नहीं करने दे रहे। आज भी पुलिस के असहयोग का आलम यह है कि बलात्कार पीड़ित महिलाएं घूंघट में आकर कलकत्ता हाईकोर्ट में बयान दर्ज करा रही हैं।

कई कारणों से सिर्फ बशीरहाट सीट का जनादेश पूरे बंगाल का भविष्य इंगित करेगा। इसी निर्वाचन क्षेत्र में संदेशखाली है, जहां की डरावनी कहानियां झकझोर देती हैं। हिंदी में ठीक-ठाक बात करने में सक्षम रेखा पात्रा को तृणमूल ने बाहरी मान लिया है। वैसे, तृणमूल हिंदी बोलने वालों को बाहरी ही कहती रही है। कुछ साल पहले आसनसोल में एक चुनावी सभा में ममता ने हिंदी भाषियों को अतिथि कहा था।

ऐसे माहौल में, भाजपा ने सही दांव चलते हुए संदेशखाली की पीड़िताओं को एकजुट करने वाली रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया, ताकि पूरे चुनाव में महिला सम्मान का विमर्श जिंदा रहे। ममता की बड़ी ताकत राज्य की 49 प्रतिशत महिला वोटर हैं। इस सीट पर तृणमूल ने मुस्लिम आबादी को देखते हुए एक बार सांसद रह चुके हाजी नुरुल इस्लाम को टिकट दिया है, जिन पर वर्ष 2010 में इसी इलाके में दंगे भड़काने का आरोप लगा था। अभी चार अप्रैल को उत्तर बंगाल की चुनावी सभा में ममता ने लोगों से कहा कि वे दंगा न करें, और दंगा न होने दें। रामनवमी से ठीक पहले यह संदेश जारी करने की क्या जरूरत थी?

बशीरहाट का बड़ा हिस्सा सुंदरबन के जंगलों व टापुओं पर बनी बस्तियों से घिरा है। यहां साढ़े 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें करीब 87 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 46.3 फीसदी मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति के करीब 25.4 प्रतिशत लोग हैं और रेखा पात्रा इसी समुदाय से हैं। पिछले दो महीनों से इलाके की महिलाओं के लक्ष्मी भंडार के रुपये खातों में नहीं आ रहे हैं। इन महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए पूछा कि क्या यह राशि तृणमूल दे रही है? इन मेहनतकश महिलाओं के प्रति किसी की ममता अगर नहीं छलकती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?

सात अप्रैल को उत्तरबंगाल के धूपगुड़ी में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अपराधियों को बचाने के लिए तृणमूल सरकार केंद्रीय एजेंसियों पर हमले करवा रही है। मुख्यमंत्री होकर राष्ट्र से लड़ने का दुस्साहस दीदी को भारी पड़ सकता है। कई बार शक होता है कि कहीं ममता खुद ही राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं ले जा रही हैं, ताकि क्षेत्रीयता का बवंडर उठाया जा सके? हालांकि भाजपा ऐसा 'मौका' नहीं देने के पक्ष में है।

edit@amarujala.com

कल्पमेधा

स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के आश्रय पर जीवित नहीं रहते हैं। वे सहारा अवश्य मांगते हैं, पर अपमानित कभी नहीं होना चाहते, यही उनकी विशेषता है।

– टोरी

शक्ति और सम्मान

संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने संबंधी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पिछले मानसून सत्र में पारित हो गया। हालांकि यह कानूनी प्रावधान अगले लोकसभा चुनाव से प्रभावी होगा, पर लंबे समय से रुकी पड़ी इस मांग के पूरा हो जाने से इसलिए महिलाओं में उत्साह है कि राजनीति में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी और वे व्यवस्था संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णयों में सहभागिता कर सकेंगी। मगर महिलाओं को लेकर खुद राजनेताओं में जैसा संकुचित दृष्टिकोण देखा जाता है, उससे संदेह होता है कि उन्हें वास्तव में कितनी शक्ति और कितना सम्मान मिल पाएगा। चुनावी गहमागहमी में राजनेता अक्सर प्रतिद्वंद्वी नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी परहेज नहीं करते। वे भूल जाते हैं कि किसी महिला के बारे में अशोभन टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ममता बनर्जी, हेमा मालिनी और कंगना रनौत पर की गई टिप्पणियां इसका ताजा उदाहरण हैं। इसके पहले भी कई चुनाव अभियानों के दौरान विभिन्न पार्टियों के जिम्मेदार माने जाने वाले नेताओं की तरफ से प्रतिद्वंद्वी पार्टी की महिला उम्मीदवारों और नेताओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों और लहजों को याद किया जा सकता है। चुनाव के अलावा, सामान्य अवसरों पर भी, महिला नेताओं के खिलाफ कई बार अशोभन वक्तव्य सुने गए हैं।

लोकतंत्र में राजनेता अपने प्रतिद्वंद्वी पर तीखी टिप्पणियां कर सकते हैं, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि लोकतंत्र की मर्यादा को ताक पर रख दिया जाए। राजनीति में सार्वजनिक वक्तव्यों का महत्त्व होता है। अगर कोई बड़ा नेता अपने किसी प्रतिद्वंद्वी के बारे में टिप्पणी करता है, तो निचली कतार के नेता उसे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए उनसे न केवल शब्दों के चुनाव, बल्कि लहजे पर लगाम की भी अपेक्षा की जाती है। राजनीति में भाषा एक बड़ा औजार होता है। अगर उसे ठीक से बरतना न आए, तो कई बार खुद को भी जख्मी कर लेने का खतरा रहता है। किसी महिला के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल तो यह भी जाहिर करता है कि टिप्पणी करने वाले का महिला समाज के प्रति दृष्टिकोण क्या है। संसद में महिला आरक्षण को लेकर चली बहसों के समय की कुछ टिप्पणियों की गूंज आज तक इसीलिए बनी हुई है कि उनसे पूरे महिला समाज के सम्मान पर प्रश्नचिह्न लगा था। राजनीतिक दलों की अगली कतार में सामान्य महिलाओं की उपस्थिति वैसे भी न के बराबर है। ऐसे में महिलाओं के प्रति दुराग्रहपूर्ण टिप्पणियां इस विडंबना को और गहरा करती हैं।

यह भी चिंता का विषय है कि आखिर राजनीति में भाषा की मर्यादा इतनी धुंधली क्यों होती जा रही है कि राजनेता संसद और विधानसभाओं से लेकर सार्वजनिक मंचों तक पर बेलगाम कुछ भी बोलने में संकोच नहीं करते। महिलाओं के प्रति हमारे पुरुष प्रधान समाज का नजरिया किसी से छिपा नहीं है। मगर जिन पर समाज और व्यवस्था की विसंगतियां दूर करने की जिम्मेदारी है, अगर वे भी उसी संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त हों, तो महिला शक्ति और उसके सम्मान की आकांक्षा भला कहां तक पूरी हो पाएगी। शीर्ष नेतृत्व की संकीर्णता और दुराग्रह छन कर नीचे तक पहुंचते हैं। हर राजनीतिक दल महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने का दम भरता देखा जाता है, सत्ता में आने पर महिला सुरक्षा के दावे करता भी नहीं थकता, मगर जब तक खुद राजनेताओं के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक उन्हें शक्ति दिला पाना संभव नहीं होगा।

अपराध का मानस

कई बार यह सोच कर भी हैरानी होती है कि महज एक माचिस की तीली न देने पर कोई किसी की हत्या कर सकता है। पिछले कुछ समय से दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों से बहुत मामूली बातों पर आपा खोकर मारपीट करने और जान तक ले लेने की जैसी खबरें आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के तिमारपुर इलाके में दो लड़कों ने एक युवक पर सिर्फ इसलिए चाकू से हमला कर दिया कि उसने मांगने पर माचिस की तीली नहीं दी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से युवक की मौत हो गई। इसके बाद खोजबीन करके जब पुलिस ने दोनों हमलावरों को पकड़ा तो दोनों नाबालिग निकले। जाहिर है, अब हत्या की इस वारदात को आम अपराध मान कर ही कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मगर इस घटना की प्रकृति को देखते हुए ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि बेहद मामूली बातों पर भी इस कदर आपा खोने और हत्या तक कर देने की घटनाओं का दायरा जिस तरह फैल रहा है, आखिर उसके कारण क्या हैं!

दिल्ली में इस प्रकृति की यह कोई अकेली घटना नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आने लगे हैं, जिनमें बहुत मामूली बात पर कहा-सुनी और फिर जानलेवा हमले हो जाते और किसी को पीट-पीट कर या किसी हथियार से मार डाला जाता है। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है! दिल्ली की ताजा घटना में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग हैं, मगर इसी उम्र में चाकू लेकर चलना और बिना खौफ के अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस उनके भीतर कैसे आया? क्या उनके भीतर कानून का कोई खौफ नहीं था या वे अपराध की दुनिया में शामिल हो गए, तो इसके पीछे क्या कारण होंगे? हत्या जैसी वारदात के बाद दोषी साबित होने पर संबंधित कानूनों के तहत उन्हें निर्धारित सजा मिलेगी। मगर इस बात पर अब विचार करने की जरूरत है कि क्या कोई ऐसी समाज-मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां हैं या अन्य कारण हैं, जिनकी वजह से लोग इस कदर मामूली बातों पर भी आपा खोकर मरने-मारने की घटना को अंजाम दे रहे हैं।

तंत्रिका तंत्र की सेहत से जुड़ी चुनौतियां

दुनिया भर में लगभग पांच करोड़ से अधिक लोग मिर्गी से ग्रसित हैं, जो विश्व स्तर पर सबसे आम तंत्रिका तंत्र रोगों में से एक है।

रामानुज पाठक

तंत्रिका तंत्र शरीर का ऐसा नियंत्रक स्थल है, जिसके आदेश के बगैर न आप सोच सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, न याद कर सकते हैं और न ही विभिन्न क्रियाओं, जैसे दिल का धड़कना, फेफड़ों और पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली, शरीर के तापमान पर नियंत्रण आदि का संचालन संभव है। मगर इस तंत्र की जानकारी लोगों में कम देखने को मिलती है, साथ ही इसकी सेहत की अनदेखी भी की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार तंत्रिका तंत्र से जुड़ी छह सौ से अधिक समस्याएं हैं, जिनमें अल्जाइमर्स, पार्किंसन्स और डिमेंशिया, ब्रेन स्ट्रोक, माइग्रेन, मिर्गी आदि प्रमुख हैं। 'दि लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' में हाल में छपा एक अध्ययन देश में तंत्रिका तंत्र (न्यूरोलाजिकल) की समस्याओं के बढ़ते बोझ की तस्वीर सामने रखता है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, इसमें मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं। यह दुनिया की सबसे पुराना पहचाना हुआ रोग है, जिसके लिखित दस्तावेज 4000 ईसा पूर्व के हैं।

दुनिया भर में लगभग पांच करोड़ से अधिक लोग मिर्गी से ग्रसित हैं, जो विश्व स्तर पर सबसे आम तंत्रिका तंत्र रोगों में से एक है। इस विकार को दवाओं और उपचारों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एटीईएसटी के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक करोड़ से अधिक लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, जिसे 'अपस्मार' भी कहा जाता है। हालांकि लगभग 60-70 फीसद मिर्गी को केवल दवाओं से दूर किया जा सकता है। यह तंत्रिका तंत्र की समस्या है, जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। हालांकि जब दौरा पड़ता है तो शरीर भी प्रभावित होता है। मिर्गी को मस्तिष्क में बार-बार पड़ने वाले दौरे की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ लोगों को जागते समय दौरे पड़ते हैं, जिन्हें 'जागृत दौरे' कहा जाता है। कुछ लोगों को सोते समय दौरे पड़ते हैं, जिन्हें 'नींद के दौरे' (या 'रात के दौरे') कहा जाता है।

यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेटस (460-377 ईसा पूर्व) पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सोचा था कि मिर्गी मस्तिष्क में शुरू होती है। अधिकांश लोगों को 'सामान्य परिस्थितियों' में दौरे नहीं पड़ते। दौरे तब पड़ते हैं जब मस्तिष्क के सामान्य रूप से काम करने के तरीके में अचानक रुकावट आ जाती है। दौरे के बीच मस्तिष्क सामान्य रूप से कार्य करता है। मिर्गी एक परिवर्तनशील स्थिति है, जो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करती है। चिकित्सक सलाह देते हैं कि मिर्गी से पीड़ित रोगी उचित चिकित्सा देखभाल लें और समाज इस बीमारी के बारे में अपने पुराने और अपमानजनक विचारों को बदले। मिर्गी असाध्य रोग नहीं है, इसका उपचार संभव है।

मिर्गी को लेकर प्राचीन भ्रांतियां आज भी मौजूद हैं। इससे बहुत सारे कलंक जुड़े हुए हैं। 'एपिलेप्सी सोसाइटी' के एक अध्ययन से पता चला है कि ब्रिटेन में लगभग दो फीसद लोग अब भी मानते हैं कि मिर्गी बुरी आत्माओं के कारण होती है। पचहत्तर फीसद से अधिक लोग दौरा पड़ने पर कुछ सामान्य प्राथमिक उपचार करने के बजाय एंबुलेंस बुलाते हैं। मिर्गी किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है। कुछ लोगों की मिर्गी दूर हो सकती है

और उन्हें दौरे आना बंद हो जाते हैं। यह अलग-अलग कारणों से होती है। कुछ कारण जटिल हो सकते हैं, और उन्हें पहचानना कठिन हो सकता है। शोधकर्ता मानते हैं कि मिर्गी विकसित होने की संभावना हमेशा कुछ हद तक आनुवंशिक होती है। हालांकि, किसी व्यक्ति को मस्तिष्क की चोट या

> **मिर्गीग्रस्त रोगियों में असमय मृत्यु की दर तीन गुना अधिक होती है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, मिर्गी रोगियों की मृत्यु दर, उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफी अधिक है। मिर्गी से पीड़ित लगभग आधे वयस्कों में कम से कम एक अन्य स्वास्थ्य समस्या होती है। इसमें अवसाद और चिंता शामिल हैं। मिर्गी से पीड़ित तेईस फीसद वयस्क अवसाद और बीस फीसद व्यग्रता का अनुभव करते हैं। इसके दौरे से मानसिक स्वास्थ्य खराब और जीवन की गुणवत्ता कम हो सकती है। मिर्गीग्रस्त तीस से चालीस फीसद बच्चों को विकास और सीखने जैसे कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।**

आघात के कारण दौरे पड़ने शुरू हो सकते हैं।

मिर्गी के निदान के लिए कई अलग-अलग परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे 'इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम' (ईईजी) या 'मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग' (एमआरआइ) स्कैन। मिर्गी का इलाज आमतौर पर जब्ती-रोधी दवा (एएसएम) से किया जाता है। एएसएम का उद्देश्य दौरे पड़ने से रोकना है। सही एएसएम के साथ, मिर्गी से पीड़ित सत्तर फीसद लोगों के दौरे को नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला एएसएम 1912 में फेनोबार्बिटोन था। अब यूके (यूनाइटेड किंगडम) में तीस से अधिक एएसएम उपलब्ध हैं। जिन लोगों के दौरे एएसएम से नियंत्रित नहीं होते, उनके लिए सर्जरी एक विकल्प हो सकता है। इसमें उनके मस्तिष्क के उस हिस्से को हटाया जा सकता है, जो दौरे का कारण बनता है।

'इंटरनेशनल ब्यूरो फार एपिलेप्सी' (आइबीई) मिर्गी से पीड़ित लोगों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों के जीवन की सामाजिक स्थिति और गुणवत्ता में सुधार करता है। आइबीई एक गैर-लाभकारी, कानूनी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया राज्य में पंजीकृत है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं गैर-सरकारी संगठनों, 'इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी' और 'इंटरनेशनल ब्यूरो फार एपिलेप्सी' ने संयुक्त रूप से शोध करके एक निष्कर्ष निकाला, जिसे 'एपिलेप्सी, ए पब्लिक हेल्थ इंप्रेटिव' में प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि कम आय वाले देशों में रहने वाले मिर्गी से ग्रस्त रोगियों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाता। जिस कारण लोगों में समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। लोग इसे जीवन पर एक धब्बा भी मानते हैं। 'इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी' (आइएलएई) की स्थापना 1909 में हुई थी और यह सौ से अधिक राष्ट्रीय संस्थाओं का संगठन है। इसका उद्देश्य मिर्गी के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसके इलाज के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने 2019 में मिर्गी को लेकर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता रपट जारी की थी। यह मिर्गी पर पहली वैश्विक रपट थी, जिसमें मिर्गी के बोझ तथा वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर उपलब्ध साक्ष्य का सारांश प्रस्तुत किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन 'मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम' (एमएचजीएपी) का उद्देश्य विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए मानसिक, स्नायविक और मादक द्रव्यों के सेवन से पैदा होने वाले विकारों के लिए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ाना है।

मिर्गीग्रस्त रोगियों में असमय मृत्यु की दर तीन गुना अधिक होती है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, मिर्गी रोगियों की मृत्यु दर, उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफी अधिक है। मिर्गी से पीड़ित लगभग आधे वयस्कों में कम से कम एक अन्य स्वास्थ्य समस्या होती है। इसमें अवसाद और चिंता शामिल हैं। मिर्गी से पीड़ित तेईस फीसद वयस्क अवसाद और बीस फीसद व्यग्रता का अनुभव करते हैं। इसके दौरे से मानसिक स्वास्थ्य खराब और जीवन की गुणवत्ता कम हो सकती है। मिर्गीग्रस्त तीस से चालीस फीसद बच्चों को विकास और सीखने जैसे कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मिर्गी से पीड़ित व्यक्तियों को दौरे की आवृत्ति कम करने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए तनाव पर काबू पाना जरूरी है।

संदेशों का संसार

दुनिया मेरे आगे

अशोक कुमार

परिवर्तन को प्रकृति के शाश्वत नियम के रूप में स्वीकार किया गया है। जो बीते हुए कल में था, वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा, क्योंकि मानव मन नित नए प्रयोग में रत है। सृजन की शृंखला में मानव विकास के नूतन आयाम जुड़ते जा रहे हैं, जबकि नकारात्मक नभ के बादल भी काल के कपाल पर यदा-कदा घनीभूत होते रहते हैं। हस्तलिपि विधा का प्रचलन हजारों साल से हमारे सामाजिक परिवेश में संचालित है। कभी पेड़ के पत्तों, कपड़ों और विभिन्न धातु यथा स्वर्ण, चांदी, पीतल, ताम्रपत्र पर भी संवाद-उक्ति अंकन किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसी कड़ी में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास ने संदेश प्रेषण के रूप में पत्र लेखन की परंपरा की खोज की थी। कभी राजतंत्रीय व्यवस्था में एक राजा दूसरे राजा को अपना संदेश पीले कपड़ों पर लिखवाकर घुड़सवार दूत के माध्यम से भेजा करते थे। ब्रिटिश शासकों ने अपने प्रारंभिक काल में इस जटिल प्रक्रिया में आधुनिक ज्ञान-कौशल का रूपातंरण करते हुए डाकघर की स्थापना की और इसके आधारभूत ढांचे को विकसित किया। संदेश प्रेषण में पीले रंग का चयन शायद इसलिए किया गया होगा कि यह शुभ का प्रतीक माना गया है। शादी के मौके पर पहले ग्रामीण इलाकों में निमंत्रण सूचना सफेद कागज पर लाल स्याही से कार्यक्रमों का विवरण लिखे जाने की परंपरा छिटपुट रूप में आज भी जीवित है। उक्त पत्र को हल्दी के रंग से चिह्नित भी कर दिया जाता था। डाकघर से जारी पोस्टकार्ड का रंग भी हल्का पीलापन लिए हुए है।

> **पहले पत्र पढ़कर प्रतीत होता था कि यह किसी के हृदय से प्रस्फुटित स्वर है। मान्यता है कि पत्र हाथ से लिखते समय हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है और जिसे हम पत्र लिख रहे होते हैं, उसकी पूरी छवि और व्यक्तित्व आंखों के सामने तैरने लगता है।**

समय के प्रवाह ने इस प्रक्रिया से आमजन को धीरे-धीरे युक्त किया और अभिरुचि के आंगन में संदेश भेजने की कला ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू किया। चूंकि भारत गांवों का देश माना गया है, इसलिए पत्र लिखने-लिखाने का क्रम गांव-देहात में अधिक लोकप्रिय हुआ। परदेस में रोजी-रोटी कमाने वाले अपने घर साल में एक या दो बार आते थे। परदेसी के गांव से शहर वापस होते समय उन्हें टोले-मुहल्ले के लोग घर के बने कुछ व्यंजन सहित पत्र भी जरूर सौंपते थे, ताकि उनके साथ या समीप नौकरी कर रहे लोगों के पास यह पहुंच जाए। डिजिटल प्रगति के दौर में जब इंटरनेट की तरंग से मोबाइल जुड़ा, लोगों का बोलने-बतियाने का यह तुरंता माध्यम बन गया। चंद पलों में हाथ की अंगुलियों के करामात ने संवाद का आगमन और प्रेषण अत्यंत सुलभ कर दिया है। पत्रों का पर्याय अब मोबाइल फोन, ई-मेल, एसएमएस आदि सशक्त स्रोत सिद्ध हो गया है।

पहले पत्र पढ़कर प्रतीत होता था कि यह किसी के हृदय से प्रस्फुटित स्वर है, लेकिन वर्तमान में हाथ से लिखे पत्रों का युग अवसान के दौर में जाता दिख रहा है। मान्यता है कि पत्र हाथ से लिखते समय हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है और जिसे हम पत्र लिख रहे होते हैं, उसकी पूरी छवि और व्यक्तित्व आंखों के सामने तैरने लगता है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि चिट्ठी लिखते समय मस्तिष्क का 'रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर' अधिक संवेदनशील हो सक्रियता के दौर में आ जाता है। पत्र लेखन के विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि इस प्रक्रिया से पत्र लिखने वाले के मन में अच्छे विचारों का समूह उन्हें पोषित करता है और सही शब्दों के चयन में सहायता मिलती है। खुद का लेखन अनुभव सारांश है कि हाथ से पत्र लिखने से हमारी एकाग्रता, धैर्य, आत्मीयता एवं सहिष्णुता के क्रम में वृद्धि होती है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा व्यावहारिक नहीं रह गया है, क्योंकि दैनिक जीवन की जटिलताओं को हमारा कम्प्यूटर बहुत हद तक दूर कर रहा है। पत्र लिखना जितना सुखद है, उनता ही मनोरम भी है उसे पढ़ना। संसार के किसी क्षेत्र में बैठकर दूर से आए पत्र को पढ़कर व्यक्ति संवाद के जोश से कभी लैस हो जाया करता था। यह प्रकल्प अकेलेपन से मुक्त होने का सबल साधन भी था। सूचना क्रांति के इस दौर ने डाक-व्यवस्था को शिथिल कर दिया है तो अचरज नहीं होना चाहिए कि पत्र-लेखन और पत्र प्रेषण का दौर भी शीत-निष्क्रियता का शिकार है।

कभी बापू के पास देश के हर कोने से पत्र आते थे और वे बड़े चाव से उसका जवाब खुद ससमय दिया करते थे। जेल से नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा था, उसकी अहमियत आज भी स्वीकार की जाती है। उस काल के प्रसिद्ध राजनेता कहा करते थे कि पुत्री के नाम पिता के इन पत्रों ने इंदिरा के व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका अदा की थी।

विश्व का सबसे प्राचीन पत्र 2009 ईसा पूर्व बेबीलोन के खंडहरों से प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं, जो एक प्रेम पत्र के रूप में मिट्टी की पटरी पर लिखा गया था। पहले के पत्रों में 'पूज्य पिताजी, आदरणीय मौसी जी, चरण-स्पर्श' जैसे आदर के संबोधन बेहद आत्मीयता से भरपूर हुआ करते थे। 'खत को तार समझना' जैसे पत्र के अंत के अंश संबंधों के शिलालेख पर मजबूती बनाए रखते थे। पत्र पढ़ने समय प्रतीत होता था कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति बिल्कुल सामने बैठकर कथा की व्यथा व्यक्त कर रहा है।

अब बिसरी हुई विरासत लौट नहीं सकती, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ ने हमें विज्ञान के चकाचौंध के बीच ला खड़ा किया है, इसलिए सुझाव यही है कि मोबाइल फोन के विविध विधान से अपनों से बोलने-बतियाने का क्रम हम निश्चित रूप से जारी रखें, लेकिन मन जब किसी दूर बैठे मित्र या सगे-संबंधियों को हृदय तल से याद करे तो झटपट एक खत उन्हें लिखकर रवाना कर देना चाहिए। मन सुकून की वाटिका में खिल उठेगा।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

विचार की शक्ति

इंसान की तकदीर बनाने वाला मुख्य रत्न हमारा खुद का विचार होता है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि हम जिन विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं, वही बाद में वास्तविक प्रतीत होने और धीरे-धीरे करके साकार होने लगते है। उन्हीं से हमारे कल की नींव भी धीरे-धीरे तैयार होने लगती है। किसी को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना पड़ता है। जैसे एक पौधे को उगाने के लिए सबसे जरूरी चीज बीज होता है, क्योंकि बीज से ही पौधा उगता है और बिना बीज के कोई भी पौधा नहीं होता। इंसान का दिमाग भी किसी बगीचे की तरह होता है। वह बगीचा किस तरह से वृद्धि करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं। इस दुनिया में जो भी सफल इंसान हुए हैं, वे अपने विचारों की बदौलत ही हुए हैं। जब तक नए मार्ग नहीं खुलेंगे तब तक कोई सही कार्य नहीं हो पाएगा। जब नए मार्ग इंसान को मिल जाते हैं, तभी से इंसान अपने विचारों के अनुरूप कार्य करने लगता है। इंसान को अपने दिमाग में सही उद्देश्य या लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए शिद्दत से लग जाना चाहिए।

– समराज चौहान, कार्बी आंग्लांग, असम

सामूहिकता की शक्ति

बढ़ती गर्मी और मौसम के रूखेपन के कारण कई आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। अभी रबी फसल तैयार अवस्था में है। अब उसकी कटाई होने वाली है। गांव देहात में अभी भी बहुत सारे लोगों के घर फूस के होते हैं। अगर उनमें आग लग जाए तो परिवार बिखर जाता है, घर-द्वार नष्ट हो जाते हैं। पूंजी और फसल राख हो जाते हैं। ऐसे मौसम में हम सभी को सूझबूझ और सतर्कता से रहना चाहिए। खाना बनाते वक्त अपने साथ पानी लेकर बैठना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कोई चिंगारी इधर-उधर न उड़े। बाकी लोगों को भी फसल वाले क्षेत्र या उन सक्रिय जगहों पर बीड़ी-सिगरेट नहीं पीना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आग लगने की घटना पर काबू पाने के लिए लोगों को सिखाया/ दिखाया जाना चाहिए। कोई आपदा घटित हो तो सभी को जन सहयोग की भावना के साथ राहत और बचाव कार्य करना चाहिए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। सभी की एकजुटता से विपदा पर काबू पाने या राहत कार्य को कुछ आसान बनाया जा सकता है।

– तारामुनी देवी, लालगंज, वैशाली

सिकुड़ते पर्यावास

'मनुष्य से संघर्ष करते वन्यजीव' (लेख, 5 मार्च) सराहनीय है। सियार पहले जंगल में ही रहते थे। गांव की तरफ बिल्कुल भी नहीं आते थे। आजकल भूख की मार के चलते सियार गांव के आसपास देखे जा सकते हैं। हिरण, नीलगाय आजकल गांवों के आसपास कम नजर आते हैं। वन्यजीवों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। धीरे-धीरे वन कम होते जा रहे हैं और वन्यजीवों की सुरक्षा घटती जा रही है। वन विभाग को चाहिए कि वन्यजीवों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे। अन्यथा होगा यही कि अगर बाघ, तेंदुआ या हाथी जैसे जीव अगर अपने पर्यावास सिकुड़ने की वजह से मानव बस्तियों में प्रवेश करेंगे तो उसका खमियाजा मनुष्यों को उठाना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र और उसके संतुलन को बनाए रखना धरती के जीवन के लिए जरूरी है।

– कुमेर सिंह गुर्जर, राजस्थान

साइकिल की सवारी

साइकिल रिक्शे पर यात्रा का आनंद उस पर बैठकर ही महसूस किया जा सकता है। शब्दों से उसके वर्णन में उस आनंद का दसवां भाग भी नहीं मिलेगा। धीमी गति से चलने वाला यह वाहन बाजार की पूरी हलचल बहुत सुंदरता से देखने और महसूस करने का अवसर देता है। यह अवसर तेज गति से चलने वाले परिवहन साधनों में नहीं मिल सकता! अब तेज गति का जमाना है और सड़कों पर वाहनों का इतना जमावड़ा हो गया है कि दम घुटने लगता है। साइकिल रिक्शा कभी हमारी जरूरत था, मगर अब धीरे-धीरे संकरे बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ है। लोग फिर साइकिल रिक्शा की ओर ही रुख करेंगे, क्योंकि भीड़ भरे संकरे मार्गों पर ईंधन वाले या बैटरी वाले वाहनों को चलाना संभव नहीं होगा। साइकिल रिक्शा से न तो कोई प्रदूषण फैलता है और न ही किसी प्रकार का फालतू शोरगुल होता है।

– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.readwhere.com

चिंतन

मानवता के लिए युद्धविराम

विराम पर विचार करना होगा

रह रहकर ऐसी खबरें आ रही है कि इजराइल-हमास में युद्धविराम हो सकता है। ब्रिटेन समेत विश्व बिरादरी के अनेक देश इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मासूम बच्चों की खातिर मानवीय आधार पर युद्ध रोके जाने का आह्वान किया। ऐसा करना जरूरी भी हो गया है। इजराइल और हमास की जंग में पिस रहे गाजा के 22 लाख लोग देखते-देखते मानव निर्मित अकाल और भुखमरी का शिकार होने के कगार पर हैं। इंसानी समाज के सामूहिक विवेक पर भारी पड़ता यह सवाल हर पल वास्तविकता में तब्दील होने की ओर बढ़ रहा है। युद्ध शुरू होने के साथ ही गाजा के हालात की भयावहता को लेकर ऐसी आशंकाएं थीं, मगर दावों और प्रतिदावों के बीच वास्तविक स्थिति का पता करना मुश्किल हो रहा था। पिछले महीने इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन सिस्टम की रिपोर्ट ने इस भयावहता की तस्वीर को साफ कर दिया है। इजराइल ने भी इस रिपोर्ट का खंडन नहीं किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि गाजा की कुल आबादी का आधा हिस्सा और गाजा शहर में अब भी रह रहे करीब 3 लाख लोगों का पचास फीसदी हिस्सा अकाल के कगार तक पहुंच चुका है। अब तक भूख से हुई मौतों का कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक साल पहले तक गाजा में दो साल से कम उम्र के 29 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रस्त थे अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। हालात ये हैं कि 66 फीसदी परिवार महीने में कम से कम 10 बार चौबीसों घंटे भूखे रहने को मजबूर हैं। युद्ध के चलते न केवल गाजा में राहत सामग्री का पहुंचना मुश्किल हुआ है, बल्कि धमाकों के बीच इनके वितरण में भी परेशानी आ रही है। पिछले महीने ही एक खाद्य वितरण केंद्र पर बम गिरने की खबरें भी आई थी। यही नहीं, आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि इजराइली सेना ने खेती की ज्यादातर जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते यहां पैदा होने वाले खाद्यान्न पर भी उसका कब्जा हो गया है। युद्ध के पीछे इजराइल के अपने तर्क हैं। उसका कहना है कि जब तक उसके नागरिकों को रिहा नहीं किया जाता युद्ध खत्म नहीं होगा। इजराइली अधिकारियों का कहना है कि हमास द्वारा बंदी बनाए गए उसके नागरिकों के शव बरामद हो रहे हैं, इसलिए युद्ध को बीच में नहीं रोक सकते। अगर हमास सभी बंदियों को छोड़ देगा तो युद्ध खुद खत्म हो जाएगा। अगर इजराइल सरकार की यह बात मान भी ली जाए कि लड़ाई हमास के खिलाफ है और आम लोगों को नुकसान पहंचाने का उसका कोई इरादा नहीं है तो भी व्यवहार में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। गाजा की आबादी को भुखमरी जैसे हालात से बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि तत्काल युद्धविराम लागू कर बड़े पैमाने पर राहत और खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए। सुरक्षा परिषद भी इस आशय का प्रस्ताव पारित कर चुकी है, लेकिन इस पर अमल के कोई आसार नहीं दिख रहे। सोमवार को यह खबरें आई कि युद्ध विराम हो सकता है। इजराइली सेना साउथ गाजा के खान यूनिस शहर से पीछे हट गई है, लेकिन कुछ ही देर बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान सामने आ गया कि इजराइली सेना खान यूनिस से हटने के बाद, राफा शहर में जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। यहां जंग शुरू होने के बाद से हवाई हमले हो रहे थे। अब सैनिक शहर में घुसकर आतंकियों को मारेंगे। तय है कि इससे हालात और विकट होंगे। पहले ही भूखमरी के शिकार हो रहे बच्चों का जीवन खतरे में चला जाएगा। इजराइल के अपने तर्क सही हैं, लेकिन मानवता के आधार पर उन लोगों के बारे में भी विचार करना जरूरी है, जो बेवजह युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं।

चुनावी बॉन्ड

आलोक शुक्ला

राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता जरूरी

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में चुनावी बॉन्डों को असंवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद से सोशल मीडिया ओर टीवी चैनलों पर राजनीतिक फंडिंग में शुचिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सारे विपक्षी दल इसे सदी का सबसे बड़ा घोटाला कह रहे हैं,परन्तु राजनीतिक फंडिंग में भ्रष्टाचार केवल चुनावी बॉन्डों तक ही सीमित नहीं है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी वित्तीय तंत्र यदि अपारदर्शी हो तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में चुनावी बॉन्डों की योजना आने के पहले भी राजनीतिक फंडिंग पूरी तरह से अपारदर्शी रही है और बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार का स्रोत भी रही है। चुनावी बॉन्डों ने इस भ्रष्टाचार को परवान चढ़ाया है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में सभी राजनीतिक दलों की आय के लगभग 71 प्रतिशत के स्रोत की जानकारी नहीं है। इसमें चुनावी बॉन्डों से प्राप्त आय, कूपन विक्रय से आय, अन्य स्रोतों से आय, स्वैच्छिक चंदा, मीटिंग एवं मोर्चा आदि के लिए चंदा, आदि मद शामिल हैं। मुख्य बात यह है कि राजनीतिक दलों को यह धन किसने दिया इस बात की कोई जानकारी नहीं है। विकीपीडिया के एक आलेख में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में भाजपा की 61 प्रतिशत आय, टीएमसी की 97 फीसदी आय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 72 फीसदी आय एवं सीपीएम की 48 प्रतिशत आय के स्रोत की जानकारी नही है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता के संबंध में भारत में वैधानिक प्रावधान बहुत लचीले हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी के अंतर्गत राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति अथवा कंपनी से चंदा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वह शासकीय कंपनी न हो। धारा 29सी के अंतर्गत इस प्रकार प्राप्त चंदे की घोषणा करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार बीस हजार रुपये से अधिक का चंदा देने वाले व्यक्तियों का विवरण देना अनिवार्य किया गया है और यह प्रावधान भी है कि यदि कोई राजनीतिक दल यह विवरण चुनाव आयोग को नहीं देता है तो उसे आयकर की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकांश राजनीतिक दल यही कहते रहे हैं कि उन्हें लगभग सभी व्यक्ति बीस हजार रुपये से कम चंदा देते हैं, इसलिए न तो उन्हें चंदा देने वालों का विवरण आयोग को देने की आवश्यकता है और न ही वे उनका विवरण अपने पास रखते हैं। वर्ष 2009 से 2014 के मध्य में स्वयं चुनाव आयोग में था। आयोग ने उस समय राजनीतिक दलों से इस बात का प्रमाण मांगना प्रारंभ किया था, कि उन्हें वास्तव में प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये से कम राशि मिली है। इसके लिए आयोग ने राजनीतिक दलों से चंदे की रसीदों के काउंटर फॉयल मांगने प्रारंभ किए। नतीजा यह हुआ कि राजनीतिक दलों ने फर्जी काउंटर फॉयल बनाना प्रारंभ कर दिया। अनेक चुनावों में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा डाले गए छापों में राजनीतिक दलों के कार्यालयों से ऐसे फर्जी काउंटर फॉयलों के बंडल तक

मिले,क्योंकि इस संबंध में कोई आपराधिक धाराएं कानून में नहीं हैं इसलिए किसी राजनीतिक दल पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। राजनीतिक दल इस प्रकार बीस-बीस हज़ार रुपये का हिसाब रखते हुए काफी परेशान थे, इसलिए वर्ष 2013 में एक इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत इलेक्टोरल ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में पंजीकृत किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अथवा कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को धन दे सकते हैं। इसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट अपनी मर्जी से इस धन से राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है। इस योजना के द्वारा चंदा देने वाले व्यक्ति और चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के बीच सीधा संबंध समाप्त कर दिया गया। इससे कुछ हद तक राजनीतिक चंदा देने वालों की गोपनीयता रखने की गुंजाइश हो गई। कानूनी रूप से ट्रस्ट के लिए दानदाता की इच्छा के अनुसार राजनीतिक दलों को चंदा देने का कोई बंधन नहीं है। यदि कोई कंपनी बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा दे रही है, और उस ट्रस्ट का अधिकांश पैसा किसी विशेष राजनीतिक दल को ही जा रहा है जो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी किस राजनीतिक दल की फंडिंग कर रही है। इससे निपटने के लिए वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में चुनावी बॉन्ड दानदाता की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय कर दी गई, इसीलिए चुनावी बॉन्ड योजना ने राजनीतिक चंदे को पूरी तरह अपारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार का रास्ता खोल दिया। पूर्व में केवल वही कंपनी चुनावी चंदा दे सकती थी जो कम से कम 3 साल से अस्तित्व में हो। कंपनी द्वारा दिया गया चंदा पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता था और इस चंदे का खुलासा कंपनी को प्रत्येक वित्त वर्ष में अपने शेयरहोल्डरों को दी जाने वाली रिपोर्ट में करना अनिवार्य था। वर्ष 2018 के संशोधन व्दारा इन तीनों ही शर्तों को हटा दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि यदि कोई कंपनी आज ही बनी हो तो भी वह राजनीतिक चंदा दे सकती है, कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है, और कंपनी को अपने शेयरधारकों को इसकी जानकारी देना भी आवश्यक नहीं है। हाल ही में चुनावी बॉन्डों का डेटा सार्वजनिक होने के बाद यह पता लगा है कि कई कंपनियों ने कुल राजस्व से भी अधिक राशि चंदे में दी है।

भारत में राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता न होने के प्रमुख कारण हैं निर्वाचन आयोग की एक्सपेंडीचर गाइडलाइन किसी कानून के अंतर्गत नहीं है और इसलिए उसका पालन नहीं करने वालों पर कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो पाती, निर्वाचन आयोग को दी जाने वाली जानकारी की आयकर विभाग, न तो ठीक प्रकार से स्क्रूटिनी करता है और न ही उसे बाध्य करने का कोई कानून है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 केवल अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय को विनियमित करती है। राजनीतिक दलों के व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं है, चुनावी चंदे में कोई पारदर्शिता नहीं है। यहां तक कि उन्हें अपने शेयरधारकों तक को बताने की आवश्यकता नहीं है, चुनावी बॉन्ड पूरी तरह अपारदर्शी है। चुनाव आयोग की तथाकथित सख्ती और जब्ती का कोई लाभ तब तक नहीं होगा जब तक चंदे और दान में पारदर्शिता न रखी जाए। दुःख इस बात का है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाने वाला चुनाव आयोग भी पारदर्शिता की नहीं, बल्कि गोपनीयता की वकालत करता दिख रहा है। दिनांक 16 मार्च 2024 को लोक सभा चुनावों की घोषणा करते समय अपनी प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 2 बार कहा कि इलेक्टोरल बॉन्डों के दानदाताओं की गोपनीयता रखना आवश्यक है। इलेक्टोरल बॉन्डों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को आसरा दिया है। उम्मीद करनी चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का इंतज़ार किए बिना सर्वोच्च न्यायालय से ही हमें राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शी व्यवस्था मिल सकेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

> सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में चुनावी बॉन्डों को असंवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद से सोशल मीडिया ओर टीवी चैनलों पर राजनीतिक फंडिंग में शुचिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कोई भी वित्तीय तंत्र यदि अपारदर्शी हो तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में चुनावी बॉन्डों की योजना आने के पहले भी राजनीतिक फंडिंग पूरी तरह से अपारदर्शी रही है और बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार का स्रोत भी रही है। चुनावी बॉन्डों ने इस भ्रष्टाचार को परवान चढ़ाया है। राजनीतिक दलों के व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं है, चुनावी चंदे में कोई पारदर्शिता नहीं है। चुनावी बॉन्ड पूरी तरह अपारदर्शी हैं।

सारा संसार

कोयम्बटूर का भगवान गणेश को समर्पित ईचनारी विनयगर, 1500 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। इस जगह से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विनायक की मूर्ति को पट्टीश्वर मंदिर ले जाया जा रहा था, तो गाड़ी की एक धुरी टूट गई। उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया।

नव संवत्सर

डॉ सूर्यकांत मिश्रा

हिंदू नव वर्ष की सार्थकता

वैज्ञानिकों ने भी मानी

भारतीय पंचांग के अनुसार हमारा नया साल प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। इस वर्ष यह शुभ तिथि 9 अप्रैल को हमें विक्रम संवत 2081 में प्रवेश दिलाने जा रही है। हिंदू धर्मावलंबी एवं सनातन धर्म को अंगीकार करने वाला हर व्यक्ति यह जानता है कि हम अपने नए वर्ष के उत्साह में फूहड़ता समझे जाने वाले किसी भी आयोजन से दूर रहते हैं। कितने गौरव की बात है कि हमारा नया वर्ष हमें 'मां भगवती' की नौ दिनों की आराधना से जोड़ते हुए भक्ति और श्रद्धा का अनुपम आनंद प्रदान करता है। हिंदू धर्म को मानने वाले यह जानते हैं कि भारतीय काल गणना के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों के पीछे कोई न कोई प्रेरणा विद्यमान है। हम यह भी जानते हैं कि हिंदी पंचांग के अंतिम माह फाल्गुन का वातावरण हमें वर्ष समाप्ति का संकेत देता है। हमें गर्व है अपने ऋषि-मुनि और संतों पर जिन्होंने ऐसी काल गणना विकसित की, जिसमें कब क्या होना है? इन तथ्यों की संपूर्ण जानकारी समाहित है। हमारा इतिहास बताता है कि बीते हजारों वर्षों में अनेक देशी और विदेशी शासकों ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की तुष्टि करने तथा राजनीतिक दृष्टि से देश को पराधीन बनाने की मंशा के साथ अनेक संवतों को चलाया। इतना कुछ होने के बाद भी भारतवर्ष की सांस्कृतिक पहचान केवल विक्रम संवत के साथ ही जुड़ी रही। नव-वर्ष के संदर्भ में महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही दिन, मास, वर्ष और युगादि का प्रारंभ माना है। इतिहास उठाकर देखा जाए तो युगों मे प्रथम सतयुग का शुभारंभ भी इसी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हुआ था। कल्पयादि-सृष्टियादि-युगादि आरंभ को लेकर इस दिवस के साथ प्राचीनता का इतिहास मिलता है। सृष्टि की रचना को लेकर भी ऋषि-मुनियों तथा वैदिक गणित के विद्वानों ने इसी दिवस की गणना की है। गणितज्ञ भास्कराचार्य ने भी इसी दिन को आधार मानते हुए गणना कर पंचांग की रचना की। यही विभिन्न ग्रहों, चंद्रमा एवं सूर्य की गति एवं दिशाओं का उतनी प्रामाणिकता के साथ निर्धारण करता है, जितना कि आधुनिक सैटेलाइट। हिंदू नव-वर्ष में रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। ठंड की समाप्ति और ग्रीष्म का प्रारंभ अत्यंत ही मधुर व आनंददायक आगमन का अनुभव देता है। पतझड़ समाप्त होता है और बसंत ऋतु के आगमन का आगाज होने लगता है। प्रकृति में हर जगह हरियाली छा जाती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे प्रकृति ने नव-श्रृंगार किया हो। यह बिना किसी संशय के कहा जा सकता है कि बिना पंचांग और कैलेंडर के प्रकृति और आकाश को पढ़कर हिंदू धर्मावलंबी अपने नए-वर्ष को पा लेते हैं। ऐसा दिव्य नव-वर्ष अन्य किसी धर्म में दुर्लभ है। सनातनी नव-वर्ष को लेकर विवेकानंद ने कहा है 'यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है, अपने अंतर्मन में राष्ट्र भक्ति के बीज को पल्लवित करना है, तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना होगा। गुलाम बनाए रखने वाले लोगों की दिनांकों पर आश्रित रहने वाला आत्म गौरव खो बैठता है। हिंदू नव-वर्ष का दिन हमारे मन में यह उद्घोष जगाता है कि हम पृथ्वी माता के पुत्र हैं। सूर्य, चंद्र तथा नवग्रह हमारे आधार हैं। प्राणी मात्र हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। यही कारण है कि हमारी संस्कृति का बोध वाक्य 'वसुधैव कुटुंबकम' को सार्थकता प्रदान करता है। विक्रमी संवत के स्मरण मात्र से ही सम्राट विक्रमादित्य और उनके विजय अभियान की याद ताजा हो जाती है। क्या हम इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं कि हम नव-वर्ष की शुरुआत गो-माता की पूजा से करते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मानव के लिए नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है?

संकलित

दर्शन

नैतिक मूल्य मानव को परिपूर्णता प्रदान कर उसे ईश्वरीय रचनाओं में श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु आधुनिकता के नाम पर इन मूल्यों का निरंतर अवमूल्यन होता जा रहा है। बढ़ता भौतिकतावाद उन्हें लील रहा है। परिणामस्वरूप नैतिकता घुट-घुटकर ही सांस ले पा रही है। यह स्थिति तब है जब नैतिकता को मानव समाज के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता मिली है। नैतिकता के अभाव में मनुष्यता का आकलन संभव ही नहीं। नैतिकता व्यक्ति के विकास में एक सीढ़ी के समान है, जिसके सहारे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों के अभाव में मनुष्य मानव जीवन को निर्थक बना देता है। प्रख्यात विचारक अल्बेयर कामू ने भी कहा है कि नैतिकता के बिना एक व्यक्ति इस दुनिया में किसी पशु के समान है। हम जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय नैतिक कसौटी पर कसने के बाद ही करते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कई बार मनुष्य उसे अनदेखा कर फैसला करता है, जो नैतिक पतन का कारण बनता है। स्मरण रहे कि ईश्वर ने हमें सिर्फ सुख भोगने के लिए ही इस संसार में नहीं भेजा है। इसीलिए केवल भौतिक सुखों के लिए नैतिकता का परित्याग करना उचित नहीं। इसका एक कारण यही है कि अब हमने अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना करना आरंभ कर दिया है। हमें यह पता होता है कि अमुक कार्य नैतिक रूप से सही नहीं, लेकिन सुख के लिए वह कार्य करने से संकोच नहीं करते। इसमें अक्सर दूसरे के हितों की बलि चढ़ जाती है।

ब्राह्मण का सपना

संकलित

प्रेरणा

एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उसपर लेटे-लेटे विचित्र सपने लेने लगा, और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपए हो जाएगा। उन सौ रुपयों से मैं दो बकरियां लूँगा। छः महीने में उन दो बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा। गौओं के बाद भैंसे लूंगा और फिर घोड़े ले लूंगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊँगा। मेरी सम्पत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी सुरुपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोमशर्मा रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल-लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोमशर्मा मुझे देखकर मां की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी मां को क्रोध से कहूँगा- 'अपने बच्चे को संभाल।' वह गृह-कार्य में व्यग्र होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारुंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तु-भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गए।

अंतर्मन

आज की पाती

कलह की शिकार हो गईं पार्टियां

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें निकट आती जा रही हैं, वैसे-वैसे सभी राजनीतिक गठबंधनों के बीच का अंदरूनी कलह बंद कमरे से बाहर निकल कर सड़को पर आता जा रहा है। महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले एकदम नई तरह की परिस्थितियां सामने आ गई है। महाअघाड़ी में शामिल शिवसेना पार्टी से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद तो प्राप्त कर लिया है, मगर उसके बाद अजीत पवार गुट के सत्ता में शामिल होने से उनकी अहमियत घटती जा रही है। क्योंकि बीजेपी की पूरे महाराष्ट्र पर अच्छी पकड़ है, इसलिए वह अपनी शर्तों पर सहयोगी दलों को सीटें आवंटित कर रही है, जिसे लेकर एनडीए में शामिल अन्य दल कसमसा रहे हैं।

- महेंद्र विश्वकर्मा, बलौदाबाजार

ट्रेंड

मोदी की गारंटी का परिणाम

छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। इस बार भी बस्तर समेत पूरे प्रदेश के मेरे परिवारजन एक सशक्त सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। मोदी की गारंटी का परिणाम है कि पहले जो भारत को आंखें दिखाते थे, आज वो आटे के लिए भटक रहे हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

चीजें उपयोग के लिए

लोगों का उपयोग करना और चीजों से प्यार करना-यह जीवन की पूरी तरह से गलतफहमी है। चीजें उपयोग के लिए हैं। लोग प्यार के लिए हैं। स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि संपूर्णता है।

-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

राजनीति में नहीं जा रहा

मैं अपने राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं या चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला करता हूं तो मैं इसकी घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा।

-संजय दत्त, अभिनेता

ऐसे बनें आदर्श व्यक्ति

मैंने अपने गुरु से पूछा 'मुझे एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए?' उन्होंने उत्तर दिया, 'एक उद्यमी का दिमाग, एक एथलीट का शरीर और एक कलाकार की आत्मा रखने का प्रयास करें।'

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

करंट अफेयर

मोदी समर्थकों ने अमेरिका के 16 शहरों में निकाली रैली

अमेरिकी राजधानी में ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और लिंकन स्मारक से लेकर ईस्ट कोस्ट में प्रतिष्ठित गोल्डन ब्रिज तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सैकड़ों समर्थकों ने आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी जीत के लिए रैलियां कीं और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के 400 से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद जताई। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (ओएफबीजेपी) यूएसए द्वारा रविवार को 'मोदी का परिवार मार्च' रैलियों का आयोजन किया गया था। एक मीडिया विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भारत में आगामी लोकसभा चुनावों में 400 से अधिक सीटें जीतने के समर्थन में 16 से अधिक शहरों में प्रमुख स्थानों पर रैलियां आयोजित की गईं। ओएफबीजेपी-यूएसए के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने कहा, 'भारत के विभिन्न राज्यों, कश्मीर से केरल और महाराष्ट्र से लेकर पूर्व का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य अमेरिका के 16 से अधिक शहरों में प्रमुख स्थानों पर 'मोदी का परिवार' के रूप में मार्च करने के लिए जुटे।

ऑफ बीट

क्या मेरा चश्मा मेरी नजर खराब कर रहा है?

कुछ लोग चश्मे पर बढ़ती निर्भरता को महसूस करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या उनकी आंखें 'आलसी' हो गई हैं। हमारी आंखें ऑटो-फोकस कैमरे की तरह ही काम करती हैं। प्रत्येक आंख के अंदर एक लचीला लेंस मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है जो लेंस को समतल करने के लिए मांसपेशियों को आराम देकर हमें दूर की वस्तुओं (जैसे फ्रुटी स्कोरबोर्ड) पर ध्यान केंद्रित करने देता है। जब मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं तो यह लेंस को उन चीजों को देखने के लिए अधिक कठोर और शक्तिशाली बनाता है जो हमारे बहुत करीब हैं (जैसे कि एक टैक्स्ट मैसेज)। लगभग 40 वर्ष की आयु से, हमारी आंख का लेंस धीरे-धीरे सख्त हो जाता है और आकार बदलने की क्षमता खो देता है। धीरे-धीरे, हम निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देते हैं। इसे 'प्रेसबायोपिया' कहा जाता है और फिलहाल इस लेंस को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। चश्मा बनाने वाले इस लेंस की कमी को चश्मे से ठीक करते हैं जो आपके प्राकृतिक लेंस का भार लेते हैं। लेंस आपको अतिरिक्त अपवर्तक शक्ति प्रदान करके उन नज़दीकी छवियों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद देते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com